{ संपादकीय }

नई दिल्ली, शुक्रवार 7 जून 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

शेयर बाजार में हुए खिलवाड़ का सच

मंगलवार, 4 जून को जब 18वीं लोकसभा के लिए चुनावों के नतीजे आए, तो इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन से यह राहत मिली कि लोकतंत्र और संविधान बच गया, लेकिन वहीं शेयर बाजार के निवेशकों के लिए यह दिन राहत की जगह आफत की खबर लेकर आया। एक्जिट पोल आने के बाद शेयर बाजार में जो उछाल देखने मिला था, वह नतीजों के आने की शुरुआत के साथ ही बुलबुले की तरह फूट गया। मंगलवार को निवेशकों के एक कारोबारी सत्र में ही 30 लाख करोड़ रुपये डूब गए। जाहिर है ये निवेशकों की जेब से निकल कर किन्हीं बड़े खिलाड़ियों की जेब में ही गए होंगे। क्योंकि लाखों करोड़ रूपए हवा में गायब नहीं हुए, एक के खाते से निकल कर दूसरे के खाते में गए। अब सवाल यही है कि वो कौन से खिलाड़ी हैं, जिन्हें शेयर बाजार में इस उछाल और गिरावट का फायदा मिला। और किस तरह इन लोगों को बाजार में होने वाली इस हलचल की पहले से ही खबर थी।

चुनावों के पहले चरण के बाद से ही शेयर बाजार मे गिरावट का सिलसिला देखा जा रहा था और तब से ही कयास लगने लगे थे कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल नहीं होगा। इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनादेश जा सकता है। क्योंकि सत्ता परिवर्तन की आहट शेयर बाजार को पहले लग जाती है। खबरें थीं कि मई माह में विदेशी निवेशकों ने बड़ी मात्रा में अपने निवेश वापस ले लिए थे, इसका नुकसान भारतीय शेयर बाजार को हुआ। लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयानों में शेयर बाजार को लेकर भविष्यवाणियां की। नरेन्द्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि 4 जून को शेयर बाजार में उछाल आएगा, वहीं अमित शाह ने भी कहा था कि निवेशकों को स्टॉक खरीद लेने चाहिए क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि 4 जून को बाजार चढ़ेगा।

याद नहीं पड़ता कि इस देश के किसी प्रधानमंत्री या गृहमंत्री ने इससे पहले इस तरह चुनावों के बीच में और खासकर परिणाम आने वाले दिन से पहले शेयर बाजार के निवेशकों को कोई सलाह दी हो। पूर्ववर्ती मोदी सरकार के अनेक अनैतिक कामों में अब इसे भी जोड़ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का काम सरकार चलाना, देश की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना है। उन्हें शेयर बाजार का खिलाड़ी नहीं बनना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें इस खेल में किसी सोची-समझी रणनीति के तहत शामिल किया गया। भाजपा के कमजोर प्रदर्शन को देखते हुए यह आशंकाएं जतलाई जा रही थीं कि शायद भाजपा फिर सत्ता में न लौट पाए। ऐसे में सरकार के संरक्षण में फल-फूल रहे उद्योगपतियों को भावी नुकसान नजर आने लगा था और शायद उन्हीं के इशारों पर शेयर बाजार का ऐसा खेल चुनाव के बीच में खेला गया, जिसमें लाखों करोड़ डूब गए और देश एक जबरदस्त आर्थिक घोटाले का शिकार हो गया।

चुनाव शुरु होने के पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सामने आया था, जिसका पूरा सच अब तक सामने नहीं आ पाया है और दोषी अब भी मजे में हैं। पीएम केयर्स फंड में किस तरह से, कितना धन आया है, यह तो मोदी सरकार ने पता लगने ही नहीं दिया। कृषि बिल, अग्निवीर योजना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, चीन की घुसपैठ, पुलवामा हमला, वैक्सीन से होने वाली मौतें ऐसी कई बातों का सच अभी सामने नहीं आया है कि आखिर किस नीयत से मोदी सरकार ने इन फैसलों को लिया या जो घटनाएं हुईं, उनकी हकीकत क्या है। और अब एक नया शेयर बाजार का घोटाला भी सामने आ गया है।

1 जून को एक्जिट पोल के आते ही जिस तरह शेयर बाजार चढ़ा था, तब से कांग्रेस इसे लेकर सवाल उठा रही थी और जब नतीजे आए तो अपने एक्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत देने वाली एक सर्वे एजेंसी के मुखिया को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने खरी-खरी बात कही थी कि उनके आकाओं के कारण देश के आम आदमी को इतना नुकसान हुआ है। पवन खेड़ा ने इसे सीधे देशद्रोह कहा था। वहीं अब राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कांफ्रेंस कर शेयर बाजार के इस घोटाले पर कड़े सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने तीन महत्वपूर्ण सवाल किए हैं- पहला, प्रधानमंत्री ने देश की जनता को निवेश की सलाह क्यों दी ? क्यों गृह मंत्री ने उन्हें स्टॉक खरीदने का आदेश दिया ?

दूसरा, दोनों जो इंटरव्यू किए गए। ये अडानी समूह के चैनल को दिए गए। उन पर पहले ही सेबी की जांच बैठी है तो उस पर जांच होनी चाहिए।

तीसरा, मोदी जी के ये जो फेक इन्वेस्टर हैं और जो विदेशी निवेशक हैं। इनके बीच क्या रिश्ता है और अगर रिश्ता है तो इसकी जांच होनी चाहिए।

राहुल गांधी ने कहा कि हम इस पूरे मामले में संसदीय समिति से जांच की मांग करते हैं। इस पूरे मामले में निवेशकों ने करोड़ों गंवाए हैं। यह एक आपराधिक कार्य था।

राहुल गांधी ने झूठे एक्जिट पोल, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की शेयर बाजार को लेकर दी गई सलाह, भाजपा की आंतरिक सर्वे रिपोर्ट, जिसमें उसे सीटें कम आ रही हैं और फिर नतीजों के बाद शेयर बाजार के धराशायी होने की पूरी क्रोनोलॉजी अपनी प्रेस कांफ्रेंस में समझाई। ठीक इसी तरह राहुल गांधी पहले भी नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना लॉकडाउन, वैक्सीनेशन, कृषि कानून, अग्निवीर योजना, जाति जनगणना, आरक्षण को लेकर भाजपा की सोच, इन सबका खुलासा जनता के बीच करते रहे। लेकिन भाजपा प्रायोजित मीडिया ने उन्हें एक नौसिखिया राजनेता की तरह ही दिखाया। हालांकि समय के साथ राहुल गांधी की कही सारी बातें सच साबित हुईं। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने शेयर बाजार में हुए बड़े घोटाले पर सवाल उठाए हैं, तो देखना होगा कि मीडिया इन सवालों पर अब कितनी चर्चाएं करता है, और नयी सरकार बनने के बाद क्या इस घोटाले की जांच होती है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश के लाखों निवेशकों के हितों को ध्यान में रखकर इस पर स्वत: संज्ञान लेकर किसी कार्रवाई के निर्देश देता है।

सहमे-सहमे सरकार नजर आते हैं

लंबे और थकाऊ चुनाव के बाद आए नतीजे हर बार की तरह कुछ नए हीरो लेकर आए हैं तो कई पुराने महारथियों की राजनैतिक विदाई का संदेश भी। ठीक इसी तरह मतदाताओं ने शासन और राजनीति के लिए भी कुछ एकदम नए संदेश दिए हैं तो कुछ पुराने ढर्रे पर अपने अपने ढंग से निर्णय भी सुनाया है और जाहिर तौर पर राजनेता दिन-रात जनता के बीच रहकर भी इन संदेशों को ठीक से नहीं समझते या इनकी उपेक्षा करते हैं तभी हर बार लगभग आधा सदन बदल जाता है। सरकार का स्वरूप बदल जाता है और कई बार तो सरकार बदल जाती है। संयोग है कि इस बार सरकार सीधे-सीधे नहीं बदली है, सरकार के मुखिया भी नहीं बदले हैं लेकिन जनादेश का सबसे ज्यादा प्रभाव उनके इकबाल पर ही दिखता है। सहमे-सहमे से सरकार नजर आते हैं और उनके कामकाज के आधार पर जनता ने उनको फेल भले न किया हो लेकिन उनको अपने रंग-ढंग बदलने का जनादेश तो दिया ही है। ऐसा संदेश या आदेश सिर्फ उनके लिए ही नहीं है। पक्ष-विपक्ष के लगभग सभी नेताओं के लिए है, बहन मायावती, नवीन पटनायक, चौटाला परिवार और महबूबा मुफ्ती के लिए तो कुछ ज्यादा ही सख्त जनादेश आया है।

लेकिन जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा प्रभावी और दूरगामी संदेश नरेंद्र मोदी और उनके जोड़ीदार अमित शाह के लिए है। उनकी उपलब्धियों को लेकर भी शंका जताई गई है लेकिन उनकी कार्यशैली पर ज्यादा सख्त निर्णय आया है। फैसले लेने की प्रक्रिया, मुसलमानों के प्रति उनका रवैया, मुद्दों का चुनाव, विपक्ष से ही नहीं अपने साथियों के साथ व्यवहार का तरीका और शासन चलाने की शैली पर बहुत साफ निर्णय आया है। सबको साथ, सबका विकास सिर्फ नारा भर नहीं होना चाहिए। यह संदेश नहीं आदेश है और एक ही दिन में प्रधानमंत्री और अमित शाह बदले-बदले लगे (उनके इशारों पर नाचने वाली मीडिया में बदलाव और ज्यादा और जल्दी दिखाई दिया)। सबकी 'फ़ाइल मेन्टेन' करना, फिर जरूरत के हिसाब से अपनी लोकतान्त्रिक सत्ता के साथ सरकारी एजेंसियों के दुरूपयोग से दबाव बनाना, मीडिया के सहारे और प्रचार पर सरकारी धन खर्च करके अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश करना, विरोध का निरादर ही नहीं मतदाताओं को फुसलाए जाने की चीज मानना, लोगों का उपयोग करके रद्दी की टोकरी में डालना, मौका पड़ने पर किसी का भी पैर पकड़ लेना (किसानों का उदाहरण सबसे चर्चित है) और निरंतर एक नकली विमर्श चलाते रहना ही इस कार्यशैली की मुख्य बातें हैं। लेकिन आप कुछ लोगों को पूरे समय बुद्धू बना सकते है, सबको कुछ समय तक बुद्धू बना सकते हैं लेकिन सबको सदा के लिए बुद्धू नहीं बना सकते।

अरविन्द मोहन

> नतीजों ने जरूर झटका दिया है लेकिन बदलाव तभी शुरू हो गया था जब नीतीश कुमार की पहल पर इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी। तब तक भाजपा जाने कितने गीदड़ और एक शेर वाला लाइन चला रही थी। इंडिया के समांतर एनडीए को जिंदा किया गया और नए सहयोगी बनाने के लिए जाने क्या कुछ नहीं किया गया। पुराने मामले खोलने और जेल भेजना भी इनमें शामिल था।

और बड़े हिसाब से देखें तो यह चुनाव प्रबंधन कौशल से जीतने के अति आत्मविश्वास या घमंड और आमजन की भावनाओं के स्वाभाविक अभिव्यक्ति के बीच का मुकाबला था। कई लोग इसे मोदी और शाह के घमंड के रूप में देखते हैं लेकिन यह बुनियादी तौर पर अपने साधन, संघ के मुफ़्त के कार्यकर्ताओं और प्रबंधन कौशल को सबसे ऊपर मानने की मानसिकता थी। और भले राहुल गांधी ने लाख अपमान सहकर भी लगातार खुद को सुधार या और मेहनत की (भाजपा उनके करीबियों को तोड़ती भी रही) तथा उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने चुनाव के समय मजबूती दिखाई। लेकिन सच कहें तो मोदी-शाह की जोड़ी की ताकत से असली लड़ाई आमजन ने लड़ी। सिर्फ लड़ी नहीं जीत भी हासिल की। ऐसे-ऐसे नए और अनाम उम्मीदवारों ने भाजपा के दिग्गजों और इस जोड़ी के दुलारे नेताओं (स्मृति ईरानी और टोनी से लेकर नृपेन्द्र मिश्र के सुपुत्र तक) को पटखनी दी कि हम आप सभी तालियां बजाने को मजबूर हुए। और इस जीत का नतीजा ही है कि भाजपा के इन दोनों नेताओं का व्यवहार और बाडी लैंग्वेज एकदम बदला है। कई बार यह सुखद लगता है, कई बार दया आती है।

नतीजों ने जरूर झटका दिया है लेकिन बदलाव तभी शुरू हो गया था जब नीतीश कुमार की पहल पर इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी। तब तक भाजपा जाने कितने गीदड़ और एक शेर वाला लाइन चला रही थी। इंडिया के समांतर एनडीए को जिंदा किया गया और नए सहयोगी बनाने के लिए जाने क्या कुछ नहीं किया गया। पुराने मामले खोलने और जेल भेजना भी इनमें शामिल था। इन तरीकों से नीतीश कुमार को तोड़ना और चंद्रबाबू को जबरिया साथी बनाने में 'सफलता मिली (आज यही दोनों लाज बचाने वाले साबित हुए हैं) लेकिन अन्नाद्रमुक और उससे भी बढ़कर बीजद को साथ ला पाना संभव नहीं हुआ। कई तरह से सहयोग तो ओवैसी जैसों ने भी दिया। लेकिन सीधा साझीदार न बनकर भी बसपा ने जिस तरह से मदद की वह खुद उसके लिए आत्मघाती साबित हुआ। अब बहनजी की दौलत बचने का भरोसा जितना है उससे ज्यादा पक्का यह लग रहा है कि बसपा का आधार ही बिखर जाए। इससे छिटके दलित मतदाताओं ने ही उत्तर प्रदेश में, भाजपा को सबसे बड़ा झटका दिया। वह संविधान ही मोदी का सबसे बड़ा बोझ साबित हुआ जिसे वे खिलौना समझ रहे थे। राहुल, प्रियंका, अखिलेश, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी, स्टालिन, ममता, कल्पना सोरेन और शरद पंवार की राजनीति को कम नहीं आंकना चाहिए लेकिन यह कहने में हर्ज नहीं है कि यह साधन, सत्ता और मैनेजरों के सहारे चुनाव जीतने के अति आत्मविश्वास और जनता पर भरोसा करने की दो अलग-अलग शैलियों की राजनीति का मुकाबला था और भले मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं लेकिन उनकी शैली हार गई है। ज्यादा से ज्यादा 240 सीटों तक ही पहुंच पाई। पहले विपक्ष और लोग सहमे थे अब सत्ता पाकर भी मोदीजी और शाह जी सहमे नजर आते हैं।

आगे इसी चीज पर गौर करना होगा कि कांग्रेस या स्टालिन या अखिलेश गठबंधन की राजनीति पर, जनता पर, देश की विविधता का आदर करने पर भरोसा करते हैं या इस बार की छोटी कामयाबी पर ऐंठकर नुकसान उठाते हैं। पर इनसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आई है जिनको राजनीति के साथ सत्ता भी चलानी है। और हमारे मोदी जी को विचार विमर्श, सहयोगियों की राय लेना, उसका आदर करना, विरोध पर भी गौर करना और काम से काम उन लोगों की राय भी जानना आता ही नहीं जो उनके फैसलों से प्रभावित होते हैं। कश्मीर में यही हुआ, किसानों के साथ यही हुआ, धर्माचार्यों के साथ वही हुआ और मुसलमान तो हिन्दू वोट के लिए चारा ही बनाए गए थे। लोगों का आदर, देश की विविधता का आदर और सबको साथ लेकर चलना उन्हें आएगा या नहीं यह चिंता की बात है। पर यह रिकार्ड भी है कि लाख सख्त दिखने के बावजूद मौका पड़ने पर कोर्स कारेक्शन में वही सबसे तेज भी हैं।

नवीन पटनायक एक टूटते हुए सितारे की तरह राजनीति पटल से हुए ओझल

■ सुशील कुट्टी

केवल एक भावुक रोमांटिक व्यक्ति ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बारे में इस समय सोच सकता है, जो बीजेडी प्रमुख के जीवन के सबसे बुरे दिन हैं। नवीन पटनायक इतिहास बन चुके हैं और उन्हें सामान्य सार्वजनिक जीवन से भुला दिया जायेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा में बीजू जनता दल के सुचारू रूप से चलने वाले शासन को एक शानदार प्रदर्शन के साथ रोक दिया, जिसका भगवा पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरण नहीं कर सकी। एक तरह से कहें तो, अगर नवीन पटनायक हार गये हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई कमाल नहीं किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में साहस का परिचय दिया, लेकिन भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा के चेहरों पर दिख रही उदासी कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी, जिसे नवीन पटनायक ने नजरअंदाज कर दिया होता। इनमें से कोई भी भाजपा नेता ओडिशा में भाजपा की शानदार जीत या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बारे में नहीं सोच रहा था। वे तो केवल नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन के आसन्न अंत को देख रहे थे।

> नवीन पटनायक अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और चंद्रबाबू नायडू फिर से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, जब तक कि वे इंडियी गठबंधन में फंसकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी समूह में शामिल नहीं हो जाते। इस स्थिति में, वे आंध्र प्रदेश के लिए वह 'विशेष दर्जा' प्राप्त कर सकेंगे, जिसकी राज्य को चाहत है और शायद अपने लिए 'उप प्रधानमंत्री' का पद भी।

लोकसभा में साधारण बहुमत हासिल न कर पाने पर भाजपा में व्याप्त दुख ने ओडिशा में पार्टी की जीत को पूरी तरह से मिटा दिया, यहां तक कि बेहद मुखर संबित पात्रा भी अपनी आवाज नहीं निकाल पाये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि ओडिशा की 20 लोकसभा सीटें भाजपा ने न जीती होतीं, तो उनके लिए उनकी भी कर्कश आवाज गुम हो जाती। ओडिशा ने मोदी और भाजपा को तत्काल शर्मसार होने से बचा लिया। प्रभु पुरी जगन्नाथ ने पात्रा की 'जुबान फिसलने' को माफ कर दिया होगा।

क्या लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा मोदी की शान को याद करेगी ? क्या ओडिशा को बीजू जनता दल के पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद नवीन पटनायक का शांत स्वभाव याद आयेगा ? 'जो जीता वही सिकंदर' वाली कहावत नवीन पटनायक के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लागू होती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू सुर्खियों में हैं, जबकि नवीन पटनायक को इस लेख में विराम चिह्न या विस्मयादि बोधक चिह्न तक नहीं मिलेगा।

चंद्रबाबू नायडू ने वह हासिल किया जो नवीन पटनायक दो दशकों से हासिल कर रहे थे। लेकिन ओडिशा में बीजेडी की जीत नवीन पटनायक को सुर्खियों में नहीं ला सकती थी, क्योंकि वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुर्खियों का लालच नहीं करता था। वह नई दिल्ली के शोरगुल वाले सत्ता गलियारों के बजाय ओडिशा के अपने शांत कोने को पसंद करता था। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू के विपरीत, जो एक समय में दिल्ली के मंच पर 'राजनीतिक प्लेबॉय' की तरह चलते थे, कठिन सौदेबाजी करते थे, और कठिन गिरावटों को झेलते थे।

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन की राजनीति की मजबूरियों के चलते झुकेंगे और बिहार, आंध्र प्रदेश और 'भाजपा के अपने ओडिशा' को 'विशेष दर्जा' देंगे, जबकि वे बराबरी के लोगों में से एक हैं और भाजपा को अपनी 'डबल इंजन' वाली छवि खोने का खतरा है ? यह कितना बड़ा पतन है - आज यहां, कल कहां ? नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक दोनों के सितारे गर्दिश में हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने सत्ता के दिनों से बाहर निकल चुके हैं और नवीन पटनायक के मुख्यमंत्री के रूप में करियर को चुपचाप दफना दिया गया है। नवीन पटनायक को ओडिया पर 'एक तमिल' थोपना नहीं चाहिए था। वीके पांडियन नवीन पटनायक के हाथ मिलाने के लिए मौजूद नहीं होंगे।

तो नवीन पटनायक अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और चंद्रबाबू नायडू फिर से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, जब तक कि वे इंडियी गठबंधन में फंसकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी समूह में शामिल नहीं हो जाते। इस स्थिति में, वे आंध्र प्रदेश के लिए वह 'विशेष दर्जा' प्राप्त कर सकेंगे, जिसकी राज्य को चाहत है और शायद अपने लिए 'उप प्रधानमंत्री' का पद भी। मुद्दा यह है कि आने वाले दिनों में 'विशेष दर्जा' मांगने पर ही मिलेगा, चाहे एनडीए सत्ता में हो या फिर सत्ता की बागडोर इंडिया गठबंधन के हाथ में हो।

नवीन पटनायक ने राज्य के दो विधानसभा क्षेत्रों, कांटाबांजी और हिंजिली से चुनाव लड़ा। वे एक से हार गये और दूसरे से जीते। क्या वे विधानसभा में उतनी बार आयेंगे, जितनी बार वे आते, अगर बीजेडी ने शासन करने का अधिकार नहीं खोया होता ? इसके अलावा, केंद्र में सरकार बनाने में बीजेडी की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन फिर नवीन पटनायक ने सत्ता में रहते हुए भी दिल्ली की राजनीति में कभी अपनी बात नहीं रखी। पटनायक का खुद को अलग-थलग कर लेना, बीजेडी के सामने नई प्रतिकूल परिस्थितियों में और भी मजबूत हो गया है।

नवीन पटनायक और चंद्रबाबू नायडू की तुलना करना, नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह की तुलना करने जैसा है। एक कार्यकारी सफारी में लिपटा हुआ है और दूसरा घरेलू सादगी में लिपटा हुआ है। एक के हर हाव-भाव में हिसाब-किताब लिखा हुआ है, दूसरा जो ज्यादातर अदृश्य रहता था और सीमित महत्वाकांक्षा रखता था। लेकिन आंध्र प्रदेश और ओडिशा दोनों ही राज्यों में क्लीन स्वीप के बाद स्थिर सरकारों का आश्वासन पाकर भाग्यशाली हैं। ऐसा कहा जाता है कि जगन मोहन रेड्डी भी नवीन पटनायक की तरह की ही नाव में हैं। जगन की बहन वाईएस शर्मिला भी बेहतर स्थिति में नहीं हैं।

एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी को मोदी की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट के लिए तैयार कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को 400 से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतने का वायदा कर रहे थे, लेकिन मोदी की इच्छा को आश्चर्यजनक रूप से कम कर दिया गया और नवीन पटनायक मोदी की स्थिति पर टिप्पणी करने के लिए मौजूद नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने 'हैट्रिक ऑफ़ टर्म्स' हासिल किया, लेकिन वे नवीन पटनायक से ज़्यादा बेहतर स्थिति में नहीं हैं। चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब चाहें मोदी के पैरों के नीचे से कालीन खींच सकते हैं। उस स्थिति में, मोदी हमेशा ओडिशा के मुख्यमंत्री पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, आखिरकार नवीन पटनायक ने इस पद के लिए 'बाहरी' वीके पांडियन को चुना था।

पावन प्रसंग

सत्य और अहिंसा स्वाभिमान के प्रतीक

व्यक्तियों में सत्य के प्रति आस्था पैदा हो जाए तो सामाजिक नैतिकता का स्वयं उच्च स्तर को प्राप्त कर सकता है और सही मायने में सत्य ही मनुष्य के आचरण की ऊंचाई मानी जाती है। सत्य और अहिंसा पर चलने के लिए संयम, मनोबल, आत्मशक्ति और ऊर्जा ही एक बड़ा विकल्प है। सत्य और अहिंसा स्वाभिमान के प्रतीक है सत्य बोलने वाला मनुष्य स्वाभिमानी होता है दूसरी तरफ असत्य आत्मग्लानि का द्योतक है। कबीर दास जी ने भी सत्य को ईश्वर मानकर कई दोहों की रचना की है।

नकारात्मक व्यवहार सामाजिक स्तर पर किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण दुर्गुण है क्योंकि इसका प्रभाव पूरे समाज एवं देश पर गंभीर परिणाम देने लगता है। झूठ बोलना और सच को नेपथ्य में धकेलना एक सबसे बड़ी सामाजिक बुराई के रूप में सामने आई है। इसीलिए सामाजिक रूप से झूठ को सबसे बड़ा पाप कहा गया है पाप इस अर्थ में कहा गया है कि यह हमें दिग्भ्रमित करके वंचित कर्तव्य एवं रोजमर्रा के आत्मीय व्यवहार से वंचित रखता है और असत्य कथन को समस्त बुराइयों अपराधों की जननी माना जाता है। हम भौतिकवादी मानसिकता से इतने अधिक ग्रसित हो गए हैं की पारिवारिक सदस्यों के बीच हमारे आत्मीय संबंध लुप्त प्राय होते जा रहे हैं और ऐसे बनावटी परिवेश में व्यक्ति तथा समाज अपनी भौतिक मानसिक विलासिता तथा सफलता के दायरे में सिमट कर रह गया है। इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति अत्यंत उन्मुक्त निसंकोच तरीके से असत्य का सहारा लेने से भी नहीं चूक रहा है। भौतिक सुख साधनों की लालसा में मनुष्य में साधनों की सत्यता तथा शुद्धता फिर भी गहरा समझौता कर समाज में असामाजिक व्यवहार को अपना लिया है जिसके दूरगामी परिणाम भारतीय समाज के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आज मनुष्य नैतिकता एवं अनैतिकता की बारीक लकीर हो पहचानने से काफी दूर हो गया है तथा भौतिक विकास के लिए किसी भी साधन को अपनाने से नहीं परहेज करता है। मानव बुद्धि विवेक संपन्न होने के कारण भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हर तरह के उपायों को नए-नए हथकंडे के रूप है उपयोग करने लगा है जिससे समाज मे विसंगतियां पैदा होकर आत्मीय संबंधों की बलि चढ़ गई है। आदिकाल से ऐतिहासिक तौर पर भी मानव की सच्चरित्रता पर सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं। समाज ने आपसी संबंधों को संचालित करने के लिए कुछ आदर्श मापदंड का प्रावधान भी रखा है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सावधान सत्य बोलने का है किंतु मनुष्य अपने सुख साधन बटोरने के लिए सदैव सत्य से परहेज करने लगा जिससे मनुष्य नैतिकता से काफी दूर हो गया एवं सामाजिक मान्यताओं को छिन्न-भिन्न करता आया है। आज भौतिक साधन संपन्नता समाज में सर्वोच्च शिखर पर है और समाजिक व्यक्तिगत आत्मीय संवेदनशील संबंध ताक पर रख दिए गए हैं। नैतिकता सिद्धांतों की परिपाटी नष्ट प्राय होती जा रही है। ऐसे में एक आदर्श समाज की कल्पना बेमानी हो गई है। आज हमें सामाजिक मूल्यों को बचाने आत्मीय संबंधों की रक्षा करने के लिए सत्य तब और संयम का सहारा लेने की आवश्यकता होगी अन्यथा भारतीय समाज को पश्चिमी समाज के रूप में यहां संवेदनशीलता आत्मीयता और मानवीय संबंधों की गरिमा खत्म होने के कगार पर है अपनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा एवं भारतीय मूल्य संस्कार संस्कृति धीरे धीरे सनातनी समाज से दूर होते जाएंगे और हम हाथ में हाथ धरे देखते रह जाएंगे। आज नैतिकता केवल दूसरों के लिए उपदेश देने की वस्तु बन कर रह गई है। मनुष्य सामाजिक व्यवस्था का स्वयं निर्माता है किंतु नैसर्गिक रूप से लोभी,आलसी, तथा संग्रहण की प्रवृत्ति वाला हो चुका है ऐसे में कम परिश्रम में ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए असत्य फरेब एवं जालसाजी का ही सहारा लेकर अनैतिकता का परचम फैलाने में लगा हुआ है। यह भारतीय परिवेश के लिए कतई शुभ संकेत नहीं है।

संजीव ठाकुर

आपके पत्र

क्यों ठहर जाता है स्लम बस्तियों में विकास का पहिया ?

हमारे देश की एक बड़ी आबादी आज भी ऐसी है जो शहरों और महानगरों में आबाद तो है, लेकिन वहां शहर के अन्य इलाकों की तरह सभी प्रकार की सुविधाओं का अभाव होता है। शहरी क्षेत्रों में ऐसे इलाके स्लम बस्ती कहलाते हैं। यह बस्तियां अधिकतर खाली पड़े सरकारी ज़मीनों पर आबाद होती हैं, जहां सरकारी सुविधाएं तो होती हैं लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाता है। यह बस्तियां केवल राजधानी दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों में ही नहीं होती हैं बल्कि बिहार पटना समेत देश की लगभग सभी राज्यों की राजधानी में आबाद होती हैं। इन बस्तियों में अधिकतर आर्थिक रूप से बेहद कमजोर तबका निवास करता है जो रोजी रोटी की तलाश में गांव से निकल कर शहर की ओर पलायन करता है। इनमें रहने वाले ज्यादातर परिवार दैनिक मजदूरी के रूप में जीवनयापन करता है। अक्सर ऐसी बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में भी चिन्हित किया जाता है।

साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 1.23 लाख स्लम एरिया हैं जिनमें करीब 6.55 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है। इनमें से अधिकतर बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सहित कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं। ऐसी ही एक स्लम बस्ती बिहार की राजधानी पटना स्थित गर्दनीबाग इलाके में भी आबाद है। बघेरा मोहल्ला के नाम से दर्ज यह बस्ती पटना हवाई अड्डे से महज 2 किमी दूर और बिहार हज भवन के ठीक पीछे स्थित है। ऐतिहासिक शाह गड्डी मस्जिद, (जिसे स्थानीय लोग सिगड़ी मस्जिद के नाम से जानते हैं), से भी इस बस्ती की पहचान है। इस बस्ती तक पहुंचने के लिए आपको एक खतरनाक नाला के ऊपर बने लकड़ी के एक कमजोर और चरमराते पुल से होकर गुजरना पड़ता है।

यहां रहने वाली 80 वर्षीय रुकमणी देवी बताती हैं कि वह इस बस्ती में पिछले 40 सालों से रह रही हैं। इस बस्ती में करीब 250-300 घर हैं, जिनकी कुल आबादी लगभग 700 के करीब है। रुकमणी देवी की पहचान क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी रही है। जो इस बस्ती की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम करती रही हैं वह बताती हैं कि 1997 में सरकार ने इस बस्ती को स्लम क्षेत्र घोषित किया था। इस बस्ती में लगभग 70 प्रतिशत अनुसूचित जाति समुदाय के लोग आबाद हैं। जिनका मुख्य कार्य मजदूरी और ऑटो रिक्शा चलाना है।

रुकमणी देवी के अनुसार, स्लम क्षेत्र घोषित करने के बाद राज्य सरकार की ओर से यहां विकास की कई योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की गई थी ताकि यहां के रहने वालों के जीवन स्तर को सुधारा जा सके। उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष काम भी किये जाने की बात कही गई, लेकिन इनमें से अधिकतर योजनाएं लागू होने की जगह फ़ाइलों में दब कर रह गई हैं।

स्कूल के प्रधानाध्यापक मुरारी कुमार बताते हैं कि कम सुविधा में भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल की ओर से हर संभव प्रयास किये जाते हैं। बच्चों को खाने में पौष्टिक आहार के अलावा समय समय पर आयरन की गोलियां और कीड़े मारने की दवाईयां भी खिलाई जाती है। वह बताते हैं कि अनिधिकृत ज़मीन पर बस्ती और स्कूल होने के कारण इस क्षेत्र को बहुत जल्द खाली कराया जा सकता है। ऐसे में यहां पढ़ने वाले बच्चों को गर्दनीबाग के अन्य प्राथमिक विध्यालयों में शिफ्ट किया जा सकता है।

ज्योति कुमारी, पटना बिहार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

महिला भागीदारी बढ़े

श्रम बल अर्थव्यवस्था के विकास का मुख्य आधार है. कामकाजी आयु (15 से 59 वर्ष) के जितने अधिक लोग कार्यरत होते हैं, वृद्धि दर को उतनी ही गति मिलती है. इसके लिए आवश्यक है कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़े. हमारे देश में कामकाजी आयु की महिलाओं की संख्या 46 करोड़ से भी अधिक है. विश्व बैंक का आकलन है कि इनमें से लगभग एक-तिहाई हिस्सा ही श्रम बल में सक्रिय है. यह भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत के वैश्विक औसत से बहुत कम है. कामकाजी आयु की महिलाओं की संख्या यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों की कुल आबादी से भी अधिक है. उल्लेखनीय है कि ये महिलाएं पूर्ववर्ती पीढ़ियों की अपेक्षा अधिक शिक्षित और स्वस्थ हैं तथा वे आकांक्षाओं से भी लबरेज हैं. हालांकि भारत की आर्थिक वृद्धि दर आज बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है तथा इस गति के बने रहने की संभावना भी है, पर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने के संकल्प को साकार करने के लिए हमें कई मोर्चों पर तेजी लाना होगा. श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना इनमें सबसे महत्वपूर्ण है. वर्ष 2018 में विश्व बैंक ने कहा था कि यदि 50 प्रतिशत महिलाएं कामकाजी हो जाती हैं, तो भारत की विकास दर नौ प्रतिशत हो सकती है. उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2023-24 में यह दर 8.2 प्रतिशत रही है, जो वर्तमान और अगले वित्त वर्ष में कम हो सकती है. चीन में ढाई दशकों में महिला भागीदारी में गिरावट आयी है, पर अभी भी वह 61 प्रतिशत के स्तर पर है. आज जब दुनिया उत्पादन और आपूर्ति शृंखला के लिए चीन के विकल्प की तलाश में है, तो यह भारत के लिए बहुत अच्छा अवसर है. इसका लाभ हमें मिल भी रहा है, पर वह देश की क्षमता एवं संभावनाओं की तुलना में बहुत कम है. यदि कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ती है, तो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का विस्तार होगा. जीडीपी में महिलाओं का योगदान अभी केवल 18 प्रतिशत है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम अनुपातों में है. ऐसा नहीं है कि महिलाएं काम नहीं करतीं. घरेलू काम और बच्चों को संभालने में वे कई घंटे लगी रहती हैं, जिसका कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता. चीन में भी ऐसी स्थिति सदियों तक रही थी, पर समानता और अवसर मिलने से वहां महिलाओं का विकास द्रुत गति से हुआ. आज चीन की अर्थव्यवस्था में वे 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान करती हैं. महिलाओं के शिक्षण-प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए हो रहे प्रयासों को तेज किया जाना चाहिए. देश में जितनी महिलाएं फैक्ट्रियों में काम करती हैं, उनमें 40 प्रतिशत से अधिक केवल दक्षिण भारतीय राज्यों में कार्यरत है. भारत के अन्य भागों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए.

यदि 50 प्रतिशत महिलाएं कामकाजी हो जाती हैं, तो भारत की विकास दर नौ प्रतिशत हो सकती है.

बरकरार है ममता बनर्जी की लोकप्रियता

जयंत घोषाल
वरिष्ठ पत्रकार
https://x.com/jayanta_ghosal1

साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें गंवाने के बावजूद पश्चिम बंगाल में भाजपा एक सफल कहानी रही है, क्योंकि उसे पहले कामयाबी मिल चुकी है. हाल तक राज्य में पार्टी की कोई उपस्थिति नहीं थी. जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही थे. मुझे याद है, जब वाजपेयी-आडवाणी दौर में भाजपा को कोलकाता नगर निगम में दो सीटें हासिल हुई थीं, तब पार्टी ने खूब जश्न मनाया था. उस समय लालकृष्ण आडवाणी, वे तब केंद्रीय गृह मंत्री थे, ने बयान दिया था कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपना खाता खोला है. उस समय से अब तक भाजपा बहुत आगे जा चुकी है. विधानसभा में उसके 77 विधायक हैं. राज्य से राज्यसभा में भी भाजपा की एक सीट है. भाजपा की इस तेज बढ़त से विपक्ष की राजनीतिक जगह को लेफ्ट और कांग्रेस हासिल नहीं कर सके. लेफ्ट तो शून्य के स्तर पर पहुंच चुका है. पिछले विधानसभा चुनाव में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार नहीं जीत सका था, जबकि एक नयी बनी मुस्लिम पार्टी आइएसएफ का एक उम्मीदवार विधायक बनने में सफल रहा था. इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली.

लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अनेक सभाएं एवं रैलियां हुईं. भाजपा का अपना तरीका है नयी पीढ़ी के नेताओं को प्रोत्साहित करने का. प्रधानमंत्री मोदी ने संदेशखाली में पार्टी की उम्मीदवार रेखा पात्रा से फोन पर बात की थी. उन्होंने कृष्णानगर से उम्मीदवार रानी मां को भी फोन किया था. यह बड़प्पन ही है कि मंच पर रेखा पात्रा भाषण दे रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनको सुन रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी एक बेहद समझदार राजनेता हैं. जहां तक इस चुनाव में भाजपा के सफल नहीं होने और ममता बनर्जी की बड़ी जीत के कारणों का सवाल है, तो मेरी दृष्टि में सबसे प्रमुख वजह यह है कि भाजपा बंगाल की पार्टी नहीं बन सकी है. बंगाल में हिंदी भाषी भी हैं, पर अधिकांश लोग तो बंगाली ही हैं. भाजपा अखिल भारतीय पार्टी बने, पर उसे बंगाल की पार्टी भी होना होगा. जब राज्य भाजपा के अध्यक्ष पद से विष्णुकांत शास्त्री को हटाकर तपन सिकदर को कमान दी गयी थी, तब आडवाणी जी ने मुझसे कहा था कि शास्त्री सरनेम लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीति नहीं की जा सकती है, इसीलिए सिकदर को लाया गया है, जो बंगाली हैं. शास्त्री जी अच्छे नेता थे. वे विद्वान व्यक्ति भी थे और कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्राध्यापक थे. वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं के अनुवादक भी थे. वे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के भी शिक्षक रहे थे. इसके अलावा वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी संबद्ध रहे थे.

अभी भाजपा के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार बंगाली ही हैं. शुभेंदु अधिकारी को भी पार्टी में लाया गया. इस तरह मोदी-शाह की रणनीति तो ठीक है, पर बंगाली मानस को ठीक से समझने की आवश्यकता है. जब राम मंदिर का मुद्दा अयोध्या में सफल नहीं हुआ, तो बंगाल में कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह नहीं है कि बंगाल के लोग राम विरोधी हैं. बंगाल की मुख्य देवी मां काली हैं और यहां के लिए दक्षिणेश्वर एवं कालीघाट अधिक महत्वपूर्ण है. बंगाल की संस्कृति में एक नास्तिक भी हिंदू हो सकता है. इसलिए उत्तर भारत में हिंदुत्व का जो मॉडल कारगर होता है, उसे पश्चिम बंगाल में थोप देना अच्छी बात नहीं है. दूसरी बड़ी वजह है ममता बनर्जी की लोकलुभावन राजनीति. उदाहरण के लिए, हर गरीब महिला को हर महीने एक हजार रुपये देने की योजना बहुत प्रभावी साबित हुई है. इस राशि में चुनाव से पहले बढ़ोतरी भी हुई थी. ममता बनर्जी ने अपने प्रचार अभियान में यह भी कहा था कि अगर भाजपा जीतती है, तो वह इस योजना को बंद कर देगी. भाजपा के भी एक धड़े ने इस योजना को गलत बताया था. ऐसे अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं. जैसे, एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें कोई भी महिला अपना मुफ्त इलाज करा सकती है. ऐसी योजनाओं का लाभ ममता बनर्जी को मिला. उन्हें मुस्लिम मतों के एकजुट होने का भी फायदा मिला. तीसरी वजह है कि भाजपा ने मुख्य रूप से ममता-विरोधी अभियान चलाया. शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें चोर तक कहा. इससे ममता बनर्जी को सहानुभूति मिली. यदि भाजपा तृणमूल सरकार के विरुद्ध अभियान चलाती, तो ऐसा नहीं होता.

चौथी बात है कि शुभेंदु अधिकारी सीबीआइ, इडी आदि एजेंसियों के प्रवक्ता के रूप में व्यवहार करने लगे थे. वे कहते थे कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. भ्रष्टाचार रोकने और दोषियों को पकड़ने की बात ठीक है, लेकिन इसकी आड़ में विरोधियों को डराने-धमकाने की कोशिश हुई. इससे ऐसा संदेश गया कि भाजपा एजेंसियों के सहारे राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है. इस बात को ममता बनर्जी भी अपने भाषणों में कहती रहीं. पांचवीं वजह है कि तृणमूल कांग्रेस ने इंटरनेट और सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल किया है, जबकि प्रधानमंत्री मुख्यधारा की मीडिया को इंटरव्यू देते रहे. उन्होंने बंगाल के ऐसे चैनलों को भी इंटरव्यू दिया, जिनकी टीआरपी बहुत कम है. डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल की योजना के सूत्रधार अभिषेक बनर्जी थे. उन्होंने भाजपा के आक्रामक आरोपों, जैसे संदेशखाली प्रकरण, का तुरंत जवाब देने की रणनीति भी अपनायी. संदेशखाली में उन्होंने एक भाजपा नेता का ही स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, जिसमें बताया गया कि यह मामला एक राजनीतिक साजिश भर है.

राज्य में सांगठनिक स्तर पर भाजपा का कमजोर रहना भी परिणामों में एक कारक रहा है. साथ ही, भाजपा के पास एक भरोसेमंद चेहरे का अभाव भी है. उत्तर प्रदेश में जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हैं, वैसे पश्चिम बंगाल में भाजपा का कोई कद्दावर नेता नहीं है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की भी बहुत अधिक लोकप्रियता है, पर उनके संदेश को घर-घर तक पहुंचाने के लिए ठोस सांगठनिक मशीनरी नहीं है. इस बार भाजपा ने अपने अभियान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पहले की तरह शामिल नहीं किया. दोनों के बीच कुछ खटास भी रही, जिसके कारण संघ उतना सक्रिय नहीं दिखा. परिणाम के बाद भाजपा के भीतर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कुछ नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है. अगर भाजपा अपनी कमियों को दूर नहीं करती है, तो 2026 के विधानसभा चुनाव में भी उसे बहुत नुकसान हो सकता है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

भाजपा ने मुख्य रूप से ममता-विरोधी अभियान चलाया. शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें चोर तक कहा. इससे ममता बनर्जी को सहानुभूति मिली. यदि भाजपा तृणमूल सरकार के विरुद्ध अभियान चलाती, तो ऐसा नहीं होता. शुभेंदु अधिकारी सीबीआइ, इडी आदि एजेंसियों के प्रवक्ता के रूप में व्यवहार करने लगे थे.

पाकिस्तान को अपनी गलती का अहसास

डॉ धनंजय त्रिपाठी
प्राध्यापक
साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नयी दिल्ली
dhananjay@sau.ac.in

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यह स्वीकार किया है कि करगिल में घुसपैठ कर और लड़ाई छेड़ कर 1999 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुए लाहौर समझौते का उल्लंघन किया था. नवाज शरीफ तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे. जब 21 फरवरी, 1999 को दोनों नेता लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तब पाकिस्तानी सेना करगिल में घुसपैठ कर रही थी. इसका नतीजा लड़ाई के रूप में सामने आया और पाकिस्तानी सेना को पीठ दिखा कर भागना पड़ा था. उस समय परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख थे और बाद में नवाज शरीफ को तख्तापलट में अपदस्थ कर राष्ट्रपति बने थे. भारत ने गलती मानने के इस बयान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और कहा है पाकिस्तान में करगिल मसले पर सही समझ उभर रही है. नवाज शरीफ पहले भी अनेक बार कह चुके हैं कि पाकिस्तानी सत्ता द्वारा वाजपेयी को धोखा दिया गया था, लेकिन इस बार बयान इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह बात उन्होंने अपनी पार्टी की शीर्ष बैठक में कही है. उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग सत्तारूढ़ दल है और वे इसके अध्यक्ष हैं तथा उनके भाई शहबाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री हैं.

नवाज शरीफ का बयान यह स्वीकार करने का संकेत भी है कि भारत के साथ संबंध खराब रख कर पाकिस्तान की उन्नति नहीं हो सकती है. राजनीतिक निर्वासन से उनकी वापसी के बाद से यह उम्मीद लगायी जा रही थी कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार का दौर शुरू होगा. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से खराब स्थिति से गुजर रही है. चुनाव में भी यह प्रमुख मुद्दा था. तब यह समझ उभर रही थी और सेना को भी लगने लगा था कि भारत के साथ आर्थिक संबंध ठीक करना होगा तथा पाकिस्तान को दक्षिण एशिया के साथ जुड़ना होगा. आज सभी पड़ोसी देशों के साथ पाकिस्तान के संबंध खराब हैं. ऐसे में उसे यह भी समझ में आने लगा है कि वैश्विक स्तर पर भी वह महत्वहीन हो गया है और उसका दोहरा चरित्र सबके सामने स्पष्ट हो चुका है. इस माहौल में अगर उसे नये सिरे से कूटनीतिक पहल करनी है, तो यह जरूरी हो जाता है कि वह भारत के साथ रिश्ते बेहतर करे. यदि पाकिस्तान की ओर से इस दिशा में प्रयास होता है, तो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर इसकी सराहना भी होगी. पाकिस्तान यह भी देख रहा है कि वैश्विक परिदृश्य में भारत का महत्व बढ़ता जा रहा है और अर्थव्यवस्था में प्रगति हो रही है. उसे यह स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से भारत के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है. ऐसे दौर में जब तमाम देश भारत के साथ संबंध बेहतर कर रहे हैं, तब पाकिस्तान के पास भारत से निकटता बढ़ाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है.

इस संदर्भ में दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण आयाम है. दक्षिण एशिया राजनीतिक रूप से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है. वह परिवर्तन यह है कि दक्षिण एशियाई देश चीन के साथ-साथ भारत के साथ भी संबंध अच्छा करना चाहते हैं. अभी हमने देखा कि किस तरह मालदीव फिर से भारत के साथ निकटता बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है. हमारे पड़ोसी देश यह अच्छी तरह देख रहे हैं कि भारत एशिया में एक उभरती हुई शक्ति है. इसका असर भी पाकिस्तान पर पड़ा है. चीन पर उसकी अत्यधिक निर्भरता न तो उसके हित में है और न ही पाकिस्तान के पुराने हितैषी अमेरिका को यह भाता है. यह भी है कि नवाज शरीफ की भारत में खास दिलचस्पी रही है. पहले हमने देखा कि दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के बाद भी लाहौर समझौता हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के प्रारंभिक वर्षों में शरीफ भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहे. तब ऐसा लगने लगा था कि दोनों देश दीर्घकालिक सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं.

नवाज शरीफ के बयान को एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए. वहां की मौजूदा सरकार को कई दलों का समर्थन प्राप्त है. सेना की ओर से भी रिश्ते बेहतरी के लिए संकेत हैं. मुझे आशा है कि जल्दी ही दोनों देशों के बीच संवाद का दौर शुरू होगा और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के प्रयास होंगे. भारत और पाकिस्तान के संबंध में सबसे बड़ा अवरोध आतंकवाद और अलगाववाद को पाकिस्तान के समर्थन एवं संरक्षण के कारण रहा है. अब पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं है कि वह भारत को क्षति पहुंचाये. असल में आतंक से सबसे अधिक त्रस्त आज पाकिस्तान ही है. वहां के लोगों, नीति-निर्धारकों तथा रणनीतिक विद्वानों को यह अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि पड़ोसी देशों में आतंकवाद और अलगाववाद को हवा देने की पाकिस्तान की नीति लंबे समय तक कारगर साबित नहीं हो सकती है, बल्कि उससे देश को ही नुकसान हुआ है तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी विश्वसनीयता बहुत कम हुई है. इसलिए उस नीति को बदलने की जरूरत है और ऐसा होगा भी. भारत-पाकिस्तान संबंधों में सुधार से दक्षिण एशिया को ही नहीं, बल्कि समूचे एशिया को लाभ होगा. इस दिशा में बड़े पहलों की आशा और संभावना बन रही है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

अगर पाकिस्तान को नये सिरे से कूटनीतिक पहल करनी है, तो यह जरूरी हो जाता है कि वह भारत के साथ रिश्ते बेहतर करे. यदि उसकी ओर से इस दिशा में प्रयास होता है, तो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर इसकी सराहना भी होगी. पाकिस्तान यह भी देख रहा है कि वैश्विक परिदृश्य में भारत का महत्व बढ़ता जा रहा है और अर्थव्यवस्था में भी प्रगति हो रही है.

देश दुनिया

दक्षिण अफ्रीकी चुनाव में एएनसी से मोहभंग के कारण

दक्षिण अफ्रीका में 29 मई को हुए चुनावों से पहले, सत्ताधारी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस (एएनसी) ने पिछले 30 वर्षों में देश में हुई सामाजिक-आर्थिक प्रगति की ओर ध्यान आकर्षित करने के बहुत प्रयास किये, ताकि मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सके. इनमें सबसे प्रसिद्ध है फरवरी में राष्ट्र के संबोधन में राष्ट्रपति और एएनसी नेता सिरिल रामफोसा द्वारा 'टिंट्स्वालो'- एक काल्पनिक अश्वेत महिला, जिसका जन्म 1994 में रंगभेद के पतन और एएनसी का सत्ता में उदय के बाद हुआ था- की कहानी के माध्यम से अपनी पार्टी की दीर्घकालिक उपलब्धियों को उजागर करने का प्रयास. राष्ट्रपति के अनुसार, टिंट्स्वालो की प्रेरक कहानी अधिकांश दक्षिण अफ्रीकी युवाओं की कहानी है और एएनसी के तहत हुई व्यापक प्रगति का एक दृष्टांत है. यह सच है कि ऐसे कई दक्षिण अफ्रीकी हैं जिनकी जीवन स्थितियों और भविष्य की संभावनाओं में एएनसी सरकारों के दौर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. परंतु इसके बावजूद टिंट्स्वालो की कहानी कई दक्षिण अफ्रीकी लोगों को 29 मई को एएनसी के पक्ष में मतदान करने के लिए मनाने में विफल रही. उसे केवल 40.18 प्रतिशत वोट मिले. एएनसी को चुनाव में मिले झटके के क्या कारण हैं? एएनसी को लंबे समय से पता था कि पार्टी के कई दीर्घकालिक समर्थक उसके हालिया प्रदर्शन से नाखुश हैं, क्योंकि उच्च स्तरीय अपराध, बेरोजगारी, खराब सेवा वितरण और भ्रष्टाचार देश की पहचान बन चुके हैं. हालांकि उसने बीते कुछ वर्षों में चीजों को सही, भ्रष्टाचार को समाप्त, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और अर्थव्यवस्था को ठीक करने का वादा किया था. हालांकि भ्रष्टाचार एकमात्र कारण नहीं है जिसके कारण मतदाताओं ने इस चुनाव में एएनसी से मुंह मोड़ लिया. सार्वजनिक सेवाओं में तेजी से जारी गिरावट निसंदेह एक और कारण रहा जिसके चलते बड़े पैमाने पर लोगों ने सत्तारूढ़ दल को वोट न देने का निर्णय लिया. **-ताफी म्हाका**

बोधि वृक्ष

जीवन में बड़ी उपलब्धि

कुछ लोग सोचते हैं कि भाग्य के कारण ही जीवन में बड़ी उपलब्धि होती है. कुछ कहेंगे अचानक हो गया, पर न तो भाग्य से कुछ होता है, न ही अचानक कुछ होता है. सब पूर्व संस्कारों का परिणाम है. मनुष्य को इसका पता नहीं होता और वह इसी को भाग्य मान लेता है. मनुष्य दुनिया में आया है परमपुरुष को पाने के लिए, परंतु इस यात्रा में जीव और परमपुरुष के बीच बाधा डालने वाली शक्ति है माया. एक जीव का मन आगे बढ़ना चाहता है, पर उसके सामने मोहक वस्तुएं, तरह-तरह के आकर्षण आ जाते हैं, जिनके चलते वह जैसा चाहता है वैसा कर नहीं पाता. जैसा सोचना चाहता है, वैसा सोच नहीं सकता. वह चाहता है कि इस विषय पर सोचूं, पर मन बार-बार हट जाता है. यहां बाधा डालने वाली शक्ति है अणुमाया. जो माया सर्वजैविक स्तर पर काम करती है, उसे कहते हैं महामाया. जो अव्यक्त और व्यक्त जगत, यानी सर्वत्र काम करती है, उसे कहते हैं विश्वमाया. जो माया जीव को शिव से या परमपुरुष से मिलने में सहायक होती है, उसे कहते हैं विष्णुमाया. साधक कहता है, 'हे परमपुरुष! तुम मेरे साथ हो, मेरे कर्म में, मेरे वचन में, मेरी चिंता में, सब में तुम रहो और मुझको बल दो ताकि मैं सतपथ पर चल सकूं. मुझे केवल तुम पर भरोसा है.' ऐसा सोचना है, अभिध्यान. सभी मनुष्य को याद रखना चाहिए कि उसके लक्ष्य, उसके ध्येय एकमात्र परमपुरुष हैं. सबके लिए परमपुरुष के प्रति भक्ति ही सबसे बड़ा उद्देश्य है. इस संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, यहां तक कि मानसिक शक्ति भी. एक बड़ा विद्वान है, कल पागल हो गया तो उसे लोग विद्वान नहीं, पागल कहेंगे. पर भक्ति स्थायी भाव है. यही मानसिक शक्ति भी देती है. परमपुरुष देश, काल, पात्र से परे हैं और भक्ति की बदौलत तुम उन तक पहुंच सकते हो. भक्ति ही अंत तक तुम्हारे साथ रहेगी. मनुष्य को भक्ति से कभी डिगना नहीं चाहिए. जिनके पास भक्ति नहीं, उनके पास सब कुछ रहने के बावजूद उनकी आत्मा रेगिस्तान है. परमपुरुष उन्हीं से जुड़ते हैं जिनके पास भक्ति भाव हो.

-श्री श्री आनंदमूर्ति

कुछ अलग

मानवीय संबंध और ज्योतिष

संतोष उत्सुक
टिप्पणीकार
santoshutsuk@gmail.com

नयी ज्योतिषीय सलाह दी जा रही है. कुंडली को दिखाकर, सलाह मानकर, समझ और जानकर प्रेम करना शुरू करें. विवाह तो सितारों के अनुसार पहले से सुनिश्चित होता है. यह बात दीगर है कि वैवाहिक सामंजस्य और विच्छेद के माहिर सलाहकार मानते हैं कि शादी एक व्यवस्था है. ज्योतिषी कह रहे हैं कि शादी के दो वर्ष बाद तक की परिस्थितियों में कौन सी तारीख, मुहूर्त अहम है पहले बता देंगे. इससे विवाह के बाद के संभावित या आशंकित बदलाव स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकते हैं. पहले से ही तय कर सकेंगे कि आपस में कैसा व्यवहार और बदलाव करना है.

ज्योतिष पूरी दुनिया में हैं. दुनियाभर में अपने-अपने विश्वास, अंधविश्वास, टोने-टोटके हैं. प्रसिद्ध लोग भी मानते हैं कि इससे लाभ होता है. विदेशों में यह प्रचलन बढ़ रहा है, क्या वहां भी जीवन में टहल रही परेशानियों के कारण, सुरक्षा घेरा बनाने के लिए, भविष्य में होने वाली अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है. पश्चिमी देशों की तरह वैवाहिक संबंधों को हमारे यहां भी चुनौती माना जाने लगा है. समाज में भौतिक विकास के साथ, विदेशी दृष्टिकोण उग रहे हैं, उन्हीं से बचने के लिए ज्योतिष की सहायता ली जा रही है. प्रश्न है कि क्या वैवाहिक रिश्ते, ज्योतिषीय सलाह और उपायों से सचमुच लाभान्वित होते रहे हैं. खरा सच यह है कि वर्तमान जीवनशैली में, घर चलाने के लिए पति-पत्नी दोनों को काम करना पड़ रहा है. सक्षम लड़कियां शादी के बाद पूरा स्पेस चाहती हैं. आपसी नोक-झोंक, परेशानी, तनाव बढ़ रहे हैं. दोनों चुपचाप अपने-अपने शांत रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को एक-दूसरे की जरूरत है. अकेले रहने की दुश्वारियां अधिक चुनौतीपूर्ण हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए. व्यावसायिक स्तर पर, विवाह संस्था खतरे में तो है, हालांकि अभिभावक यही चाहते हैं कि किसी तरह उनके बच्चों की शादी सुलटी रहे.

यदि संभावित परिस्थितियां और घटनाएं, ज्योतिषी पहले बता देगा, तो क्या विवाह का किला फतह करने जा रहे भावी पत्नी-पति का आत्मविश्वास कम नहीं होगा. उन्हें जरा-जरा सी बात के लिए खास दिन, मुहूर्त पर निर्भर रहना होगा. ज्योतिषी के निरंतर संपर्क में रहना होगा. समझदार, व्यावसायिक ज्योतिषी अपनी सेवाओं के एवज में भुगतान भी लेगा. जिंदगी की स्वाभाविक परेशानियों और आकस्मिक दुखों को झेलने, निपटने की नैसर्गिक शक्ति कमजोर हो जायेगी. संघर्ष के चंगुल में पहले से फंसा व्यक्ति, भविष्य के बारे में चिंतित होना शुरू हो जायेगा, तब क्या सभी विवाह करना चाहेंगे? सकारात्मक मानवीय सोच को कमजोर कर, बाजार के हवाले करने की कोशिश है यह, जिससे बचना लाजमी है.

आपके पत्र

आरओबी पर नहीं जलते बल्ब

दानापुर स्टेशन से फुलवारीशरीफ होकर पटना जंक्शन जाने वाली सड़क पर एक रेल ओवरब्रिज है. इसका उद्घाटन 2016 को हुआ था. आश्चर्यजनक है कि इस पर लगे लगभग दो सौ बल्ब कभी नहीं जले. हालांकि इस पुल से बड़े-बड़े रेल अधिकारी और मंत्री-सांसद भी गुजरते हैं, लेकिन रात में पुल पर छाया अंधेरा किसी को दिखाई नहीं देता. इससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है. कई बार हादसे भी हो चुके हैं. इस पर ध्यान देने की जरूरत है.

अपराजिता सिन्हा, खगौल, पटना

वट सावित्री पूजा सदियों पुरानी

महिलाएं सदियों से अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री पूजा करती आ रही हैं. इसी दिन माता सावित्री यमराज से अपने मृत पति को वापस जीवित लेकर आयी थी, तभी से पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं वट सावित्री पूजा का अनुष्ठान करती हैं. यह एक प्रकृति पूजा भी है, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में इस पूजा के दौरान वट वृक्ष के पत्ते तोड़ने की गलत परंपरा जुड़ गयी है. यह प्रकृति प्रेम का अनादर है. इस पूजा के दौरान वट वृक्ष में पानी डालना चाहिए एवं नये वट के पौधे लगाना चाहिए.

हिमांशु शेखर, केसपा, गया

https://epaper.prabhatkhabar.com

संपादकीय

इस बार जनादेश के मायने

अठारहवीं लोकसभा के चुनाव परिणाम ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि मतदाता के मन को समझना इतना आसान नहीं हैं। इसी तरह से एग्जिट पोल के परिणामों और धरातलीय परिणामों में अंतर से साफ हो जाता है कि मतदाता खुलता भी नहीं है तो किसके पक्ष में मतदान करके आया है उसे वह मुखर होकर बताता भी नहीं है। चुनाव परिणामों से सट्टा बाजार की भी पोल खुल कर रह गई है। ऐसे में सवाल यह हो जाता है कि मतदाता इस जनादेश के माध्यम से आखिर संदेश क्या देना चाहते है? लोकसभा चुनाव परिणाम से यह तो साफ हो गया है कि मतदाता ने एनडीए को तीसरी बार सरकार चलाने का अवसर दे दिया है। बहुमत के 272 की तुलना में एनडीए को 293 सीटें मिली हैं। यह अलग बात है कि पिछले दो चुनावों की तरह इस बार भाजपा अकेले स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। बावजूद इसके वह लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। देखा जाए तो 10 साल बाद किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इससे यह भी तो स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता विरोधी लहर उतनी नहीं रही जितनी दस साल के शासन के बाद सामान्यतः आ जाती है पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा आदि के माध्यम से मतदाता ने अपनी नाराजगी जाहिर करने में किसी तरह का संकोच भी नहीं किया है। दरअसल जनआकांक्षाओं और सरकार की परफारमेंस के बीच अंतर को पाटने में सरकार पूरी तरह से सफल नहीं रही। हालांकि परफारमेंस के पैरामीटर्स या यूं कहें कि मापदण्ड बदलते रहते हैं। एक बात यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह मेंडेट ने केन्द्र सरकार की वर्तमान नीतियों का नकारा नहीं है। दरअसल जनता कहीं न कहीं संतुलन चाहती हैं। सरकारों को जहां एग्रेसिव होना अच्छा लगता हैं वहीं जनता कहीं न कहीं डिलीवरी सिस्टम को लेकर भी चिंतित रहती है। केवल उज्जवल और एग्रेसिव छवि, सफल विदेश नीति, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद, धर्म, आर्थिक विकास या यूं कहें कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ही बहुत से ऐसे कारक है जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। इसमें कोई दोराय नहीं कि दुनिया का सबस बड़ा और सफलतम लोकतंत्र हमारे यहां है। लोकतांत्रिक देशों में सर्वाधिक राजनीतिक दलों वाला भी हमारा ही देश है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था व चुनाव व्यवस्था की सारी दुनिया कायल है। पर इसके साथ ही अब आमजन का मनोभाव यह है कि राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए ना कि मंडी बाजार जैसी एक-दूसरे पर छींटाकशी। वास्तविकता तो यह है कि अब प्रमुख राजनीतिक दलों का काम आरोप-प्रत्यारोप लगाने तक सीमित हो गया है। दूसरी बात धर्म की करें तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या की सीट पर भाजपा की हार ने पार्टी को निराश किया है। साफ संकेत हैं कि केवल श्रीराम लला या धर्म के नाम पर ज्यादा दिन नहीं चला जा सकता। एक अन्य बिंदु आर्थिक एजेंडा को लेकर है। कहीं भी मतदाता ने आर्थिक एजेंडे को नकारा नहीं हैं। पर लोग अब महंगाई से त्रस्त हो रहे हैं तो बाजार पर सरकार का नियंत्रण कम होने से परेशान है। जनमानस जहां आर्थिक क्षेत्र में हाई ग्रोथ चाहने लगा है तो सबसे बड़ी समस्या रोजगार के अवसरों को लेकर है। पक्ष व विपक्ष सभी का प्रिय मुद्दा नौकरियां है। सरकार जहां कहती है कि लाखों की संख्या में नौकरी के अवसर विकसित किए हैं वहीं विपक्ष नौकरियां नहीं मिलने की बात करता रहा है।

ऐतिहासिक चुनाव और परिणाम भी रहे ऐतिहासिक

मृत्युंजय दीक्षित

> संतोष की बात यह रही कि कम मतदान प्रतिशत और उत्तर पदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रान्तों में अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद भी राजग गठबंधन को सामान्य बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर मिल गया । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में आयोजित विजय कार्यक्रम में अपनी भावी सरकार की रूपरेखा व गारंटियों का एजेंडा भी प्रस्तुत कर दिया। नरेंद्र मोदी जी रहते यह विश्वास बना रहेगा कि भारत सुरक्षित हाथों में है। भाजपा की सीटें कम होने के संभावित कारण- प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर करने के लिए अनेकानेक अभियान चलाये गये, षड्यंत्र रचे गए जिसके कारण भाजपा की अपनी सीटों की संख्या कम हो गई

वर्ष- 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं। देश के इतिहास में 1962 के बाद पहली बार किसी दल या गठबंधन को लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा है । इन लोकसभा चुनावों में भीषण गर्मी के बाद भी मतदाता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई । लगभग ढाई महीने लम्बी चली चुनाव प्रक्रिया में प्रारंभ में मतदान का प्रतिशत कुछ कम रहा जिसके कारण सभी राजनैतिक दलों के माथे पर चिंता की रेखाएं भी दिखाई पड़ीं, भारत में माना जाता रहा है कि अगर कम मतदान होता है तो सरकार बदल जाती है किंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ है यद्यपि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र व हरियाणा के कारण अकेले दम पर बहुमत नहीं मिल सका। पश्चिम बंगाल को छोड़कर चुनाव से लेकर मतगणना तक शांतिपूर्वक संपन्न हो गई । इन लोकसभा चुनावों में भारत की जनता ने यह बता दिया है कि लोकतंत्र में वही सबसे बड़ी भविष्यवक्ता है। अबकी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 400 पार का नारा दिया था वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडी गठबंधन कह रहा थ कि वह मोदी जी को किसी भी कीमत पर 400पार जाने से रोकेंगे। जनता ने भाजपा गठबंधन को 292 सीटें देकर सरकार तो बनवा दी है किंतु विपक्ष को भी मजबूत कर दिया है । 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम राजनैतिक उथल- पुथल के पुराने समय की आशंका भी उत्पन्न करते हैं जब गठबंधन सरकारें हुआ करती थीं, संतोष ये है कि इस समय गठबंधन का नेतृत्व मोदी जी के सबल हाथों में है । 024 लोकसभा चुनावों के साथ सपन्न हुए चार प्रान्तों के विधान सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन की ऐतिहासिक जीत हुई, जिसमें ओडिशा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है ,वहीं आंध्र प्रदेश में तेलुगूदेशम के साथ सरकार बनेगी जबकि अरुणांचल प्रदेश में भी भाजपा लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। राजग गठबंधन की यह सफलता ऐसी है कि वह जीत कर भी उदास है और वहीं विपक्ष ऐसे हल्ला मचा

रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जादू उतर गया है जैसे उसे बहुमत मिल गया हो जबकि वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का प्रभाव है कि उनके नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू के ही कारण आज भाजपा का परचम लहरा रहा है और उसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान से लेकर हिमांचल प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिण भारत व पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी सफलता प्राप्त हुई है । केरल जैसे राज्य में भाजपा का पहली बार खाता खुल गया है। वहीं तमिलनाडु में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ गया है और उसके 10 प्रत्याशी दुसरे स्थान पर रहे हैं। ये सभी भाजपा के लिए शुभ संकेत हैं। बंगाल अवश्य भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन रहा है क्योंकि वहां पर भाजपा ने संदेशखाली में महिलाओं पर अमानवीय अत्याचारों का मुद्दा उठाया था, जिससे अपेक्षा थी कि बंगाल में भाजपा की सीटें बढेंगी किंतु वहां पर बढ़ने की बजाय घट गई हैं। बंगाल के लिए आगामी दिनों भारतीय जनता पार्टी को विशेष ध्यान देना होगा। बंगाल में जब तक हिंसा होती रहेगी तब तक भाजपा का बंगाल जीतना बहुत कठिन है। तुष्टिकरण के दम पर ममता ने वहां अच्छी पकड़ बना ली है। सबसे बड़ी निराशा- भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका उप्र में लगा है और सबसे दुखद क्षण अयोध्या (फैजाबाद) संसदीय सीट में भारी पराजय रही।यहाँ की पराजय ने विजय के स्वाद को कसैला कर दिया है जहां भव्य राम मंदिर, एयरपोर्ट, मेडिकल कालेज, नए बस व रेल स्टेशन बनने तथा वंदेभारत ट्रेन की सौगात देने के बाद भी भाजपा हार गई । फैजाबाद में हिन्दुत्व के अश्वमेध के घोड़े को जातिवाद के समीकरणों व तुष्टिकरण की राजनीति ने रोक दिया है। फैजाबाद की पराजय एक बहुत बड़ा सबक व संदेश है हिंदू समाज के लिए। प्रदेश में योगी सरकारआते ही अयोध्या का कायाकल्प आरम्भ हो गया, दीपोत्सव के साथ ही नगर की आभा लौटने लगी, उपेक्षित पड़े क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा में लाया गया। स्वयं मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की देखभाल की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 और उससे पूर्व तथा फिर चुनाव के मध्य भी अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किये तथा भव्य रोड शो निकाला। सब कुछ करने के बाद भी भाजपा का हार जाना दुखद है । संतोष की बात यह रही कि कम मतदान प्रतिशत और उत्तर पदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रान्तों में अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद भी राजग गठबंधन को सामान्य बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर मिल गया । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में आयोजित विजय कार्यक्रम में अपनी भावी सरकार की रूपरेखा व गारंटियों का एजेंडा भी प्रस्तुत कर दिया। नरेंद्र मोदी जी रहते यह विश्वास बना रहेगा कि भारत सुरक्षित हाथों में है। भाजपा की सीटें कम होने के संभावित कारण- प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर करने के लिए अनेकानेक अभियान चलाये गये, षड्यंत्र रचे गए जिसके कारण भाजपा की अपनी सीटों की संख्या कम हो गई। विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में अनेक अफवाहें फैलाई थीं जिसमें सबसे बड़ी अफवाह यह थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वह दो महीने बाद योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे भाजपा के कार्यकर्ता इस अफवाह पर नियंत्रण नही कर पाये जिसका असर उत्तर प्रदेश व राजस्थान में कई क्षेत्रों में देखा गया। इसी तरह गृहमंत्री जी के भाषण का ए.आई. की सहायता से सम्पादित आरक्षण सम्बन्धी वीडियो भी बड़ा खेल कर गया, जब तक भाजपा कुछ समझ पाती खेल हो चुका था। इन चुनावों में तथाकथित खान मार्केट गैंग ने भी भाजपा को नुकसान पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक फैले इस गैंग ने संविधान बचाने तथा आरक्षण को लेकर लगातार फेक नैरेटिव चलाये जिसका असर भी चुनाव परिणामों पर दिख रहा है। आरक्षण और संविधान बचाने के नाम पर मुस्लिम व दलित एक साथ हो गये तथा जिन इलाकों में मुस्लिम मतदाता चुनावों को प्रभावित रखने की क्षमता रखता है वहां पर उसने भाजपा को हराने के लिए एकमुश्त मतदान किया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश का बाराबंकी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत अधिक संख्या में हैं वहां पर उसने भाजपा को हराने के लिए वोट किया है जबकि आम हिंदू मतदाता अपने घरों में बैठा रहा और वह पिकनिक मनाने के लिए निकल गया। कुछ सीटों पर हिंदू मतदाता भाजपा की ओर से अच्छा उम्मीदवार न होने के कारण भी शांत हो गया। लेकिन ये बात शायद कहीं गंभीर है और गहन विवेचना मांगती है क्योंकि राजनाथ सिंह और मोदी जी को भी अपनी अपनी सीटों पर संघर्ष करना पड़ा। अंतिम सत्य यही है कि मतदाता ने एक बार फिर भाजपा गठबंधन को सरकार बनाने व पांच साल सरकार चलाने का सुनहरा अवसर दिया है। यह भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के लिए स्वर्णिम अवसर है। मतदाता ने आज भी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बनने, गगन यान जैसी वैज्ञानिक पहलों और राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपना विश्वास केवल और केवल मोदी पर व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही अपने वचनों की गारंटी ले चुके हैं अतः अब हमें भी आने वाले पांच वर्षों की तरह देखना चाहिए ।

कविता

"झूमता बसन्त है"

फूलों में, कलियों में, पत्तो में, फलियों में,
गाँव की गलियों में, प्यार के छलियों में,
झूमता बसन्त है।

रंगों में, अंगों में, प्रेम के प्रसंगों में,
बागों में, बहारों में, गांवों में, बाजारों में,
झूमता बसन्त है।

बच्चों में, जवानों में, बूढ़ो में, सयानो में,
दीवानों परवानों में, मेरे-तेरे अरमानों में,
झूमता बसन्त है।

एक में, लाखों में, प्यार भरी आंखों में,
सरसों के फूलों में, प्रीत के झूलों में,
झूमता बसन्त है।

गेंदा में, गुलाब में, आफताब मेहताब में,
फितरत में, कुदरत में, मोहब्बत में, नफरत में,
झूमता बसन्त है।

हंसने में, मुस्काने में, अदा में इतराने में,
प्यार में, जलन में, विरह में, मिलन में,
झूमता बसन्त है।

नदियों में, पहाड़ों में, गर्मी में, जाड़ो में,
दिन में रात में, बातों ही बात में,
झूमता बसन्त है।

संजीव

रोकनी होगी भोजन की बर्बादी

रमेश सर्राफ धमोरा

रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती है। जिसके बिना मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल है। इसमें रोटी सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि रोटी के बिना तो मनुष्य जिन्दा भी नहीं रह सकता है। खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित किया जाना है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में हर दस में से एक व्यक्ति दूषित भोजन का सेवन करने से बीमार पड़ जाता है। जो कि सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए इस बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस संक्षिप्त रूप में मनाया जाएगा। जिसमें लोगों को सेहत से जुड़े मुद्दों पर ऑनलाइन एक-दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। इस बार हम छठवां विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इससे खाद्य सुरक्षा लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा सकती है और विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों से होने वाली बीमारियों को भी ध्यान में लाया जा सकता है। इस दिन को मनाने के पीछे खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगो को जागरूक करने का उद्देश्य था। जो खराब भोजन का सेवन करने की वजह से गंभीर रोगों के शिकार बन जाते हैं। भोजन की कमी व दूषित भोजन खाने से प्रतिवर्ष हजारों लोगों की जान चली जाती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन को दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों का नेतृत्व करने और पौष्टिक खाने के प्रति लोगों को जागरुक करने की जिम्मेदारी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में पहली बार खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया था। इसके बाद पहली बार 7 जून 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। तब से हर वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व में अपने मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता से बात करते हुए लोगों से खाने की बबार्दी रोकने की अपील की थी। उन्होने कहा कि ऐसा करना गरीबों के साथ अन्याय व समाजद्रोह है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपने कभी सोचा है कि हम जो जूठन छोड़ देते हैं। उससे हम कितने गरीबों का पेट भर सकते है? उन्होने कहा था कि इस पर सामाजिक जागरूकता बढनी चाहिए। भारत में अनाज को अन्नदेव का दर्जा प्राप्त है। यही कारण है कि हमारे देश में भोजन झूठा छोडना या उसका अनादर करना पाप माना जाता है। मगर आधुनिकता के चक्कर में हम अपने पुराने संस्कार भूल गए हैं। हमारे यहां शादियों, उत्सवों या त्यौहारो में होने वाली भोजन की बबार्दी से हम सब वाकिफ हैं। इसके उपरांत भी हम इन अवसरों पर ढेर सारा खाना कचरे में फेंक है। कई बार तो घरों के आसपास फेंके गए भोजन से उठने वाली दुर्गंध एवं सड़ांध वहां रहने वालों के लिए परेशानी खड़ी कर देती हैं।

विचार

नागरिकों में राष्ट्रवादी चरित्र आवश्यक

संजीव

राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रवाद शालाओं की बुनियादी शिक्षा कक्षाओं और गुरु और शिष्य परंपरा के साथ देश के प्रति समर्पण के भाव से प्रस्फुटित होता है' राष्ट्रवाद राष्ट्र की रक्षा ,अखंडता एवं सशक्तिकरण नागरिकों के भाग्य को संरक्षित कर सुदृढ़ बनाता है' स्वतंत्रता के बाद विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के स्वप्न द्दष्ट प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के भावी भविष्य को पहचानते हुए बुनियादी कक्षाओं की राष्ट्रवाद के निर्माण में भूमिका को सहजता से पहचान लिया और अमेरिका की तर्ज पर भारत को तकनीकी तौर पर एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए अमेरिका के एमआईटी की तर्ज पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करवाया था ।जब खड़कपुर आईआईटी की स्थापना की गई थी तब उन्होंने अतिथि के रूप में अपने भाषण में कहा की भारत को वैज्ञानिक महाशक्ति बनाने का दायित्व इन्हीं आई,आई,टी की कक्षाओं शिक्षकों एवं छात्राओं का होगा, वे राष्ट्र को तकनीकी दिशा में मील का पत्थर बनाने में साबित होंगे'

वर्तमान में भारत आज अंतरिक्ष की बड़ी शक्तियों की कतार में शामिल है' इसके पीछे भारत के कई वैज्ञानिक सीवी रमन ,विक्रम साराभाई, सतीश धवन जैसे बड़े वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इसरो संस्थान है जिसकी कक्षाओं में मंगल तक भारतीय तिरंगे को लहराया. भाभा एटॉमिक परमाणु शक्ति बन गया है' वैश्विक स्तर पर हर बड़े स्पेस रिसर्च सेंटर पर भारत की इंजीनियर और वैज्ञानिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं' आज अमेरिका आर्थिक महाशक्ति बनने के पीछे उसके विश्वविद्यालय ,संस्थाएं हैं। हावर्ड बिजनेस स्कूल विश्व स्तरीय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में से एक माना जाता है' आर्थिक सामाजिक तथा वैज्ञानिक शोध संस्थाओं में अधिकाधिक धनराशि खर्च करके अमेरिका, रूस, ब्रिटेन ,चीन, ऑस्ट्रेलिया ,कनाडा ने विश्व में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी दिए हैं' यह तो तय है कि कोई भी देश का भाग्य तभी उन्नत तथा विकसित होगा जब वहां के छात्र शिक्षक एवं आमजन न्याय, समता ,प्रबुद्धता के प्रति अपनी अडिग प्रतिबद्धता रखें। आने वाली पीढ़ी यानी कि वर्तमान के बच्चे और भविष्य के नागरिक ही किसी देश का भविष्य निर्माण करते हैं और यह भी तय रहता है कि बुद्धिमान शिक्षक अपने छात्रों के माध्यम से किसी महान राष्ट्र की नींव रखते हैं। किसी भी महान राष्ट्र का निर्माण रातों-रात नहीं होता है इसके लिए पीढीयो का योगदान और श्रेष्ठ शिक्षक एवं छात्रों की लग्न शीलता और मेहनत की प्रतिबद्धता होती है। 1960 और 70 के दशक में चीन में गठित सांस्कृतिक क्रांति कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, खेतों ,कारखानों को एकता में बांधकर सक्रिय नीति का प्रयोग कर सभी को एक सूत्र में बांधा गया था। जापान तो प्राथमिक कक्षाओं से उपजे राष्ट्रवाद, अनुशासन तथा कर्तव्य बोध के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रहा है, जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पराजय का कड़वा घूंट पीने के पश्चात कमजोर एवं मृतप्राय जापान को एक शक्तिशाली आर्थिक राष्ट्र बना दिया। इसके विपरीत वर्तमान कक्षाएं प्रेम, अनुशासन ,करुणा जैसे पाठ ना सिखा कर ईर्ष्या, कंपटीशन, हिंसा ,कटुता जैसे अध्याय सिखा कर राष्ट्र के भविष्य को गर्त में ले जा रही है देश के अनेक विश्वविद्यालय हड़ताल ,हिंसा, जाति भेदभाव, आपत्तिजनक नारों जैसे विसंगतियों का सामना कर रहे हैं। कक्षाओं का नैतिकता, सहिष्णुता ,अनुशासन से कटाव केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में इसका फैलाव हो चुका है। अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में स्कूलों का कक्षाओं में गोली कांड इसके बड़े विकृत उदाहरण हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ट्रीस्ट विद डेस्टिनी के भाषण में भूख, भय ,बीमारी, अज्ञान से पूर्णता मुक्ति की बात को भारत की नियति या डेस्टिनी कहा है।

वर्तमान में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए की कक्षाओं को चरित्र निर्माण ,अनुशासन ,उत्कृष्ट नवाचार ,लोकतांत्रिक विचार संरचना का केंद्र बनाकर इसकी शिक्षा दीक्षा दी जानी चाहिए। कक्षाओं से बच्चे आर्थिक रूप से प्रौद्योगिकी स्थापित कर स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर आने वाले वर्षों में कई युवाओं को रोजगार देकर संपूर्ण मानवता ,पर्यावरण की रक्षा तथा राष्ट्र के उत्कर्ष को सही दिशा देने का

एक्शन इंडिया दैनिक

भगवान शंकर जी के ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

आरएनआई: HARHIN / 2016 / 68417

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक रवि भारद्वाज, 261 ग्लबोल स्पेसिज, पार्ट-2, सेक्टर-33, करनाल, हरियाणा ने मारुतिनंदन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, शक्ति कॉम्प्लेक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110042 से छपवाकर प्रकाशित किया।

"एक्शन इंडिया" में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। संपादक या प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

स्थानीय संपादक: राजकुमार शर्मा (प्रिन्स)

समूह संपादक : रवि भारद्वाज

9999889104, 9250706656

ई-मेल : actionindiaharyana@gmail.com

वैधानिक सूचना

पाठकों को सलाह है कि एक्शन इंडिया, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के आधार पर कोई निर्णय लेने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित उक्त उत्पाद या सेवा के बारे में आवश्यक जांच-पड़ताल कर लें। समाचार पत्र प्रबंधक किसी भी विज्ञापन में गुणवत्ता, सेवा आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है। अतः समाचार पत्र उक्त विज्ञापनों के बारे में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

व्यंग्य

सरकारी बाटी नेता जी खाए

रामविलास जांगिड़

बाटी चूरमा की उत्पत्ति राजस्थान में मेवाड़ साम्राज्य के संस्थापक बप्पा रावल के शासन में हुई। मैं उस टाइम पर नहीं था, वरना मुझ पर ही बाटी आविष्कार का आरोप लगता। जब मैं बाटी खाता हूं तो क्षेत्र के सारे हाथी आकर मुझे देखने लग जाते हैं। आज घर में कितनी ही जंग हो आटे को रेत में दबाए जाना सख्त मना है। घर में ऐसा कर दिया तो परम शांति काल में भी जंग मच जाता है। जब सैनिक जंग से लौटते तब तक सूरज की चिलचिलाती धूप से रेत में रखे आटे के गोले पककर तैयार मिलते थे। आजकल ऐसा नहीं होता है। पति-पत्नी दोनों नौकरी शुदा होते हैं। तब ऐसी बाटी खाने के लिए उनको बाजार का रास्ता देखना पड़ता है या फिर किसी ओवन में बाटी पकाने का जतन करना पड़ता है। इसके बाद वे सैनिक इन पकी हुई बाटियों को खोदकर निकालते थे और घी मलकर खाते थे। इधर घी मलने के लिए मात्र दलाल और चमचे ही उपलब्ध हैं। इधर बाटी खाने के कुछ रूल्स रेगुलेशन है। एक आचार संहिता, नियम, कायदा है। जैसे भ्रष्टाचार भक्षण के रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं। बाटी-खोरों को एक बड़ा सा कटोरा दिया जाता है। साथ ही उसे भाटे की एक लोडी दी जाती है। इससे बाटी को फोड़ा-कुचला जाता है। उसका कचूमर किया जाता है जैसे मंत्री जी जनता को कुचलते हैं। जब बाटी को इत्मीनान से कुचल दिया जाता है, तो फिर इसमें घी डालने का क्रियाकर्म किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया की बाटी खाते समय ऐसे ढीले-ढाले कपड़े पहनें, जैसे कोई आदमी हॉस्पिटल में गहरी बीमारी लेकर भरती होता है।

बाटी खाते समय टाइट जींस अगर किसी जातक ने पहन ली, तो उस जींस का फटना तय है। उसके बाद में जो भी रील बनेगी, वो जाने कितने सोशल मीडिया पर वायरल होगी। टाइट जींस तो सर्वथा वर्जित रहेगी। बाटी-खोर को जमीन पर ही बैठना चाहिए। आलथी-पालथी मार कर बैठते हुए दाएं-बाएं दो व्यक्तियों को बिठा लें, जो आपको लुढ़कने से बचा सकते हैं। इधर हमारे यहां एक बाटी-खोर दिखाई दिया। वह बाटियों को इतनी बेदर्दी से खाता कि अच्छे-अच्छे गधे भी उसके सामने गश खाकर पड़ जाते। बाटी लेता। दाल में मिला नींबू निचोड़ता।

सब बोलने की बातें हैं

डॉ. सुरेश कुमार

एक समय था जब झूठ बोलने पर कौवा काटता था। हो न हो यह कौआ अवश्य महात्मा गांधी जी का होगा। वरना इंसान को काटने की हिम्मत किसमें है। वैसे पर्यावरण परिवर्तन के चलते महात्मा गांधी वाले कौए तो कब के लुप्त हो गए। अब जो बचे हैं वे झूठ बोलने पर नहीं सच बोलने पर काटते हैं। इसीलिए लोग सच बोलने से डरते हैं। सच बोलकर कौन मूर्ख बेमतलब का टिटिम्मा पालेगा। सच बोलकर दूसरों को दूर करने से अच्छा है झूठ बोलकर उनके गले काटना। इस तरह गला काटने पर खून का रंग लाल हो न हो लेकिन स्वाद मीठा होता है। यदि ऐसा न होता तो आए दिन इतने गले कट रहे हैं, क्या वह बिना स्वार्थ वाले मीठे स्वाद का होता। आइंस्टीन ने महात्मा गांधी को हांड-मांस का चलता हुआ क्रांतिकारी महापुरुष बताया। उनकी बात मुझे तब सच लगी जब मैंने मुन्ना भाई एमबीबीएस और मुन्ना भाई लगे रहो में गांधीगिरी को देखा। गांधीगिरी के नाम पर टिकट खिड़कियों पर इतनी भीड़ उमड़ी कि एक बार के लिए लगा हो न हो गांधी जी फिर से वापस आ गए हैं। दो फिल्मों को छह घंटे देखकर छह सेकंड में गांधी जी को भुला देने वाली पब्लिक उनके सिद्धांतों को पुड़िया बनाकर पैरों तले कुचलने में आज की दुनियादारी समझती है। क्या होता अगर सच में गांधी जी के सिद्धांतों पर यह देश काम करता? इसमें सोचने वाली बात क्या है। स्वतंत्रता 1947 में मिली। हम वहीं के वहीं रहते। वह तो शुक्र मनाओ कि गांधी जी 30 जनवरी 1948 को जबरन इस दुनिया से चल बसे। तभी तो हम उनकी याद में असत्य, अहिंसा, अधर्म, अन्याय का सफलतापूर्वक पालन करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। सच बोलने वाले, धर्म का पालन करने वाले, न्याय का पक्ष धरने वाले, अहिंसा की बातें करने वाले आदमखोर शेर से भी खतरनाक माने जाते हैं। इसीलिए इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है या फिर राष्ट्रविरोधी कहकर उन पर गद्दार का ठप्पा लगा दिया जाता है। अब तो हर जगह झूठ का बोलबाला है साहब। पैंतीस-चालीस रुपए में पेट्रोल देने के नाम पर सरकार बनाने वाले सौ रुपए में पेट्रोल बेचते हैं। कभी गैस सिलेंडर इतने महंगे थे कि एक महान संस्कृति की पक्षधर अम्मा संसद के सामने गलाफाड़ गृहिणी के रूप में सरकार को हिला देती थीं।

दैनिक
जलते दीप

जोधपुर, शुक्रवार 7 जून 2024

अब की बार- गठबंधन सरकार

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपने गठबंधन का नेता चुन लिया है। इसके साथ ही लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभालने की दिशा में उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ा दिया। दरअसल, इस बार के आम चुनाव में खंडित जनादेश मिला है। किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हो सका है। सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। भाजपा की अगुआई वाले गठबंधन, राजग, को जरूरी बहुमत से कुछ अधिक सीटें प्राप्त हुई हैं, इसलिए वह सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहा है। चूंकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके गठबंधन के पास अस्पष्ट बहुमत है, इसलिए सरकार बनाने का दावा वाजिब है। कांग्रेस की अगुआई वाले इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने के सवाल पर संकेत दिया है कि फिलहाल वे किसी जोड़-तोड़ में नहीं जुटेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे। इससे पहले खबरें आई थीं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू शायद सैद्धांतिक आधार पर राजग के साथ जाने से इनकार कर दें और इसका फायदा इंडिया उठा ले। लेकिन भाजपा की अगुआई वाले गठबंधन की सरकार बनने की राह स्पष्ट हो गई है। पर यह भी तय है कि इस बार भाजपा का गठबंधन के सहयोगियों के साथ वही व्यवहार नहीं रह पाएगा, जो पहले की दो सरकारों के समय देखा गया। इस बार भाजपा को अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं है। उसे सरकार चलाने के लिए हर समय सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। पिछली दो सरकारों के समय भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत था, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि सहयोगी दल किसी मोड़ पर उसकी बांह मरोड़ सकते हैं। इस बार वैसी निश्चिंतता नहीं रहेगी। एक तनी हुई रस्सी पर संतुलन साधते हुए चलने जैसा होगा। जरा-सा भी असंतुलन खतरनाक साबित होगा। फिर, जिन दो दलों- तेलगु देसम पार्टी और जद (एकी) के पास सरकार चलाने के लिए निर्णायक सीटें हैं, उनके साथ संतुलन साधना सबसे अहम होगा। इन दोनों दलों के नेताओं यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भाजपा के साथ सैद्धांतिक मतभेद पहले कई बार उजागर हो चुके हैं। वे बीच में भाजपा का साथ छोड़ कर अलग राह पकड़ चुके हैं। इसलिए उन्हें लेकर भरोसेमंद दावा कोई नहीं कर सकता। वे कब किस फैसले से नाराज हो जाएं, कहना मुश्किल है। ऐसे में भाजपा के लिए उनके साथ लगातार संतुलन साधते रहना होगा। राजग की पिछली दो सरकारों के कामकाज के तरीके और फैसलों को लेकर अनेक आपत्तियां उठती रही हैं। नई सरकार में घटक दलों की बात सुनना जरूरी होगा। अपेक्षा की जाती है कि इस बार मंत्रिमंडल का गठन कुछ इस तरह से होगा कि उसमें घटक दलों की मांगों को समायोजित करना होगा। हर सहयोगी दल अपने समर्थन की बड़ी कीमत मांगेगा। उसमें अगर पदों और विभागों के बंटवारे में असंतुलन होगा, तो असंतोष भी उभरेगा और उसका असर सरकार के कामकाज पर नजर आने लगेगा। पिछली सरकारों के समय कई महत्त्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणाएं की गई थीं, वे तभी लागू होंगी और गति पा सकेंगी, जब विभागों के बंटवारे में संतुलन होगा। फिर, हर सहयोगी दल की अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताएं भी हैं, वे उन्हें ऊपर रखना चाहेंगे, इसलिए नई सरकार से हर स्तर पर संतुलन साधने की दरकार होगी।

भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल?

2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनाव परिणाम भी आ गए हैं। जो चुनाव परिणाम आए हैं। उनमें 12 राज्यों में कांग्रेस का एक भी सांसद चुनाव नहीं जीता है। वहीं नौ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद चुनाव नहीं जीत पाया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने का दम भरते हैं। पिछले कई चुनाव में कांग्रेस पिछड़ती जा रही थी। पिछले दो लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने देश के कई राज्यों में अपनी पहुंच बनाई थी। 2024 आते आते तक कोई भी ऐसा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। जिसे संसद में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु में एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। पांडिचेरी में भाजपा गठबंधन की सरकार होते हुए भी, वह लोकसभा के चुनाव में एक भी उम्मीदवार नहीं जिता पाई । सीमावर्ती राज्य पंजाब में भी भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली। पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर नगालैंड और सिक्किम में भाजपा खाता नहीं खोल पाई है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को, नौ राज्यों में एक भी लोकसभा की सीट हासिल नहीं हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी कांग्रेस भी पिछले तीन दशक से राष्ट्रीय स्तर पर काफी कमजोर होती जा रही है। नेताओं वाली पार्टी कांग्रेस को, 2014 और 2019 की तुलना में 2024 के चुनाव में बड़ी सफलता मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का प्रयास जरूर किया है। इस चुनाव में उसका लाभ कांग्रेस को मिला है। देशभर के विभिन्न राज्यों के सैकड़ो कांग्रेस नेता और हजारों कार्यकर्ता चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कई राज्यों में कांग्रेस का संगठन नहीं होने तथा राज्यों की अलग-अलग समस्याओं से कांग्रेस का कोई सीधा संबंध नहीं रह गया था। कांग्रेस और भाजपा के कमजोर होने का लाभ चुनाव मे क्षेत्रीय दलों को मिला। कई राज्यों में क्षेत्रीय दल भाषा और प्रांतीय संस्कृति के कारण बहुत मजबूत हैं। उन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा मजबूत स्थिति में नहीं है। कांग्रेस को जिन 12 राज्यों में सफलता नहीं मिली है। उसमें मध्य प्रदेश, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य भी शामिल हैं। कांग्रेस इन राज्यों में बहुत मजबूत स्थिति में हुआ करती थी। आंध्र प्रदेश को छोड़ दें, तो कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला उक्त राज्यों में होता था। इन राज्यों से कांग्रेस का एक भी सांसद जीत कर नहीं आ पाया। कांग्रेस का इस बार मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, त्रिपुरा सहित एक दर्जन राज्यों से कांग्रेस का कोई भी सांसद लोकसभा नहीं पहुंचा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें राष्ट्रीय दलों की भूमिका सर्वोपरि होती है। संघीय व्यवस्था के अनुसार क्षेत्रीय दलों का भी अपना महत्व है। लोकसभा में यदि राष्ट्रीय दल सभी राज्यों से अपना सांसद लेकर लोकसभा नहीं पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय विचारधारा एवं राष्ट्र निर्माण को लेकर बहुत सारी विसंगतियां पैदा होती हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो और भारत न्याय यात्रा के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय परिदृश्य में लाने का प्रयास किया है। संगठन का अभाव होने के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के बीच राष्ट्रीय स्तर छवि बनाई है। पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी जिस तरह जनता से दूर होती जा रही थी। उस कमी को दूर करने में कुछ समय लग सकता है। राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों से अपेक्षा की जाती है। सभी राज्यों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय दलों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय दल अपने प्रादेशिक हितों को ध्यान में रखते हुए राजनीति करते हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र एवं राज्य के बीच में समन्वय बनाए रखने मे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 1989 से लेकर 2014 तक भारत में गठबंधन की सरकारें थी। इसमें क्षेत्रीय दलों का भी प्रतिनिधित्व केंद्र में था। केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर संबंध थे। 2014 से 2024 के बीच में केंद्र में भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार रही है। भाजपा क्षेत्रीय दलों को खत्म करके उनका स्थान लेना चाहती थी। यही गलती किसी जमाने में कांग्रेस ने भी की थी। जिसके कारण क्षेत्रीय दल काफी मजबूत हुए।

प्रसंगतः दरिद्रनारायण का प्रतिनिधि

यरवडा जेल में गांधीजी का उपवास चल रहा था. जेल के दरवाजे हरिजन-सेवकों के लिए खोल दिये गए थे. जो जब चाहे, आ सकता था. उस पर कोई रोक-थाम नहीं थी. गुजरात तथा काठियावाड़ में हरिजनों के उद्धार के लिए कुछ कार्यक्रम निश्चित होने थे. उस संबंध में बात करने के लिए कुछ विशिष्ट लोग वहां आये हुए थे. गांधीजी आम के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे. लोग आकर उनके पास बैठ गये. बातों का सिलसिला चल पड़ा. वहीं पर जेल के एक अधिकारी भी बैठे हुए थे. एक बंदी गांधीजी के लिए अंगीठी पर पानी गरम कर रहा था. अंगीठी बहुत तेजी से जल रही थी. पानी बड़ी जल्दी गरम हो गया. बंदी ने यह देखा तो अंगीठी पर से पानी का बर्तन उतारकर नीचे रख दिया, पर अंगीठी को वैसा ही जलती छोड़ दिया. कोयले बड़े जोर से दहक रहे थे. वे दहकते रहे. तभी गांधीजी का ध्यान फस ओर गया. वह गुजरात और काठियावाड़ के नेताओं से बात कर रहे थे. एकदम बातचीत को रोककर गांधीजी ने बंदी से कहा, "तुनो भाई, अंगीठी को बुझा दो." बंदी ने जेल के अधिकारी की ओर देखा. अधिकारी ने मुस्कराकर कहा, "गांधीजी, आप क्यों चिन्ता करते हैं?" फिर कुछ रुककर बोले, "कोयले सरकारी हैं. जलने दीजिये." गांधीजी गंभीर हो गये. बोले, "नहीं, ये कोयले तो आम जनता के पैसे के हैं." आज जबकि देश की गरीब जनता का पैसा चारों ओर पानी की तरह बह रहा है, देशवासियों की आंखें उस मसीहा को खोज रही हैं, तरह बह रहा है, देशवासियों की आंखें उस मसीहा को खोज रही हैं, जो दरिद्रनारायण का सच्चा प्रतिनिधि था.

अब भी मोदी सबसे बड़े एवं वर्चस्वी नेता हैं

- ललित गर्ग

अठाहरवीं लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही अपने अंदर कई संदेशों को समेटे हुए हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो, भले ही इंडिया गठबंधन एक चुनौती के रूप में खड़ा हुआ हो, फिर भी तीसरी बार नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हुए नये भारत एवं सशक्त भारत को निर्मित करने के लिये वे पहले दो कार्यकाल से अधिक शक्ति, संकल्प एवं जिजीविषा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सीटों के लिहाज से भाजपा को भले ही नुकसान हुआ, लेकिन लगातार तीसरी बार वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ओडिशा और तेलंगाना में पार्टी ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको चौंकाया है। ओडिशा में लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में भी पार्टी ने बीजू जनता दल का 24 साल से चला आ रहा वर्चस्व तोड़ा। अरुणाचल प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 54 प्रतिशत मत और 46 सीटों के प्रचंड बहुमत के बल पर भाजपा सरकार बनाने में सफल हुई है। वहीं, गुजरात, छतीसगढ़ और मध्य प्रदेश भाजपा के गढ़ बने हुए हैं, जबकि देश की राजनीति में अब भी मोदी सबसे बड़े एवं वर्चस्वी नेता है। वे अब भी अपने चौंकाने वाले एवं आश्चर्य में डालने वाले विलक्षण एवं अनूठे फैसलों से राष्ट्र को विकास की नई उड़ान देते रहेंगे। भाजपा को कम सीटें मिले कारणों की समीक्षा एवं मंथन करते हुए अपनी हार के कारणों को सहजता एवं उदारता से स्वीकारना चाहिए एवं जिन गलतियों के कारण कम सीटें मिली, उन्हें दूर करना चाहिए।

इस बार के चुनाव को नियोजित एवं प्रभावी तरीके से सम्पन्न करने में चुनाव आयोग की भूमिका सराहनीय रही। भले ही इडिया गठबंधन ने ई.वी.एम. और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगाकर देश एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कलंकित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम ने न केवल इस प्रकार के भ्रामक, गुमराह करने वाली बातों एवं मिथकों को तोड़ दिया, बल्कि इसने भारत के जीवंत, बहुलतावादी, पंथनिरपेक्षी और स्वस्थ लोकतांत्रिक छवि को पुनर्स्थापित किया है। प्रधानमंत्री मोदी का अंधविरोध करने वाला वाम-जिहादी-सम्प्रदायवादी राजनीतिक समूह अपने इस वाहियात प्रलाप एवं राष्ट्र-विरोधी षड़यंत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिये चुनाव परिणाम अनेक अर्थों में संतोषजनक रहे हैं।

कांग्रेस के लिये यह चुनाव नये जीवन का वाहक बना हैं। वैसे भी एक आदर्श लोकतंत्र के लिये सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है, यही लोकतंत्र को खूबसूरती देता है। भारतीय मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को विपक्षी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने का संदेश दिया है।

इस बार के चुनाव परिणाम अनेक राजनीतिक दलों के सामने भी अनेक प्रश्न खड़े किये हैं। कौन जेल में रहेगा, इसका फैसला अदालतें करती हैं। परंतु दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव को अपने जेल के अंदर रहने या बाहर रहने का अधिकार मतदाताओं को सौंपा था, जिसका नतीजा यह रहा कि उनके शासित वाले दिल्ली में 'आप' का खाता तक नहीं खुला, तो वहीं उनकी पार्टी पंजाब में विधानसभा चुनाव-2022 का चमत्कार दोहराने में विफल हो गई और 13 में से केवल 3 सीटें ही जीत पाई। शरद पवार का राजनीतिक वारिस कौन और असली शिवसेना किसकी? क्या माया और ममता अब भी ताकतवर हैं?

यह चुनाव ऐसे ही कई सवालों के साथ शुरू हुआ था। इनमें से कुछ के जवाब मिल गए हैं और कुछ के बाकी हैं। जिस तरह के नतीजे आए हैं, उससे यह संदेह भी पैदा हुआ है कि क्या देश में आर्थिक सुधार जारी रहेंगे? क्या देश विकास के पथ पर अग्रसर होता रहेगा? नीतिगत स्थिरता का क्या होगा? शायद इसी संदेह की वजह से शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। लेकिन नरेन्द्र मोदी के पहले भाजपा मुख्यालय में दिये उद्बोधन एवं गठबंधन दलों के साथ हुई बैठक में इन सवालों के जवाब काफी हद तक मिल गये, जिससे शेयर बाजार ने भी तेजी पकड़ी है एवं भाजपा एवं सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है।

देश एक बार फिर गठबंधन सरकारों के युग में प्रवेश कर रहा है। अब यह एक हकीकत है कि मौजूदा जनादेश के मद्देनजर गठबंधन सरकार बनाना भाजपा की मजबूरी हो गई है। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाने और अल्पमत में सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाने में बड़ा फर्क है। सवाल उठाया जा रहा है कि पूर्ण बहुमत वाले दो कार्यकालों में देशहित के बड़े फैसले लेने वाली भाजपा क्या गठबंधन के सहयोगियों के दबाव के बीच शासन करने में खुद को सहज महसूस कर सकेगी? लेकिन मोदी के नेतृत्व में सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और अपने संकल्पों एवं योजनाओं को आकार देगी, इसमें कोई संदेह नजर नहीं आती। देश में केंद्रीय स्तर 2009 के बाद पहली बार गठबंधन सरकार बनने जा रही है। अतीत में नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन सरकारों का कुशलता से संचालन भी किया है और आवश्यक सुधारों को भी आगे बढ़ाया है। मनमोहन सिंह ने भी दस वर्ष तक गठबंधन सरकार का संचालन किया है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उन्हें किस तरह कई बार सहयोगी दलों के अनुचित दबाव में झुकना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी भी गठबंधन सरकार की चुनौतियों से जूझते रहे। लेकिन मोदी की स्थितियां भिन्न है, वे राजनीति के धुंरधर खिलाड़ी है, अमित शाह राजनीतिक जोड़ तोड़ के खिलाड़ी है, इसे देखते हुए भाजपा और उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक अपना काम कर सकेगी, ऐसा विश्वास है। न केवल सरकार बल्कि भाजपा के बड़े मुद्दों का भी क्रियान्वयन होगा। जब-जब भाजपा के सामने अनुचित राजनीतिक दबाव की स्थितियां बनेगी, सरकार कोई सार्थक रास्ता निकाल लेगी।

वैसे भी भाजपा बहुमत के आंकड़े से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि तेलुगु देसम पार्टी, जनता दल-यू, शिवसेना समेत अन्य सहयोगी दलों के साथ उसके लिए सरकार चलाना कहीं अधिक आसान होगा। इसके बाद भी इतना तो है ही कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार गठबंधन सरकार का संचालन करेंगे। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के तहत कार्य करने के कारण वह ऐसी सरकार के संचालन के तौर-तरीकों से अवगत हैं, लेकिन स्वयं उनके लिए ऐसी सरकार चलाना एक नया अनुभव होगा। लेकिन वे भाजपा संगठन में अनेक पदों पर रहते हुए संगठन की गतिविधियों के कुशल संचालन से भिज्ञ है। देश-विदेश के दबावों को झेलते हुए उन्होंने भारत को एक शक्ति के रूप में खड़ा किया है, दुनिया जब आर्थिक संकट झेल रही है, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, निश्चित ही गठबंधन सरकार का उनका संचालन उनकी नेतृत्व क्षमता और सबको साथ लेकर चलने के राजनीतिक कौशल को एक नया आयाम देगी। उनके पास चुनौतियों के बीच देश की समस्याओं का समाधान करने की एक राजनीतिक दृष्टि एवं कौशल है।

गठबंधन सरकारों के कुछ सकारात्मक पक्ष होते हैं तो कुछ नकारात्मक पक्ष भी। गठबंधन सरकारों का नेतृत्व करने वाले को घटक दलों से समन्वय के साथ चलना होता है। इसमें समस्या तब आती है, जब घटक दल अनुचित मांगें मनवाने लगते हैं अथवा सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति के लिए दबाव की राजनीति करने लगते हैं। इन स्थितियों की निबटने के लिये मोदी सरकार पहले ही अन्य निर्दलयी सांसदों एवं अन्य राजनीतिक दलों को अपने साथ जोड़ने का उपक्रम कर रही है। सहयोगी दल अनुचित मांग एवं दबाव की बजाय अपने राज्य के राजनीतिक एवं आर्थिक हितों की चिंता करें, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें राष्ट्रीय हितों को ओझल नहीं करना चाहिए। यह उन्हें भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गठबंधन सरकार सुगम तरीके से चले।

निश्चित ही मोदी सरकार के सामने चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं, जिस तरह महाभारत युद्ध में पांडवों के सामने जटिल स्थितियां थी।

आज द्रोण नहीं तुष्टिकरण है, कृपाचार्य नहीं भ्रष्टाचार है, अश्वत्थामा नहीं आतंकवाद है, दुर्योधन नहीं महत्वाकांक्षा एवं अनैतिकता है, शकुनि नहीं आंतरिक और वैश्विक षड्यंत्र है, राष्ट्रवाद नहीं समस्त प्रकार की विघटनकारी शक्तियां-भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, स्वार्थवाद आदि हैं और कर्ण नहीं कट्टरवाद है। साथ में महंगाई, बेरोजगारी, असंतोष आदि की अत्यंत जटिल समस्याएं भी हैं और अब भारत इनमें फंसा हुआ है। फिर भी नरेन्द्र मोदी रूपी उजाला अपनी नई पारी में अधिक सशक्त होकर भारत के इन सभी चक्रव्यूह को भेदेगा। अपने राजनीतिक जीवन की सबसे सफलतम पारी खेलते हुए वह एक बार फिर नकारात्मक एवं अराष्ट्रवादी शक्तियों को उनकी जमीन दिखायेंगा।

महिलाओं के आत्म मूल्य की भावना को पोषित करती है 'आध्यात्मिकता'

आध्यात्मिकता, लैंगिक न्याय और महिला सशक्तिकरण विषयक राज्य-स्तरीय परामर्श 14 को

शिबि डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा मंजरी संस्था जयपुर, वाग्धारा राजस्थान, प्रयत्न संस्था और मानवाधिकार एवं सामाजिक कल्याण केंद्र के सहयोग से आध्यात्मिकता, लैंगिक न्याय और महिला सशक्तिकरण विषय पर एक राज्य-स्तरीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन 14 जून को इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, जयपुर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 20 दिसंबर 2022 को आयोजित 'आध्यात्मिकता और महिला सशक्तिकरण' आध्यात्मिकता की भूमिका थीम पर आधारित बैठक की अंतर्दृष्टियों को और गहराई से समझना है। महिला सशक्तिकरण में आध्यात्मिकता की भूमि, जो विविधता और व्याख्या में समृद्ध है, अक्सर दैनिक जीवन की व्यावहारिकताओं से अलग मानी जाती है। हालांकि हमारी सामूहिक समझ इसके विपरीत है। आध्यात्मिकता, जो अस्तित्व के सार में गहराई से निहित है, महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। यह आत्म-मूल्य की भावना को पोषित करती है, स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है और महिलाओं को केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए सशक्त करती है।

समुदाय और संबंध- हमारी संस्थाओं का एक मौलिक विश्वास है कि आध्यात्मिकता संबंधों को प्रोत्साहित करती है। समुदायों और समर्थन नेटवर्क बनाने के द्वारा आध्यात्मिकता महिलाओं के समृद्ध होने के लिए एक पोषण वातावरण प्रदान करती है। साझा अनुभवों और सामूहिक क्रिया के माध्यम से, ताकत और एकता की भावना मिलती है, जो व्यक्तिगतता की सीमाओं को पार करके आम कल्याण और सहयोगात्मक प्रयासों को अपनाती है। ये संबंध महत्वपूर्ण हैं, एक समर्थन प्रणाली प्रदान करते हैं जो लचीलापन को सुदृढ़ करता है और एक ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें महिलाएं पनप सकती हैं।

विशेषज्ञों की अंतर्दृष्टियां- गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी विभागों और शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञ विचारों के एक समृद्ध आदान-प्रदान को सुनिश्चित करेंगे। आगामी परामर्श यह जांचने का प्रयास करेगा कि आध्यात्मिकता लैंगिक न्याय की खोज के साथ कैसे जुड़ती है। विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं पर चर्चा करके हम उन अंतर्निहित सिद्धांतों को उजागर करने का प्रयास करेंगे जो जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देते हैं, जिससे सतत विकास में योगदान मिलता है।

परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में आध्यात्मिकता- आध्यात्मिकता को केवल एक निष्क्रिय बल के रूप में नहीं बल्कि एक परिवर्तनकारी क्रिया के उत्प्रेरक के रूप में पहचानते हैं, जो महिलाओं को अन्याय और असमानता को चुनौती देने के लिए सशक्त बनाता है। इसमें न केवल सशक्तिकरण के आध्यात्मिक आयामों को पहचानना शामिल है, बल्कि इन अंतर्दृष्टियों को सामाजिक परिवर्तन के लिए व्यावहारिक रणनीतियों में सक्रिय रूप से एकीकृत करना भी शामिल है।

परिवर्तन की आवाज़ें- वाग्धारा के जयेश जोशी ने बताया कि आध्यात्मिकता, लैंगिक न्याय और महिला सशक्तिकरण पर एक दिवसीय राज्य-स्तरीय परामर्श आध्यात्मिकता की परिवर्तनकारी क्षमता की समझ को गहरा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने आगे कहा कि विविध दृष्टिकोणों और अनुभवों से एकत्र की गई अंतर्दृष्टियों को सक्रिय करके, हम सभी लिंगों के लिए अधिक समावेशी, न्यायसंगत और सशक्त समाज की ओर मार्ग प्रशस्त करने की आकांक्षा रखते हैं। शिबि डेवलपमेंट सोसाइटी की शेख सफीना ने कहा कि सहयोगात्मक प्रयासों और साझा दृष्टिकोण के माध्यम से हम लैंगिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं, अंततः एक ऐसे समाज को बढ़ावा देना जहां सभी व्यक्ति, चाहे वे किसी भी लिंग के हों, फल-फूल सकें।

सशक्तिकरण के आंकड़े और जानकारी- महिलाओं की शिक्षा और रोजगार, अंतरराष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-2021 के अनुसारः 15-49 वर्ष की महिलाओं में साक्षरता दर 71.5 प्रतिशत है। 15-49 वर्ष की महिलाओं के लिए रोजगार दर 24.5 प्रतिशत है। यह आंकड़े शिक्षा और रोजगार में सुधार की गुंजाइश को दर्शाते हैं, जिसे आध्यात्मिक और सामुदायिक समर्थन द्वारा प्रबलित किया जा सकता है।

मानसिक स्वास्थ्य पर आध्यात्मिकता का प्रभाव- जर्नल ऑफ रिलिजन एंड हेल्थ (2020) में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जो महिलाएं नियमित आध्यात्मिक प्रथाओं में संलग्न हैं, वे कम तनाव और जीवन संतोष के उच्च स्तर की रिपोर्ट करती हैं। आध्यात्मिक समुदायों में भाग लेने वाली महिलाएं अक्सर संबंध और समर्थन की मजबूत भावना का अनुभव करती हैं, जो मानसिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है।

महिला नेतृत्व- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (2023) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रबंधकीय पदों पर 39 प्रतिशत महिलाएं हैं। आध्यात्मिक समुदाय अक्सर नेतृत्व गुणों का पोषण करते हैं, जिससे अधिक महिलाएं नेतृत्व की भूमिकाएं निभाने के लिए प्रेरित होती हैं।

सशक्तिकरण की सफलता की कहानियां- स्व-नियोजित महिला संघ आध्यात्मिकता और काम को एकीकृत करती है। 1.5 मिलियन से अधिक महिलाओं को समर्थन नेटवर्क और उनके आजीविका में सुधार के लिए संसाधन प्रदान करके सशक्त बनाती है। ग्रामीण बैंक (बांग्लादेश) हालांकि यह सख्त रूप से आध्यात्मिक नहीं है। ग्रामीण बैंक का माइक्रोफाइनेंसिंग मॉडल विश्वास और सामुदायिक समर्थन की आध्यात्मिक अवधारणाओं पर आधारित है, जिसने लाखों महिलाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए सशक्त बनाया है।

आध्यात्मिकता और लैंगिक समानता- प्यू रिसर्च सेंटर (2016) ने पाया कि 62 प्रतिशत भारतीयों का मानना है कि धर्म उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए आध्यात्मिक ढांचे का उपयोग करने की क्षमता को दर्शाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि विभिन्न धर्मों की आध्यात्मिक शिक्षाएं अक्सर समानता, करुणा और न्याय पर जोर देती हैं, जिन्हें लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। आध्यात्मिकता, लैंगिक न्याय और महिला सशक्तिकरण पर यह परामर्श आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक सशक्तिकरण रणनीतियों के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है। संबंधों को प्रोत्साहित करके, अनुभवों को साझा करके और सामूहिक क्रिया को संगठित करके हम एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जिसमें महिलाएं उन्नति कर सकें और सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व कर सकें। यह सहयोगात्मक प्रयास लैंगिक न्याय और एक अधिक समावेशी समाज प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- कल्याण सिंह कोठारी
जवाहर नगर, जयपुर।

https://t.me/AINewsPaperPdf

सम्पादकीय

पानी के लिए आत्महत्या, राज्य सरकार के लिए शर्मनाक

ये खबर वाकई चौकानें और विचलित करने वाली है कि पानी की समस्या को लेकर परेशान एक बुजुर्ग ने अलवर में आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर लिया। ये राज्य सरकार के लिए काफी शर्मनाक बात है। क्योंकि राज्य सरकार हर घर नल और पेयजल उपलब्धता को लेकर बड़े-बड़े दावे करके लोकसभा चुनाव में वोट ले रही थी। नतीजों के दूसरे ही दिन आई इस खबर ने पेयजल की समस्या की पोल खोल कर रख दी है साथ ही उन अधिकारियों की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल है जिन्होंने लगातार शिकायत करने के बावजूद बुजुर्ग की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल एक दिन पहले पानी की समस्या से परेशान एक वकील ने सुसाइड कर लिया। वह बुधवार सुबह करीब करीब साढ़े आठ बजे अपने कमरे में फंदे पर लटके मिले। अलवर के भैरू सिंह चबूतरे निवासी वकील मोहनलाल सैनी (78) ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। उनकी बेटी आरती ने मौत का कारण पानी बताया है। वकील मोहनलाल अपनी छोटी बेटी आरती और पत्नी शशिबाला के साथ रहते थे। पत्नी चलने-फिरने में असमर्थ है। इस कारण वकील को ही घर से पानी के लिए करीब 350 मीटर दूर पुरुषार्थी धर्मशाला जाना पड़ता था। वहां एक-एक बाल्टी पानी के लिए एक घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ता था। इस कारण वह परेशान हो गए थे।

घर में पानी की सप्लाई नहीं आ रही थी। ज्यादा उम्र के कारण दूर तक जाने में असमर्थ होने लगे थे। बेटी के अनुसार उसके पिता डेढ़ महीने से पानी की समस्या से परेशान थे। उन्हें घर काफी दूर जाकर बोरवेल से पानी लाना पड़ता था। घटना के दिन बुधवार सुबह करीब 5 बजे वकील उठे। उन्होंने अपने पड़ोसी हरिओम से जाकर पूछा कि पानी आया या नहीं। हरिओम ने कहा कि कई बार मोटर चला ली। पानी नहीं आया। मोहन लाल (मृतक) ने कहा कि बहुत परेशान हो गए। क्या करें। बाद में 8 बजे के आस-पास बेटी उठी। उसने देखा तो पिता फंदे से लटके हुए थे। वकील के दामाद खोहर मोहल्ला निवासी बाबूलाल ने बताया कि पानी के लिए परेशान थे। कई बार उनको भी पानी के लिए इधर-उधर फोन करने पड़े हैं, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। मृतक ने कलक्टर, पीएचईडी के एसई, एक्सईएन, जेईएन को लिखित में शिकायत दी थी। फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जेईएन ने अपने किसी परिचित को पानी ज्यादा देने के चक्कर में वॉल्ब दूर लगा दिया, जिसके कारण आगे पानी आना कम हो गया। ओसवाल स्कूल की तरफ पानी ज्यादा जाने लग गया, जिसकी शिकायत एसई, एक्सईएन और एईएन को भी की थी। किसी भी अधिकारी ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। और तो और जलदाय विभाग के जिम्मेदार अधिकारी तो इस पर अब भी पर्दा डाल रहे हैं। उनका कहना है कि पानी की सप्लाई तो चल रही थी कोई पानी के लिए भी आत्महत्या कर सकता है क्या? उन अधिकारियों को पेयजल का महत्व इसलिए नहीं पता क्योंकि उनके एक आर्डर पर पानी उपलब्ध हो जाता है। इस गर्मी के मौसम में प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पेयजल को लेकर क्या चल रहा है ये इस आत्महत्या ने साफ कर दिया है।

अब भी मोदी सबसे बड़े एवं वर्चस्वी नेता हैं

इस बार के चुनाव को नियोजित एवं प्रभावी तरीके से सम्पन्न करने में चुनाव आयोग की भूमिका सराहनीय रही। भले ही इडिया गठबंधन ने ई.वी.एम. और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगाकर देश एवं लोकतांत्रिक प्रि याओं को कलंकित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम ने न केवल इस प्रकार के भ्रामक, गुमराह करने वाली बातों एवं मिथकों को तोड़ दिया, बल्कि इसने भारत के जीवंत, बहुलतावादी, पंथनिरपेक्षी और स्वस्थ लोकतांत्रिक छवि को पुनर्स्थापित किया है। प्रधानमंत्री मोदी का अंधविरोध करने वाला वाम-जिहादी-सम्प्रदायवादी राजनीतिक समूह अपने इस वाहियात प्रलाप एवं राष्ट्र-विरोधी षड़यंत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिये चुनाव परिणाम अनेक अर्थों में संतोषजनक रहे हैं। कांग्रेस के लिये यह चुनाव नये जीवन का वाहक बना हैं। वैसे भी एक आदर्श लोकतंत्र के लिये सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है, यही लोकतंत्र को खूबसूरती देता है। भारतीय मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को विपक्षी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने का संदेश दिया है।

ललित गर्ग

अठाहरवीं लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही अपने अंदर कई संदेशों को समेटे हुए हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो, भले ही इंडिया गठबंधन एक चुनौती के रूप में खड़ा हुआ हो, फिर भी तीसरी बार नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हुए नये भारत एवं सशक्त भारत को निर्मित करने के लिये वे पहले दो कार्यकाल से अधिक शक्ति, संकल्प एवं जिजीविषा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सीटों के लिहाज से भाजपा को भले ही नुकसान हुआ, लेकिन लगातार तीसरी बार वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ओडिशा और तेलंगाना में पार्टी ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको चौंकाया है। ओडिशा में लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में भी पार्टी ने बीजू जनता दल का 24 साल से चला आ रहा वर्चस्व तोड़ा। अरुणाचल प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 54 प्रतिशत मत और 46 सीटों के प्रचंड बहुमत के बल पर भाजपा सरकार बनाने में सफल हुई है। वहीं, गुजरात, छतीसगढ़ और मध्य प्रदेश भाजपा के गढ़ बने हुए हैं, जबकि देश की राजनीति में अब भी मोदी सबसे बड़े एवं वर्चस्वी नेता है। वे अब भी अपने चौंकाने वाले एवं आश्चर्य में डालने वाले विलक्षण एवं अनूठे फैसलों से राष्ट्र को विकास की नई उड़ान देते रहेंगे। भाजपा को कम सीटें मिले कारणों की समीक्षा एवं मंथन करते हुए अपनी हार के कारणों को सहजता एवं उदारता से स्वीकारना चाहिए एवं जिन गलतियों के कारण कम सीटें मिली, उन्हें दूर करना चाहिए।

इस बार के चुनाव परिणाम अनेक राजनीतिक दलों के सामने भी अनेक प्रश्न खड़े किये हैं। कौन जेल में रहेगा, इसका फैसला अदालतें करती हैं। परंतु दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव को अपने जेल के अंदर रहने या बाहर रहने का अधिकार मतदाताओं को सौंपा था, जिसका नतीजा यह रहा कि उनके शासित वाले दिल्ली में 'आप' का खाता तक नहीं खुला, तो वहीं उनकी पार्टी पंजाब में विधानसभा चुनाव-2022 का चमत्कार दोहराने में विफल हो गई और 13 में से केवल 3 सीटें ही जीत पाई। शरद पवार का राजनीतिक वारिस कौन और असली शिवसेना किसकी? क्या माया और ममता अब भी ताकतवर हैं? यह चुनाव ऐसे ही कई सवालों के साथ शुरू हुआ था। इनमें से कुछ के जवाब मिल गए हैं और कुछ के बाकी हैं। जिस तरह के नतीजे आए हैं, उससे यह संदेह भी पैदा हुआ है कि क्या देश में आर्थिक सुधार जारी रहेंगे? क्या देश विकास के पथ पर अग्रसर होता रहेगा? नीतिगत स्थिरता का क्या होगा? शायद इसी संदेह की वजह से शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। लेकिन नरेन्द्र मोदी के पहले भाजपा मुख्यालय में दिये उद्बोधन एवं गठबंधन दलों के साथ हुई बैठक में इन सवालों के जवाब काफी हद तक मिल गये, जिससे शेयर बाजार ने भी तेजी पकड़ी है एवं भाजपा एवं सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। देश एक बार फिर गठबंधन सरकारों के युग में प्रवेश कर रहा है। अब यह एक हकीकत है कि मौजूदा जनादेश के मद्देनजर गठबंधन सरकार बनाना भाजपा की मजबूरी हो गई है। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाने और अल्पमत में सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाने में बड़ा फर्क है। सवाल उठाया जा रहा है कि पूर्ण बहुमत वाले दो कार्यकालों में देशहित के बड़े फैसले लेने वाली भाजपा क्या गठबंधन के सहयोगियों के दबाव के बीच शासन करने में खुद को सहज महसूस कर सकेगी? लेकिन मोदी के नेतृत्व में सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और अपने संकल्पों एवं योजनाओं को आकार देगी, इसमें कोई संदेह नजर नहीं आती। देश में केंद्रीय स्तर 2009 के बाद पहली बार गठबंधन सरकार बनने जा रही है। अतीत में नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन सरकारों का कुशलता से संचालन भी किया है और आवश्यक सुधारों को भी आगे बढ़ाया है। मनमोहन सिंह ने भी दस वर्ष तक गठबंधन सरकार का संचालन किया है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उन्हें किस तरह कई बार सहयोगी दलों के अनुचित दबाव में झुकना पड़ा।

अटल बिहारी वाजपेयी भी गठबंधन सरकार की चुनौतियों से जूझते रहे। लेकिन मोदी की स्थितियां भिन्न है, वे राजनीति के धुंरधर खिलाड़ी है, अमित शाह राजनीतिक जोड़ तोड़ के खिलाड़ी है, इसे देखते हुए भाजपा और उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक अपना काम कर सकेगी, ऐसा विश्वास है। न केवल सरकार बल्कि भाजपा के बड़े मुद्दों का भी क्रियान्वयन होगा। जब-जब भाजपा के सामने अनुचित राजनीतिक दबाव की स्थितियां बनेगी, सरकार कोई सार्थक रास्ता निकाल लेगी। वैसे भी भाजपा बहुमत के आंकड़े से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि तेलुगु देसम पार्टी, जनता दल-यू, शिवसेना समेत अन्य सहयोगी दलों के साथ उसके लिए सरकार चलाना कहीं अधिक आसान होगा। इसके बाद भी इतना तो है ही कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार गठबंधन सरकार का संचालन करेंगे। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के तहत कार्य करने के कारण वह ऐसी सरकार के संचालन के तौर-तरीकों से अवगत हैं, लेकिन स्वयं उनके लिए ऐसी सरकार चलाना एक नया अनुभव होगा। लेकिन वे भाजपा संगठन में अनेक पदों पर रहते हुए संगठन की गतिविधियों के कुशल संचालन से भिज्ञ है। देश-विदेश के दबावों को झेलते हुए उन्होंने भारत को एक शक्ति के रूप में खड़ा किया है, दुनिया जब आर्थिक संकट झेल रही है, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, निश्चित ही गठबंधन सरकार का उनका संचालन उनकी नेतृत्व क्षमता और सबको साथ लेकर चलने के राजनीतिक कौशल को एक नया आयाम देगी। उनके पास चुनौतियों के बीच देश की समस्याओं का समाधान करने की एक राजनीतिक दृष्टि एवं कौशल है। गठबंधन सरकारों के कुछ सकारात्मक पक्ष होते हैं तो कुछ नकारात्मक पक्ष भी। गठबंधन सरकारों का नेतृत्व करने वाले को घटक दलों से समन्वय के साथ चलना होता है। इसमें समस्या तब आती है, जब घटक दल अनुचित मांगें मनवाने लगते हैं अथवा सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति के लिए दबाव की राजनीति करने लगते हैं। इन स्थितियों की निबटने के लिये मोदी सरकार पहले ही अन्य निर्दलयी सांसदों एवं अन्य राजनीतिक दलों को अपने साथ जोड़ने का उपक्रम कर रही है। सहयोगी दल अनुचित मांग एवं दबाव की बजाय अपने राज्य के राजनीतिक एवं आर्थिक हितों की चिंता करें, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें राष्ट्रीय हितों को ओझल नहीं करना चाहिए।

यह उन्हें भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गठबंधन सरकार सुगम तरीके से चले। निश्चित ही मोदी सरकार के सामने चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं, जिस तरह महाभारत युद्ध में पांडवों के सामने जटिल स्थितियां थी। आज द्रोण नहीं तुष्टिकरण है, कृपाचार्य नहीं भ्रष्टाचार है, अश्वत्थामा नहीं आतंकवाद है, दुर्योधन नहीं महत्वाकांक्षा एवं अनैतिकता है, शकुनि नहीं आंतरिक और वैश्विक षड्यंत्र है, राष्ट्रवाद नहीं समस्त प्रकार की विघटनकारी शक्तियां-भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, स्वार्थवाद आदि हैं और कर्ण नहीं कट्टरवाद है।

आज का इतिहास

7 जून की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- नेपल्स के राजा लैडिसलाव ने 1413 में रोम पर कब्जा किया।
- बक्सर के पास चौसा की लड़ाई में अफ़गान शेरशाह सूरी ने 1539 में मुग़ल बादशाह हुमायूँ को हराया।
- इंग्लैंड ने 1546 में स्कॉटलैंड/आयरलैंड के साथ आंद्रेस शांति समझौता किया।
- इंग्लैंड ने 1557 में फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- लुई चतुर्दश 1654 में फ्रांस के राजा बने।
- कैरिबियाई देश जमाइका के पोर्ट रॉयल में 1692 को आये भूकंप से तीन हजार लोगों की मौत।
- एंटी-कैथोलिक दंगा लंदन में 1780 को शुरू हुआ जिसमें करीब 100 लोगों की मौत हो गई।
- संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन दास व्यापार खत्म करने पर 1862 को राजी हुए।
- फ्रांसीसी सेना ने 1863 में मेक्सिको शहर पर कब्जा किया।
- अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति के लिए 1864 को दूसरी बार रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाये गये।
- महात्मा गांधी ने 1893 में दक्षिण अफ़्रीका में प्रथम बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया।
- बेटिकन सिटी पूर्ण संप्रभु राष्ट्र 1928 को बना।
- वेटिकन सिटी एक संप्रभु देश 1929 में बना।
- जार्ज षष्टम तथा एलिजाबेथ 1939 में ब्रिटेन के पहले राजा और रानी बने जिन्होंने अमेरिका का दौरा किया।
- वामपंथियों ने 1948 को पूरी तरह से चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया।
- सोनी कॉर्पोरेशन ने 1966 में अपने नए ब्रांड वाला वीडियो टेप रिकॉर्डर पेश किया।
- पहले विश्व कप का पहला मैच 1975 में भारत-इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला गया।
- भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर-एक को 1979 में सोवियत संघ के बीयर्स लेक से छोड़ा गया।
- नार्मन थैगार्ड अंतरिक्ष की कक्षा में सबसे लम्बे समय तक रहने वाले अमेरिकी 1995 में अंतरिक्ष यात्री बने।
- स्पेन के कार्लोस मोया ने 1998 को फ़्रेंच ओपन प्रतियोगिता का पुरुष एकल ख़िताब जीता।
- श्रीलंका में प्रचलित आव्रजन नियम 1999 को निरस्त।
- इंडोनेशिया में 1955 के बाद पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव 1999 में हुआ।
- एक अमेरिकी अदालत द्वारा 2000 में माइक्रोसॉफ़्ट कंपनी को दो भागों में बांटने का निर्देश दिया।
- इस्रायली मंत्रिमंडल ने 2004 को गाजा क्षेत्र से बस्तियाँ हटाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- भारत द्वारा नेपाल को आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए एक अरब रुपये देने का निर्णय 2006 में लिया।
- अमेरिका ने सऊदी अरब के राजदूत रहे प्रिंस बांदरे बिन सुल्तान के हथियारों की दलाली में करोड़ों पाउंड के घोटाले का खुलासा 2007 में हुआ।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोई गैस पर लगने वाले 4त्न वैट को पूरी तरह से 2008 में समाप्त घोषित किया।
- अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने स्टेम सेल के अनुसंधान को मंजूरी देने के विरुद्ध दूसरी बार विटो का प्रयोग 2008 में किया।

7 जून को जन्मे व्यक्ति

- प्रसिद्ध फ़िल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख़्वाजा अहमद अब्बास का जन्म 1914 में हुआ
- भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्म 1974 में हुआ।

विशेष आलेख

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस

रोकनी होगी भोजन की बर्बादी ??

रमेश सर्राफ धमोरा

रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती है। जिसके बिना मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल है। इसमें रोटी सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि रोटी के बिना तो मनुष्य जिन्दा भी नहीं रह सकता है। खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित किया जाना है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में हर दस में से एक व्यक्ति दूषित भोजन का सेवन करने से बीमार पड़ जाता है। जो कि सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए इस बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस संक्षिप्त रूप में मनाया जाएगा। जिसमें लोगों को सेहत से जुड़े मुद्दों पर ऑनलाइन एक-दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। इस बार हम छठवां विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इससे खाद्य सुरक्षा लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा सकती है और विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों से होने वाली बीमारियों को भी ध्यान में लाया जा सकता है। इस दिन को मनाने के पीछे खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगो को जागरूक करने का उद्देश्य था। जो खराब भोजन का सेवन करने की वजह से गंभीर रोगों के शिकार बन जाते हैं।

भोजन की कमी व दूषित भोजन खाने से प्रतिवर्ष हजारों लोगों की जान चली जाती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन को दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों का नेतृत्व करने और पौष्टिक खाने के प्रति लोगों को जागरुक करने की जिम्मेदारी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में पहली बार खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया था। इसके बाद पहली बार 7 जून 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। तब से हर वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाने लगा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व में अपने मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता से बात करते हुए लोगों से खाने की बर्बादी रोकने की अपील की थी। उन्होने कहा कि ऐसा करना गरीबों के साथ अन्याय व समाजद्रोह है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपने कभी सोचा है कि हम जो जूठन छोड़ देते हैं। उससे हम कितने गरीबों का पेट भर सकते है? उन्होने कहा था कि इस पर सामाजिक जागरूकता बढनी चाहिए। भारत में अनाज को अन्नदेव का दर्जा प्राप्त है। यही कारण है कि हमारे देश में भोजन झूठा छोडना या उसका अनादर करना पाप माना जाता है। मगर आधुनिकता के चक्कर में हम अपने पुराने संस्कार भूल गए हैं। हमारे यहां शादियों, उत्सवों या त्यौहारो में होने वाली भोजन की बर्बादी से हम सब वाकिफ हैं। इसके उपरांत भी हम इन अवसरों पर ढेर सारा खाना कचरे में फेंक है। कई बार तो घरों के आसपास फेंके गए भोजन से उठने वाली दुर्गंध एवं सड़ांध वहां रहने वालों के लिए परेशानी खड़ी कर देती हैं। शादियों में खाने की बर्बादी को लेकर भारत सरकार भी चिंतित है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि वह शादियों में मेहमानों की संख्या के साथ ही परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या सीमित करने पर विचार कर रहा है। इस बारे में विवाह समारोह अधिनियम, 2006 कानून भी बनाया गया है। हालांकि इस कानून का कड़ाई से कहीं भी पालन नहीं किया जाता है। भारत में हर वर्ष जितना भोजन तैयार होता है उसका एक तिहाई बर्बाद चला जाता है। बर्बाद जाने वाला भोजन इतना होता है कि उससे करोड़ो लोगों की खाने की जरूरत पूरी हो सकती है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में बढ़ती सम्पन्नता के साथ ही लोग खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं। खर्च करने की क्षमता के साथ ही खाना फेंकने की प्रवृति बढ़ रही है। विश्व खाद्य संगठन के अनुसार देश में हर साल पचास हजार करोड़ रूपये का भोजन बर्बाद चला जाता है। एक ऑकलन के मुताबिक बर्बाद होने वाले भोजन की धनराशि से पांच करोड़ बच्चों की जिदगी संवारीं जा सकती है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य अपव्यय को रोके बिना खाद्य सुरक्षा सम्भव नहीं है। इस रिपोर्ट में वैश्विक खाद्य अपव्यय का अध्ययन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से करते हुए बताया है कि भोजन के अपव्यय से जल,जमीन और जलवायु के साथ साथ जैव-विविधता पर भी बेहद नकारात्मक असर पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमारी लापरवाही के कारण पैदा किए जाने वाले अनाज का एक तिहाई हिस्सा बर्बाद कर दिया जाता है। देश में एक तरफ करोड़ो लोग खाने को मोहताज है। वहीं लाखों टन खाना प्रतिदिन बर्बाद किया जा रहा है। हमारे देश में हर साल उतना गेहूं बर्बाद होता है, जितना आस्ट्रेलिया की कुल पैदावार है। नष्ट हुए गेहूं की कीमत लगभग 50 हजार करोड़ रुपये होती है और इससे 30 करोड़ लोगों को सालभर भरपेट खाना दिया जा सकता है। हमारे देश में 2.1 करोड़ टन अनाज केवल इसलिए बर्बाद हो जाता है। क्योंकि उसे रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त भंडारण की सुविधा नहीं है। औसतन हर भारतीय एक साल में छह से 11 किलो अन्न बर्बाद करता है। साल में जितना सरकारी खरीदी का धान व गेहूं खुले में पड़े होने के कारण नष्ट हो जाता है। उतनी राशि से गांवो में पांच हजार वेयर हाउस बनाए जा सकते हैं। आज कल कई शहरो में समाजसेवी लोगो ने मिलकर रोटी बैंक बना रखा हैं। रोटी बैंक से जुड़े कार्यकर्ता शहर में घरो से व विभिन्न समारोह स्थलों से बचे हुये भोजन को एकत्रित कर जरूरत मंद गरीबो तक पहुंचाते हैं। इससे जहां भोजन की बर्बादी रूकती हैं वहीं जरूरत मंदो को भोजन भी उपलब्ध होता है। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अभियान सोंचे, खाए और बचाए भी एक अच्छी पहल है। इसमें शामिल होकर की भोजन की बर्बादी रोकी जा सकती है। वर्तमान समय में समाज के सभी लोगों को मिलकर भोजन की बर्बादी रोकने के लिये सामाजिक चेतना लानी होगा। तभी भोजन की बर्बादी रोकने का अभियान सफल हो पायेगा। खाने की बर्बादी रोकने की दिशा में देश में महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। महिलाओं को अपने घर के बच्चों में बचपन से यह आदत डालनी होगी कि जितनी भूख हो उतना ही खाना लो। एक-दूसरे से बांट कर खाना भी भोजन की बर्बादी को बड़ी हद तक रोक सकता है। भोजन की बर्बादी रोकने के लिए हमें अपनी आदतों को सुधारने की जरूरत है। धार्मिक लोगों एवं स्वयंसेवी संगठनों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए।

सब के मन में एक सवाल- राम की अयोध्या वाली सीट कैसे हार गई भाजपा ?

रामस्वरूप रावतसरे

लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है। देश भर में कई जगह मतदाताओं ने चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं। इनमे से सबसे अधिक चौंकाने वाला परिणाम उत्तर प्रदेश के अयोध्या (फैजाबाद) से आया है। यहाँ भाजपा हार गई है। यहाँ भाजपा सांसद लल्लू सिंह को सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने हरा दिया है। अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से शिकस्त दी है। यह सीट सपा ने 1998 के बाद पहली बार जीती है। लोगों का कहना है कि भाजपा वह सीट हारी है जहाँ भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ ऐसा कैसे हो सकता है। राम मंदिर को लेकर संघर्ष करने वाली पार्टी का अयोध्या से ही हार जाना लोगों को अचरज में डाल रहा है। 4 जून, 2024 को परिणाम आने के बाद देश भर में यह सीट चर्चा का बिंदु बनी हुई है। इस मुद्दे पर आम जनता से लेकर राजनीतिक पंडित तक लगातार चर्चा कर रहे हैं, वह यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्यों भाजपा अयोध्या सीट हारी। चुनाव के परिणामों के बाद मीडिया ने इस मामले पर अपने हिसाब से कई निष्कर्ष दिए हैं। मीडिया ने अयोध्या में भाजपा की इस हार के एक से अधिक कारण बताए हैं। इसमें कार्यकर्ताओं की नाराजगी से लेकर सांसद रहते लल्लू सिंह का जमीन पर ना जाना और भाजपा के दलित वोट खिसकना आदि शामिल है। जमीन अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे भी अहम् बताए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया है कि अयोध्या जिले में भाजपा के सामान्य कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई। मंदिर बनने के बाद टप्च् जिला होने से यहाँ बड़े नेताओं की ही चली और स्थानीय कार्यकर्ताओं का फीडबैक ऊपर तक नहीं पहुँचा। इसी कारण से कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग उदासीन हो गया और नाराज रहा, जिससे नुकसान हुआ। इसके अलावा 2014 से लगातार सांसद रहे लल्लू सिंह का जमीन पर ना उतरना भी मुद्दा बताया गया, इससे उनकी जनता में छवि को धक्का लगा। लल्लू सिंह ने नाराजगी के अलावा जो भी वोट भाजपा को मिले वह पीएम मोदी की लोकप्रियता और राम मंदिर के मुद्दे पर ही पड़े। सपा ने इस सीट से दलित प्रत्याशी उतारा। सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद 9 बार के विधायक हैं। उनको दलितों का वोट काफी बड़े स्तर पर मिला। भाजपा से दलित वोट का छिटकना भी एक हार का एक बड़ा कारण रहा। बताया गया कि इस लोकसभा क्षेत्र में 26 प्रतिषत दलित वोट को सपा ने अपने प्रत्याशी के चयन से ही अपनी तरफ मिला लिया। इसके अलावा मुस्लिम वोटर भी एकतरफा सपा की तरफ गए जिसने यहाँ उसे बढ़त दिलाई। सपा से कॉन्ग्रेस के गठबंधन के कारण मुस्लिम वोट छिटका नहीं। बड़े स्तर पर मुस्लिम वोट ने सपा को यहाँ बढ़त दिलाई, जिससे उसे जीत हासिल करने में आसानी हुई। भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान एक बयान में भाजपा के 400 सीट वाले नारे पर संविधान बदलने का तर्क दिया। उन्होंने कहा कि 400 सीट होंगी तो संविधान बदला जा सकेगा। इस बयान का संदेश उनके लोकसभा क्षेत्र में सही नहीं गया। दलित वोटर्स में इस कारण से उनके प्रति दुराव आया और उन्हें इस तबके के वोट नहीं मिले। अयोध्या में विकास के लिए काफी जमीन अधिग्रहण किया गया। प्रशासन ने इसके लिए स्थानीय लोगों की काफी जमीन ली। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अयोध्या में जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ियाँ हुईं और मुआवजे का बँटवारा सही से नहीं हुआ।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताए और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
कार्य सफलता और विरोधियों पर विजय का नशा आपके दिलो-दिमाग पर छाया रहेगा, इससे प्रसन्नता अनुभव करेंगे। भाई-बहनों के साथ मिलकर घर पर कोई आयोजन करेंगे। ऑफिस तथा काम-काज की जगह अधिकारियों की नाराजगी का शिकार होना पड़ेगा।

वृष
आपका आज का दिन शुभ फलदायी साबित होगा। निर्धारित काम सफलता से पूरे होंगे। अधूरे काम पूरे होंगे। ननिहाल पक्ष से आनंददायक समाचार मिलेंगे। बीमारी में राहत महसूस होगी। नौकरीपेशा वर्ग को नौकरी में लाभ होगा।

मिथुन
अपनी कला को बाहर लाने के सुनहरे अवसरों को हाथ से न जाने दें। आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्ति अधिक निखरेगी। शारीरिक, मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी। मनोरंजन की प्रवृत्ति में दोस्तों तथा परिजनों के साथ भाग लेंगे।

कर्क
परिवार में आज आनंद का वातावरण रहेगा। वाणी की मधुरता और न्यायप्रिय व्यवहार से आप लोकप्रियता प्राप्त करेंगे। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। विद्यार्थियों के विद्याध्ययन के लिए अनुकूल समय है। मित्रों के साथ घूमना-फिरना होगा।

सिंह
अविवाहित लोगों के विवाह के योग बनेंगे। आपको पत्नी अथवा संतान से लाभ हो सकता है। व्यापार के लिए होने वाला प्रवास लाभदायक साबित होगा। आपके उच्च अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। पदोन्नति होने की संभावना है।

कन्या
शारीरिक- मानसिक अस्वस्थता का अनुभव होगा। छाती में दर्द या किसी विकार से परिवार में अशांति होगी। महिलाओं के साथ मनमुटाव और तकरार होने की संभावना है। सार्वजनिक रूप से मानहानि होने से दुख होगा। दांपत्य जीवन में विशेष मधुरता रहेगी।

तुला
सुंदर भोजन, वस्त्र और वाहन सुख की प्राप्ति होगी। प्रिय व्यक्ति की मुलाकात तथा काम में सफलता का योग है। आज आपके विदेश में बसने वाले स्नेहीजन या मित्रों से शुभ समाचार मिलने की संभावना है। समय से भोजन नहीं मिलेगा।

वृश्चिक
पारिवारिक जीवन में उत्साह का वातावरण रहेगा। संतान की प्रगति से आपको संतोष का अनुभव होगा। आज आपको बेचैनी, थकान का अनुभव होगा। शरीर में ताजगी का अभाव रहेगा। इससे काम करने का उत्साह नहीं रहेगा।

धनु
आज आपका दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। आयात निर्यात से जुड़े व्यापारियों को धंधे में लाभ और सफलता मिलेगी। आपकी खोई हुई वस्तु वापस मिलने की संभावना है। प्रवास आर्थिक लाभ और वाहन सुख की संभावना है।

मकर
आमोद-प्रमोद की प्रवृत्तियों में पैसे खर्च होंगे। दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ निकटता के पल व्यतीत कर सकेंगे। कोर्ट-कचहरी के मामलों में संभलकर कार्य करना उचित रहेगा। ऑफिस में स्त्री वर्ग से लाभ होने की संभावना है।

कुंभ
आज आप आर्थिक लाभ के साथ समाज में आदर प्राप्त कर सकेंगे। आपके परिवार में सुख और संतोष बना रहेगा। आपकी आय बढ़ेगी और व्यापार में भी लाभ होगा। प्रिय व्यक्ति के साथ सुखद समय बिताएंगे।

मीन
आज संतान और जीवनसाथी के संबंध में चिंता होगी। वाद-विवाद या चर्चाओं में गहरे न उतरना हित में रहेगा। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। मित्रों के लिए खर्च की संभावना है। पेट संबंधी बीमारियों से तकलीफ होगी। मौज-शौक और घूमने-फिरने के पीछे खर्च होगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अब भी मोदी सबसे बड़े एवं वर्चस्वी नेता हैं

-ललित गर्ग

अठारहवीं लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही अपने अंदर कई संदेशों को समेटे हुए हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो, भले ही इंडिया गठबंधन एक चुनौती के रूप में खड़ा हुआ हो, फिर भी तीसरी बार नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हुए नये भारत एवं सशक्त भारत को निर्मित करने के लिये वे पहले दो कार्यकाल से अधिक शक्ति, संकल्प एवं जिजीविषा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सीटों के लिहाज से भाजपा को भले ही नुकसान हुआ, लेकिन लगातार तीसरी बार वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ओडिशा और तेलंगाना में पार्टी ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको चौंकाया है। ओडिशा में लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में भी पार्टी ने बीजू जनता दल का 24 साल से चला आ रहा वर्चस्व तोड़ा। अरुणाचल प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 54 प्रतिशत मत और 46 सीटों के प्रचंड बहुमत के बल पर भाजपा सरकार बनाने में सफल हुई है। वहीं, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भाजपा के गढ़ बने हुए हैं, जबकि देश की राजनीति में अब भी मोदी सबसे बड़े एवं वर्चस्वी नेता है। वे अब भी अपने चौंकाने वाले एवं आश्चर्य में डालने वाले विलक्षण एवं अनूठे फैसलों से राष्ट्र को विकास की नई उड़ान देते रहेंगे। भाजपा को कम सीटें मिले कारणों की समीक्षा एवं मंथन करते हुए अपनी हार के कारणों को सहजता एवं उदारता से स्वीकारना चाहिए एवं जिन गलतियों के कारण कम सीटें मिली, उन्हें दूर करना चाहिए।

इस बार के चुनाव को नियोजित एवं प्रभावी तरीके से सम्पन्न करने में चुनाव आयोग की भूमिका सराहनीय रही। भले ही इंडिया गठबंधन ने ई.वी.एम. और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगाकर देश एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कलंकित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम ने न केवल इस प्रकार के भ्रामक, गुमराह करने वाली बातों एवं मिथकों को तोड़ दिया, बल्कि इसने भारत के जीवंत, बहुलतावादी, पंथनिरपेक्षी और स्वस्थ लोकतांत्रिक छवि को पुनर्स्थापित किया है। प्रधानमंत्री मोदी का अंधविरोध करने वाला वाम-जिहादी-सम्प्रदायवादी राजनीतिक समूह अपने इस वाहियात प्रलाप एवं राष्ट्र-विरोधी षड़यंत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिये चुनाव परिणाम अनेक अर्थों में संतोषजनक रहे हैं। कांग्रेस के लिये यह चुनाव नये जीवन का वाहक बना हैं। वैसे भी एक आदर्श लोकतंत्र के लिये सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है, यही लोकतंत्र को खूबसूरती देता है। भारतीय मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को विपक्षी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने का संदेश दिया है।

इस बार के चुनाव परिणाम अनेक राजनीतिक दलों के सामने भी अनेक प्रश्न खड़े किये हैं। कौन जेल में रहेगा, इसका फैसला अदालतें करती हैं। परंतु दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव को अपने जेल के अंदर रहने या बाहर रहने का अधिकार मतदाताओं को सौंपा था, जिसका नतीजा यह रहा कि उनके शासित वाले दिल्ली में ह्यआपह्न का खाता तक नहीं खुला, तो वहीं उनकी पार्टी पंजाब में विधानसभा चुनाव-2022 का चमत्कार दोहराने में विफल हो गई और 13 में से केवल 3 सीटें ही जीत पाई। शरद पवार का राजनीतिक वारिस कौन और असली शिवसेना किसकी? क्या माया और ममता अब भी ताकतवर हैं? यह चुनाव ऐसे ही कई सवालों के साथ शुरू हुआ था। इनमें से कुछ के जवाब मिल गए हैं और कुछ के बाकी हैं। जिस तरह के नतीजे आए हैं, उससे यह संदेह भी पैदा हुआ है कि क्या देश में आर्थिक सुधार जारी रहेंगे? क्या देश विकास के पथ पर अग्रसर होता रहेगा? नीतिगत स्थिरता का क्या होगा? शायद इसी संदेह की वजह से शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। लेकिन नरेन्द्र मोदी के पहले भाजपा मुख्यालय में दिये उद्बोधन एवं गठबंधन दलों के साथ हुई बैठक में इन सवालों के जवाब काफी हद तक मिल गये, जिससे शेयर बाजार ने भी तेजी पकड़ी है एवं भाजपा एवं सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है।

देश एक बार फिर गठबंधन सरकारों के युग में प्रवेश कर रहा है। अब यह एक हकीकत है कि मौजूदा जनादेश के मद्देनजर गठबंधन सरकार बनाना भाजपा की मजबूरी हो गई है। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाने और अल्पमत में सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाने में बड़ा फर्क है। सवाल उठाया जा रहा है कि पूर्ण बहुमत वाले दो कार्यकालों में देशहित के बड़े फैसले लेने वाली भाजपा क्या गठबंधन के सहयोगियों के दबाव के बीच शासन करने में खुद को सहज महसूस कर सकेगी? लेकिन मोदी के नेतृत्व में सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और अपने संकल्पों एवं योजनाओं को आकार देगी, इसमें कोई संदेह नजर नहीं आती। देश में केंद्रीय स्तर 2009 के बाद पहली बार गठबंधन सरकार बनने जा रही है। अतीत में नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन सरकारों का कुशलता से संचालन किया है और आवश्यक सुधारों को भी आगे बढ़ाया। मनमोहन सिंह ने भी दस वर्ष तक गठबंधन सरकार का संचालन किया है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उन्हें किस तरह कई बार सहयोगी दलों के अनुचित दबाव में झुकना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी भी गठबंधन सरकार की चुनौतियों से जूझते रहे। लेकिन मोदी की स्थितियां भिन्न है, वे राजनीति के धुंरधर खिलाड़ी है, अमित शाह राजनीतिक जोड़ तोड़ के खिलाड़ी है, इसे देखते हुए भाजपा और उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक अपना काम कर सकेगी, ऐसा विश्वास है। न केवल सरकार बल्कि भाजपा के बड़े मुद्दों का भी क्रियान्वयन होगा। जब-जब भाजपा के सामने अनुचित राजनीतिक दबाव की स्थितियां बनेगी, सरकार कोई सार्थक रास्ता निकाल लेगी। वैसे भी भाजपा बहुमत के आंकड़े से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि तेलुगु देसम पार्टी, जनता दल-यू, शिवसेना समेत अन्य सहयोगी दलों के साथ उसके लिए सरकार चलाना कहीं अधिक आसान होगा। इसके बाद भी इतना तो है कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार गठबंधन सरकार का संचालन करेंगे। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के तहत कार्य करने के कारण वह ऐसी सरकार के संचालन के तौर-तरीकों से अवगत हैं, लेकिन स्वयं उनके लिए ऐसी सरकार चलाना एक नया अनुभव होगा। लेकिन वे भाजपा संगठन के अनेक पदों पर रहते हुए संगठन की गतिविधियों के कुशल संचालन से भिज्ञ है। देश-विदेश के दबावों को झेलते हुए उन्होंने भारत को एक शक्ति के रूप में खड़ा किया है, दुनिया जब आर्थिक संकट झेल रही है, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, निश्चित ही गठबंधन सरकार का उनका संचालन उनकी नेतृत्व क्षमता और सबको साथ लेकर चलने के राजनीतिक कौशल को एक नया आयाम देगी। उनके पास चुनौतियों के बीच देश की समस्याओं का समाधान करने की एक राजनीतिक दृष्टि एवं कौशल है।

गठबंधन सरकारों के कुछ सकारात्मक पक्ष होते हैं तो कुछ नकारात्मक पक्ष भी। गठबंधन सरकारों का नेतृत्व करने वाले को घटक दलों से समन्वय के साथ चलना होता है। इसमें समस्या तब आती है, जब घटक दल अनुचित मांगें मनवाने लगते हैं अथवा सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति के लिए दबाव की राजनीति करने लगते हैं। इन स्थितियों की निबटने के लिये मोदी सरकार पहले ही अन्य निर्दलीय सांसदों एवं अन्य राजनीतिक दलों को अपने साथ जोड़ने का उपक्रम कर रही है। सहयोगी दल अनुचित मांग एवं दबाव की बजाय अपने राज्य के राजनीतिक एवं आर्थिक हितों की चिंता करें, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें राष्ट्रीय हितों को ओझल नहीं करना चाहिए। यह उन्हें भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गठबंधन सरकार सुगम तरीके से चले।

निश्चित ही मोदी सरकार के सामने चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं, जिस तरह महाभारत युद्ध में पांडवों के सामने जटिल स्थितियां थी। आज द्रोण नहीं तुष्टिकरण है, कृपाचार्य नहीं भ्रष्टाचार है, अश्वत्थामा नहीं आतंकवाद है, दुर्योधन नहीं महत्वाकांक्षा एवं अनैतिकता है, शकुनि नहीं आंतरिक और वैश्विक षड्यंत्र है, राष्ट्रवाद नहीं समस्त प्रकार की विघटनकारी शक्तियां-भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, स्वार्थवाद आदि हैं और कर्ण नहीं कट्टरवाद है। साथ में महंगाई, बेरोजगारी, असंतोष आदि की अत्यंत जटिल समस्याएं भी हैं और अब भारत इनमें फंसा हुआ है। फिर भी नरेन्द्र मोदी रूपी उजाला अपनी नई पारी में अधिक सशक्त होकर भारत के इन सभी चक्रव्यूह को भेदेगा। अपने राजनीतिक जीवन की सबसे सफलतम पारी खेलते हुए वह एक बार फिर नकारात्मक एवं अराष्ट्रवादी शक्तियों को उनकी जमीन दिखायेंगे।

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद भाजपा की घटती संख्या के कारण व निराकरण

अशोक भाटिया

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जनता का फैसला अब सामने आ चुका है। मतगणना के दो दिन बाद, तस्वीर और ज्यादा साफ हो गई है। 543 सदस्यीय लोकसभा में 292 सीटें हासिल करने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने जीत हासिल की है। इंडिया गठबंधन ने सभी एग्जिट पोल और भविष्यवाणियों को धता बताते हुए 234 सीटें हासिल की हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों से सबसे बड़ी बात यह रही है कि भाजपा की सीटों की संख्या में गिरावट आई है। 2019 के चुनाव में 303 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा इस बार 240 सीटों पर सिमट गई। यह भाजपा के लिए एक कठिन राजनीतिक तस्वीर पेश करता है। नई सरकार अपने गठबंधन सहयोगियों खासकर तेलुगु देशम पार्टी- टीडीपी और जनता दल (यूनाइटेड) पर बहुत अधिक निर्भर होगी। नए जनादेश के कारण एक दशक के एकल-दल के प्रभुत्व का अंत होगा और केंद्र में गठबंधन सरकार की वापसी होगी। लेकिन भाजपा के लिए क्या गलत हुआ? वे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से इसकी सीटें कम हुईं, कुछ तमाम अध्ययन और मनन के बाद कुछ कारण सामने आ रहे हैं। इनमें बड़े राज्यों में खराब प्रदर्शन, क्षेत्रीय पार्टियों का मजबूत होना आदि वजह हैं। भाजपा के खराब प्रदर्शन का एक सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में उसका प्रदर्शन है। दरअसल, भारतीय राजनीति में यह कहावत सच साबित हो रही है कि ह्यदिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपने दम पर 33 और अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ 36 सीटें जीती हैं। 2014 के चुनाव में यूपी से भाजपा ने 71 सांसद लोकसभा में भेजे थे और 2019 में उसने अपने दम पर 62 और अपने सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) के साथ दो सीटें जीतीं।

कई विश्लेषकों ने पाया है कि अखिलेश यादव का पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) फॉर्मूला इसके बेहतर प्रदर्शन और भाजपा के खराब प्रदर्शन का एक कारण है। इसके अलावा, इस बार टिकट वितरण में भी बदलाव किया गया है।बड़े राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि इस बार टिकट वितरण कुछ सर्वेक्षण एजेंसियों और कुछ खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर आधारित था। आलाकमान ने टिकट के दावेदारों के बारे में अपने खुद के मानदंड, पसंद और नापसंद तय कर लिए। जमीनी हकीकत पर एक शब्द भी नहीं सुना।

उत्तर प्रदेश में भाजपा को सबसे बड़ा झटका फैजाबाद सीट पर लगा। अयोध्या फैजाबाद सीट में ही आती है और यहां इस साल 22 जनवरी को बड़ी ही धूमधाम से रामलला की स्थापना और राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। कयास ये लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में केवल राम मंदिर ही भाजपा को रिकॉर्ड सीटों से जीत दिला देगा। लेकिन यहां तो खुद अयोध्या की सीट के लाले पड़ गए। हरियाणा की बात करें तो यहां भी भाजपा को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा में लगातार 2 बार भाजपा सभी 10 सीटें पर जीत रही थी, लेकिन इस बार आधी सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। कांग्रेस 5 सीटों पर कब्जा करने में सफल रही। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने यहां सत्ता परिवर्तन किया था। साथ ही यहां चल रहा जननायक जनता पार्टी-जजपा गठजोड़ भी तोड़ दिया। 25 सीटों वाले राजस्थान में भी भाजपा को चोट पहुंचाई है। यहां भाजपा को 14, कांग्रेस को 8, सीपीआई-एम, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी-आरएलटीपी और भारत आदिवासी पार्टी ने एक-एक सीट जीती हैं। भी क्षेत्रीय दलों ने भाजपा की नींव खोखली करने का काम किया है।बताते है कि राजपूतों की बेरुखी भी भाजपा को भारी पड़ गई । न्यूज 24 चैनल के अनुसार भाजपा का जाट प्रेम और राजपूतों से दूरी भाजपा को ले डूबी ।7 में से केवल एक जाट जीता जबकि तीनों राजपूत उम्मीदवार विजयी रहे । भाजपा द्वारा विधानसभा की गलती दोहरे गई । हालाँकि गुजरात , ऊतार्प्रदेश औए राजस्थान के कुछ हिस्सों में राजपूतों द्वारा एहर , इतिहास व कुछ अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा का खासा विरोध रहा । मंत्रिमंडल विस्तार में राजपूतों की संख्या बढ़ाने पर पुनर्विचार ।पार्टी को डेमेज कंट्रोल की कवायत करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाद भाजपा को सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा है। यहां भाजपा ने 48 में से 9 सीटें जीतीं। उसके सहयोगी दल शिवसेना (शिंदे गुट) ने 7 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- एनसीपी ने एक सीट जीती। इससे राज्य में एनडीए की सीटों की संख्या 17 हो गई। इसकी तुलना 2019 से करें, महाराष्ट्र में भाजपा ने अपने दम पर 23 सीटें जीती थीं। इससे पता चलता है कि 2022 में शिवसेना और 2023 में एनसीपी का अलग होना मतदाताओं को रास नहीं आया है। राजनीतिक पंडितों का यह भी तर्क है कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए मराठा आंदोलन ने भी नतीजों को प्रभावित किया है।

भाजपा के खराब प्रदर्शन के पीछे एक और कारण यह हो सकता है कि पार्टी देश में बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने में असमर्थ रही है। भाजपा के घोषणापत्र में महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र तक नहीं था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों की दुर्दशा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं, जिन्हें सत्तारूढ़ भाजपा हल करने में विफल रही है। इसके अलावा, कई पंडितों का मानना है कि भाजपा ने अल्पकालिक अग्निपथ योजना को लेकर लोगों के गुस्से को ध्यान में नहीं रखा। कई ग्रामीण युवाओं ने सैन्य भर्ती योजना को लेकर अपना असंतोष व्यक्त किया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के दम पर भाजपा के तेजी से बढ़ते कद ने क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय राजनीति के हाशिये पर धकेल दिया था। हालांकि, 2024 के चुनाव ने फिर से स्थिति बदल दी है।उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर भाजपा को बड़ा झटका दिया है। इसी तरह, एग्जिट पोल के पूवार्नुमानों को झुठलाते हुए ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस-टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 29 सीटें हासिल की हैं, जिससे भाजपा बहुत पीछे रह गई है। इससे टीएमसी, कांग्रेस और सपा के बाद विपक्षी दल भारत में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है।इसी तरह, तेलगु देशम पार्टी-टीडीपी और जनता दल (यू) ने भी बड़ा प्रदर्शन किया है। चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली टीडीपी ने कुल 16 सीटें हासिल की हैं, जबकि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडी(यू) ने 12 सीटें जीती हैं।

चुनाव से पहले, भाजपा ने अपने नेताओं की अनदेखी करके कांग्रेस और अन्य दलों से पार्टी में आए नेताओं को टिकट दिया। हालांकि, उन्होंने वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा पार्टी चाहती थी। हिमाचल और पंजाब में कांग्रेस से भाजपा में आए कई दलबदलू लड़खड़ा गए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से भाजपा में आए छह दलबदलुओं में से चार हार गए। पंजाब में कांग्रेस से भाजपा में आए रवनीत बिट्टू और आम आदमी पार्टी- आप से भाजपा में आए सुशील रिंकू चुनाव हार गए। इससे साफ पता चलता है कि मतदाता दलबदलुओं से नाखुश थे और उन्होंने उन्हें बाहर कर दिया। कहा जा रहा है कि दलबदलुओं के कारण भाजपा का नारा ह्यअब की बार, 400 पार उल्टा पड़ गया।

यह भी चर्चा है कि इस बार भाजपा के दिग्गज नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ- आरएसएस के स्वयंसेवकों और पार्टी के जमीनी कार्यकताओं की अनदेखी की। जानकार कहते हैं कि 2014 और 2019 के चुनाव में आरएसएस ने जिस प्रकार जमीन पर उतरकर काम किया, इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब एक चर्चा यह चल रही है कि लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पार्टी पर पकड़ बढ़ जाएगी। सच्चाई यह है कि संघ और भाजपा के संबंध में किसी तरह का बदलाव आने नहीं जा रहा है। संघ खुद को पार्टी के रोजाना के कामकाज से दूर रखने की कोशिश करता है। संघ के अगले साल 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में उसका फोकस अपने आधार पर व्यापक बनाने पर है। संघ के कार्यकर्ता भाजपा में राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के सचिव या संयुक्त सचिव की भूमिका निभा रहे हैं। ये कार्यकर्ता फुल टाइम वर्कर हैं जिन्हें प्रचारक कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र खुद एक प्रचारक रह चुके हैं। वह भाजपा में संगठन के सचिव का पद भी संभाल चुके हैं। भाजपा और संघ के बीच पावर को लेकर किसी तरह का टकराव या खींचतान नहीं रही है। इसकी वजह यह है कि दोनों अलग-अलग क्षेत्र में काम करते हैं। संघ का नेतृत्व यह बात अच्छी तरह से समझता है कि राजनीति की कुछ अपनी मजबूरियां हैं और भाजपा को इन मजबूरियों से बाहर निकलने का रास्ता खुद तलाशना है। अगर कोई बात भाजपा नेतृत्व तक पहुंचानी है तो उसे संगठन के सचिवों के जरिए पहुंचाया जाता है। संघ न तो शासन के कामकाज में हस्तक्षेप करता है और न ही भाजपा की राजनीतिक गतिविधियों में उसकी हिस्सेदारी होती है। उसकी भूमिक विचारधारा के स्तर पर एक मार्गदर्शक की होती है। भारतीय जनसंघ के समय से ही संघ का राजनीति से रिश्ता इसी तरह से चला आ रहा है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्रे मोदी के बीच किसी तरह का विरोधाभास है। यह याद रखना होगा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही संघ प्रचारक नानाजी देशमुख को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जब कभी भाजपा किसी मुश्किल में होती है, यह चर्चा शुरू हो जाती है कि संघ और पार्टी नेतृत्व के बीच खींचतान चल रही है। संघ की रोजाना 60,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं और अलग-अलग संगठनों के जरिए दो लाख कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। संघ को इसके बाद कोई समय नहीं बचता है। उसकी भाजपा को नियंत्रित करने की न तो कई इच्छा है और न ही कोई महत्वाकांक्षा।

रोकनी होगी भोजन की बबार्दी ?

7 जून विश्व खाद्ध सुरक्षा दिवस

-रमेश सर्राफ धमोरा

-रमेश सर्राफ धमोरा

रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती है। जिसके बिना मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल है। इसमें रोटी सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि रोटी के बिना तो मनुष्य जिन्दा भी नहीं रह सकता है। खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित किया जाना है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में हर दस में से एक व्यक्ति दूषित भोजन का सेवन करने से बीमार पड़ जाता है। जो कि सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए इस बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस संक्षिप्त रूप में मनाया जाएगा। जिसमें लोगों को सेहत से जुड़े मुद्दों पर ऑनलाइन एक-दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा।

इस बार हम छठवां विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इससे खाद्य सुरक्षा लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा सकती है और विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों से होने वाली बीमारियों को भी ध्यान में लाया जा सकता है। इस दिन को मनाने के पीछे खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगो को जागरूक करने का उद्देश्य था। जो खराब भोजन का सेवन करने की वजह से गंभीर रोगों के शिकार बन जाते हैं।

भोजन की कमी व दूषित भोजन खाने से प्रतिवर्ष हजारों लोगों की जान चली जाती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन को दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों का नेतृत्व करने और पौष्टिक खाने के प्रति लोगों को जागरुक करने की जिम्मेदारी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में पहली बार खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया था। इसके बाद पहली बार 7 जून 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। तब से हर वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व में अपने मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता से बात करते हुए लोगों से खाने की बबार्दी रोकने की अपील की थी। उन्होने कहा कि ऐसा करना गरीबों के साथ अन्याय व समाजद्रोह है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपने कभी सोचा है कि हम जो जूठन छोड़ देते हैं। उससे हम कितने गरीबों का पेट भर सकते है? उन्होने कहा था कि इस पर सामाजिक जागरूकता बढनी चाहिए। भारत में अनाज को अन्नदेव का दर्जा प्राप्त है। यही कारण है कि हमारे देश में भोजन झूठा छोडना या उसका अनादर करना पाप माना जाता है। मगर आधुनिकता के चक्कर में हम अपने पुराने संस्कार भूल गए हैं। हमारे यहां शादियों, उत्सवों या त्यौहारो में होने वाली भोजन की बबार्दी से हम सब वाकिफ हैं। इसके उपरांत भी हम इन अवसरों पर ढेर सारा खाना कचरे में फेंक है। कई बार तो घरों के आसपास फेंके गए भोजन से उठने वाली दुर्गंध एवं सड़ांध वहां रहने वालों के लिए परेशानी खड़ी कर देती हैं। शादियों में खाने की बबार्दी को लेकर भारत सरकार भी चिंतित है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि वह शादियों में मेहमानों की संख्या के साथ ही परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या सीमित करने पर विचार कर रहा है। इस बारे में विवाह समारोह अधिनियम, 2006 कानून भी बनाया गया है। हालांकि इस कानून का कड़ाई से कहीं भी पालन नहीं किया जाता है। भारत में हर वर्ष जितना भोजन तैयार होता है उसका एक तिहाई बर्बाद चला जाता है। बर्बाद जाने वाला भोजन इतना होता है कि उससे करोड़ो लोगों की खाने की जरूरत पूरी हो सकती है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में बढ़ती सम्पन्नता के साथ ही लोग खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं। खर्च करने की क्षमता के साथ ही खाना फेंकने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। विश्व खाद्य संगठन के अनुसार देश में हर साल पचास हजार करोड़ रुपए का भोजन बर्बाद चला जाता है। एक ऑकलन के मुताबिक बर्बाद होने वाले भोजन की धनराशि से पांच करोड़ बच्चों की जिदगी संवारीं जा सकती है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य अपव्यय को रोके बिना खाद्य सुरक्षा सम्भव नहीं है। इस रिपोर्ट में वैश्विक खाद्य अपव्यय का अध्ययन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से करते हुए बताया है कि भोजन के अपव्यय से जल,जमीन और जलवायु के साथ साथ जैव-विविधता पर भी बेहद नकारात्मक असर पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमारी लापरवाही के कारण पैदा किए जाने वाले अनाज का एक तिहाई हिस्सा बर्बाद कर दिया जाता है। देश में एक तरफ करोड़ो लोग खाने को मोहताज है। वहीं लाखों टन खाना प्रतिदिन बर्बाद किया जा रहा है। हमारे देश में हर साल उतना गेहूं बर्बाद होता है, जितना आस्ट्रेलिया की कुल पैदावार है। नष्ट हुए गेहूं की कीमत लगभग 50 हजार करोड़ रुपये होती है और इससे 30 करोड़ लोगों को सालभर भरपेट खाना दिया जा सकता है। हमारे देश में 2.1 करोड़ टन अनाज केवल इसलिए बर्बाद हो जाता है। क्योंकि उसे रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त भंडारण की सुविधा नहीं है। औसतन हर भारतीय एक साल में छह से 11 किलो अन्न बर्बाद करता है। साल में जितना सरकारी खरीदी का धान व गेहूं खुले में पड़े होने के कारण नष्ट हो जाता है। उतनी राशि से गांवो में पांच हजार वेयर हाउस बनाए जा सकते हैं। आज कल कई शहरो में समाजसेवी लोगो ने मिलकर रोटी बैंक बना रखा हैं। रोटी बैंक से जुड़े कार्यकर्ता शहर में घरो से व विभिन्न समारोह स्थलों से बचे हुये भोजन को एकत्रित कर जरूरत मंद गरीबो तक पहुंचाते हैं। इससे जहां भोजन की बबार्दी रूकती हैं वहीं जरूरत मंदो को भोजन भी उपलब्ध होता है। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अभियान सोंचे, खाए और बचाए भी एक अच्छी पहल है। इसमें शामिल होकर की भोजन की बबार्दी रोकी जा सकती है। वर्तमान समय में समाज के सभी लोगों को मिलकर भोजन की बबार्दी रोकने के लिये सामाजिक चेतना लानी होगा। तभी भोजन की बबार्दी रोकने का अभियान सफल हो पायेगा। खाने की बबार्दी रोकने की दिशा में देश में महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। महिलाओं को अपने घर के बच्चों में बचपन से यह आदत डालनी होगी कि जितनी भूख हो उतना ही खाना लो। एक-दूसरे से बांट कर खाना भी भोजन की बबार्दी को बड़ी हद तक रोक सकता है। भोजन की बबार्दी रोकने के लिए हमें अपनी आदतों को सुधारने की जरूरत है। धार्मिक लोगों एवं स्वयंसेवी संगठनों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए।

खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर होता भारत

7 जून वैश्विक खाद्य सुरक्षा दिवस पर विशेष

- सुरेश सिंह बैस शाश्वत

एक समय था जब भारत अपनी खाद्यान्न आपूर्ति के लिये दूसरे देशों की दया पर निर्भर था। हमारे पास न उस समय कृषि के साधन थे, और न ही उन्नत तकनीक थी। फलतः आज का वही कृषक पहले अपनी कृषि से वैसा उपज नहीं प्राप्त कर पाता था, जैसा कि आज वह प्राप्त कर रहा है। आज कई मायनों में भारत खाद्यान्नों के मामले में अब आत्म निर्भर हो चुका है। इस संबंध में समाजशास्त्रियों का भिन्न-भिन्न मत है। कुछ कहते हैं कि ये ठीक है कि आज हम खाद्यान्न उपज के मामले में पूर्व से बहुत बेहतर हैं, पर आज हमारी जनसंख्या भी तो बहुत बढ़ गई है, जिससे हमारी खाद्यान्न उत्पादन की बढ़ी हुई क्षमता तो जैसी की तैसी ही रह गई अर्थात हम जहाँ पहले वे आज भी वहीं है कोई परिवर्तन नहीं है। जबकि दूसरे मत के समाजशास्त्री कहते हैं कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि हुई है यह सही बात है, पर इस तथ्य को भी हमें नहीं भूलना चाहिये कि यहाँ अब श्रम करने वाले हाथ भी तो उतने ही बढ़ गये हैं, जो खाद्यान्न उत्पादन के लिये आवश्यक है। अर्थात जहाँ कम क्षेत्रफल में कम हाथों (श्रमजीवी किसान) द्वारा जो कार्य किया जा रहा था। बहुत सीमित एरिया सीमित मात्रा में था, वह अब असीमित होकर हमारी क्षमता को बेहतर और वृहत्तर बना रहा है। वैसे दूसरा मत वास्तविकता के नजदीक जान पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। एक दिन मैं एक पुरानी पत्रिका ?नवनीत? जो मई 1973 को प्रकाशित हुई थी, उसके पृष्ठ को पढ़ रहा था तो उसमें एक जगह सरकारी विज्ञापन दिखाई दिया जिसमें लिखा था,.... कम अनाज खाइये खाद्यान्नों के मूल्य कम करना आपके हाथ में है, गेहूँ चावल कम खाईये, सप्ताह में कम से कम एक बार बिना अनाज का ?भोजन लीजिये। उक्त विज्ञापन से साफ जाहिर होता है कि आज से कुछ वर्षों पूर्व हम खाद्यान्न के मामले में बहुत पीछे थे, हमारे यहाँ खाद्यान्नों जैसे गेंहू, चावल की बहुत कमी थी, तभी तो सरकार ने मजबूर होकर ऐसा विज्ञापन दिया रहा होगा। पर क्या आपने आजकल गत वर्षों में ऐसा कुछ विज्ञापन देखा है....? इसका जवाब होगा बिलकुल नहीं। इसका मतलब यही हुआ न कि अब हमारे यहाँ वैसी स्थिति नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। अब तो यह स्थिति है कि अब हम चायपत्ती उत्पादन में विश्व में प्रथम चावल में द्वितीय, गेहूँ में, तीसरी एवं चीनी उत्पादन में दूसरे, कपास में भी दूसरा स्थान पर है। देश में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य प. बंगाल एवं दूसरा आंध्र प्रदेश है, किंतु चावल की प्रति हेक्टेयर उपज पंजाब में सर्वाधिक है, मध्यप्रदेश आज देश में, सोयाबीन का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। देश में मध्यप्रदेश ज्वार में प्रथम, तुअर में तथा अन्य दालों में द्वितीय, गेहूँ एवं चने में तृतीय और धान (चावल) में तीसरा स्थान रखता है। किंतु प्रतिव्यक्ति औसत उत्पादन में पंजाब और हरियाणा के पश्चात तृतीय है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ की फसले 57 प्रतिशत क्षेत्र में और रबी की फसले 43 प्रतिशत क्षेत्र में बोई जाती हैं। विभिन्न खाद्यान्नों में कुछ क्षेत्र लगभग 82 लाख हेक्टेयर है, जिससे खाद्यान्न लगभग 71 लाख हेक्टेयर में और अन्य फसले 22 लाख हेक्टेयर में है। छत्तीसगढ़ में धान लगभग 18 लाख हेक्टेयर (कुल क्षेत्र का 22 प्रतिशत), गेहूँ लगभग 11 लाख हेक्टेयर, ज्वार लगभग 8 लाख हेक्टेयर और लगभग दाले 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जाती है, तिलहनें लगभग 12 लाख हेक्टेयर में तथा अन्य क्षेत्र में गन्ना, कपास आदि एसले बोई जाती है। उत्पादन की दृष्टि से सन 1988-89 में धान (चावल) 18.81, दाले 26.81, सोयाबीन सहित तिलहन 22.12 कपास 3.3, गन्ना 225 लाख मेट्रिक टन की पैदावार प्रदेश में प्राप्त की गई थी। सारे देश में उत्पादित चावल, गेहूँ, दालें, दलहन, कपास एवं गन्ने में सामान्यतःअविभाजित मध्यप्रदेश का योगदान 9, 11, 11, 8, 4, 7 प्रतिशत है। देश में अविभाजित मध्यप्रदेश ज्वार में प्रथम तुअर में द्वितीय, गेहूँ एवं चने में तृतीय चावल में तीसरा स्थान रखता है। खाद्यान्न व्यवस्था में पशुधन भी एक महत्वपूर्ण सहयोग स्त्रोत है। पशु मूल्यवान प्रोटीन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कृषि के कार्य और ग्रामीण परिवहन के लिये चलशक्ति प्रदान करते हैं। सन 1987 की पशु संगठनों के अनुसार अविभाजित मध्यप्रदेश में 4.63 करोड़ पंशु और 92 लाख कुक्कुट थे। सन 1988-89 में 47.64 लाख लीटर दुग्ध संकलन एवं 58.65 लाख लीटर का वितरण सिर्फ डेयरी विकास निगम के द्वारा प्रदेश में किया गया। इसी प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या, सीमित कृषि क्षेत्र तथा संतुलित एवं पौष्टिक आहार की दृष्टि से मछली उत्पादन का कार्य भी सहयोगी खाद्यान्न उत्पादन कार्य के लिये किया गया।

सरसरी तौर पर देखा जाये तो यह निश्चित है कि खाद्यान्न उत्पादन के मामले में हमारा देश एक सीमा तक आत्मनिर्भर हो चुका है। आज स्थिति यह है कि गेहूँ, चीनी हमारे यहाँ गोदामों में ठसाठस भरे पड़े हैं, उनके सुरक्षित रखने की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। पिछले वर्षों में गन्ना का रिकार्ड उत्पादन होने के कारण कृषकों को औने पौने दाम पर अपनी उपज बेचने पर मजबूर होना पड़ा था। यही कारण था कि चालू वर्ष में अधिकतर कृषकों ने गन्ने की उपज के बजाय दूसरे खाद्यान्नों की फसले ली। रिकार्ड बना उत्पादन के कारण हमारे यहाँ अभी भरपूर मात्रा में चीनी का स्टाक है (परंतु फिर भी न जाने किस नीति के तहत चीनी का बाहरी देशों जैसे बांग्लादेश आदि से आयात किया गया।) पर .उसका उचित समय पर उपयोग नहीं होने से कृषक जगत में गलत संदेश जाता है। इसकी व्यवस्था को खासा ध्यान देना चाहिये। प्रदेश में उत्पादन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिये उनकी आर्थिक उन्नति हेतु विश्व खाद्य कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत श्रमिकों के पारिश्रमिक से निश्चित राशि काटकर उन्हें अनाज, दाल और खाद्य तेल वितरित किया जाता है। काटी गई राशि कल्याण निधि में जमा की जाती है। एशिया महाद्वीप में अपनी तरह की विशालतम वह योजना का चौदहवां चरण आरंभ हो चुका है। इसके अंतर्गत चार वर्षों की अवधि में 150 करोड़ रुपये मूल्य के खाद्यान्न तेल तथा दाल का वितरण किया जायेगा। इससे पूर्व विश्व खाद्य कार्यक्रम की योजना मजदूरों के कल्याण के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत संचित कल्याण निधि से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम में जनहित के कार्यों के अंतर्गत प्रदेश में अभी तक 813 डेम 193 शाला भवन 108 श्रमिक विश्राम स्थल तथा सामुदायिक भवन, 200 हेण्डपम्प, 335 कुँएँ, 80 झूलाघर, 156 ट्यूबवेल 218 गोबर गैस संयंत्र, 881 रपटें, 678 कि.मी. पहुँच मार्ग, 87 उद्वहन सिंचाई योजना, 106 आंगन बाड़ी एवं आदिवासी छात्रावास, 9 स्वास्थ्य केंद्र तथा 76 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया गया है। 14 एम्बुलेन्स क्रय की गई है, इसके अलावा 31 पशु शिविरों की भी स्थापना की गई है। वर्तमान में पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि भारत अब खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर एवं काफी तरक्की कर चुका है। पंजाब हरियाणा के कृषक तो अब बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे, गोदाम अब लबालब भरे पड़े रहते हैं। परंतु हमें यह देखकर निश्चिंत होने की कतई जरूरत नहीं है, हमें नित नए तकनीको को इस्तेमाल करने की जरूरत है जिससे के ऊपज और फसलें बढ़े, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती रहें ।साथ ही उत्पादकता भी बड़े यह तो तय है, कि हर आने वाला वर्ष अपने साथ बढ़ी हुई जनसंख्या को लेकर आएगा। तो इसके लिए हमें निश्चित तौर पर यह तैयारी करनी होगी कि हर पेट को अन्न मिले। और खाद्यान्न की किसी भी प्रकार की कमी ना होने पाएं। वह इसके साथ हमें इसके लिए भी चौकन्ना रहना है कि आज के हमारे भारत देश की एक सौ अड़तीस करोड़ की जनता के लिए हर पेट को भोजन मिल सके और सब की पूर्ति हो सके। इसके लिए इतना अनाज जिसे शीतकेंद्रों, अनाज गोदामों व अनाज केंद्रों में रखने की वैसी ही सुदृढ़ व्यवस्था का होना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके लिए भारत के हर राज्य में हर जगह हर स्थान में एक निश्चित योजना के अनुरूप बड़े-बड़े खाद्यान्न गोदामों की श्रृंखला विभिन्न राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार सुंदर योजना बनाकर तैयार किया जाना आवश्यक है। तभी तो हम करोड़ों मीट्रिक टन अनाजों को हम सुरक्षित और उपयोगी बनाकर रख सकेंगे। यह उतना ही आवश्यक तथ्य है, जितना कि अनाज का उत्पादन और उसकी सुरक्षाका ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना कि उसका उत्पादन करना।

-सुरेश सिंह बैस शाश्वत

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

प्रकृति के साथ बदलता जीवन सार

इस संसार में जो भी कुछ है। उसमें बदलाव प्रकृति के नियमों के अनुकूल होता रहता है। वक्त के साथ कर्म दिशा में परिवर्तन हर कि सी में होना ही जीवन का मूल मंत्र है। मनुष्य का जीवन समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। यह परिवर्तन अनेक कालरुप से गुजरता है और हर काल में समय के साथ बदले हुए जीवन का परिवर्तित होना ही जीवन का सार है। यह जीवन तो बचपन से शुरू होकर निरंतर बढ़ता चलता चला जाता रहता है। बदलाव के साथ बालपन, किशोरावस्था से युवावस्था और उसके बाद जवानी फिर अधेडता और अंत में बुढ़ापा के साथ समाप्त होने वाले से इस जिंदगी के मायने क्या है ? जी हां हम यही कहना चाह रहे हैं कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे। हंसते खेलते तितली बनते, सब कुछ भुला कर मस्ती काटते, कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं, बस अपने ही लौ में भागमभाग, खेलकूद, दोस्ती यारी, यही सब कुछ बचपन में हमने और आपने देखा होगा और आज यही सब कुछ याद आ रहा है।अपने छोटे से पोते को देखकर।मन मिजाज खुशी से भर जाता है, मन मयूर नाच उठता है। यही तो बचपन था हमारा भी, यानी बचपन को देखते हैं, उसी में झांकते हैं, हम भी कभी उसी के उम्र के हुआ करते थे।पर हमारा बचपन आज के बच्चों के बचपन से कुछ अलग हुआ करता था। आज आधुनिक काल आ गया है। जब मैं पैदा हुआ था तो गांव और शहर आज से बहुत कुछ अलग थे।आज आधुनिक काल में लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए बेताब रहते हैं और तब हमारे लिए मां बाबूजी गुरुजी सर्वोपरि हुआ करते थे। जो ज्ञान संस्कार दीक्षा और पढ़ाई कराया करते थे। बाद को गांव के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की और फिर मैट्रिक परीक्षा के बाद शहरों के कॉलेजों में दाखिला दिलाने के लिए अपने अभिभावकों के साथ दौड़ लगाते थे। दाखिला हो जाता था तो मन खुश हो जाता था और दाखिले के लिए वहां ज्ञान और मिले मार्क को ही तरजीह दी जाती थी, साक्षात्कार किया जाता था और तब दाखिला यानी कॉलेजों में जो इन दिनों की तरह जहां-तहां फैला नहीं था, अब तो गांव, कस्बों, अनुमंडल और जिलों में कालेजों की भरमार है। तब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैं बचपन की बात कर रहा था बचपन में बात बात पर जीद और? माँ बाबूजी के सामने रोना बात बात पर ज़िद पकड़ना और अपनी जिद पूरा कराना यही सब कुछ हुआ करता था, बचपन में खेलकूद स्कूल जाने न जान की बहाने बाजी। मां बाबूजी के मार डांट फटकार के साथ पढ़ाई और बस उसी पढ़ाई के बल पर जिंदगी बेहतर बनाने की कवायद। बचपन की यादें बहुत सारी किन किन को बताया जाए, किन-किन से नाता जोड़ा जाए।अब तो सब नाते रिश्ते मतलब के रह गए। बचपन बीत गया, लेकिन बचपन की यादें जेहन में अभी उमरती घुमरती है। हां तो बचपन की बात कर रहा था उस बचपन की जब हम अपने मां बाबूजी भाई बहनों के साथ रहा करते थे तब बात बात पर भाइयों और बहनों से झगड़ना रोना और फिर मां बाबूजी के पास शिकायतें लेकर जाना वह सब कुछ इस आधुनिक युग में बदल चुका है आजके बच्चे अपने स्कूल बैग के बोझ तले दबे होते हैं, उन पर शिक्षकों द्वारा स्कूल में दिए गए टास्क बनाने के लिए माता पिता का दबाव ऐसा कुछ हो गया है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ही लगाकर, उसे योग्य बनाने की सोच रखते हैं, तब ऐसा कुछ नहीं था। तब जो नहीं पढ़ पाते थे, वे किसी अन्य जगह में बहुत अच्छा कर पाते थे। खेलकूद भी एक ऐसी आदत बचपन की होती है, जो किसी को आबाद तो किसी को बर्बाद करता ही करता है।लेकिन अब तो खेलकूद भी आवाद ही करता है बच्चों को, जिसमें उनकी रुचि हो वहीं कुछ करने देना चाहिए, तभी वे अपने जीवन को सार्थक रूप दे पाएंगे। आज उस बचपन को हम याद कर रहे हैं, जिसमें हमारे दादा जी, दादी जी फुआ, मामा, मौसा सब कोई एक परिवार में इस तरह से हुआ करते थे, कि जब कभी एक साथ होते तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता था।सब को देख कर सबके साथ हिल मिलकर सब कुछ मिल जाता था। पर अब सब कुछ बदल सा गया। बचपन की सारी चीजें बदल बदल गई। जीवन बस बिताने भर के रह गये और इस बिताने में ही एक-एक दिन गुजर जाता है। तब की बात कुछ और थी, तब बचपन में हर कुछ बिना कुछ किए ही मिल जाता था। अब तो ऐसा है, पूरी जिंदगी खटकर कमाने पर भी अधूरी अभिलाषा के साथ कटती है। जिंदगी के मायने क्या है? यह अब पता चला है!जब बचपन, जवानी अधेडा अवस्था से गुजरते बुढ़ापा में आया है और मानव रूपी शारिरीक तन का बना जीवन सुख-दुख, मोह माया की परिभाषा को लांघता हुआ ज्यादतर संघर्षों से ही गुजरता हुआ, ऊपर वाले की साधना आराधना के साथ खत्म हुआ जाता है और विचार करने पर सोचने पर लगता है, जीवन तो बस जीवन है! जीवन के रास्ते तो सभी के अलग-अलग हैं पर मायने तो सभी के एक हैं, जीवन का गुजरना! कोई हंसी-खुशी जीवन को काटता है, तो कोई कष्टों में गुजरता है। ऊपर वाले की महिमा सब पर होती है। सभी उसे पुकारते हैं। अंत जब आता है भगवान दिखाई देते हैं। क्योंकि धरा पर माता-पिता का माध्यम बनकर पैदा होने वक्त तो बस माता-पिता परिजन होते हैं बाद को संगी साथी, बाल बच्चे साथ गुजारते हैं। लेकिन इस धरा से जीवन को समाप्त हो जाने वक्त तक सब अपने अपने कर्म दिशा की ओर मुड जाते हैं, लग जाते हैं चले जाते हैं और बुढ़ापा तो बस अपने आप में जीने का जीवन के मायने को ढूंढने का एक जरिया बनकर रह जाता है। यही कुछ समझ में आया है और आपके बीच इसे बांटकर विचारने का एक विषय रख रहा हूं कि आखिर जीवन जीने का मायने क्या है! जीवन है क्या? हंसते खेलते तितली बनते या फिर हर लम्हा दर्द से गुजरते बुढ़ापा, क्योंकि जीवन का सार तो यही है।सब कुछ यहीं है। यही जीवन जीने का जरिया बनता है। इस संसार का सार यही तो दिखता है। प्रकृति के नियम के अनुसार बदलाव चाहे वह मनुष्य का जीवन हो, पशु पंछी का जीवन हो या कोई भी जीव जंतु हो, सब के साथ बदलाव का नियम लागू होता है और इस नियम से कोई भी बच नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही नहीं जीवन के हर क्षेत्र में दुनिया में बदलाव होता रहता है और हर किसी को इसी बदलाव के साथ जीना होता है।फिर एक दिन समाप्त भी हो जाना होता है। जीवन की यही है, प्रकृति ही जीवन का मूल सार और मनुष्य को इसी सार के सहारे जीवन बिताना होता है। बदलते हालात और परिस्थितियां मनुष्य के जीवन को एक नई धारा प्रदान करते हैं।अब इस धारा में जो भी कठिनाइयां हो, परेशानियां हो उसे तो मनुष्य को झेलना ही होता है। परिवर्तन के साथ परेशानियों का जुड़ाव ही होता है और इसी जुड़ाव को हल करते आप आगे बढ़ते हो निश्चित रूप से जीवन के बदलाव को आप अपने अनुकूल ढाल देते हैं। जीवन है तो संसार है और इसी संसार में दुख सुख का समावेश होता है, जो जीवन में भोगना पड़ता है। हर तरह के कष्ट परेशानियों से आदमी जूझता रहता है।हर पल हर क्षण जीवन में शारीरिक मानसिक दुख सुख की अनुभूति होती है और संघर्ष देखने को मिलता है आज के आधुनिक परिवेश में मानव जीवन भले ही सिमट कर रह गया हो, बावजूद इसके संसार तो वही है, जिसमें जीना होता है। इस जीवन के कई आयाम होते हैं और उन आयामों से व्यक्ति को गुजरना होता है। परिवर्तन और बदलाव दो ऐसे शब्द है जो सुख भी देता है और दूध भी देता है खुशी और गम इसी में छुपी होती है परिवर्तन से व्यक्ति बुरा और भला हो सकता है बदलाव से भी व्यक्ति में वह चेतना जागृत होती है जो उसे कुछ करने में सहजता और असहजता का एहसास कराता है पर जीवन चलते रहता है और इसी को जीवन कहते हैं जो बदलते रहे समय अनुकूल समय के साथ चलता है। परेशानियां और समस्याओं से जुझते हुए जीवन को सफल बनाना ही मनुष्य जीवन की महानता में शामिल होता है। बदलाव को अपनाना और उसके साथ जीवन को चलाना मनुष्य के लिए आवश्यक है और उसके अनुरूप चलकर जीवन को सफल बनाना ही जीवन का अचार होता है जो मनुष्य जीवन को सार्थक करना कहलाता है।

प्रभात वर्मा

असाध्य वीणा : गहन आत्मचिंतन की कविता

प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय एक प्रतिभासंपन्न कवि हैं। उनकी कविताएँ अंग्रेजी कवि विलियम वड्र्सवर्थ, टी. एस. इलियट और आई. ए. रिचर्ड्स की भाँति गहन आत्मचिंतन से प्रस्फुटित होती हैं। विलियम वड्र्सवर्थ के शब्दों में कहें तो अज्ञेय की कविताएँ 'प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है।' समय से कदमताल करती हुई उनकी कविताएँ पाठक को 'स्पोण्टेनियस' के चरम तक ले जाती हैं। 'चिन्ता', 'इत्यलम', 'भग्नदूत', 'हरी घास पर क्षण भर', 'अरी ओ करुणा प्रभामय', 'बाबरा अहेरी', 'इन्द्रधनुष रौंदे हुए', 'कितनी नावों में कितनी बार', 'आंगन के पार द्वार' आदि काव्य कृतियाँ ऐसी ही हैं। 'आंगन के पार द्वार' में संकलित कविता 'असाध्य वीणा' कवि की संपूर्ण रचनात्मकता का उत्कर्ष है। यह कविता लगभग अज्ञेय जी के अंतिम समय की कविता है, जब वे रचनात्मकता के शिखर पर पहुँच चुके थे। सही मायने में अगर अज्ञेय ने एकमात्र कविता 'असाध्य वीणा' ही लिखा होता तो भी वे इतने ही चर्चित होते। 'असाध्य वीणा' अज्ञेय की संपूर्ण सृजनात्मक प्रतिभा का चरम है। यद्यपि यह कविता एक चीनी लोककथा पर आधारित है, परंतु इलियट की भाषा में कवि ने 'ट्रेडिशन' से प्राप्त सामग्री को अपने 'इंडीविजुअल टैलेंट' से चमत्कारिक बना दिया है। या यूँ कहें कि कवि ने परंपरा से प्राप्त चीनी लोककथा का अपनी वैयक्तिक प्रज्ञा से भारतीयकरण कर दिया है। चीनी लोककथा के अनुसार - 'लुंगामिन की खाल में एक विशालकाय कीरी वृक्ष था, जिससे इस वीणा का निर्माण किया गया था। अनेक कलावंत वादक इसे बजाने का प्रयत्न कर हार गये, परंतु वीणा नहीं बजा। इसी कारण इस वीणा का नाम 'असाध्य वीणा' पड़ गया। अंत में बीनकरों के राजकुमार 'पीवो' ही उस वीणा को साध सका। इस वीणा से उसने ऐसी तान छेड़ी कि उससे तरह-तरह की स्वर लहरियाँ प्रस्फुटित होने लगीं। कभी उसमें से प्रेम गीत निकलते, तो कभी युद्ध का भयानक राग। वीणा को साधते समय राजकुमार पीवो इतना बेसुध हो गया कि उसे स्वयं के होने का बोध ही न रहा। वह यह भी न समझ पाया कि वाद्य-यंत्र पीवो है, या पीवो वाद्य-यंत्र है। कला -साधना में कलाकार का कला के साथ एकमेक हो जाना, दरअसल समाधि की अवस्था है। जहाँ पहुँच कर मनुष्य शरीर की विस्मृति की अवस्था में होता है। कला- साधना के क्रम में कलाकार का आत्मिक समर्पण और अहं का विस्मरण ने ही अज्ञेय जी को 'असाध्य वीणा' रचने को प्रेरित किया होगा। इस कविता का असाध्य वीणा उन समस्त कलाकृति का प्रतीक है, जो सच्चे साधक के अभाव में मूक है। प्रकारांतर से यह संपूर्ण काव्य-जगत को प्रतीकित करता है, जिसे सच्चे व्याख्याकार की अपेक्षा है। कला और कलावंत को एकमेक कर देना बेहद महत्त्वपूर्ण है, चूँकि आत्मिक समर्पण के बिना कला-साधना संभव नहीं है। इस कविता में करीटी-तरु की एक शाखा से असाध्य वीणा का निर्माण हुआ है। कवि ने किरीटी-तरु की विराटता का जो वर्णन किया गया है, वह अखंड ब्रह्म के रूप में है, जिसमें यह दृश्य संसार समाया है। विज्ञान के अनुसार इस संसार की सारी चीजें आपस में संबद्ध हैं। अज्ञानता के कारण हमें उसकी अखंडता के बजाय खंडता का बोध होता है। सही अर्थ में ज्ञान का अर्थ सृष्टि की अखंडता और संपूर्णता का बोध है। किरिटी तरु की विराटता देखिए- "अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था। उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कथा कहा करते थे उसके कंधों पर बादल सोते थे। उसकी करिशुंडों- सी डालें हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थीं परित्राण कोटर में भालू बसते थे केहरि उसके वत्कल से कंधे खुजलाने आते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुँची थी पाताल लोक उसकी गंध प्रवणता शीतलता से फण टिका नाग वासुकी सोता था।" चीनी लोककथा में असाध्य वीणा का निर्माण कीरी तरु से दिखाया गया है, परंतु उस वीणा के निमार्ता को गौण रखा गया है। अज्ञेय जी ने असाध्य वीणा के साधक केशकम्बली प्रियंवद से पूर्व वज्रकीर्ति जैसे पात्र को उपस्थित किया है, जिसने इस वीणा का निर्माण किरीटी- तरु से किया था। इस वीणा के निर्माण में उसका पूरा जीवन खप जाता है। वीणा बजे, यह उनकी साध थी, जो जीते जी पूरी नहीं हो सकी! इस प्रकार कला- साधना से पूर्व कला- निर्माण की प्रक्रिया और उसकी महत्ता पर विचार करना कवि की सूक्ष्म दृष्टि को रेखांकित करता है। पंक्ति देखिए- "उसी किरीटी-तरु से वज्रकीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा : हठ साधना थी उस साधक की - वीणा पूरी हुई, साथ साधना, साथ ही जीवन लीला।" राजा भरी सभा में प्रियंवद से कहते हैं कि इस असाध्य वीणा को साधने का प्रयास मेरे राज्य के सभी कलाकारों, संगीतकारों ने किया, किन्तु वे गुणीजन हार गए, उनकी विद्या अकारथ हो गई, दर्प चूर-चूर हो गया, क्योंकि वे इसे साधने में असमर्थ रहे। राजा को विश्वास है कि वज्रकीर्ति की कृच्छ तपस्या व्यर्थ नहीं थी। इस वीणा को जिस दिन कोई सच्चा साधक अपनी गोद में लेगा, यह वीणा बजेगी। "मेरे हार गये सब जाने- माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ, दर्प चूर, पर मेरा अब भी है विश्वास कृच्छ- तप वज्रकीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा- स्वर सिद्ध गोद में लेगा।" प्रियंवद सही अर्थों में कलावंत है, चूँकि उनमें कलावंत होने का कोई दंभ नहीं है। वह एक सच्चा साधक है, जो अपनी साधना को अनवरत जारी रखना चाहता है। जिस दिन कोई मनुष्य अपनी किसी स्थिति को जीवन का चरम मान लेता है, उसी दिन से उसका अधःपतन प्रारंभ हो जाता है। महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था -'मैं बस एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ।' प्रियंवद सदैव शिष्य साधक होने का भाव रखता है। वह कहता है- "राजन! पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी।" प्रियंवद में कोई अहं भाव नहीं है। इसीलिए वह असाध्य वीणा के बहाने उस विशालकाय किरीटी-तरु का स्मरण करता है और स्वयं को सौंप देता है। मौन प्रियंवद वीणा को साधने से पूर्व स्वयं को शोधता है। जो स्वयं को शोध नहीं सकता, वह स्वयं को सौंप नहीं सकता और जो स्वयं को सौंप नहीं सकता, उसे कुछ भी पाने का अधिकार नहीं मिलता। इस संदर्भ में कबीर ने भी कहा है- 'सिर सौंपे सोई पिवै, नहीं तो पिया न जाई।' यहाँ सिर अहंकार का वाचक है। जो शिष्य अपने समस्त अहंकारों का उत्सर्ग कर गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, उसे ही परम ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है। असाध्य वीणा का प्रियंवद सच्चे साधक के रूप में सत्य का अनुसंधान कर वीणा के मूल रहस्य तक पहुँचना चाहता है। इस निमित्त वह पहले स्वयं को शोधता है और फिर स्वयं को किरीटी-तरु को सौंप देता है। अज्ञेय जी लिखते हैं - "मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा- नहीं, स्वयं अपने को शोध रहा था सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीटी- तरु को।" वीणा को साधते हुए प्रियंवद भूल गया था राज- सभा को। वह अकेलेपन में डूब गया था। इस तरह समाधिस्थ हो जाता है वह। उसकी समाधि में साक्षी है केवल विशालकाय जीवित किरीटी- तरु। समाधिस्थ होने के कारण ही प्रियंवद 'ईगो- लेश' हो जाता है। किरीटी- तरु के प्रति उनका समर्पण देखिये - "ओ दीर्घकाय ! ओ पूरे झारखण्ड के अग्रज, तात, सखा, गुरु, आश्रय, त्राता महाच्छाय, ओ व्याकुल मुखरित वन - ध्वनियों के वृंदावन के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं अनिमेष, स्तब्ध, संयत, संयुक्त, निर्वाक कहाँ साहस पाऊं छू सकूँ तुझे!" कवि ने किरीटी-तरु को ईश्वर का रूप प्रदान करते हुए उसे उन गुणों से संपन्न दिखाया है, जो परमात्मा के गुण हैं। इसीलिए किरीटी- तरु के प्रति प्रियंवद का अहंकार- विहीन समर्पण वस्तुतः परमात्मा के प्रति आत्मा का समर्पण प्रतीत होता है। प्रियंवद में आत्मोत्सर्ग का भाव कूट- कूट कर भरा है। भक्ति साहित्य में इसे 'प्रपत्तिभाव' कहा गया है। इस भाव में साधक स्वयं को परमात्मा पर उसी प्रकार छोड़ देता है, जैसे कोई बालक माँ के भरोसे पर अपने को छोड़ता है। अंग्रेजी कवि की एक प्रसिद्ध पंक्ति है- 'ओ लेडी! वी रिसीव बट वॉट वी गिव।' (भद्रे! हम महज उतना ही पाते हैं, जितना देते हैं।) असाध्य वीणा में लगता है कि अज्ञेय प्रियंवद के माध्यम से सीधे विराट नियति को संबोधित कर रहा है- "नहीं, नहीं! वीणा यह मेरी गोद में रखी है, रहे, किन्तु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद- भरा बालक हूँ, ओ तरु- तात! संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाय : मैं सुनूं, गुनूं, विस्मय से भर आंकूं तेरे अनुभव का एक- एक अन्तःस्वर तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय- गा तू : तेरी लय पर मेरी सांसें भरें, पुरें, रीतें, विश्रांति पायें।" ज्ञान समग्रता का बोध कराता है, परंतु अज्ञानता द्वैत और विश्रृंखलता का। ज्ञानियों को सबकुछ संबद्ध दृष्टिगोचर होता है। प्रियंवद को भी इसी समग्रता का ज्ञान है, तभी वह समर्पण भाव से कहता है- "गा तू! यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग - किन्तु अंगी तू अक्षत, आत्म भरित रस विद, तू गा मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा स्मृति का श्रुति का -" इस कविता में कवि ने प्रियंवद के माध्यम से ज्ञान की सूक्ष्मता का जो वर्णन किया है, वह अनिवर्चनीय है। प्रियंवद को घनी रात में महुए का चुपचाप टपकने से लेकर गड़ेरियों की अनमनी बासुरी और कठफोरे के ठेके तक का ज्ञान है। इसकी कुछ और बानगी देखिए - "मुझे स्मरण है उझक क्षितिज से किरण भोर की पहली जब ताकती है ओस बूंदों को उस क्षण की सहसा चौंकी सिहरन।" सूक्ष्म ज्ञान के बावजूद भी उनमें कोई अहंकार नहीं है। साधक प्रियंवद केशकम्बली ने स्वयं के अहं को विसर्जित कर मौन भाव से स्वयं को समर्पित कर दिया। वह एक अबोध बालक की भांति निश्छल है। वह कहता है - "मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी - मुझे ओट दे, ढ़क दे ओ शरण्य !" आखिरकार असाध्य वीणा बजती है। प्रियंवद उसे साध लेता है। कवि लिखते हैं - "अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू जिसमें सोता है अखंड ब्रह्म का मौन अशेष प्रभामय। डूब गये सब एक साथ सब अलग-अलग एकाकी पार तिरे।" जब असाध्य वीणा से स्वर लहरियाँ फूटती हैं तो वह 'अनहद नाद' की भाँति सबको अलग-अलग सुनाई पड़ता है। जिस प्रकार ब्रह्म की अनुभूति पृथक - पृथक होती है, उसी प्रकार वीणा के स्वर की प्रतीति अलग-अलग हो रही है। ऐसे ही अवसर पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है- 'जाकी रही भावना जैसी। तिन हरि मूरति देखिये तैसी।' वीणा के स्वर में भी पार्थक्य का कारण सभासदों की भावनात्मक भिन्नताएँ हैं। यह स्वर किसी को प्रभु का कृपा वाक्य प्रतीत हुआ, किसी को आतंक से मुक्ति का आश्वासन, किसी को तजोरी में सोने की खनक, किसी को अनाज की खूशबू, किसी को नयी वधू की पायल-ध्वनि, तो किसी को मंदिर की ताल युक्त घण्टा- ध्वनि। असाध्य वीणा के स्वर को सुनकर राजा के मन में निहित ईर्ष्या, द्वेष, महात्वाकांक्षा और चाटुकारिता जैसी दुर्भावनाएँ नष्ट हो जाती हैं। राजमुकुट उसे शिरीष के फूलों- सा हल्का लगने लगता है। रानी ने भी मणि- माणिक, कण्ठहार, पट-वस्त्र, मेखला आदि को अंधकार का कण कहकर उत्सर्ग कर दिया। वीणा के नाद ने उसे जीवन की शाश्वतता का बोध करा दिया। पंक्ति देखिए- "राजमुकुट सहसा हल्का हो आया था मानो वह फूल सिरिस का ईर्ष्या, महात्वाकांक्षा, द्वेष, चाटुता सभी पुराने लुगदे से झर गये, निखर आया था जीवन - कांचन। तुम्हारे ये मणि-माणिक, कण्ठहार, पट- वस्त्र मेखला- किंकिणि सब अंधकार के कण हैं, ये आलोक एक है।" इस कविता में सच्चा साधक प्रियंवद केशकम्बली अहंकार का विस्मरण कर चुका है। वह वीणा को इसीलिए साध पाता है, चूँकि वह स्वयं को सौंप देता है। उनमें प्रपत्तिभाव कूट-कूट कर भरा है। इसीलिए वीणा बजाने के बाद भी वह इसका श्रेय नहीं लेना चाहता। उनमें 'तथता' का भाव है। इस शब्द का प्रयोग बौद्ध- दर्शन में किया गया है। तथता वस्तुतः स्वयं को भीतर की ओर मोड़ना है। वह अहंकार शून्य- भाव से कहता है - -"श्रेय नहीं कुछ मेरा : मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में - वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था - सुना आपने जो वह मेरा नहीं, न वीणा का था : वह तो सब कुछ मेरी 'तथता' थी महाशून्य वह महामौन अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय जो शब्दहीन सब में गाता है।" असाध्य वीणा में सृष्टि की अखंडता की अभिव्यक्ति है। सद्ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पार्थक्यता का भाव स्वतः मिट जाता है। प्रियंवद एकांत साधक है। वह अपनी सत्ता को परम सत्ता में मिला देता है। वह वीणा के साथ एकमेक हो जाता है। उसका यह भान भी मिट जाता है कि वीणा उसकी गोद में है या वह स्वयं वीणा की गोद में। वह वीणा को साध रहा है या वीणा स्वयं उसे साध रही है। सच में यह अज्ञेय की संपूर्ण काव्य-साधना की परिणति है, जिसमें कला को अंतःप्रज्ञा के साथ जोड़ने की चेष्टा की गई है। यह कविता बाहरी कोलाहल से परे कला -साधक को अपने भीतर की ओर मोड़ने की प्रेरणा देती है। यह कविता अहं के विस्मरण का संदेश देती है। यह कविता मानव के अंतस में सुषुप्त परम चेतना को उद्बुद्ध करती है।

दस्तक प्रभात
डॉ. उमेश कुमार शर्मा

कहानी

कोरोना, कोरेंटाईन, और ससुराल

... आठवीं क्लास में हिंदी वाले सर जिस क्लास में जाते एक ही निबंध 'समय रहत न एक समान' अपनी डायरी खोलकर जरूर लिखवाते.. सीनियर स्टुडेंट्स का एकमत कहना था कि 'हिंदी सर 'को उनके विद्वान शिक्षक विश्वनाथ मिश्र 'आनंद' जी ने उनके छात्र जीवन में जो कुछ लिखवाया था.. उसी को 'हिंदी सर' डायरी में लिखे रहते हैं और अपने हर क्लास में यही निबंध लिखवाते हैं..मानो ऐसा कर अपने गुरु को श्रद्धांजलि देते हैं.. खैर उनका निबंध शुरू होता अंग्रेजी के एक कहावत से... ..."Misfortune never comes alone " या फिर बीच में कहीं... Man proposess and God disposess. " जरुर होता... मैं क्या जानता था कि यह बात झूठी नहीं होगी...! ... मोदीजी को जो करना था.. लाकडाऊन.. सो वे कर दिए.. एकबार से दिल न भरा तो चार-पांच बार कर दिए.. मेरी शादी पिछले ही साल हुई थी.. अभी इंटर की परीक्षा दिया था और अगुआ को मैं जंच गया.. परिणाम सुंदर रहा... मतलब इंटर के परीक्षाफल निकलने के पहले ही विवाह का फल मिला... सुंदर सी गोरी सी पत्नी... घर में सबको लड़की का फोटो दिखाया जा रहा था.. तो मुझे भी चोरी से देखने का सुअवसर मिल ही गया.. आह! बिल्कुल शमीर्ला टैगोर.. बाबूजी की प्रिय हिरोइन.. टीवी पर जब पुरानी फिल्में आतीं.. और उसमें शमीर्ला टैगोर की फिल्म हो तो फिर कहना ही क्या..? सब काम धाम छोड़कर टीवी से चिपक जाते., 'आराधना' फिल्म की तो गिनती ही नहीं कितनी बार देखे.. 'आराधना' फिल्म का इतना प्रभाव पड़ा कि बचपन से मेरे सपने में शमीर्ला टैगोर ताक झांक शुरू कर दी.. बाबूजी व्यवहार में 'मुगलेआजम' के 'जहांपनाह' थे ...पर फिल्म के कारण घर की हर स्त्री वर्ग अपने को' शमीर्ला टैगोर 'और हर पुरुष वर्ग अपने को 'राजेश खन्ना' ही समझता... भले ही मेरे पूरे खानदान को देखकर कौआ भी शरम से मेरे घर के मुंड़ेर को कभी पवित्र नहीं किया.. ऐसे वातावरण में लड़की के नाक नक्स रंग रुप का शमीर्ला टैगोर से हू ब हू मिलना.. ऐसा गजब ढाया कि बाबूजी भारतीय संविधान की खुले आम धज्जी उड़ाने को अड़ गए.. भावार्थ यह कि मेरा सर्टिफिकेट से उम्र 18 भी पूरा नहीं हुआ था.. लेकिन बाबूजी तो 1960-70 मोडल थे.. कानून की परवाह कम ही करते... सो शमीर्ला टैगोर को दुल्हन के रूप में अपने आंगन में लाने को बेताब दिखे.. शादी तो काफी धूमधाम से पिछले साल हो गई.. पर ससुराल वालों का अजीब रिवाज... .. "लड़की को हमलोग शादी में विदा नहीं करते.. एक साल बाद गंवना या 'रोकसदी ' करते हैं.. उसी में लड़की की बिदाई और पलंग, तोसक, आदि सारा सामान देकर विदा करते हैं.. " गुस्सा तो मुझे बहुत आया पर मामा, फूफा, मौसा, चाचा, बाबूजी के सामने क्या बोलता? वैसे विदाई के समय दो घंटे तक बाराती और शराती में वाक युद्ध होता रहा .., लड़की की बिदाई हो या न हो.. कई बार तो लगा कि दोनों तरफ की 'भोथरी' तलवारें म्यान से अपनी सारी मयार्दायें तोड़ निकल ही पड़ेंगी.. पर गाँव की 'देबी मईया' के एकबाल से आल्हा -उदल का महोबा बनने से बच गया मेरा ससुराल...!....... गाँव में बिन दुल्हन के बारात क्या लौटी...!.. लगा कि कोई मुर्दा जलाकर लौटे हैं सारे लोग... सालभर गाँव वालों को मेरे घर का मजाक उड़ाने का लाइसेंस मिल गया था.... यह तो भला हो 4 ॠ मोबाईल और मुकेश अंबानी के Geo सिम का.. कि पूरा परिवार.. जिसको जब मौका मिलता है घर की बहू 'शमीर्ला टैगोर' से बारी बारी से विडियो काल पर बात होती ही रहती है.... मां, बाबूजी . हाँ 'दुल्हिन... हाँ दुल्हिन 'रटते अघाते नहीं... छोटकी बहिनियां निशवा' और छोटका भईवा 'रमेशवा' तो 'हाँ भाभी जी, हाँ भाभी जी' में इतना व्यस्त हो जाते कि किसी को लाज, शरम का ख्याल ही नहीं रहता कि इस घर के 'चकोर' और 'चकोरी शमीर्ला टैगोर' का आपस में बातचीत करने का भी कोई हक बनता है... .... बाबूजी पंडित जी को बुलाकर पत्रा दिखाए कि दुल्हिन का गंवना का मुहूर्त कब बनता है?.. तो पंडित जी ने कहा "" 30 मई के बाद शुक्रस्त हो जाएगा. इसके पहले गंवना करवा लीजिए.. नहीं तो अगले एक साल के लिए फिर फंस जाइएगा...... गंवना दिन से श्वसुर जी और पिताजी के रविवार, मंगलवार, गुरुवार मान दिन और नक्षत्र, तिथि के गठजोड़ में ऐसा उलझा कि आठ, बार पंडित जी बुलाए गए... ... गंवना का दिन निश्चित हुआ कि नहीं.. लेकिन मोदी जी बड़े दुलार से लाकडाऊन 1:0 घोषित कर दिए.... न गाड़ी.. न घोड़ा.न टेम्पू... यहाँ तक कि मोटरसाइकिल पर किसी नवयुवक को लफुआ समझ पुलिस वाले खदेड़ खदेड़ कर अपनी ड्यूटी की कुंठा निकाल रहे थे.... इसी बीच एक और दुर्घटना घट गई थी.... (हांलाकि यह गुप्त बात अपने जिगरी दोस्त से भी छिपाए रखा) .... घर के लोग 'शमीर्ला टैगोर' को मुझसे बात करने का मौका ही नहीं देते.. तब एक दिन शाम को खेत की मेड़ पर अकेले बैठा दो साल छोटी साली को विडियो काल लगा दिया... पहले तो ऊपर-ऊपर, हल्का -फुल्का मजाक के बाद कब विषय वस्तु कसमें वादे.. जीने मरने.. लैला मजनूं, शिरी फरहाद की जीवन गाथा जो उभरी.. तीन घंटे अंधेरे खेत में सांप-बिच्छू का भय भूलकर जो डंटे रह गए कि अब रात -रातभर साली साहिबा 'रिम्पी' से जो चैटिंग होती रही...उसमें कब शमीर्ला टैगोर का ख्याल भूल गया.. पता ही नहीं चला... ... नशा इतना चढ़ा कि साईकिल से रामपुर, गया से 160 किलोमीटर प्रातः चार बजे से चलकर रात 9 बजे रोहतास के गाँव ससुराल में पहुंचा..(गाँव का नाम नहीं बताऊंगा) .. .. जैसे ही साईकिल से थकान का मारा पहुंचा कि नहीं...कि सारे गाँव मे शोर मचा गया....कि . रिंकी(शमीर्ला टैगोर) के पहुना आए हैं.. . "मुखिया, सरपंच ग्रामीण सब अवाक.!....... पाहुन गया से 160 किलोमीटर साईकिल से आए हैं.. !...... बाप रे बाप!.... ई तो दूसरा तुलसीदास हो गए.. !..... " .... मुखिया जी ने कहा- "" पाहुन! पता नहीं आप किस किस से मिले होंगे... हमलोग गाँव में कोरोना के भय से घुसने नहीं देंगे...आप लौट जाईये..नहीं तो गाँव के कोरेंटाईन स्थल स्कूल में 14 दिन रहिए" ससुराल में एतना अपमान.... लेकिन साली साहिबा 'रिम्पी' के प्रेम के नशे में यह जहर भी पी लिया.... एक बार भी 'दीदार' हो जाए... .. आ गए ससुराल के कोरेंटाईन में.. पर आठवें दिन मेरा पोलीटिक्स रिपोर्ट क्या आया कि भेज दिया गया टटउल्र, पटना में..... यहाँ तीन बार के रिपोर्ट में नैगेटिव रिपोर्ट आया तो जान में जान आई... लेकिन ससुराल के कोरेंटाईन में शाम को खिड़की के उसपार से खाना देने आती 'रिम्पी' की डबडबाई आंखों की भाषा अपने मोबाईल के इनबाक्स में बार बार पढ़ता हूँ.. "मै हूँ कितना पास तुम्हारे, फिर भी कितनी दूरे एक नदी के दो किनारे, मिलने से मजबूरे" .. अब याद आ रहा है हिंदी सर का कोटेशन... "मैन प्रोपोजेज, गोड डिस्पोजैज " या "मिस्फोरचुन नेवर कम्स अलोन"

दस्तक प्रभात
अवध किशोर मिश्र

कविता

बदल गया है जमाना

आज कितना बदल
गया है जमाना,
अपने ही बच्चों को
मुश्किल है समझाना।
जिसकी किलकारी से था
सांसों का आना जाना,
आज वही समझ बैठा
है हमें अब बेगाना।
सुख से भर देता था
जिसका बाहों में आ समाना,
जिसे पाकर लगा था पाया
मैंने खुशियों का खजाना।
हर पल की चाहत थी
बस उसे ही संवारना सजाना,
भूल कर सारे गम सीखा
था हमने उससे ही मुस्कराना।
परख लेते थे भाषा उसकी
और उसका वो तुतलाना,
वही बच्चे अब सीख
गए हैं हमें आजमाना।
दामन को थामे उसका
सीने में छुप जाना,
अब चाहत है उसकी घर
के बाहर दिल बहलाना।
अपने हठ मनवा कर
हाय अब उसका इतराना,
वह क्या जाने दर्द देता है
उसका अब सपनों को बिखरना।
उंगली थाम कर सिखाया था
जिन्हें एक दिन हमने चलना,
सीख गया है मुँह मोड़ना
और ठोकर हमें लगाना।
मुश्किल था अपने ही कदमों
पर जिसका कभी खड़ा रह पाना,
वही सोचता है आज
उनके कदमों में है जमाना।
हर सीख को उपदेश समझ
कर उसकी हँसी उड़ाना,
जाने कहां से सीख गया है
जवाब देना वह मुँह लगाना।
कभी आनंद से भर देता था
जिनका रूठना मनाना,
तोड़कर दिल को वही सीख
गया है कहकहे लगाना।
अभी कल तक तो उसका हर
बंदिश पर सर झुकाना,
अब छोटी सी बात पर उसका
आसमान सिर पर उठाना।
लाख कहें अब मेरी एक
बात न मानना
भरना पड़ता है मुझे उसकी
हर गलती का जुमार्ना।
कमी कहाँ थी जो उसने मेरे
प्यार को नहीं पहचाना,
जीने की ख्वाहिश रही नहीं
दिल चाहता है मर जाना।
बड़ा कठिन है हँसकर अपने
आँसू को अब छुपाना,
बहुत मुश्किल है बच्चों से
अपनी आबरू को बचाना।
आज कितना बदल गया
है जमाना।

दस्तक प्रभात/वेदना

https://t.me/AllNewsPaperPaid

देशप्राण
स्वतंत्र हिन्दी दैनिक

मतदाताओं ने नेताओं को चौंकाया

एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद आए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जरूर कई लोगों को चौंकाया होगा। नतीजों ने बताया कि राजनीतिक पंडित कितने भी गुणा-गणित और विश्लेषण कर लें, कई बार वे जनता का मूड भांपने में गलती कर जाते हैं। इनमें भी सबसे अधिक हैरान किया 80 सीटों वाले यूपी ने। 2014 और 2019 में भाजपा को केंद्र की सत्ता तक पहुंचने में इस राज्य ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इस बार यहां भाजपा और इंडी गठबंधन में करीब-करीब बराबरी का मुकाबला दिखा, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी।बिहार, कर्नाटक और बंगाल में भी भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। इनमें से बिहार और कर्नाटक में पार्टी ने पिछले चुनावों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। इन चुनावों में कई रीजनल पार्टियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसी तरह एनडीए के घटक दलों को भी नई ऑक्सीजन मिली है। उनकी तालमेल की क्षमता बढ़ गई है। एग्जिट पोल्स में अकेले भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाया गया था। अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास के इकलौते राजनेता बन जाते, जिनके नेतृत्व में हर जीत पहले से बड़ी होती गई। लेकिन, चुनाव परिणाम एकतरफा नहीं रहा। एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों के पास जश्न मनाने के लिए कुछ न कुछ है। सीटों के लिहाज से भाजपा को भले ही नुकसान हुआ, लेकिन लगातार तीसरी बार वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ओडिशा और तेलंगाना में पार्टी ने प्रदर्शन से सबको सरप्राइज किया। ओडिशा में लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में भी पार्टी ने बीजू जनता दल का 24 साल से चला आ रहा वर्चस्व तोड़ा। वहीं, गुजरात और मध्य प्रदेश भाजपा के गढ़ बने हुए हैं, जबकि देश की सियासत में अब भी ब्रैंड मोदी सबसे बड़ा है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास इतनी भी सीटें नहीं थीं कि वह सदन में विपक्ष का आधिकारिक दर्जा हासिल कर सके। लेकिन, कांग्रेस ने वापसी कर जाहिर कर दिया कि देश में भाजपा को टक्कर देनी है तो उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इस चुनाव में कांग्रेस ने कई जगह गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका निभाई। लेकिन, इंडी गठबंधन को जितनी सीटें मिलीं, उससे पार्टी का कद जरूर बढ़ेगा। शरद पवार का राजनीतिक वारिस कौन और असली शिवसेना किसकी? क्या माया और ममता अब भी ताकतवर हैं? यह चुनाव ऐसे ही कई सवालों के साथ शुरू हुआ था। इनमें से कुछ के जवाब मिल गए हैं और कुछ के बाकी हैं। जिस तरह के नतीजे आए हैं, उससे यह संदेह भी पैदा हुआ है कि क्या देश में आर्थिक सुधार जारी रहेंगे? नीतिगत स्थिरता का क्या होगा? शायद इसी संदेह की वजह से शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। आशा है कि इन सवालों का जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा, लेकिन नतीजों से यह भी तय है कि देश की राजनीति ने एक करवट ले ली है।

शेखचिल्ली वाले मंसूबे राहुल के !

के. विक्रम राव

लोकसभा की 543 सीटों में 272 चाहिए बहुमत हेतु। कांग्रेस की 99 सीटें हैं, अर्थात 173 कम। उनके इंडी गठबंधन के पास 235 हैं, 37 कम। फिर भी कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा ठोकने का ऐलान कर दिया। उधर भाजपा अपने 240 सांसदों और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के करीब 290 हैं। बहुमत से अधिक। सीधा गणित है कि राष्ट्रपति किसका दावा मानें ? पर राहुल हैं कि पिले पड़े हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए।

आगे बढ़ें। घटना 1999 वाली याद करें।

एक तत्व पर और गौर करें। कांग्रेस के कभी गढ़ रहे क्षेत्र राजधानी दिल्ली, कश्मीर, आंध्र-प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, त्रिपुरा, सिक्किम आदि में कांग्रेस का नामलेवा कोई नहीं मिला। सूपड़ा साफ हो गया। जहां कांग्रेस का राज रहा गत वर्षों तक वहां क्या दशा थी ? मसलन यूपी के 80 में से मात्र छः मिले। हिमाचल में पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री के पुत्र को एक फिल्मी भाजपाई अभिनेत्री (कंगना राणावत) ने मंडी से पराजित कर दिया। राजस्थान में 10 साल से पेशेवर जादूगर अशोक गहलोत सीएम रहे। उनके 25 में से केवल 8 जीते। असम में 14 में केवल तीन कांग्रेसी जीत पाये। भारत सरकार बनाने का दावा करने वाले राहुल की पार्टी एक चौथाई लोकसभाई क्षेत्र में ही सिकुड़ गई। ताड़ के पेड़ पर चढ़ने चले थे। खजूर पर अटक गए। पश्चिम बंगाल में 42 में से कांग्रेस सिर्फ एक ही जीत पाई। मगर यहां के बरहरामपुर लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा में नेता कांग्रेस विपक्ष के बड़बोले अधीर रंजन चौधरी को ममता बनर्जी ने गच्चा दे दिया। सुदूर बड़ौदा से क्रिकेटर यूसुफ पठान को बंगाल आयात कर ममता ने अधीर बाबू के सामने खड़ा कर दिया। कांग्रेस नेता पराजित हो गए। जब कि इंडिया गठजोड़ के ही दोनों ही साथ हैं। केरल में ही इंडिया के खास अंग है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भाकपा। दोनों राहुल गांधी से मिन्नतें करते रह गए।

उनकी अम्मा सोनिया गांधी ने भी सरकार बनाने के दावे के साथ प्रतिबद्ध राष्ट्रपति दलित के.आर. नारायण को लंबी समर्थकों की सूची भेजी थी। प्रधानमंत्री की शपथ की तैयारी हो गई थी। रोम से राहुल की नानी और अन्य कुनबा 10 जनपथ आ पहुंचे थे। तभी अखिलेश यादव के स्वर्गीय पिता श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने दल का समर्थन देने से इंकार कर दिया। सोनिया का सत्ता वाला सपना चूर-चूर हो गया। फिर भी राहुल को वह हादसा याद नहीं रहा। क्या विद्रूप है कि आज उन्हीं लोहियावादी का बेटा सोनिया पुत्र के साथ हैं।

एक तत्व पर और गौर करें। कांग्रेस के कभी गढ़ रहे क्षेत्र राजधानी दिल्ली, कश्मीर, आंध्र-प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, त्रिपुरा, सिक्किम आदि में कांग्रेस का नामलेवा कोई नहीं मिला। सूपड़ा साफ हो गया। जहां कांग्रेस का राज रहा गत वर्षों तक वहां क्या दशा थी ? मसलन यूपी के 80 में से मात्र छः मिले। हिमाचल में पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री के पुत्र को एक फिल्मी भाजपाई अभिनेत्री (कंगना राणावत) ने मंडी से पराजित कर दिया। राजस्थान में 10 साल से पेशेवर जादूगर अशोक गहलोत सीएम रहे। उनके 25 में से केवल 8 जीते। असम में 14 में केवल तीन कांग्रेसी जीत पाये। भारत सरकार बनाने का दावा करने वाले राहुल की पार्टी एक चौथाई लोकसभाई क्षेत्र में ही सिकुड़ गई। ताड़ के पेड़ पर चढ़ने चले थे। खजूर पर अटक गए। पश्चिम बंगाल में 42 में से कांग्रेस सिर्फ एक ही जीत पाई। मगर यहां के बरहरामपुर लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा में नेता कांग्रेस विपक्ष के बड़बोले अधीर रंजन चौधरी को ममता बनर्जी ने गच्चा दे दिया। सुदूर बड़ौदा से क्रिकेटर यूसुफ पठान को बंगाल आयात कर ममता ने अधीर बाबू के सामने खड़ा कर दिया। कांग्रेस नेता पराजित हो गए। जब कि इंडिया गठजोड़ के ही दोनों ही साथ हैं। केरल में ही इंडिया के खास अंग है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भाकपा। दोनों राहुल गांधी से मिन्नतें करते रह गए। गठबंधन धर्म का पालन करें और भाकपा राष्ट्रीय सचिव डी. राजा की पत्नी डी. राजा के विरोध में प्रत्याशी न बनें। रायबरेली में ही रहें। राहुल ने गठबंधन के साथी भाकपा की महिला को हरा दिया। इंडिया के दोनों घटक टकरा गए। ऐसा गठबंधन ?

पार्टी मुखिया, दलित नेता 81-वर्षीय मापन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र रत्न राधा कृष्ण दोड्डमणि खुद कांग्रेस-शासित कर्नाटक में सत्ताईस हजार वोटो से पराजित हो गए। सरकार बनाने को उतावले कांग्रेस प्रमुख अपने लकतेजिगर को संसद नहीं पहुंचा पाए। बड़बोले शशि थरूर (जो खड़गे के विरोध में पार्टी मुखिया का चुनाव लड़े थे) सागरतटीय तिरुअनंतपुरम से मात्र पंद्रह हजार वोटो से सिसकते हुए जीते। कांग्रेस के दबंग सचिव और सोनिया-राहुल के संग हर फोटो में नजर आने वाले के.सी. वेणुगोपाल ने इंडिया गठबंधन के घटक माकपा के एम.थम. आरिफ को केरल में शिकस्त दी। दो हम गठबंधन वाले हैं।

बात हो उड़ीसा की। यहां डेढ़ दशक से बीजू पटनायक के पुत्र नवीन मुख्यमंत्री बने रहे। आज वहां भाजपा की राज्य सरकार बन गई। हां, अयोध्या में भाजपा की हार बड़ी शोचनीय रही। मुहावरी भाषा में यह हादसा चिराग तले अंधेरा सरीखा हो गया। देश में रामलला के नाम पर वोट पड़े। पर जन्म स्थान अयोध्या में रामजी की कृपा से भाजपा वंचित रही। लल्लू सिंह ने नाम को सार्थक साबित कर दिया। लल्लू निकले। मगर भाजपा को संतोष मिलेगा कि बालाजी (तिरुपति) और जगन्नाथ (पुरी) की उस पर अनुकम्पा रही। ओम नमो नारायण के नाम पर दोनों राज्यों से कांग्रेस बुरी तरह हार गई। भाजपा ने भुवनेश्वर में भी सरकार बना दी। भगवान विष्णु ने शायद कृपा आधी ही दिखाई थी। शायद अर्चना में तनिक कमी रह गई हो।

अब उल्लेख हो परिवर्तनशील अर्थात श्रीमान पलटू कुमार का। राहुल की बचकानी सोच है कि केवल बारह लोकसभा सांसद वाले नीतीश मोदी के रथ का चक्का जाम कर सकते हैं। तुर्रा यह कि केवल दो लोकसभा (बेटी सुप्रिया को मिलाकर) पार्टी के पुराने दलबदलू शरदचंद्र गोविंदराव पवार ने नीतीश और नायडू से संपर्क साधा था। कांग्रेस के जाने-माने पलटू पवार ने इंदिरा गांधी की हार के बाद कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर महाराष्ट्र में जनता पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री बने थे। चल नहीं पाए। पुरानी आदत छूटती नहीं है। मगर वक्त बदलता है।

यदि मान भी लें कि नायडू और नीतीश प्रधानमंत्री पद की लालच में राहुल के बहलाने-फुसलाने में आ भी जायें, तो सभी को याद रहे कैसे राहुल के पिता ने बलिया के ठाकुर चंद्रशेखर सिंह को प्रधानमंत्री बनवाकर चंद सप्ताह में बेदखल कर दिया था। दादी इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनवा कर, तख्त पर चढ़ा दिया। पानी भी नहीं पी पाये बेचारे चौधरी साहब। राहुल की हरकत बाप-दादी की परंपरा से जुदा नहीं है। पर अब पात्र सावधान हो गए हैं। भूल बार बार नहीं होती।

https://t.me/Newspaperpdf

भारत के चुनाव परिणाम से दुनिया भी हैरान है

नीरज कुमार दुबे

भारत की राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दशक काफी बड़े और कड़े फैसलों वाला रहा और उनके निर्णयों और नेतृत्व की धमक देश में ही नहीं पूरी दुनिया में रही जिसके चलते वह समूचे विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में उभरे। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम उनके लिए आश्चर्य लेकर आये जब उनकी पार्टी भाजपा ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया और सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों पर निर्भर हो गयी। इन चुनाव परिणामों ने मोदी की अजेय रहने वाले नेता की छवि पर बहुत बड़ा असर डाला है जिसकी गूंज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे रही है। देखा जाये तो भारत में तो विपक्ष मोदी को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाहता ही था साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई ऐसी शक्तियां थीं जोकि मोदी की ग्लोबल लीडर के रूप में पुख्ता होती छवि को नुकसान पहुंचाना चाहती थीं। कह सकते हैं कि भारत में विपक्ष को और विदेशों में भारत विरोधी शक्तियों को कहीं ना कहीं अपने मिशन में थोड़ी-बहुत कामयाबी मिल गयी है। लेकिन यह भी सत्य और एक तथ्य है कि मोदी की कार्यशैली मक्खन पर नहीं अपितु पत्थर पर लकीर खींचने की है इसलिए वह तीसरे कार्यकाल में अपने कामकाज से विरोधियों को तगड़ा जवाब अवश्य ही देंगे।

चुनाव परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि 'अबकी बार 400 पार' के नारे की ही नहीं बल्कि 'मोदी है तो मुमकिन है' और 'जो राम को लाये हैं हम उनको लाएंगे' जैसे नारों की भी हवा पूरी तरह निकल गयी है। चुनाव प्रचार की बात हो या भाजपा के संकल्प पत्र में किये गये वादों की, सब कुछ 'मोदी की गारंटी' के ही इर्द गिर्द केंद्रित था इसलिए कहा जा सकता है कि मोदी ब्रांड की छवि पर सीधा असर पड़ा है। इसलिए अब समय आ गया है जब भाजपा को सिर्फ मोदी नाम के सहारे रहने की बजाय और भी पहलुओं पर काम करना पड़ेगा। जबसे मोदी केंद्र की राजनीति में आये हैं तबसे यही देखने को मिलता है कि पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव पर भाजपा सिर्फ मोदी नाम के सहारे ही रहती है। भाजपा ने चुनाव में 'मोदी की गारंटी' के अलावा 'विकास भी और विरासत भी' का नारा दिया था और करोड़ों लोगों के गरीबी रेखा से बाहर निकलने तथा भारत के सांस्कृतिक गौरव की बहाली की दिशा में उठाए गये कदमों का हवाला दिया था फिर भी वह स्पष्ट बहुमत से बहुत दूर रह गयी।

दूसरी ओर, भाजपा की सीट घटने से सिर्फ पार्टी के ही नेता हैरान और परेशान नहीं हैं बल्कि कई विदेशी नेता भी इस बात से हैरान हैं कि दिन-रात अपने देश के लिए काम करते रहने वाले प्रधानमंत्री को चुनावों में जनता ने क्यों सजा दे दी है। आप दुनिया भर की समाचार वेबसाइटों को देखेंगे तो सभी ने मोदी की सीटें घटने पर हैरानी जताई है। इन चुनाव परिणामों ने मोदी के विदेशों में रुतबे को निश्चित रूप से प्रभावित किया है। दरअसल, जिस तरह का माहौल बनाया गया था उसमें ना तो देश में और ना ही दुनिया में किसी को इस तरह के चुनाव परिणामों की अपेक्षा थी। यही कारण है कि भाजपा तो अपने चुनावी प्रदर्शन पर मंथन कर ही रही है दुनिया के भी कई बड़े नेता भारत के चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इसके कारणों की समीक्षा कर रहे हैं।

हम आपको यह भी बता दें कि साल 2024 में दुनिया के अधिकांश देशों में चुनाव होने हैं। कई छोटे-बड़े देशों में जून महीने की शुरूआत तक चुनाव हो चुके हैं और अमेरिका सहित कई अन्य देशों में चुनाव इस साल के अंत से पहले होने हैं। एक खास बात यह है कि अब तक जितने देशों में चुनाव हुए हैं उनमें से ज्यादातर में सरकारें वापस सत्ता में नहीं लौटी हैं लेकिन मोदी दस साल राज करने के बाद भी तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लौट आये हैं। भले उनकी सीटों की संख्या कम हो गयी है लेकिन काम करने के लिए उनके पास स्पष्ट जनादेश है। मोदी ने जब 2014 में भारत सरकार की कमान संभाली थी तबसे दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष बदल चुके हैं लेकिन मोदी सत्ता में कायम हैं जिसका सीधा मतलब यही है कि जनता को उनके नेतृत्व और उनकी नीतियों में विश्वास है। यह विश्वास ही तो है कि विपक्ष के घोषणापत्र में की गयी फ्री की तमाम सौगातों की बजाय जनता ने मोदी के वादों को तवज्जो दी है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक की बात करें तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हार-जीत राजनीति का हिस्सा है और नंबर गेम चलता रहता है। उन्होंने कहा है कि लेकिन इस सबका असर देश के विकास पर नहीं पड़ना चाहिए। वैसे देखा जाये तो लोकतंत्र में नंबर गेम ही मायने रखता है लेकिन मोदी के लिए इसका खास महत्व नहीं है। इस बात को हम गुजरात के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा ने 2002 में 127 सीटों पर जीत हासिल की थी उसके बाद पार्टी अगले चुनाव में 117 सीटों पर और उसके बाद 116 सीटों पर पहुँच गयी थी। यही नहीं, मोदी के दिल्ली आने के बाद गुजरात में जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भाजपा 99 सीटों पर आ गयी थी लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने गुजरात में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये थे। नंबर गेम ऊपर नीचे होता रहा लेकिन मोदी ने गुजरात के विकास को जरा भी प्रभावित नहीं होने दिया। बहरहाल, देखा जाये तो लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले तक माना जाता था कि देश में मोदी के बराबर का कोई नेता नहीं है लेकिन विपक्ष के तमाम नेताओं को जनता ने जो ताकत दी है उससे मोदी के आसपास अब कई नेता खड़े हो गये हैं।

नई संसद में जो दलीय स्थिति बनी है और स्पष्ट बहुमत की बजाय गठबंधन सरकार की जो नौबत आई है उसको देखते हुए मोदी की चुनौतियां तो बढ़ गयी हैं लेकिन मोदी चुनौतियों को चुनौती देकर मंजिल पर समय से पहले पहुँचने वाले नेता हैं यह बात सबको याद रखनी चाहिए।

हम आपको यह भी बता दें कि साल 2024 में दुनिया के अधिकांश देशों में चुनाव होने हैं। कई छोटे-बड़े देशों में जून महीने की शुरूआत तक चुनाव हो चुके हैं और अमेरिका सहित कई अन्य देशों में चुनाव इस साल के अंत से पहले होने हैं। एक खास बात यह है कि अब तक जितने देशों में चुनाव हुए हैं उनमें से ज्यादातर में सरकारें वापस सत्ता में नहीं लौटी हैं लेकिन मोदी दस साल राज करने के बाद भी तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लौट आये हैं। भले उनकी सीटों की संख्या कम हो गयी है लेकिन काम करने के लिए उनके पास स्पष्ट जनादेश है। मोदी ने जब 2014 में भारत सरकार की कमान संभाली थी तबसे दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष बदल चुके हैं लेकिन मोदी सत्ता में कायम हैं जसका सीधा मतलब यही है कि जनता को उनके नेतृत्व और उनकी नीतियों में विश्वास है। यह विश्वास ही तो है कि विपक्ष के घोषणापत्र में की गयी फ्री की तमाम सौगातों की बजाय जनता ने मोदी के वादों को तवज्जो दी है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक की बात करें तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हार-जीत राजनीति का हिस्सा है और नंबर गेम चलता रहता है।

संपादकीय

लोकतंत्र की जय...

इस आम चुनाव के दौरान पक्ष और विपक्ष के गठबंधनों में जैसी गहमागहमी, जिस तरह के आरोप-प्रत्यारोप देखे गए, विपक्षी पार्टियों ने निर्वाचन आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैए के आरोप लगाए और मशीनों में मतों की गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की गई, नतीजों ने उन सबको धुल-पोंछ दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से स्पष्ट है कि जनता ने अपने विवेक से प्रतिनिधियों का चुनाव किया है। उन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय, मुफ्त की योजनाओं आदि के बहकावे में न आकर एक ऐसी सरकार के पक्ष में मतदान किया, जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने, देश की असल समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करे।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्तापक्ष के विरोध में कोई स्पष्ट लहर नहीं थी, मगर यह संकेत लगातार मिल रहा था कि जनता बदलाव चाहती है। विपक्षी दलों के गठबंधन ने जरूर महंगाई और बेरोजगारी जैसे कुछ बुनियादी मुद्दे उठाए थे, मगर सत्तापक्ष ने उन्हें किनारे करने की हर संभव कोशिश की। वह लगातार भावनात्मक मसले उठाता रहा। पर लोगों ने चुप रह कर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उत्तर प्रदेश के नतीजे हैं। वहां अयोध्या में राममंदिर निर्माण को सत्तापक्ष अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करता रहा, मगर वहां के लोगों ने उसे नकार दिया। यहां तक कि अयोध्या के भाजपा प्रत्याशी को भी अपना समर्थन नहीं दिया।

चुनावों में हर राजनीतिक दल अपना गणित बिठाने की कोशिश करता है, जाति और धर्म का समीकरण इसमें बहुत मायने रखता है, पर इस बार वह समीकरण भी बहुत कारगर साबित नहीं हुआ। बेशक भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, मगर जनादेश उसके खिलाफ ही कहा जा सकता है। वह अपने बल पर पूर्ण बहुमत की संख्या नहीं जुटा सकी। जबकि इस चुनाव में भाजपा ही सबसे साधन संपन्न पार्टी थी। उसने चुनाव पर जितना खर्च किया, उतना सारे दलों ने मिल कर भी शायद न किया हो।

प्रचार-प्रसार में दूसरे दल उसके सामने फीके पड़ गए थे। संचार माध्यमों पर हर जगह उसकी मौजूदगी नजर आती थी। फिर भी अपने दम पर तीन सौ सत्तर और गठबंधन के स्तर पर चार सौ से पार सीटें जीतने का जो लक्ष्य लेकर वह चली थी, उसके आसपास पहुंचना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। इस चुनाव में एक बार फिर क्षेत्रीय दल मजबूत होकर उभरे हैं। इससे भी साबित होता है कि लोगों के लिए निजी समस्याएं और स्थानीय मसले ज्यादा अहम थे।

चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल अपनी सफलता या विफलता की समीक्षा करता और उससे आगे के चुनावों के लिए सबक लेता है। वह सब होगा, पर महत्त्वपूर्ण यह है कि जनादेश को समझा जाए। यह केवल सीटों के बंटवारे में जाति-धर्म का समीकरण बिठाने और गठबंधन में पार्टियों के मतों के परस्पर जुड़ जाने का नतीजा भर नहीं है। इसमें सत्तापक्ष के प्रति लोगों की निराशा और उदासीनता भी ध्वनित होती है। मुफ्त के राशन और कुछ अन्य सुविधाएं लोगों में जीवन की बेहतरी का भरोसा नहीं जगा पाई। इससे यह स्पष्ट हो गया कि सत्तापक्ष जिन सुविधाओं और आर्थिक तरक्की को अपनी उपलब्धियां बताता रहा, उन पर लोगों का विश्वास नहीं बन पाया। इसलिए अब जो भी सत्ता की बागडोर संभालेगा, उससे यही अपेक्षा रहेगी कि वह इस जनादेश के निहितार्थों को समझते हुए ही नीतियों और योजनाओं का निर्धारण करे।

गुरु वाणी

(१)यह सुन्दर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलिन रहते हुए जीते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यन्त भूल में हैं ।

(२)शरीरों के इस कारागार से छूटने का यत्न सीखो और छूटो । सन्तों का उपदेश इसी कारागार से छूटने का हैं । (३)परम भक्त योगीजन भगवत भजन के तार को कभी टूटने नहीं देते चाहे वे जाग्रत वा स्वपन में किसी आवश्यक तथा स्वभाविक काम करते हों, फिर भी सार शब्द की अभंग धार को पकड़े रहते हैं ।

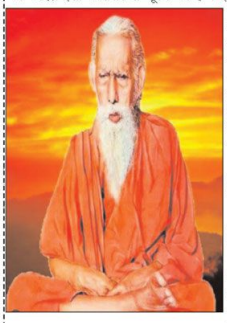

(४)जैसे कोई कुएँ में गिर पड़ा है तो वह ऊपर चला आयेगा । उसी तरह शब्द की डोर पकड़ कर ईश्वर तक जाना होता है ।

(५)जो ज्योति और शब्द को पकड़ता है, वह महान्‍ पुरूष हो जाता है। रिद्धि - सिद्धि सब आ जाती है और वह ईश्वर को पाता है ।

(६)ब्रह्म के दो स्वरूप हैं निर्गुण और सगुण। सत्संग करके दोनों स्वरूप की प्राप्ति का भेद जानना चाहिए । केवल सगुण रूप से ही करके उसी में सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए ।

(७)जो केवल मायाकृत नर-रूप राम को ही जानेगा, उसमें व्यापक आत्म-रूप-राम को नहीं जानेगा,उसका माया भ्रम कभी नहीं मिटेगा ।

(८)ध्यान-योग में पारंगत होने पर ही सब में ईश्वर को देख सकते हो । केवल किसी के कहने पर कि सबमें ईश्वर को देखो, नहीं देख सकते ।

(९)अक्षर-ज्ञान देने वाला शिक्षक यदि अधकचरा हो तो एक बार का काम चल सकता है, परन्तु आत्म - दर्शन कराने वाले अधुरे शिक्षक (गुरु) से हरगिज काम नहीं चलाया जा सकता है ।

(१०)सफलता गुरु की खोज में ही है ।

- संत सदगुरु महर्षि मेँहीँ परमहँस जी महाराज।

आज का कार्टून

मोदी युग के अंत की हुई शुरुआत...!

हिंदुत्व, उग्र राष्ट्रवाद, और उन्माद की हद तक भावनात्मक माहौल बना कर चुनावी सफलता हासिल करते रहने का खुद नरेंद्र मोदी में आत्म-विश्वास इतना गहरा था कि 2024 आते-आते उन्होंने विकास या जन-कल्याण की बात करनी ही छोड़ दी। या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि ऐसा करने की उनकी क्षमता चूक गई। क्षमता संभवतः इसलिए चूक गई, क्योंकि उनके शासनकाल का जो रिकॉर्ड है, उसे देखते हुए लोगों के लिए उनके ऐसे उनके वायदों पर भरोसा करना संभव नहीं रह गया। 2024 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनके रणनीतिकारों ने 'विकसित भारत' की कहानी तैयार की थी। लेकिन मतदान का पहला चरण आते-आते यह साफ हो गया कि वैसे ऊंचे सपनों में अब आम जन की रुचि नहीं है। जब उनकी अपनी जिंदगी अवनति की तरफ हो, तब यह लाजिमी है कि उन्नत या विकसित भारत के कथानक में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो मोदी और उनकी पार्टी ने पहले चरण के मतदान के बाद इस कहानी चर्चा ही छोड़ दी। उसके बाद वे हिंदू-मुस्लिम के अपने आजमाए फॉर्मूले पर लौट गए।

सत्येन्द्र रंजन

चुनावी राजनीति का एक हद तक सामान्य रूप रूप में लौटने का संकेत ही इस आम चुनाव की विशेषता है। इसका अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी परिघटना पर विराम लग गया है। यह धारणा टूट गई है कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा चुनावों में उसकी सफलता की गारंटी बना रहेगा। इस आम चुनाव में वास्तव में यही कथित करिश्मा जख्मी हुआ है।

साल 2024 में आकर राष्ट्रीय जनादेश एक बार फिर खंडित रूप में सामने आया है। वैसे 2014 और 2019 में भी जनादेश इलाकाई आधार पर खंडित रहा था। तब उत्तर और पश्चिमी भारत में भाजपा का सिक्का चला था। दक्षिण में कर्नाटक तक उसके पांव जरूर पसरे थे, लेकिन बाकी दक्षिणी राज्यों में उसकी पहुंच नहीं बन सकी थी। पूर्वी भारत और उत्तर-पूर्व की तस्वीर मिली-जुली रही थी। 2024 में उत्तर और पश्चिम भी बंट गए। यह जरूर है कि वोट प्रतिशत के लिहाज से भाजपा के पांव दक्षिणी राज्यों में अधिक पसरे हैं, भले ही उसे सीटों के अर्थ में वहां उस हद तक फायदा ना हुआ हो।

इस सूरत को देखते ताजा जनादेश के बारे में कोई समग्र निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। भाजपा को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तगड़ी चोट लगी है। इसके अलावा कई राज्यों में उसे सीटों का नुकसान हुआ है। मगर ये वो राज्य हैं, जहां वह दो बार से चरम सफलता हासिल कर रही थी। वैसे में उसे नुकसान होना राजनीति का सामान्य स्तर पर लौटना माना जाएगा।

बहरहाल, चुनावी राजनीति का एक हद तक सामान्य रूप रूप में लौटने का संकेत ही इस आम चुनाव की विशेषता है। इसका अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी परिघटना पर विराम लग गया है। यह धारणा टूट गई है कि आम जन की जिंदगी से जुड़े विभिन्न मोर्चों पर भाजपा सरकार का प्रदर्शन चाहे जैसा रहे, नरेंद्र मोदी का करिश्मा चुनावों में उसकी सफलता की गारंटी बना रहेगा। इस आम चुनाव में वास्तव में यही कथित करिश्मा जख्मी हुआ है।

ऐसा होने के परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। आखिर इसी करिश्मा में यकीन के कारण देश के कॉरपोरेट सेक्टर और अन्य शासक वर्गों ने पिछले एक दशक से अपना पूरा दांव मोदी पर लगा रखा है। यह दांव लगाने की शुरुआत तब से हुई थी, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। असल में ÷गुजरात मॉडल÷ यही था कि कॉरपोरेट मोदी के पीछे अपनी पूरी ताकत लगाएं और उस बदौलत सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार उनके माफिक नीतियों पर अमल करे। इस मॉडल का एक बड़ा आयोजन वाइब्रेंट गुजरात होता था, जहां पहुंच कर 2007-08 से ही देश के बड़े पूंजीपतियों ने मोदी को भारत का भावी प्रधानमंत्री घोषित करना शुरू किया था। मोदी का वह फॉर्मूला राष्ट्रीय स्तर पर भी कारगर रहा। उसी के परिणामस्वरूप पिछले दस साल आम जन की दुर्दशा बढ़ी है। मगर इस चुनाव में वह फॉर्मूला अगर पूरी तरह से पिटा नहीं है, तो कम-से-कम यह तो कहा ही जाएगा कि उसमें बड़े छेद हो गए हैं।

तो यह लाजिमी है कि मोदी पर अब तक दांव लगाने वाले धनी-मानी तबके अब इस सवाल पर सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या एकमात्र उसी चेहरे पर दांव लगाए रखना बुद्धिमानी होगी, जिसके चुनावी मुकाबले में पिटने की शुरुआत हो गई है?

हिंदुत्व, उग्र राष्ट्रवाद, और उन्माद की हद तक भावनात्मक माहौल बना कर चुनावी सफलता हासिल करते रहने का खुद नरेंद्र मोदी में आत्म-विश्वास इतना गहरा था कि 2024 आते-आते उन्होंने विकास या जन-कल्याण की बात करनी ही छोड़ दी। या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि ऐसा करने की उनकी क्षमता चूक गई। क्षमता संभवतः इसलिए चूक गई, क्योंकि उनके शासनकाल का जो रिकॉर्ड है, उसे देखते हुए लोगों के लिए उनके ऐसे उनके वायदों पर भरोसा करना संभव नहीं रह गया।

2024 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनके रणनीतिकारों ने 'विकसित भारत' की कहानी तैयार की थी। लेकिन मतदान का पहला चरण आते-आते यह साफ हो गया कि वैसे ऊंचे सपनों में अब आम जन की रुचि नहीं है। जब उनकी अपनी जिंदगी अवनति की तरफ हो, तब यह लाजिमी है कि उन्नत या विकसित भारत के कथानक में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो मोदी और उनकी पार्टी ने पहले चरण के मतदान के बाद इस कहानी चर्चा ही छोड़ दी। उसके बाद वे हिंदू-मुस्लिम के अपने आजमाए फॉर्मूले पर लौट गए। मगर चुनाव नतीजों से जाहिर है कि यह फॉर्मूला भी अब पहले जैसा कारगर नहीं रह गया है।

2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी ने जन-कल्याण की सोच के खिलाफ जंग छेड़ते हुए लड़ा। इसे उनका दुस्साहस ही कहा जाएगा कि 2023-24 के बजट में (जो आम चुनाव के पहले का आखिरी पूर्ण बजट था) उनकी सरकार ने जन-कल्याण के तमाम कार्यक्रमों के लिए आवंटन में कटौती कर दी। यह सिलसिला 2024-25 के अंतरिम बजट में भी जारी रहा। इस बीच मोदी ÷रेवड़ी संस्कृति÷ के खिलाफ जुबानी मुहिम भी छेड़ चुके थे। 2024 के चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने बढ़ती गैर-बराबरी को सही ठहराने की कोशिश की, कुछ हाथों में धन संग्रहण की चिंताजनक परिघटना को उन्होंने वेल्थ क्रियेटर्स की कामयाबी के रूप में पेश किया, और गरीब आवाम को दी जाने वाली राहत को देश के विकास में बाधक बताया। इस तरह उन्होंने ऐसी समझ लोगों के सामने रखी, मानों देश और आम जन कोई अलग-अलग चीज हो!

आज अगर पिछले दो आम चुनावों की तुलना में और भी ज्यादा खंडित जनादेश हमारे सामने आया है, तो यह बेशक कहा जा सकता है कि जिन आम जन के प्रति प्रधानमंत्री ने अपमान का ऐसा भाव दिखाया, उसके एक बड़े हिस्से ने फिलहाल उनकी पार्टी से बदला लिया है। यही वो तबके हैं, जिनके मन में 'अच्छे दिन' के वादे ने ऊंची उम्मीदें जगाई थीं। मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री के अपने पहले कार्यकाल में 'लाभार्थी' संस्कृति का हौव्वा खड़ा कर उन उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन 2024 आते-आते उन्होंने आम जन को लाभ पहुंचाने की सोच पर ही हमला बोल दिया।

उसका नतीजा सामने है। हिंदुत्व के अंडरकरंट से हुए ध्रुवीकरण के साथ 'अच्छे दिन' के वादे ने भाजपा के लिए जो प्लस वोट जोड़े थे, वे अगर पूरे देश में नहीं, तो कम-से-कम कुछ राज्यों में जरूर ही, उससे अलग हो गए हैं। नतीजतन, भाजपा ने लोकसभा में बहुमत गंवा दिया है।

1989 में भारतीय राजनीति पर कांग्रेस का वर्चस्व खत्म होने के बाद से और 2014 में मोदी के उदय के पहले तक- एक समझ यह थी कि भारत में अब कोई राष्ट्रीय जनादेश नहीं होता। बल्कि प्रांतीय स्तर पर उभरने वाले जनादेश के कुल योग से राष्ट्रीय राजनीतिक सूरत उभरती है। 2024 में फिर से बात वहीं पहुंचती दिखी है। और इसके साथ ही भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी युग के अंत की शुरुआत हो गई है।

संदेशों से निकलते मन के भाव...

सुवाक्य कई बार जीवन की दिशा ही बदल देने की शक्ति रखते हैं। कई बार उलाहने भी जीवन को नई रोशनी देने में सहायक होते हैं। उलाहनों को चुनौती मानते हुए जो प्राणप्रण से जुट जाते हैं, वे सफल होकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आज हमारे सामने जो सुवाक्य आ रहे हैं, उसे अगर ध्यान से पढ़ा जाए, तो ये भी दिन को प्रफुल्लित बनाने का काम कर सकते हैं। कई बार ये सुवाक्य हमें हताशा से भी बाहर निकालते हैं। इनमें एक अलग तरह की सुवास होती है। जैसे-जैसे उसे पढ़ा जाए, वैसे-वैसे उसकी सुगंध हमारे आसपास फैलने लगती है।

महेश परिमल

सुवाक्य, आज के विचार, अनमोल बोल आदि नामों से प्रचलित वाक्य हमारे लिए सदैव औषधि का काम करते रहे हैं। पहले इस तरह के वाक्य बहुत मुश्किल से पढ़ने को मिलते थे। अपने स्कूलों की दीवारों पर इस तरह के वाक्य अक्सर हम पढ़ते थे। उसके बाद इसका धीरे-धीरे विस्तार होता गया। कहीं-कहीं इस तरह के सुवाक्य आज भी पढ़ने को मिल जाते हैं। हालांकि हाल के दिनों में सुवाक्यों की बाढ़-सी दिखने लगी है। लोग मोबाइल पर सुबह की राम-राम के बजाय सुवाक्य डालने लगे हैं। वाट्सएप से जो भी जुड़ा है, उसके सामने से रोज ही सुवाक्यों की पूरी श्रृंखला गुजरती है।

सुवाक्यों में एक अलग ही प्रकार की सुगंध होती है। उसे हम जैसे-जैसे पढ़ते हैं, उसकी सुगंध उतनी ही फैलती रहती है। कई वाक्य हमें तुरंत ही प्रभावित करते हैं। कई कालांतर में याद आते हैं। कई वाक्यों को हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। कई वाक्य हमें आंदोलित भी करते हैं। कई बार तो हमें लगता है कि यही तो मेरे साथ हुआ है। काशज मैं इसे पहले समझ जाता। कई वाक्य हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि इस पर तुरंत अमल कर लिया जाए। हम उसे अमल में लाते भी हैं। पर कुछ दिन बाद जिंदगी अपनी पटरी पर लौट आती है। सुवाक्यों की

दुनिया बहुत ही छोटी होती है। हम जैसे ही पढ़ते हैं, हमारा मस्तिष्क उससे प्रभावित होता है। हमें लगता है कि इसे तुरंत अमल में लाया जाए, तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। पर वाक्य का असर कुछ ही देर होता है। उसे अमल में लाने के कुछ देर बाद वह कहीं विलीन हो जाता है।

आजकल देश में वाट्सएप पर पढ़े-लिखे और यहां तक कि अनपढ़ लोग भी संदेशों का आदान-प्रदान करने लगे हैं। ऐसा लगता है मानो देश के सभी लोग अति-शिक्षित हो गए हैं। ज्ञान का भंडार खुल गया है। हर कोई ज्ञानी बन गया है। वहएक से एक संदेश देने लगा है। सारे संदेश और उपदेश केवल देने के लिए ही होते हैं, ऐसा मानकर वह दिन भर एक से एक संदेश देने का काम करता रहता है। अगर इन संदेशों का मर्यादा में उपयोग हो, तो यह अपने विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। आजकल इस माध्यम का दुरुपयोग अधिक हो रहा है। अच्छी जानकारी कहीं दबकर रह जाती है, पर समाज में नकारात्मकता फैलाने वाली सामग्री बहुत ही तेजी से फैलने लगी है।

हमारे मोबाइल में विभिन्न तरह के संदेशों की भरमार है। किसी को भी संदेश भेजा जाए, तो उसके पीछे के भाव, उसका अर्थ भी जानना चाहिए। इस तरह के सुवाक्य हमें केवल मोबाइल में ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है। सामान्य जीवन में हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कई चिंतकों, विचारकों, वक्ताओं, कथाकारों और दैनंदिन जीवन में होने वाले वार्तालापों से भी हमें सीखने के लिए बहुत कुछ प्राप्त होता रहता है। जिसे कुछ सीखना हो, तो वह बच्चों की तुतली वाणी से भी सीख सकता है। कई बार मूक प्राणी भी अपनी हरकतों से बिना कहे हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। सामान्य रूप से हम रोज ही कई संदेशों को 'डिलीट' कर देते हैं। इसके बाद भी कुछ संदेशों को हटाते समय ऐसा लगता है कि इसे रख लिया जाए। जिसे सुरक्षित रखा जाता है, वे संदेश संतों, महान व्यक्तियों के होते हैं, जिनसे हम सदैव प्रेरित होते रहते हैं। उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं।

सुवाक्य कई बार जीवन की दिशा ही बदल देने की शक्ति रखते हैं। कई बार उलाहने भी जीवन को नई रोशनी देने में सहायक होते हैं। उलाहनों को चुनौती मानते हुए जो प्राणप्रण से जुट जाते हैं, वे सफल होकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आज हमारे सामने जो सुवाक्य आ रहे हैं, उसे अगर ध्यान से पढ़ा जाए, तो ये भी दिन को प्रफुल्लित बनाने का काम कर सकते हैं। कई बार ये सुवाक्य हमें हताशा से भी बाहर निकालते हैं। इनमें एक अलग तरह की सुवास होती है। जैसे-जैसे उसे पढ़ा जाए, वैसे-वैसे उसकी सुगंध हमारे आसपास फैलने लगती है।

पहले कई लोगों के पास एक किताबनुमा नोटबुक हुआ करती थी, जिस पर वे विभिन्न स्थानों, लोगों से प्राप्त सुवाक्यों को लिखकर उसका संग्रह तैयार करते थे। इस तरह के सुवाक्यों का विशाल भंडार है। कुछ लोग तो विख्यात लोगों के सुवाक्यों को अपने नाम से लिखकर अपनों को भेजने लगे हैं। अब दीवारों पर सुवाक्य नहीं दिखते। वाट्सएप की दुनिया में तो सुवाक्यों का भंडार है। लोग अपने-अपने समूहों में सुवाक्यों का आदान-प्रदान करते रहते हैं। कई लोग इसे पढ़ते भी नहीं, तुरंत ही दूसरों को भेज देते हैं।

सुवाक्य तो अपनी जगह ठीक हैं, पर कई लोग इन सुवाक्यों के बीच जहर फैलाने का काम भी करने लगे हैं। लोगों को इससे बचकर रहना होगा, क्योंकि लोगों को बुरी चीजें तुरंत आकर्षित करती हैं। इसलिए जैसे ही इसकी भनक मिले, हमें सचेत हो जाना चाहिए। नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हमारे मोबाइल में भी सुवाक्यों को जमा करने की व्यवस्था है। इसे अगर हम 'नोटपैड' पर जमा कर लें, तो कई बार ये हमें हताशा के सागर से निकलने में सहायता करेंगे। हमारी छाया जब हमारे कद से बड़ी हो जाए, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि सूरज डूबने वाला है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मिलन ग्रुप द्वारा मिलन प्रिंटर्स, औद्योगिक क्षेत्र, बरारी, जिला- भागलपुर, बिहार से प्रकाशित एवं दैनिक भाष्कर प्रेस, तिलकामांझी, भागलपुर से मुद्रित। आरएनआई नंबर: BIHHIN/2009/30172 संस्थापक संपादक-स्मृति शेष मोहन मिलन,
संपादक- हिमांशु मिलन* फोन नंबर-06424-222022, 9430059511, 7258803511, ईमेल - *angbharat@gmail.com* * पी आरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी । सभी मामलों का न्यायिक क्षेत्र बांका न्यायालय होगा।

संपादकीय

" उस व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं, जिसने पूरा जीवन एक ही विचार को समर्पित कर दिया। -फ्रांसिस क्रिक

पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की चालीसवीं बरसी पर खालिस्तान समर्थन में नारे लगना चिंताजनक है। पंजाब ने आतंकवाद का एक लंबा दौर देखा है और अब दोबारा वह उस काले दौर में नहीं लौट सकता। ऐसे में, केंद्र सरकार के साथ पंजाब सरकार को भी सतर्क रहने की जरूरत है।

सतर्कता जरूरी

पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की चालीसवीं बरसी पर स्वर्ण मंदिर परिसर में भारी भीड़ की मौजूदगी के बाद भी कोई हिंसक घटना बेशक न घटी हो, लेकिन वहां जिस तरह तलवारें लहराते हुए खालिस्तान समर्थन के नारे लगाए गए, वह चिंताजनक होने के साथ सीमावर्ती राज्य के लिए खतरे की घंटी भी है। इस खतरे को समझने के लिए घटनाओं के क्रम को समझना होगा। पंजाब में तीन दिन पहले आए लोकसभा चुनाव परिणामों में भी दो खालिस्तान समर्थक रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। इससे पहले, किसान आंदोलन के दौरान भी खालिस्तानी अलगाववादियों के शामिल होने के आरोप लगे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने मणिपुर हिंसा में भी अलगाववादियों की लिप्तता का खुलासा किया था, जब पिछले वर्ष एक शीर्ष कुकी नेता के खालिस्तानी अलगाववादियों से कथित संपर्क के सिलसिले में गिरफ्तारियां की गई थीं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की संचालक कंपनी मेटा ने हाल ही में खुलासा किया कि चीन से संचालित हो रहे फर्जी खाते किस तरह खालिस्तान के नाम पर सिखों को भड़काते हुए एक फर्जी आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पंजाब में आतंकवाद के सफाए के बाद खालिस्तानी नेताओं ने पाकिस्तान में पनाह ली और अपना नेटवर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से चलाना शुरू किया। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका में भी खालिस्तानी गुटों ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनयिक मिशनों को भी निशाना बनाने की कोशिशें की हैं। पिछले वर्ष स्कॉटलैंड में खालिस्तानी अलगाववादियों ने जिस तरह से भारतीय उच्चायुक्त को स्थानीय गुरुद्वारे में प्रवेश से रोक दिया था, वह उनकी बढ़ी हुई हिम्मत को ही दिखाता है। कनाडा में प्रतिबंधित केटीएफ (खालिस्तानी टाइगर फोर्स) के सरगना हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से अलगाववाद को गहरा झटका जरूर लगा था। कनाडा इसके पीछे भारत की लिप्तता का मनगढ़ंत आरोप जरूर लगाता रहा, लेकिन इस कुत्सित अभियान में उसे

अपने सहयोगी देशों तक का समर्थन नहीं मिला। पंजाब ने आतंकवाद का एक लंबा दौर देखा है, जिससे उबरने में उसे खासा वक्त भी लगा है और अब दोबारा वह उस काले दौर में नहीं लौट सकता। आतंकवाद दोबारा सिर न उठाए, इसके लिए जरूरी है कि केंद्र व राज्य स्तर पर बेहतर समन्वय हो और आतंकियों की फंडिंग रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। लोकतंत्र में सरकार से असहमति या विरोध स्वाभाविक है और देश का इतिहास ऐसे विरोध और असहमतियों से भरा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही यह भी देखने की जरूरत है कि निहित स्वार्थ इसकी आड़ में राष्ट्रीय हितों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे।

उदार अमेरिका में कट्टरपंथियों का ठिकाना

अमेरिका बांग्लादेशियों को आकर्षित करता है, तो इसकी वजह वहां नौकरी करने, व्यापार करने, स्वतंत्रता से चलने-फिरने, अपने धर्म का पालन करने और बच्चों को स्कूलों में मुफ्त में पढ़ाने की सुविधा है। इसके बावजूद अमेरिका में रहने वाले ये लोग अमेरिकी आदर्शों को थोड़ा भी नहीं मानते।

तसलीमा नसरीन
चर्चित लेखिका

कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क में सुचित्रा सेन चलचित्र उत्सव का आयोजन हुआ। इसका आयोजन न्यूयॉर्क में रह रहे अनिवासी बांग्लादेशियों ने किया था। इससे कुछ ही दिनों पहले न्यूयॉर्क में बांग्ला पुस्तक मेला और साहित्य अनुष्ठान आयोजित हुए थे। इनके आयोजक भी अनिवासी बांग्लादेशी थे। इससे ऐसा लगता है कि अमेरिका में रहने वाले सभी बंगाली शायद प्रगतिशील हैं, सभी शायद साहित्य या संस्कृति प्रेमी हैं। क्या सच में ऐसा है?

बेशक ढाका और न्यूयॉर्क में बहुत अंतर है। अमेरिका और बांग्लादेश में जो अंतर है, ढाका और न्यूयॉर्क में वही अंतर है। अमेरिका चूंकि बांग्लादेश की तुलना में अत्यधिक विकसित और सभ्य देश है, इस कारण बड़ी संख्या में बांग्लादेशी अमेरिका की स्थायी नागरिकता पाने के लिए अमेरिका जाते हैं। कट्टर मुस्लिम भी, जो हमेशा धर्म के नशे में चूर रहते हैं, ईसाइयों-यहूदियों से घृणा करते हैं, उन्हें गाली देते हैं, मौका मिलने पर वे भी अमेरिका जाने का जुगाड़ बिठाते हैं। वे अगर चाहें, तो आराम से अरब देशों में बस सकते हैं, पर वे ऐसा नहीं करते।

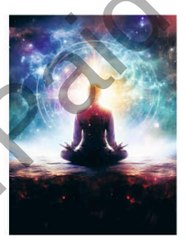

बांग्लादेशियों को भी अमेरिका बहुत आकर्षित करता है। अमेरिका की नागरिकता मिलने पर उनका जीवन धन्य हो जाए। स्थायी निवास के लिए उन्हें ईसाइयों, यहूदियों और नास्तिकों का देश अमेरिका ही पसंद है। बहुत लोग तो जोखिम उठाकर भी पश्चिमी देशों में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। रात के अंधेरे में नाव से भूमध्यसागर पार कर यूरोप पहुंचते हैं। नाव के डूब जाने से बहुतों की जान भी जाती है। इसके बावजूद नाव से समुद्र पार करने की जोखिम भरी कोशिशों पर विराम नहीं लगता। अरब देश में हज करने जाने, अरब देशों की पोशाक पहनने, अरब देशों की भाषा और आचार-व्यवहार का अनुसरण करने और अरब लोगों को महामानव समझने के बावजूद बांग्लादेश के लोग अरब देशों में बसने की उत्सुकता नहीं दिखाते। इसके बजाय अरब देशों में श्रमिक

का काम करने गए लोग जितनी जल्दी संभव हो सके, घर लौट आने के बारे में सोचते हैं। और अरब देशों में लोगों के घरों में काम करने वाली बांग्लादेशी महिलाएं अपनी जान बचाने के लिए घर लौट आती हैं, या फिर लाश बनकर लौटती हैं।

अमेरिका बांग्लादेशियों को आकर्षित करता है, तो उसकी वजह है। अमेरिका में नौकरी करने, व्यापार करने, स्वतंत्रता से चलने-फिरने, अपने धर्म का पालन करने, बच्चों को स्कूलों में मुफ्त में पढ़ाने की सुविधा है। वहां रुपये-पैसे न रहने पर फूड पैकेट मिलता है, मुफ्त में इलाज, दवा, आया आदि की सुविधा है। सर्वोपरि, अमेरिका में मानवाधिकार पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है, जबकि बांग्लादेश में मानवाधिकार की किसी को परवाह ही नहीं है। इसके बावजूद अमेरिका में रहने वाले ये लोग अमेरिकी आदर्शों को थोड़ा भी नहीं मानते। अमेरिका इन्हें उदार नहीं बना पाता। अमेरिका में रहते हुए भी ये बांग्लादेशी बने रहते हैं। भोजन की खोज इन्हें हलाल मीट की दुकान पर ले जाती है। अमेरिका में आने के बावजूद ये बांग्लादेश का पहनावा नहीं छोड़ते। महिलाएं बुर्का और नकाब नहीं छोड़तीं। अमेरिका में रहते हुए भी ये धार्मिक कट्टरता को बरकरार रखते हैं। ये मानते हैं कि उनका धर्म दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वहां रहकर भी ये लोग मानते हैं कि ट्विन टावर्स को ध्वस्त कर देने वाले आतंकवादियों ने बहुत बड़ा काम किया था। इनमें से कुछ तो यह सपना तक देखते हैं कि पश्चिम के तमाम देश मुस्लिमों से भर गए हैं और यह पृथ्वी सिर्फ मुस्लिमों के लिए है।

बांग्लादेशियों की नई पीढ़ी में अमेरिका जाने की इच्छा प्रबल है। यही नहीं, ये लोग अपने देश से बाहर यह बताने में भी कतराते हैं कि उनके माता-पिता बांग्लादेशी हैं। दूसरी ओर, अपने घर में कट्टरवादियों द्वारा लगातार ब्रेनवॉश किए जाने के कारण कुछ लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। इस तरह के भटके हुए लोग दूसरे देशों के मुस्लिमों को अपना समझने की गलती कर डालते हैं। हालांकि दूसरी तरफ यह भी सच है कि अमेरिका में पैदा हुई पीढ़ी के अनेक बच्चे बांग्ला में बातचीत करते हैं, बांग्ला गीत गाते हैं। हालांकि यह इस पर निर्भर करता है कि इन बच्चों के माता-पिता घर में बांग्ला संस्कृति को कितना प्रोत्साहित करते हैं।

अनिवासी बांग्लादेशियों ने अमेरिका के विभिन्न शहरों में छोटे-छोटे बांग्लादेश बना लिए हैं। पश्चिम उनके जीवन-यापन और सोच-विचार में किसी प्रकार का बदलाव नहीं ला पाया है। अमेरिका में रह रहे बांग्लादेशी अब भी जात-पांत, अंधविश्वास और कठोर पुरुषतंत्री सोच में जकड़ा हुआ है। इनके अपने देश में नारी विरोध का जो इतिहास है, उसे ये बांग्लादेशी बंगाल की खाड़ी के किनारे से अटलांटिक और प्रशांत महासागर के किनारे तक ढोकर ले आए हैं। अनिवासी नागरिक शायद ऐसे ही होते हैं। जिस मिट्टी से वे आते हैं, आजीवन उसी मिट्टी से जुड़े रहते हैं। विदेशी संस्कृति से वे वस्तुतः उतना ही ग्रहण करते हैं, जितना उनके रोजगार के लिए जरूरी होता है। लेकिन सोच-विचार की दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए जिस दर्शन की जरूरत होती है, उसे वे कभी जान-सीख-अपना नहीं सकते। वे आजीवन सिर्फ उसी पर चर्चा करते हैं, जो अपने देश से सीखकर आए होते हैं।

मैं यह नहीं कह रही कि न्यूयॉर्क में बांग्ला साहित्य और संस्कृति के कर्णधारों ने सिर्फ मुझे ही प्रतिबंधित किया। हो सकता है, और भी लेखकों-कवियों-संस्कृतिकर्मियों को उन्होंने प्रतिबंधित किया हो, और भविष्य में भी करते रहेंगे। और वहां आमंत्रित कवियों-लेखकों ने न तो इस प्रतिबंध के विरोध में कुछ कहा, न भविष्य में कुछ कहेंगे। धारा के विरुद्ध चलने वाले या अलग विचार रखने वालों की उपेक्षा करते हुए बांग्ला पुस्तक मेला इसी तरह सालोंसाल आयोजित होते रहेंगे। इसी कारण मैं कहती हूं कि बांग्लादेश और अमेरिका में भले ही फर्क हो, लेकिन इन जगहों में रहने वाले बांग्लादेशियों में आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। जिस तरह ढाका में होने वाले पुस्तक मेले में मेरा प्रवेश प्रतिबंधित है, ठीक उसी तरह न्यूयॉर्क में होने वाले पुस्तक मेले में भी मुझे प्रतिबंधित किया जाता है। सात समुद्र पार बस जाने के बावजूद संकुचित बंगाली संकुचित ही रह जाता है।

जीवन धारा

एंजेला डकवर्थ

सभी बच्चे एकसमान प्रतिभावान नहीं होते, लेकिन सबमें कुछ न कुछ खासियत जरूर होती है। यदि उनमें सीखने की ललक है, तो वे पहले से घोषित प्रतिभावान से आगे निकल सकते हैं।

सही दिशा में की गई मेहनत जरूर सफल बनाती है

जाहिर है कि योग्यता सफलता की गारंटी नहीं होती। हालांकि परंपरागत ज्ञान तो यही कहता है कि गणित एक ऐसा विषय है, जिसमें विद्यार्थी जितने ज्यादा प्रतिभावान होंगे, उनके सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। वे कक्षा के उन साथियों को पीछे छोड़ देंगे, जो वास्तविकता में गणित के लायक नहीं हैं। ईमानदारी से कहूं तो स्कूल की शुरुआत मैंने भी इसी धारणा के साथ की थी। मैंने ऐसा समझ लिया था कि जो विद्यार्थी आसानी से बातें समझते हैं, वे अपने साथियों से आगे बने रहेंगे। स्कूल में पढ़ाने के दौरान प्रतिभा के विषय ने मेरा ध्यान विचलित कर दिया था। धीरे-धीरे मैंने खुद से कठिन सवाल पूछना शुरू कर दिया। मैंने कोई पाठ पढ़ाया और वह अवधारणा विद्यार्थियों को समझ नहीं आई, तो इसके क्या कारण हैं? क्या मुझे अपना तरीका बदलना पड़ेगा? बाद में सोचा कि शिक्षक होने के नाते क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है?

अब मैंने कमजोर विद्यार्थियों की आवाज बनने की ठान ली। वे अपनी पसंदीदा बातें करते हुए खुल जाते थे। बास्केटबाल, गानों आदि पर उनसे खूब संवाद किया। जब हम लोग एक-दूसरे के साथ खुल गए तब कमजोर विद्यार्थियों की पेचीदगियां समझ आईं। दरअसल सभी विद्यार्थी एकसमान प्रतिभावान नहीं होते। लेकिन सबमें कुछ न कुछ खासियत जरूर होती है। भले ही कोई विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन यदि उसके अंदर सीखने की ललक और निष्ठा है, तो वह पहले से घोषित प्रतिभावान से आगे निकल सकता है। यह साबित किया मेरे एक विद्यार्थी डेविड लुओंग ने। वह एकदम शांत रहता था और कक्षा में एकदम पीछे बैठता था। वह ब्लैकबोर्ड पर सवाल हल करने के लिए बड़ी मुश्किल से आता था। लेकिन मैंने उसके अंदर एक बात देखी कि उसे जब भी कोई काम दिया गया, तो वह अच्छे से करता था। मैंने उसकी प्रतिभा का आकलन किया और तत्काल डेविड को विभाग प्रमुख के पास ले गई और कहा कि इसे उन विद्यार्थियों के ग्रुप में शामिल कीजिए जो तेज हैं। डेविड ने तेज बच्चों में पहुंचकर खुद को कुछ समय तक असहज महसूस किया, लेकिन मैंने उसकी जो खूबी पहचानी थी, उसने वैसा ही किया। वह परिस्थितियों से घबराया नहीं और उसने खूब मेहनत कर खुद को इस लायक बनाया कि वह अव्वल विद्यार्थियों की बराबरी कर सके। दरअसल शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि वे विद्यार्थी की खूबी को पहचानकर आगे बढ़ें। डेविड एयरोस्पेस कॉरपोरेशन में इंजीनियर बनने के बाद मुझसे मिला, उसने बताया कि यदि आप मुझे अपनी कक्षा से निकालकर तेज विद्यार्थियों के ग्रुप में शामिल नहीं करवातीं, तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। जाहिर है, प्रतिभावान होना अच्छा है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत आपको जरूर सफल बनाती है।

एंजेला डकवर्थ की 'द ग्रिट' किताब के अनूदित अंश

डार्विन ने कहा

सूत्र

डार्विन ने अपने भाई को लिखा था कि केवल मूर्खों को छोड़कर बुद्धिमत्ता के हिसाब से लोगों में ज्यादा अंतर नहीं होता। अंतर केवल जिद और कड़ी मेहनत में होता है। इसलिए डार्विन के विचार पर ज्यादा गहराई से सोचने की जरूरत है। दरअसल जिद और कड़ी मेहनत बौद्धिक क्षमता से ज्यादा मायने रखती है। डार्विन की जीवनी लिखने वाले भी यही दावा करते हैं कि वे अलौकिक प्रतिभा के धनी नहीं थे, लेकिन मेहनती इन्सान थे।

दूसरा पहलू

आस्ट्रेलिया में घरेलू हिंसा के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। 2022-23 में 34 महिलाओं की हत्या उनके मौजूदा या पूर्व पार्टनरों ने की थी।

घरेलू हिंसा से जूझतीं ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं

विगत अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुकी है। अल्बानीज को ऐसा कहना पड़ा, क्योंकि औरतों के खिलाफ हिंसा के खिलाफ देश के अलग-अलग शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। एक आंकड़े के मुताबिक, इस साल अब तक घरेलू हिंसा से त्रस्त 29 महिलाएं आत्महत्या कर चुकी हैं। जबकि एक सरकारी आंकड़े के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में 34 महिलाओं की हत्या उनके मौजूदा या पूर्व पार्टनरों ने की थी। फिलहाल भले यह आंकड़ा अमेरिका में घरेलू हिंसा के आंकड़ों से कम हो, लेकिन इस सच से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ऑस्ट्रेलिया में घरेलू हिंसा के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।

यह इतनी बड़ी समस्या है कि नए संघीय बजट में अल्बानीज सरकार ने घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं व बच्चों की मदद के लिए अगले पांच साल में एक अरब डॉलर का आवंटन किया है। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और विशेषज्ञों का मानना है कि बजट आवंटन से समस्या हल नहीं होगी। वुमैन इलावारा नाम के गैरलाभकारी संगठन के लिए काम करने वाली मिशेल ग्लासगो के मुताबिक, जो दशकों से घरेलू हिंसा झेलने वाली महिलाओं के साथ काम कर रही हैं, अनेक महिलाएं घरेलू हिंसा, यौन अत्याचार, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित आवास व नौकरी में महिलाओं की समान हिस्सेदारी मांग रही हैं। लेकिन इनमें से बहुत कम ही महिलाओं को अपेक्षित मदद मिल पाई है। मिशेल के मुताबिक, कोविड लॉकडाउन के बाद से ही उनके इलाके में उनके संगठन द्वारा पीड़ित महिलाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, अदालती मदद आदि की मांग काफी बढ़ गई है। मेलबर्न के उपनगरीय इलाकों में खुद घरेलू हिंसा से पीड़ित एक महिला टारा शुल्ज कहती हैं कि कम आय और मामूली पृष्ठभूमि की कम उम्र महिलाओं के घरेलू हिंसा का सामना करने की आशंका अब भी सबसे अधिक है, और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। वह कहती हैं कि ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई युवतियां अब भी उन्हीं समस्याओं से जूझती हैं, जिनसे कभी वह जूझती रही थीं। और यह समस्या सिर्फ शहरी-उपनगरीय इलाकों में नहीं, बल्कि दूरस्थ इलाकों में भी है। मसलन, नॉर्दन टेरिटरी में, जहां देश की मात्र एक फीसदी आबादी रहती है, घरेलू हिंसा में मरने वाली महिलाओं का आंकड़ा राष्ट्रीय आंकड़े की तुलना में सात गुना ज्यादा है। जाहिर है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार इन दिनों घरेलू हिंसा की बड़ी चुनौती का सामना कर रही है।

जुलिया बर्गिन

यह इतनी बड़ी समस्या है कि नए बजट में सरकार ने घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं व बच्चों की मदद के लिए अगले पांच साल में एक अरब डॉलर का आवंटन किया है।

मेलबर्न के उपनगरीय इलाकों में कम आय और मामूली पृष्ठभूमि की कम उम्र महिलाओं के घरेलू हिंसा का सामना करने की आशंका अब भी सबसे अधिक है, और उनकी कहीं सुनवाई भी नहीं होती।

आंकड़े

आमों के शौकीन

विदेश में बड़े स्तर पर भारतीय आम को पसंद किया जाता है। इनमें यूएई, ब्रिटेन और अमेरिका सबसे बड़े आयातक हैं।

देश	हिस्सा
यूएई	38.16%
ब्रिटेन	18.9%
अमेरिका	16.62%
कुवैत	4.84%
कतर	3.59%

3.18 फीसदी के साथ कनाडा छठे नंबर पर है।

स्रोत : DGCIS

अंतर्यात्रा

संकलित

अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने पर अर्जुन और सुधन्वा के बीच भीषण युद्ध हुआ। दोनों भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण को आना पड़ा।

भगवान में लीन हो गए सुधन्वा

महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा चंपकपुरी राज्य में पहुंचा, तो वहां के महाराज हंसध्वज ने सेना और योद्धाओं को बुलाया, लेकिन उनके छोटे बेटे सुधन्वा को पहुंचने में विलंब हुआ।

राजा ने पूछा कि इसे क्या सजा दी जाए, तो पुरोहितों ने कहा कि पूर्व घोषणा के अनुसार, गर्म तेल के कढ़ाहे में डाला जाए। सुधन्वा भगवान का नाम लेकर कढ़ाहे में उतर गए, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। शंका हुई कि राजा ने ठंडा तेल डलवाया होगा। परखने के लिए उसमें नारियल डाला तो वह दो हिस्सों में फट गया। इसके बाद यज्ञ का घोड़ा पकड़ने के लिए सुधन्वा को भेजा। उनके साथ पांडव सेना ने अर्जुन के नेतृत्व में युद्ध किया। अर्जुन सुधन्वा का सामना नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि महाभारत में कई योद्धाओं को परास्त किया, लेकिन यहां क्या हुआ। सुधन्वा ने याद दिलाया कि यहां आपके सारथी भगवान कृष्ण नहीं हैं। उन्हें बुलाएं। अर्जुन ने भगवान का आह्वान किया।

भगवान के प्रकट होने पर दोनों ने उनको नमन किया। सुधन्वा ने कहा, पार्थ अब युद्ध कीजिए। अर्जुन बोले कि मैं तीन बाण में तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं तो नरक का गामी बनूं। सुधन्वा बोले, मैं उनको काट दूंगा। अर्जुन के तीनों ही बाण सुधन्वा ने काट दिए, लेकिन अंतिम बाण के एक टुकड़े ने निकलकर सुधन्वा की गर्दन काट दी। सुधन्वा के शरीर से ज्योति निकलकर भगवान में ली हो गई। इस तरह भगवान ने दोनों ही भक्तों के प्रण की रक्षा की।

आज का इतिहास

शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन

इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास न सिर्फ अपने में घटनाओं को समेटे होता है बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। सात जून का दुनिया के सात अजूबों में शुमार संगमरमरी इमारत ताजमहल से गहरा रिश्ता है। दरअसल शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन सात जून को हुआ था। बुरहानपुर में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय मुमताज महल ने अंतिम सांस ली। शाहजहां ने उनकी याद में आगरा में यमुना के किनारे सफेद संगमरमर का मोहब्बत का अजीम मुजसम्मा तामीर करवाया, जिसे मुमताज के नाम पर ताजमहल का नाम दिया गया। 1971 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से लगे भारत के सीमावर्ती इलाकों में हैजे से तीन हजार लोगों की मौत की पुष्टि की। 1974 में टेनिस के खेल में भारत का नाम दुनियाभर में रौशन करने वाले महेश भूपति का जन्म।

भूमि पर रेंगती मौत है मरुस्थलीकरण

दुनिया भर के कई क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण एक कठोर वास्तविकता बन गया है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका को खतरा है।

वीर सिंह | **संकट**

भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण, और सूखा प्रतिरोधकता। इस महत्वपूर्ण और चुनौती भरे विषय पर केंद्रित इस वर्ष का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टीफिकेशन (यूएनसीसीडी) की पार्टियों का 16वां सम्मेलन रियाद में 2 से 13 दिसंबर तक होना है। इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में विश्व को भूमि की सुरक्षा व जलवायु परिवर्तन के सामने मरुस्थलीकरण और सूखे से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्यवाही की तत्काल आवश्यकता को पहचानने का आह्वान किया गया है।

मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता व आजीविका के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जिससे पारिस्थितिक रूप से सुदृढ़ भूमि

प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना अनिवार्य हो जाता है। प्रत्येक बीते वर्ष के साथ, इन चुनौतियों से निपटने की तात्कालिकता और अधिक स्पष्ट हो जाती है, जिससे हमें उनके प्रभाव को कम करने के लिए सामूहिक प्रयासों के महत्व की अनुभूति होती है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित जितने भी अंतरराष्ट्रीय दिवस हैं, उनमें पर्यावरण दिवस ऐसा है, जिसे उत्साह और चिंतन के साथ मनाया जाता है। हमारे ग्रह के भूमि संसाधनों के लिए मरुस्थलीकरण सबसे घातक खतरों में से एक है, जो चुपचाप पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता और आजीविका पर अतिक्रमण कर रहा है। मरुस्थलीकरण वास्तव में भूमि पर रेंगती मौत है। एक बार यह जिस भूखंड पर रेंग जाता है, वह भूमि का मृत हिस्सा बनकर रह जाता है, वहां की मिट्टी सांस नहीं ले सकती, वहां कोई पौधा नहीं पनप सकता, वहां जीवन की खाद्य श्रृंखला टूट जाती है। मरुस्थलीकरण कोई यकायक घटी प्रलयंकारी घटना नहीं, वरन भूमि क्षरण की क्रमिक प्रक्रिया है, जिसमें वनस्पति की हानि, मिट्टी का क्षरण और जल संसाधनों की कमी सम्मिलित है। यह शुष्क, अर्ध शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में होता है, जहां जलवायु परिवर्तन और अस्थिर भूमि प्रबंधन प्रथाएं और शहरीकरण भूमि के क्षरण में योगदान करते हैं, जिससे मरुस्थलीकरण का प्रसार बढ़ता है। मरुस्थलीकरण प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। इससे पारिस्थितिक तंत्रों में जैव विविधता की हानि, मिट्टी की उर्वरता में कमी तथा सूखे और वनों की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं की एक अटूट श्रृंखला शुरू हो जाती है। दुनिया भर के कई क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण एक कठोर वास्तविकता बन गया है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका को खतरा है और सतत विकास के प्रयास कमजोर हो रहे हैं। विशेष रूप से अफ्रीका में विशाल भूमि मरुस्थलीकरण की निरंतर प्रगति का शिकार हो रही है। मरुस्थलीकरण की गंभीर वास्तविकताओं के बीच कार्यवाही के लिए आशा और अवसर उपलब्ध हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने का प्रयास किया है। 1994 में अपनाया गया यूएनसीसीडी इस दिशा में एक ऐतिहासिक समझौता है, जिसका उद्देश्य स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना और सूखे के प्रभावों को कम करना है। पुनर्वनीकरण और वनीकरण की पहल मरू भूमि को बहाल करने और मरुस्थलीकरण को कम करने, वन्यजीवों के लिए आवश्यक आवास प्रदान करने और कार्बन पृथक्करण लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि वानिकी, संरक्षण कृषि और एकीकृत जल प्रबंधन जैसी टिकाऊ कृषि प्रथाएं मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने, सूखे के प्रति लचीलापन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में योगदान करती हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 112 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

चुनाव परिणाम

जटिल व्याख्या

चुनाव परिणाम की व्याख्या बहुत जटिल है। भारतीय राजनीति के बारे में पूर्वानुमान करना मानसून की भविष्यवाणी या अगले विश्व कप विजेता पर दांव लगाने जैसा है। आमतौर से चुनाव परिणाम परंपरागत समझ को खारिज करते हैं और वे सबसे ज्यादा चालाक राजनीति शास्त्रियों को भी आश्चर्यचकित कर देते हैं। अकेली सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भाजपा पूर्ण बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई है, जबकि 100 से थोड़ा पीछे रह जाने वाली कांग्रेस इसे ही अपनी 'नैतिक विजय' बता कर उत्सव मना रही है। कांग्रेस नीत विपक्ष ने पूरे चुनाव प्रचार में भाजपा के खिलाफ जनता में भ्रम पैदा करने तथा संविधान और लोकतंत्र के 'खतरे' में होने का शोर मचाया। वह मतदाताओं के एक हिस्से में यह भ्रम पैदा करने में भी सफल हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी 400 सीटें पाने के बाद 'आरक्षण' समाप्त कर सकते हैं। यह दुष्प्रचार इतना अधिक था कि भाजपा को रक्षात्मक स्थिति में आना पड़ा। उसने कहा कि पिछले दो कार्यकाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के बावजूद भाजपा ने आरक्षण पर यथास्थिति बनाए रखी है। भाजपा ने यह मुद्दा भी उठाया कि कांग्रेस शासित राज्यों ने एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम जातियों को शामिल कर उनको नुकसान पहुंचाया है, जबकि संविधान धर्म-आधारित आरक्षण की इजाजत नहीं देता है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने इस संबंध में उल्लेखनीय निर्णय दिया था, लेकिन संभवत: समय कम होने के कारण भाजपा अपनी बात पूरी तरह मतदाताओं तक पहुंचा नहीं पाई।

विपक्ष के दुष्प्रचार तथा कुछ अन्य कारणों से संसद में अधिकांश सीटों पर कब्जा करने के बावजूद भाजपा पिछले दो लोकसभा चुनावों की तुलना में

अपनी सीट संख्या बढ़ाने में विफल रही। इस परिघटना को अनेक आयामों से जोड़ा जा सकता है, जिसमें सत्ता-विरोधी भावनायें, मतदान पैटर्न में क्षेत्रीय विविधतायें व 'इंडिया' समूह का उभार, जनता की आर्थिक कठिनाइयां तथा अनेक अन्य चीजें शामिल हैं। विपक्ष तथा उसके समर्थक बुद्धिजीवी इसे भाजपा की 'विजय के बावजूद पराजय' बता रहे हैं। हालांकि, कांग्रेस पिछले दो लोकसभा चुनावों की तुलना में अपनी शक्ति बढ़ाने में सफल हुई है, पर लगातार तीसरी बार सत्ता से वंचित होने के बावहूद इसे वह अपनी 'नैतिक विजय' मानती है। कांग्रेस ने 'राजग' में शामिल तेदेपा नेता चंद्रबाबू नायडू तथा जदयू नेता नीतीश कुमार पर डोरे डालने के प्रयास किए, पर इन प्रयासों में विफल होने के बाद अंतत: उसने फिलहाल अपनी 'सत्ता की दावेदारी' छोड़ दी है। राजग ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता चुन लिया है और वे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस प्रकार मोदी देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे जो लगातार तीन बार सरकार बनाने में सफल हुए। चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि उनके अगले कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी तथा वे भारत को 'विकसित' देश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विडंबना है कि विपक्ष अब भी शेखचिल्ली की तरह राजग में मतभेद विकसित होने की उम्मीद में है। राजग में शामिल अन्य परिपक्व नेताओं की तरह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार 'विकसित भारत' की इस यात्रा में भाजपा के मजबूत साथी हैं। भाजपा ने तेदेपा के साथ मिल कर आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई है और नीतीश कुमार बिहार के विधानसभा चुनाव में राजग का मुख्यमंत्री चेहरा हैं। ऐसे में राजग की मजबूती पर किसी शक तथा मोदी पर सहयोगियों के 'दबाव' की कल्पना का कोई औचित्य नहीं है।

मोदी सरकार का संभावित एजेंडा

मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में परिवर्तनकारी व महत्वाकांक्षी कदम उठाएगी ताकि भारत के समक्ष उपस्थित अनेक चुनौतियों का सामना कर अवसरों का लाभ उठाया जा सके।

कल्याणी शंकर
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-राजग की सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में परिवर्तनकारी व महत्वाकांक्षी कदम उठाएगी ताकि भारत के समक्ष उपस्थित अनेक चुनौतियों का सामना कर अवसरों का लाभ उठाया जा सके। हालांकि, वर्तमान लोकसभा चुनाव परिणामों ने बहुत से लोगों को आश्चर्यचकित किया है, पर इसके पहले भी अनेक चुनावों में आश्चर्यजनक परिवर्तन सामने आए हैं। भारत का स्थायित्व इस बात पर निर्भर है कि देश में सत्ता हस्तांतरण बहुत सहज ढंग से करने की क्षमता मौजूद है। वर्तमान लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं और विजेता की घोषणा हो गई है। अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत को स्थिर सरकार की जरूरत है। इसके साथ ही विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है। भारतीय मतदाताओं ने इस बार भी मजबूत विपक्ष देने के साथ ही स्थिर व मजबूत सरकार बनाने में सफलता पाई है। लोकसभा चुनाव में सात चरणों में मतदान के बाद 4 जून को घोषित परिणामों से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि, अनेक क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन 'इंडिया' ने भी चुनावों में तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया, पर वह सत्ता से बहुत दूर रह गया है।

भारत में चुनाव परिणाम अक्सर आश्चर्यचकित करते रहे हैं। 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 'संप्रग' ने सरकार बनाई थी जो तत्कालीन भाजपा सरकार के 'इंडिया शाइनिंग' अभियान के विफल होने से संभव हुआ था। इन चुनाव परिणामों के बावजूद सत्तारूढ़ पार्टी तथा विपक्षी समूह को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दावा किया है कि उनकी पिछले दस साल की सत्ता केवल 'झांकी' थी और 'असली फिल्म' उनके तीसरे कार्यकाल में दिखाई देगी। मोदी ने कहा है, 'तीसरे कार्यकाल में बड़े निर्णयों की प्रतीक्षा करें। मैं पहले से ही ऐसे रोडमैप पर काम कर रहा हूं जिसे जल्दी पूरा किया जाएगा।'

मोदी के तीसरे कार्यकाल की महत्वाकांक्षा न केवल सभी क्षेत्रों में अपनी विरासत छोड़ना है, बल्कि वे अनेक साहसी कदम उठाना चाहते हैं। वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के तीन कार्यकाल में हुए कामों का रिकार्ड भी तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन उनकी इस महत्वाकांक्षा के समक्ष अनेक चुनौतियां भी हैं। इनमें जनता की राय और पार्टी की आंतरिक गत्यात्मकतायें भी हैं जिनसे राजनीतिक परिदृश्य काफी सीमा तक प्रभावित हो सकता है। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी के पिछले दो कार्यकालों की काफी उपलब्धियां हैं, पर 'मोदी-3' सरकार के समक्ष अनेक चुनौतियां भी होंगी। इनमें कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के दुष्प्रभावों से निपटने, सामाजिक अशांति के कुछ कारकों को संबोधित करने तथा विदेश नीति संबंधी मुद्दों से निपटने के साथ ही मतदाताओं के विविधतापूर्ण समूहों की उम्मीदें पूरी करना शामिल है। मोदी को अभी भाजपा के कुछ प्रमुख मुद्दों को लागू करना बाकी है। इन मुद्दों में 'समान नागरिक संहिता' और 'एक देश एक चुनाव' लागू करना शामिल है। इसके साथ ही भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना तथा भूमि और श्रम नीतियों में लगातार आवश्यक परिवर्तन जारी रखना भी शामिल हैं। पिछले तीन महीनों से मोदी सरकार, अगली सरकार बनने पर लागू करने वाली '125 दिवसीय योजना' पर काम कर रही थी। शुरुआत में 100 दिन की कार्ययोजना बनाई जा रही थी, पर बाद में उसका विस्तार 25 दिन और कर दिया गया। इस योजना में नौजवानों को केन्द्र में रखा गया है। इस एजेंडे में 50 से 70 प्रमुख लक्ष्य शामिल होंगे जिनको नई सरकार की दिशा और प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दिया जाएगा। इसके साथ ही मोदी के नेतृत्व में भाजपा रणनीतिक रूप से विरोधियों पर निशाना लगा सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों को बदनाम करने तथा संभवत: विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। मोदी चाहते हैं कि देश में स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय चुनाव तक सभी एकसाथ हों जिसे वे 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का नाम देते हैं। इस परिवर्तन से चुनाव व्यवस्था ज्यादा सक्षम एवं संगठित हो जाएगी। लेकिन आशंका है कि इससे सत्तारूढ़ पार्टी के हाथ में सत्ता केन्द्रित हो जाएगी तथा चुनावों की बारंबारता घट जाएगी।

मोदी ने पहले ही अपने इस प्रस्ताव के लिए जमीनी काम कर लिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति पहले ही लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एकसाथ कराने की संस्तुति कर चुकी है।

लेकिन इसके लिए परिसीमन करना होगा जिसके अंतर्गत संसदीय तथा विधानसभा चुनाव क्षेत्रों की सीमायें तय करनी होंगी। इसके पहले हर दशक में होने वाली जनगणना भी पूरी करनी होगी। परिसीमन के महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव होंगे। यह खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए महत्वपूर्ण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक शपथपत्र के अनुसार परिसीमन के बाद लोकसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान 543 के बजाय 888 तथा राज्यसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान 250 से बढ़ कर 384 हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल में संसद की नई इमारत बनवा कर यह सुनिश्चित कर दिया है कि नई संसद में इतने लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के बैठने और कामकाज करने की समुचित सुविधा होगी।

विडंबना है कि विपक्ष ने न केवल नई संसद इमारत की निर्माण परियोजना का विरोध किया था और सर्वोच्च न्यायालय तक इसके निर्माण के खिलाफ दरवाजा खटखटाया था, बल्कि उसने नई संसद के उद्घाटन में भी भाग नहीं लिया था। वैसे दक्षिण भारत को परिसीमन के बारे में चिन्ता है। दक्षिण भारतीय राज्यों में जनता द्वारा स्वैच्छिक रूप से परिवार नियोजन व्यापक रूप से स्वीकार करने के कारण उनकी जनसंख्या में कमी आई है। इसके कारण संभवत: परिसीमन प्रक्रिया के अंतर्गत दक्षिण भारत से आने वाले सांसदों की संख्या में 100 की कमी आएगी। इस समस्या के कारण 'उत्तर-दक्षिण विभाजन' जैसी स्थिति पैदा हो सकती है जिससे दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दलों में टकराव बढ़ेगा। भाजपा भारत के सभी नागरिकों पर लागू होने वाली 'समान नागरिक संहिता' पर जोर दे रही है, भले ही उनका धर्म चाहे जो हो। भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड ने इसके क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाए हैं तथा अन्य भाजपा शासित राज्य भी शीघ्र इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

भले ही समान नागरिक संहिता विभिन्न समुदायों की महिलाओं और बच्चियों को अनेक समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाली सिद्ध हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से कट्टरपंथी इसका विरोध कर रहे हैं। इससे समाज में टकराव तथा कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों का विरोध सामने आ सकता है। चुनाव अभियान में विपक्ष के अनेक नेताओं ने चिन्ता प्रकट की थी कि भाजपा संविधान में परिवर्तन कर 'पंथनिरपेक्ष' शब्द हटा सकती है। उनका आरोप था कि प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन कर 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्षता' शब्द हटा देगी जिनको 42वें संशोधन से जोड़ा गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

मोदी 'विकसित भारत' के माध्यम से भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं और इसके लिए विनिर्माण, तकनीक, ढांचागत संरचना तथा हरित ऊर्जा पर जोर देना चाहते हैं। लेकिन फंडिंग, क्रियान्वयन तथा सार्वजनिक स्वीकार्यता इसकी सफलता तथा भारतीय राजनीतिक परिदृश्य प्रभावित कर सकते हैं। विपक्षी दलों ने पिछले वर्षों में एक संयुक्त मोर्चा बनाने में सफलता पाई है। लेकिन इसके बावजूद वे तीसरी बार मोदी को सत्ता तक पहुंचने से रोकने में विफल रहे हैं। भाजपा के अपने दम पर पूर्ण बहुमत न पाने के बाद देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने राजग सहयोगियों के साथ कितनी योजनाओं को जमीनी स्तर पर मूर्त रूप देने में सफल होंगे। मोदी की सभी योजनाओं तथा नई सरकार की '125 दिवसीय' कार्ययोजना पर सबकी सहमति जरूरी होगी।

केरल सरकार की विवादास्पद मदिरा नीति

"केरल में शराब के कारोबार के राष्ट्रीयकरण के बाद, शराब पीने वालों को अपनी दैनिक शराब की खुराक पाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।"

कुमार चेलप्पन
(लेखक, दि पायनियर के वरिष्ठ संवाददाता हैं)

राज्य के सभी बार मालिकों से मांग की जा रही है कि वे सरकार के उस आदेश को रद्द करने के बजाय प्रति प्रतिष्ठान 2.5 लाख रुपए का भुगतान करें, जिसके तहत हर महीने की पहली तारीख को सभी बार बंद करने और अधिक बार होटल खोलने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। इससे यह राय स्पष्ट होती है कि केरल सरकार को शराब के कारोबार से बाहर आ जाना चाहिए।

आबकारी विभाग के कानूनों में बदलाव के लिए सत्ताधारियों द्वारा बार मालिकों से रिश्वत के रूप में अत्यधिक धनराशि की मांग के बारे में नवीनतम विवाद यह स्थापित करता है कि माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ बारी-बारी से राज्य को ठग रही हैं, यह आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में अपने चुनावी भाषणों के दौरान बार-बार लगाया है। सरकार का कारोबार करने का कोई काम नहीं है और शराब के कारोबार के मामले में तो यह और भी अधिक है। अन्य राज्यों के विपरीत, केरल और तमिलनाडु शराब की नीतियों का पालन करते हैं जो उच्च-स्तरीय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। इन दोनों राज्यों की सरकारें शराब के कारोबार में एकाधिकार रखती हैं। केरल के बेवरेजेज कॉरपोरेशन और तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन, राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाएं ही ऐसी संस्थाएं हैं जो शराब खरीद और बेच सकती हैं।

निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाले बार रेस्तरां को इन दोनों संस्थाओं द्वारा आपूर्ति की गई शराब खरीदनी चाहिए। बहुत पहले इन राज्यों में निजी शराब की दुकानें थीं जो खूब कारोबार कर रही थीं।

केरल में शराब के कारोबार के राष्ट्रीयकरण के बाद, शराब पीने वालों को अपनी दैनिक शराब की खुराक पाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें उन ब्रांडों का सेवन करने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है जो उन पर 'थोपता' है। पहले, शराब पीने वालों के पास अपने पसंदीदा ब्रांड खरीदने और पीने का विकल्प था। सरकार द्वारा शराब के कारोबार को अपने हाथ में लेने के बाद, राज्यों में बेचे जाने वाले ब्रांड सत्ता में रहने वाली पार्टी द्वारा तय किए जाते हैं और दुकानों या रेस्तराँ (बार) के माध्यम से कारोबार की जाने वाली शराब के चयन में कोई पारदर्शिता नहीं है। सत्ताधारी दलों को पैसे देने वाले शराब निर्माता ठेका लेते हैं और बैंकों पर हंसते हैं।

सरकार का दावा है कि राष्ट्रीयकरण केरल में पूर्ण शराबबंदी की शुरुआत की प्रस्तावना है। यह एक ऐसा सपना है जो तब तक साकार नहीं होगा जब तक कि अन्य राज्य शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून नहीं लाते। पड़ोसी राज्य कर्नाटक शराब पीने वालों के लिए स्वर्ग है क्योंकि निजी दुकानों पर उपभोक्ताओं द्वारा पसंद किए जाने वाले सभी लोकप्रिय ब्रांड बिकते हैं।

जबकि केरल और तमिलनाडु में देशी शराब, अरक प्रतिबंधित है, वहीं देश के बाकी हिस्सों में भी यह उपलब्ध है, जो कि मजदूर वर्ग के लिए बहुत खुशी की बात है। जो लोग सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं, उन्हें दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद थोड़ा आराम चाहिए होता है और इसलिए सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है।

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि ताड़ी सबसे पौष्टिक पेय है, शराब नहीं। तमिलनाडु ने ताड़ी निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे गरीब मजदूरों को शाम के लिए शराब खरीदने के लिए अपनी मेहनत की कमाई के साथ जाना पड़ता है। अगर इन राज्यों में अरक प्रतिबंधित नहीं होता (जहां शराब तस्करों से नकली अरक उपलब्ध है) तो मजदूरों को दिन भर की कमाई सरकारी शराब की दुकानों पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती।

यह धारणा खत्म होनी चाहिए कि शराब से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। वैज्ञानिक शोध के माध्यम से कई निष्कर्षों की पुष्टि हुई है कि मध्यम मात्रा में शराब पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। शराब के बारे में एक चीनी कहावत है: एक आदमी एक ड्रिंक लेता है। ड्रिंक और ड्रिंक लेता है। अंत में, ड्रिंक आदमी को ले जाती है। अगर अधिकारी आदमी को कम ड्रिंक पीने के लिए मजबूर कर सकें, तो यह शराब की लत का सबसे अच्छा समाधान होगा। लेकिन यह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारकर नहीं किया जाना चाहिए। हम ऐसे युग में रह रहे हैं जब भारत में बनी स्कॉच ने स्कॉटलैंड और अमेरिका में बनी स्पिरिट को पछाड़ दिया है और वैश्विक बाजार में उनके प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरे हैं।

कोलंबो और उपनगर, कोच्चि से मुश्किल से एक घंटे की हवाई यात्रा इसके विपरीत एक अध्ययन है। हालांकि श्रीलंका में कई शराब की दुकानें हैं, लेकिन इन दुकानों के सामने शराब पीने वालों की लंबी कतारें नहीं देखी जा सकती हैं। केरल उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश देवन रामचंद्रन ने हाल ही में कहा कि पीने वालों को क्ष्वङ्कष्ट्ह दुकानों से बेहतर व्यवहार की आवश्यकता है। वे सरकार का ध्यान शराब पीने वालों की दुर्दशा की ओर आकर्षित कर रहे थे, जिन्हें शाम को अपनी दैनिक शराब की खुराक लेने के लिए चिलचिलाती धूप और भारी बारिश का सामना करते हुए घंटों कतार में खड़े रहना पड़ता है। साथी पत्रकार सुनील कुमार ने कहा कि सरकार के सख्त और पुराने नियम ही लोगों को अधिक से अधिक शराब पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर महीने की पहली तारीख को शराब की दुकानों के शटर बंद करने का फैसला एक प्रतिगामी कदम है क्योंकि इससे शराब पीने वालों को अगले दिन के लिए स्टॉक करने के लिए पिछली शाम को एक अतिरिक्त बोतल खरीदनी पड़ती है। लेकिन होता यह है कि वे उसी शाम उस अतिरिक्त बोतल को पी जाते हैं और बंद वाले दिन उन्हें बेकार रहना पड़ता है। शराब पीने वालों को अपनी कोटा की शराब पीने की आजादी होनी चाहिए।

देश में पूर्ण शराबबंदी असंभव है। वरिष्ठ सांसद पीलू मोदी ने शराबबंदी पर बहस के दौरान कहा कि वे कितने भी साल शराब से दूर रह सकते हैं। लेकिन मैं शराब पीने के अधिकार के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता, पीलू मोदी ने कहा था। बेहतर समझ की जीत होनी चाहिए।

आप की बात

मोदी का जादू

लोकसभा 2024 में भाजपा की जीत दर्शाती है कि आज भी देश की जनता नरेन्द्र मोदी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहती। हालांकि भाजपा 400 का आंकड़ा नहीं छू सकी, किन्तु सत्ता में तीसरी बार आने में वह सफ्ल रही। मध्यप्रदेश की सभी 29 सीटों पर भाजपा की जीत ने विपक्षियों के चारों खाने चित कर दिया। असल में भाजपा की यह जीत भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाए जाने की भावना से जुड़ी है। तमाम तरह के वादों-दावों के बाद भी इंडिया गठबंधन सत्ता तक नहीं पहुंच सका। श्रीराम मंदिर, धारा 370 समाप्त करने तथा अन्य प्रभावी मसलों ने देश की जनता को तो एक सीमता तक प्रभावित किया, पर वह जातीय गणित तथा सत्ता तक पहुंचने के लिए मुस्लिम वोटबैंक के प्रयोग को रोक नहीं सकी। अनेक वंशवादी व परिवारवादी राजनेता आज भी सत्ता पाने के लिए विभिन्न हिंदू जातियों को आपस में लड़ा कर तथा मुस्लिम जातियों से गठजोड़ कर सत्ता तक पहुंचने में सफल होते हैं। ऐसे में मोदी के जादू को विस्तार देने के लिए देश में अनेक नए आयामों पर भी विचार करना पड़ेगा क्योंकि सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भाजपा को वोट देने के बजाय जातियों, संप्रदायों और स्थानीय नेताओं के गिरोहों में बंट जाते हैं।

-**अंकित सोनी,** मनावर

चुनाव नतीजे के सबक

चुनावी नतीजे में एनडीए की सीटें कम आने में विपक्षी दालों के परिश्रम से अधिक संभवत: भाजपा कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता तथा कहीं-कहीं उसका भीतरघात जवाबदेह है। उत्तर प्रदेश में अति आत्मविश्वासके साथ-साथ कुछ सीटों पर भारी असंतोष के बावजूद उम्मीदवारों को थोपा गया जिससे जमीनी कार्यकर्ता नाराज हुए। भाजपा द्वारा पहले ही अबकी बार चार सौ पार के नारे से कार्यकर्ता जीत पक्की मान कर शिथिल हो गए। लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों की जनता और मतदाताओं ने बिना बहकावे में आए मजबूत राष्ट्र के लिए भाजपा को एकतरफा वोट वोट दिए। आश्चर्य है कि गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल और उम्मीदवार बार-बार बदलने वाली भाजपा ने उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में अनेक नाकारा, अलोकप्रिय तथा मेहनत न करने वाले सांसदों के टिकट नहीं काटे। इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा। भाजपा और आरएसएस को चुनाव नतीजे से कई सबक लेने होंगे। हिंदूवाद अब भी जातीय विभाजनों को समाप्त करने में सफल नहीं हुआ है तथा अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले खासकर अल्पसंख्यकों ने भाजपा को वोट नहीं दिए।

– **सुभाष बुड़ावन वाला,** रतलाम

कन्हैया की पराजय

दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर कांग्रेस नेता और पूर्व-कम्युनिस्ट कन्हैया कुमार की पराजय उल्लेखनीय घटना है। इस सीट पर भाजपा ने शुरू से ही बढत बना ली थी। लगातार बढ़त को देखकर कन्हैया कुमार ने भी अंदाज लगा लिया कि अब उनकी दाल यहां गलने वाली नहीं है। कन्हैया पर हमेशा बढ़-चढ़ कर बोलने का आरोप लगता रहा है। देश तोड़ने जैसे नारे लगाने वालों से भी उनकी दोस्ती रही है। जनता आज भी यह सब नहीं भूली है। कन्हैया कुमार जैसे लोग जहां से भी जिस भी पार्टी में चुनाव लड़ेंगे, इनका यही हाल होगा। देश का हर व्यक्ति जानता है कि कन्हैया कुमार ने देश के खिलाफ बोलने वालों का साथ दिया है और स्वयं भी उनमें शामिल रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे-इंशाअल्ला इंशाअल्ला जैसे नारे लगाने वालों को भले ही किसी समय में बर्दाश्त कर लिया जाता हो, पर आज भारत बदल गया है और ऐसे लोगों व उनके समर्थकों को स्वीकारने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में कन्हैया जैसे लोगों को सार्वजनिक जीवन में रहने के लिए जरूरी है कि वे अपने पुराने कृत्यों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। हो सकता है कि देश की जनता अच्छा आचरण करने पर उनके पुराने गुनाह माफ करने पर विचार करे।

– **मनमोहन राजावत,** शाजापुर

गठबंधन सरकार

लोकसभा चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। भाजपा बहुमत का जादुई आंकड़ा छूने से दूर रह गई है । फिर भी वह सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई है। इसके परिणामस्वरूप 10 वर्ष बाद पुन: गठबंधन सरकार बनने जा रही है। भाजपा को अपने गठबंधन साथियों के साथ कदम मिला कर चलना होगा तथा संतुलन बनाए रखना होगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लचीलेपन तथा सबको साथ लेकर चलने की असल अग्निपरीक्षा होगी । जब भाजपा पूरी तरह से अपने दम पर बहुमत में थी तो कोई भी फैसला लेना बहुत ही आसान था। ऐसे में अच्छा होगा कि गठबंधन सरकार जनता के जमीनी मुद्दों पर भी ज्यादा ध्यान दे। गरीबी, महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, महंगी व बदहाल होती शिक्षा व्यवस्था तथा खराब स्वास्थ्य व्यवस्थायें सुधारने को प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए। अधिसंख्य जनता को सार्वजनिक सरकारी स्कूलों व अस्पतालों की अधिक दरकार होती है। स्कूलों और अस्पतालों की हालत सुधारने को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर गठबंधन सरकार देश के साथ ही जनता का विकास सुनिश्चित करेगी।

– **हेमा हरि उपाध्याय,** उज्जैन

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 96

नैसर्गिक राजनीतिक व्यवस्था

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लोक सभा चुनावों में बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई है और इस बात ने अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों को आश्चर्यचकित किया है। खासतौर पर इसलिए कि किसी भी एक्जिट पोल या ओपिनियन पोल में ऐसी संभावना नहीं जताई गई थी। हालांकि राज्यों के राजनीतिक हालात के आधार पर चुनाव नतीजों का अलग-अलग पहलुओं से विश्लेषण किया जा रहा है लेकिन यह कहा जा सकता है कि केंद्र में गठबंधन की सरकार देश की नैसर्गिक राजनीतिक व्यवस्था का अंग है और बीते 10 वर्ष इस लिहाज से थोड़ा अलग थे। बीते 10 वर्षों को छोड़ दिया जाए तो सन 1989 से ही देश में गठबंधन की सरकारें रही हैं। उससे पहले 1984 में कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला था लेकिन 1989 में पार्टी हार गई थी। बीते दो आम चुनावों की प्रकृति कुछ अलग थी। भाजपा को 2014 में महत्त्वपूर्ण जीत मिली थी और उस चुनाव में जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया था। 2019 में पुलवामा और बालाकोट के बाद पार्टी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और मजबूत जीत हासिल की। इस बार अपेक्षाकृत सामान्य चुनाव में पार्टी सामान्य बहुमत से पीछे रह गई। इस चुनाव में शासन और स्थानीय मुद्दे प्रमुख थे। बहरहाल, भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) आराम से सरकार बनाने की स्थिति में है।

देश के राजनीतिक मानचित्र पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि हालात केंद्र में गठबंधन सरकार के अनुकूल रहे हैं। देश में 11 ऐसे राज्य हैं जहां क्षेत्रीय दलों की महत्त्वपूर्ण उपस्थिति है-उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पंजाब, जम्मू-कश्मीर तथा केरल (यदि वाम को क्षेत्रीय ताकत माना जाए)। इन राज्यों में 347 लोक सभा सीट हैं। अन्य 10 राज्य ऐसे हैं जहां राज्यस्तरीय दलों का पराभव हुआ है या उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये राज्य हैं-कर्नाटक, तेलंगाना, असम, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन राज्यों में 169 लोक सभा सीटें हैं। कुल मिलाकर इन सभी राज्यों में 500 से अधिक सीटें हैं। ताजा परिणाम दिखाते हैं कि कांग्रेस ने दूसरी श्रेणी के कुछ राज्यों में भाजपा को चुनौती देने का तरीका तलाश लिया है। कांग्रेस का पराभव भी भाजपा के बहुमत तक पहुंचने की एक वजह थी। समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और लोक सभा में भाजपा को बहुमत नहीं मिलने देने में उसकी भी अहम भूमिका रही है। ऐसे में देश के राजनीतिक हालात को देखते हुए भाजपा को अब अपने हिंदुत्ववादी बयानों को नियंत्रित करना होगा ताकि क्षेत्रीय दल उसके साथ बने रहें। अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला जनता दल यूनाइटेड समय पर साथ नहीं आया होता तो भाजपा के लिए हालात बहुत मुश्किल हो जाते। कांग्रेस की क्षेत्रीय दलों में स्वीकार्यता बढ़ी है तथा वह उनके लिए जगह खाली करने की इच्छुक है। यह बात भी बताती है कि गठबंधन देश में प्राकृतिक हैं।

वित्तीय बाजारों में तथा अन्य स्थानों पर यह चिंता है कि केंद्र में गठबंधन की सरकार होने से सुधार प्रभावित होंगे, लेकिन इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि गठबंधन सरकारें सुधारों के क्रियान्वयन के मामले में बेहतर साबित हुई हैं।

वास्तव में राजग सरकार में जनता दल यूनाइटेड और तेलुगू देशम पार्टी के रूप में दो क्षेत्रीय दलों की मौजूदगी के कारण केंद्र और राज्यों के बीच रिश्ते और सहज होने चाहिए। सरकार में क्षेत्रीय दलों की इस प्रकार मौजूदगी से जरूरी सुधारों को लेकर सहमति बनाने में मदद मिलेगी। काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि नई राजग सरकार इसे लेकर किस प्रकार आगे बढ़ती है।

चुनाव नतीजों के मुताबिक बदलाव की जरूरत

आम चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो देश के मतदाताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं बल्कि समावेशी वृद्धि चाहते हैं। बता रहे हैं अजय छिब्बर

हालिया आम चुनाव से दो अहम संकेत निकले हैं: पहला, विभाजनकारी, ध्रुवीकरण की राजनीति कारगर नहीं है। इस बात का संकेत तो इसी बात से मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या (फैजाबाद) की सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा जहां बाबरी मस्जिद विध्वंस स्थल पर राम मंदिर बनाया गया है। दूसरा, देश में अधिक समावेशी वृद्धि मॉडल की आवश्यकता है। देश प्रगति कर रहा है लेकिन हमारा वृद्धि मॉडल टिकाऊ नहीं नजर आता है। कृषि और विनिर्माण क्षेत्र जूझ रहे हैं। सेवा क्षेत्र के कई हिस्से खासकर आईटी से संबद्ध हिस्से (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बढ़ती तादाद के साथ) जरूर बेहतर काम कर रहे हैं। बहरहाल, सीमित रोजगार की वजह से बड़ी तादाद में लोग कृषि क्षेत्र में फंसे हुए हैं और असमानता तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निराशा बढ़ती जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था को अरबपति राज कहा जा रहा है। अगर इन हालात में सुधार नहीं हुआ तो देश की बढ़ती युवा आबादी की बेरोजगारी और ग्रामीण संकट तथा बढ़ती असमानता भारी पड़ेगी। मैं तीन अहम सुधारों का सुझाव देता हूं।

पहला है कृषि सुधार। पिछले कार्यकाल में सरकार ने कृषि क्षेत्र की आय दोगुनी करने का वादा किया था लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। उसने नए कृषि कानून लाने का प्रयास किया लेकिन किसानों के तीक्ष्ण विरोध के बीच उन्हें वापस लेना पड़ा। इसके बजाय सरकार को किसानों के समक्ष भविष्य की एक स्पष्ट योजना पेश करनी चाहिए। शांता कुमार आयोग ने ऐसा एक विजन प्रस्तुत भी किया था लेकिन उसे अज्ञात वजहों से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब सरकार फंस गई है क्योंकि उसने पांच साल तक मुफ्त राशन का वादा किया है। अब वह भारतीय खाद्य निगम की सरकारी खरीद पर आधारित इस महंगी योजना को चालू रखने के लिए विवश है। इसके साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी जारी रखना होगा।

मेक्सिको और तुर्किये जैसे मध्यम आय वाले अन्य देशों की तरह भारत को भी समर्थन मूल्य तथा कच्चे माल जैसे कि उर्वरक, बिजली, कीटनाशक आदि पर सब्सिडी से दूरी बनानी चाहिए। इनकी वजह से कृषि क्षेत्र पांच दशक पहले के हालात में अटक गया है। इसकी जगह सरकार को पीएम किसान में इजाफा करना चाहिए, हर प्रकार की सब्सिडी समाप्त करनी चाहिए और किसानों को अपने फसल मिश्रण में बदलाव के लिए स्वतंत्र करते हुए उन्हें अपनी जमीन का उत्पादक इस्तेमाल करने देना चाहिए। भारत की खपत में इजाफे को देखते हुए फल और सब्जियों, तिलहन तथा दालों की और अधिक आवश्यकता है जबकि अनाज और गन्ने की कम। एमएसपी की व्यवस्था के कारण फसल का मिश्रण गैर किफायती और अनुत्पादक हो गया है। इसके चलते भूजल स्तर प्रभावित हो रहा है और जमीन की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। सीएसडीएस-लोकनीति का एक सर्वेक्षण दिखाता है कि केवल 26 फीसदी किसान खेती का काम जारी रखना चाहते हैं और उनमें से भी अधिकांश ऊंची एमएसपी के बजाय सीधे अपने बैंक खाते में पैसे चाहते हैं।

दूसरा, भारत कारक बाजार सुधारों से भी बच नहीं सकता है। देश के श्रम कानूनों की बात करें तो जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि वे श्रमिक विरोधी हैं क्योंकि वे लोगों को काम पर रखने को हतोत्साहित करते हैं। हमारा फ्लोर एरिया अनुपात दुनिया में सबसे कम है और हम जमीन का किफायती इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जटिल श्रम कानूनों से बचने के लिए कंपनियां पूंजी पर अधिक ध्यान देती हैं और अनुबंधित दैनिक श्रमिकों से काम लेती हैं। दुनिया में सबसे अधिक दैनिक मजदूर भारत में हैं। हमारे यहां ढेर सारी जमीन गैर किफायती छोटी जोत में फंसी है। अधोसंरचना सुधरी है लेकिन पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है, उत्पादकों को बिजली महंगी पड़ती है और हमारा रेल माल भाड़ा भी दुनिया में सबसे अधिक है। इससे उत्पादन और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल होता है। ईंधन को अगा जीएसटी व्यवस्था के 28 फीसदी के उच्चतम स्लैब में लाया जाए तो अब की तुलना में इनकी कीमत में कमी आएगी। इससे हम चीन का मुकाबला कर पाएंगे जहां ईंधन हमसे 30 फीसदी सस्ता है।

विभिन्न उत्पादकों के लिए बिजली कीमतों की बात करें तो यह उन्हें 30 फीसदी महंगी पड़ती है और मालभाड़ा भी चीन से तीन गुना अधिक है। इन्हें कम करने से हमारा विनिर्माण अधिक प्रतिस्पर्धी होगा। कीमतों को इस प्रकार तार्किक बनाने से देश का विनिर्माण अधिक बेहतर बनेगा। सेवा क्षेत्र की भांति देश के जनांकिकीय लाभांश का भी फायदा उठाना होगा। इसके लिए हमें प्रतिस्पर्धी श्रम, गहन विनिर्माण और निर्यात पर जोर देना होगा।

तीसरा, चीन ने सन 1995 में अहम प्रशासनिक सुधार किए और अपनी सरकार का आधुनिकीकरण किया। मलेशिया ने भी सन 2000 के आसपास ऐसा ही किया। भारत में ऐसे सुधार नहीं हुए और हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी 19वीं सदी की प्रशासनिक और विधिक व्यवस्था से संचालित है। ई-सेवाएं और आधार ने कुछ सेवाओं और सब्सिडी की आपूर्ति में मदद की है लेकिन बुनियादी प्रशासनिक ढांचा दिक्कतदेह बना हुआ है। इसके निचले स्तर पर बहुत बड़ी तादाद में कर्मचारी हैं और जटिल नियमन और प्रक्रियाओं के साथ विवेकाधीन शक्तियां भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। इसमें बदलाव जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनैशनल के अनुसार भारत के नागरिकों ने साल 2021 में एशिया में सबसे अधिक रिश्वत दी। यहां रिश्वत का स्तर बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी अधिक रहा। इसके साथ ही सरकारी संस्थानों को कमजोर करके राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ काम पर लगाना भी कारगर नहीं। न्याय का पहिया बहुत धीमा घूम रहा है। न्याय में देरी का अर्थ है न्याय का न होना।

स्थानीय स्तर पर काम का बंटवारा करने की आवश्यकता है। महापौरों को अधिकार संपन्न बनाए बिना स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति नहीं की जा सकती है और शहरीकरण की स्थिति गड़बड़ बनी रहेगी। स्मार्ट सिटी कार्यक्रम इन समस्याओं का हल नहीं हैं। देश के शहर अधिकार संपन्न शासन से बेहतर बनेंगे। 16वें वित्त आयोग के माध्यम से अगर स्थानीय प्रशासन को संसाधन देने के मसले को हल किया जाए तो बेहतर होगा। शहरों में उच्च संपत्ति कर का प्रयोग भी मददगार हो सकता है जैसा कि चेन्नई में किया गया। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए शहरी सरकारों और गांव के सरपंचों को भी अधिक अधिकारों की आवश्यकता है।

गांधी जी ने उचित ही कहा था कि हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर है कि हम आज क्या करते हैं। कुछ लोग कहेंगे ऐसे बड़े सुधार अगले पांच वर्षों में गठबंधन सरकार के कार्यकाल में संभव नहीं होंगे। बहरहाल, अतीत बताता है कि हमने गठबंधन सरकारों के दौर में ही बड़े और साहसी सुधार किए हैं। भारत को बेरोजगारी, ग्रामीण संकट से निपटते हुए समावेशी वृद्धि की प्रक्रिया को अपनाना होगा ताकि रोजगार तैयार हो सकें। मतदाता भी संभवतः यही चाहते हैं।

(लेखक जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनैशनल इकनॉमिक पॉलिसी के प्रतिष्ठित विजिटिंग स्कॉलर हैं)

देश में स्टार्टअप क्षेत्र की प्रेरणादायक शख्सियतों की खलती कमी

वर्ष 2015 के 'बिजनेस इनसाइडर' के एक लेख के मुताबिक एडविन लैंड से मिलना स्टीव जॉब्स के लिए किसी तीर्थस्थल पर जाने जैसा ही था। लैंड ने वर्ष 1937 में पोलरॉयड कॉरपोरेशन की स्थापना की थी और उन्होंने इंस्टैंट फोटोग्राफी की शुरुआत की थी। वह अपने दौर के स्टीव जॉब्स ही थे। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर एक ऐसे उत्पाद की कल्पना की जिसकी जरूरत के बारे में खरीदारों को भी अंदाजा नहीं था।

वर्ष 2011 में न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख के मुताबिक उन्होंने 1960 के दशक में पोलरॉयड के शेयरधारकों की बैठक बेहद नाटकीय तरीके से आयोजित की जिसके लिए कला-निर्देशकों ने सेटिंग तैयार की थी और इसमें लाइव म्यूजिक तक था (बाद में जॉब्स ने इसे एक कला में बदल दिया)। हालांकि अगर तीर्थस्थल वाले संदर्भ को गंभीरता से लिया जाए तब यह कहा जा सकता है कि जॉब्स उनके मुरीद थे।

लेकिन जॉब्स के चाहने वाले भी कम नहीं थे। जॉब्स का निधन अक्टूबर 2011 में 56 वर्ष की आयु में हो गया लेकिन दुनिया भर के स्टार्टअप संस्थापकों द्वारा पहने जाने वाली बंद गले की शर्ट और जींस में उनकी यादें जिंदा हैं, भले ही इनमें से कई उनकी दूरदर्शिता और काम करने के तरीके को लेकर अनुसरण करने में सफल नहीं रहे हैं।

अमेरिका में केवल जॉब्स ही स्टार्टअप क्षेत्र के प्रेरणास्रोत नहीं हैं। जॉब्स के बड़े प्रतिद्वंद्वी बिल गेट्स भी एक महत्त्वपूर्ण ताकत बने हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट के बिना कोई ओपनएआई नहीं होता, हालांकि अब माइक्रोसॉफ्ट का चेहरा मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) सत्य नाडेला हैं। वहीं 1970 के दशक में ओरैकल की शुरुआत करने वाले लैरी एलिसन इस वर्ष के टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे अधिक प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल हैं।

इंटरनेट के दौर वाली पीढ़ी में गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन मजबूती से बने हुए हैं। जेफ बेजोस की ई-कॉमर्स कंपनी, एमेजॉन दुनिया में 'सभी चीजों' के लिए सबसे बड़ा स्टोर बना हुआ है और इसका विस्तार अब नए क्षेत्रों जैसे कि क्लाउड में भी हो रहा है। वहीं इनसे भी युवा मार्क जुगरबर्ग ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप की कमान संभाली हुई है और अब उन्होंने मेटा के साथ अपनी स्थिति को बेहतर बनाया है।

इसके अलावा एक पेपल माफिया है और यह जुमला उन निवेशकों और उद्यमियों के लिए है जो पेपल से निकले हैं और जिसे पीटर थिएल और मैक्स लेवचिन ने बनाया और बेचा। पेपल ने ऑनलाइन भुगतान पेशकश कर इंटरनेट की दिशा बदल दी। इंटरनेट पर कई मशहूर नामों का वास्ता पेपल माफिया से है जिनमें फेसबुक, यूट्यूब और स्पेसएक्स तक शामिल है। थिएल, वर्ष 2012 में स्टैनफर्ड में स्टार्टअप से जुड़ा एक कोर्स पढ़ाया करते थे और वह अमेरिका की सिलिकन वैली में एक बड़ी ताकत हैं।

सुवीन सिन्हा

यह सूची असीमित है और यह बिल ह्यूलिट और डेविड पैकर्ड की कहानी के बिना अधूरी रहेगी। दोनों कॉलेज के दिनों के दोस्त थे और उन्होंने एक गैराज में कंप्यूटर कंपनी एचपी की शुरुआत की थी। महज 12 गुना18 फुट के गैराज को सिलिकन वैली का जन्मस्थान माना जाता है। यह जगह अब भी स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी के नजदीक अपने मूल स्थान पर पेड़ों की कतार से लगी सड़क पर मौजूद है।

प्रेरणास्रोत

ये सभी और कुछ और (सबका नाम इस स्तंभ में शामिल करना संभव नहीं) ने उद्यमियों की पीढ़ियों को न केवल अमेरिका में प्रेरित किया है बल्कि दुनिया में भी इसका प्रभाव देखा गया। उन्होंने अमेरिका को सबसे अधिक उद्यमियों वाले देशों की सूची में शीर्ष पर रखे जाने में अहम भूमिका निभाई है जो नवाचार और नई तरह के विचारों का प्रमुख केंद्र है। अब ऐसे में सवाल यह है कि भारत में स्टार्टअप की आकांक्षा को जगाने वाला प्रकाशस्तंभ कौन है और ऐसे महत्त्वाकांक्षी संस्थापक कौन हैं जिन्हें रोल मॉडल माना जाता है?

भारत हमेशा से उद्यमियों का देश रहा है। लेकिन अगर हम भारत की पहली पीढ़ी के आधुनिक, इंटरनेट संचालित, उपभोक्ताओं वाले स्टार्टअप पर नजर डालें तो कुछ नाम स्वतः ही उभरकर सामने आते हैं जिनमें फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, पेटीएम के विजय शेखर शर्मा, बैजूस के बैजू रवींद्रन, स्नैपडील के कुणाल बहल और रोहित बंसल, ओयो के रितेश अग्रवाल, फ्रीचार्ज के कुणाल शाह, रेडबस के फणींद्र समा और ओला के भवीश अग्रवाल का नाम शामिल है।

भवीश की रफ्तार अब थमती नहीं दिख रही है। वह अब एक, दो नहीं बल्कि तीन यूनिकॉर्न के संस्थापक बनकर अपनी स्थिति और बेहतर बना चुके हैं। उन्होंने अपने खाते में एक इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक और आर्टिफिशल स्टार्टअप 'कृत्रिम' को जोड़ा है। स्टार्टअप क्षेत्र के अधिकांश लोगों को भी अटूट समर्थन मिलता है और उनके प्रशंसक वर्ग हैं। उदाहरण के तौर पर शाह, सीआरईडी (क्रेड) के साथ एक नया मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर हैं। उनके एक्स अकाउंट पर 881,700 फॉलोअर हैं और उनके द्वारा पोस्ट की गई कोई भी चीज वायरल हो जाती है ('इंजीनियर डॉक्टर की नौकरी खा सकते हैं', 25 मई को पोस्ट किया गया जिसमें 3,500 लाइक मिले, इस पोस्ट को 547 बार रिपोस्ट किया गया और 685 जवाब दिए गए)। यही चीजें अन्य लोगों के साथ भी है। इनमें से कई अन्य स्टार्टअप में निवेशक के तौर पर भी व्यस्त हैं। लेकिन क्या हमारे पास जॉब्स, गेट्स, जुकरबर्ग, या थिएल जैसा कोई व्यक्ति है? इसका जवाब फिलहाल स्पष्ट नहीं है।

संस्थापकों की तकदीर

फ्लिपकार्ट अब वॉलमार्ट की कंपनी है। स्नैपडील छोटी हो गई है, शॉपक्लूज लगभग गायब हो चुकी है। पेटीएम को नियामकों की सख्ती के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बैजूस की भी अपनी परेशानियां हैं।

हाल ही में रितेश अग्रवाल ने एक्स पर कहा कि वित्त वर्ष 2024 ओयो के लिए पहले शुद्ध लाभ वाला वित्त वर्ष साबित हुआ है और वित्त वर्ष 2025 अधिक शानदार होगा। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि उत्तरी यूरोप के देशों, दक्षिण पूर्व एशिया, अमेरिका और ब्रिटेन में भी वृद्धि की बात की। हमें यह देखना होगा कि यह किस तरह नजर आता है। ओयो के अब तक सार्वजनिक निर्गम लाने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं।

वास्तव में, भारत के कई स्टार्टअप संस्थापकों ने अपने लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। सूत्रों का कहना है कि गुड़गांव में बन रहे बेहद लक्जरी घरों में देखी जा रही तेजी में स्टार्टअप संस्थापकों की ढेर सारी बुकिंग का भी योगदान है। लेकिन उन्होंने जिन स्टार्टअप की स्थापना की वे स्थायी रूप से सफल नहीं हुए हैं और ऐसा लगता है कि स्थायी तौर पर लंबी अवधि में बने रहने की संभावना भी नहीं है। ऐसा इसलिए है कि कुछ भारतीय स्टार्टअप मूल विचारों के साथ नहीं बनते हैं? सही या गलत, कुछ लोगों को यह कहना अच्छा लगता है कि एमेजॉन और उबर जैसी कंपनियां ही मूल कंपनियां थीं।

हालांकि, चीजें जल्दी बदल सकती हैं। मुमकिन है कि पेटीएम और बैजूस वापसी करें। स्टीव जॉब्स की वापसी से पहले ऐपल भी लगभग बंद होने की स्थिति में आ गया था। ऊबर और एमेजॉन को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सचिन बंसल, नवी स्टार्टअप के साथ वित्तीय क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। ऐसे में मुमकिन है कि हमें अपने देश में ही स्टार्टअप के महत्त्वपूर्ण प्रेरणादायक शख्सियत मिल जाएं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आपका पक्ष

तालाबों को गहरा और चौड़ा करना समय की जरूरत

मध्य प्रदेश में 5 जून (पर्यावरण दिवस) से 15 जून तक जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत जल संरचनाओं को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उन्हें समाज के लिए संरक्षित किया जाएगा। इस प्रकार का अभियान देशभर में चलना चाहिए। असल में, ऐसी मुहिम के जरिए तालाबों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। जलसंकट हल करने के लिए समय रहते वर्षा जल को तालाबों के माध्यम से सहेजने के प्रयास करने होंगे। अभी जो प्रयास हो रहे हैं वे महज कागजी खानापूर्ति हैं। यही कारण है कि तालाबों में पानी का नामोनिशान नहीं है। समय की आवश्यकता को देखते हुए न केवल नए तालाब बनाना जरूरी है, अपितु पुराने और अनुपयोगी तालाबों का भी सीमांकन, गहरा करना और जीर्णोद्धार जरूरी है। पुराने तालाबों का अस्तित्व फिर से लौटाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जन-भागीदारी समितियों की तालाब निर्माण और रखरखाव में महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। पंचायतों की सक्रियता, मनरेगा के माध्यम से शासन के सहयोग और जनभागीदारी से मृतप्राय तालाबों का कायाकल्प किया जा सकता है। जब से लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए तालाबों को पाटना शुरू किया, इनके बुरे दिन शुरू हो गए और वे मैदान बनते चले गए। इसके अलावा तालाबों के आसपास अतिक्रमण हो रहा है। भू-माफिया वहां नई- नई कालोनियां बना रहे हैं तथा तालाबों में पानी की आवक के स्रोतों को बंद कर देते हैं। ऐसे में तालाब पूरी तरह भर नहीं पाते और समय से पहले सूख जाते हैं। इंसानी स्वार्थ इतना हावी हो जाता है कि जनहित की बलि दे दी जाती है। जब तालाब की गहराई और चौड़ाई बढ़ेगी तो उसमें जल संग्रहण की क्षमता बढ़ेगी। परिणामस्वरूप वर्षभर पानी रहेगा।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पर्यावरण के प्रति अब लोगों का जागरूक होना जरूरी हो गया है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के सामने कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाएंगी

पर्यावरण के प्रति होना होगा जागरूक

5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। अगर हमारे पूर्वजों ने पौधे न लगाए होते और आज की तरह वृक्षों को धड़ाधड़ काटते रहते तो क्या आज हमें पेड़ों से मिलने वाला सुख मिल रहा होता। अगर आज हम पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो क्या आने वाली पीढ़ी स्वच्छ पर्यावरण में जी सकेगी। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने स्टॉकहोम (स्वीडन) में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दुनिया भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। पर्यावरण संभालने के लिए विश्वव्यापी संस्थाएं काम कर रही हैं। साल 1963 में जैव समस्याओं के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय जैव कार्यक्रम शुरू हुआ था। पृथ्वी हमें निःस्वार्थ भाव से जीवन की सभी आवश्यक चीजें देती हैं मगर हमलोग नासमझ की तरह इसे नुकसान पहुंचाते हैं। महात्मा गांधी ने पर्यावरण और सतत विकास पर कहा था कि आधुनिक शहरी औद्योगिक सभ्यता में ही उसके विनाश के बीज निहित हैं। अभी भी वक्त है इंसान अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद कर दे और पेड़-पौधों की रखवाली करने लगे तो पर्यावरण को संभाला जा सकता है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

तमिलनाडु में मामल्लपुरम के पास खुदाई के दौरान प्राचीन मुरुगन मंदिर मिला है। इस मंदिर के संरक्षण कार्य में जुटे श्रमिक।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

सुधारनी होगी भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग

भारत में इंजीनियरिंग शिक्षण के शीर्ष संस्थान आइआइटी बॉम्बे ने दुनिया के 150 संस्थानों में जगह बनाते हुए पिछली 149वीं रैंक में सुधार करते हुए 118 वां स्थान हासिल कर लिया है। ऐसा ही सुधार आइआइटी दिल्ली ने भी किया है जो पिछली 197वीं रैंक से 150 वीं रैंक पर आने में कामयाब हुआ है। निश्चित ही यह माना जाना चाहिए कि खास तौर से इंजीनियरिंग व प्रबंध पाठ्यक्रमों में हमारे देश के संस्थानों का नंबर वैश्विक स्तर के संस्थानों में आने लगा है।

दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करने वाली संस्था 'क्यूएस वर्ल्ड ' जब रैंकिंग के आंकड़े जारी करती है तब ही हमारे यहां इन संस्थानों की चर्चा होकर रह जाती है। ज्यादा से ज्यादा हमारे आइआइटी और प्रबंध संस्थान इस स्पर्धा में आगे आएं इस पर विचार शायद ही कोई करता हो। दुनिया के शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों में जब हमारे देश के संस्थानों का नाम आता है तो गौरव की अनुभूति होना स्वाभाविक है। लेकिन चिंता इस बात की भी है कि चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो या फिर आइआइटी रुड़की, आइआइटी इन्दौर हो अथवा फिर विश्वविद्यालयों में बीएचयू हो या जेएनयू, घूम फिर कर ये कुछ संस्थान ही वैश्विक रैंकिंग में जगह बना पाते हैं। ये संस्थान अपनी गुणवत्ता न केवल बनाए हुए हैं बल्कि इनमें सुधार करते हुए रैंकिंग के पायदान में भी ऊपर की जगह बनाते जा रहे हैं। मद्रास, खड़गपुर व कानपुर आइआइटी के प्रदर्शन को भी इसी रूप में देखा जा सकता है। लेकिन कुछ और संस्थान भी इस सूची में जुड़ें तो न केवल भारतीय बल्कि विदेशी छात्रों को भी इनकी ओर आकर्षित किया जा सकता है। अभी तो स्थिति यह है कि बड़ी संख्या में हमारे छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए दुनिया के दूसरे देशों का रुख करना पड़ता है। विदेश में उच्च शिक्षा को लेकर आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि विदेश में शिक्षा के लिए भारतीय विद्यार्थियों का खर्च लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अच्छे शिक्षक और अनुकूल शैक्षणिक माहौल हो तो हमारे बच्चों को इस तरह से दुनिया के दूसरे देशों में जाने की भला जरूरत ही क्यों पड़े? विदेश जाने के बाद इनके फिर से भारत का रुख करने की उम्मीद कम ही होती है।

देश में निजी विश्वविद्यालय खूब हैं पर इनके हाल किसी से छिपे नहीं। ज्यादातर का ध्यान पांच सितारा होटलों जैसी इमारतें दिखा मनमानी फीस वसूली पर रहता है। जाहिर है, हमें वैश्विक रैंकिंग में सम्मानजनक स्थान पाने वाली शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ानी होगी। उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाने के साथ इनको वैश्विक स्तर के बनाने पर जोर देना होगा।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज : लोगों में जागरूकता बढ़ाने से बीमारियों पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी

देखभाल कर खाएं, सेहत को बेहतर बनाएं

भागीरथ चौधरी
संस्थापक निदेशक, साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, जोधपुर
@patrika.com

भारत की 140 करोड़ आबादी को सुरक्षित, पौष्टिक और किफायती भोजन उपलब्ध कराना ही राष्ट्र के लिए असली खाद्य सुरक्षा है। भोजन सुरक्षित है या नहीं, इसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए।

हाल ही भारत से निर्यातित मसालों के कुछ नमूनों में हांगकांग और सिंगापुर में एथिलीन ऑक्साइड (ईटीओ) गैस के कुछ अंश पाए जाने की खबरें सुर्खियों में रहीं। इन खबरों ने कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग और खाद्य सुरक्षा से संबंधित सरकारी संस्थानों पर सवालिया निशान खड़े किए।

भारतीय कृषि खाद्य उत्पादन के नए आयाम स्थापित किए हैं। भारत ने 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन में 330 मिलियन टन और बागवानी में 350 मिलियन टन का रेकॉर्ड उत्पादन किया। बढ़ते खाद्य और बागवानी उत्पादन के साथ भारत वैश्विक खाद्य व्यापार में 50 बिलियन अमरीकी डॉलर का खाद्य निर्यात कर वैश्विक खाद्य सुरक्षा में अहम योगदान दे रहा है। विडम्बना यह है कि खाद्य पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता होते हुए भी भारत के लोग खाने की गुणवत्ता, भोजन में पौष्टिक तत्वों की मात्रा और सुरक्षित भोजन से कोसों दूर हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को हंगर इंडेक्स के 125 देशों में 111वां स्थान दे कर देश में भूख की गंभीरता को दर्शाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में आज भी तकरीबन 22.4 करोड़ लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है और वे कुपोषण का शिकार हैं। हालांकि भारत की सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 की रिपोर्ट का हवाला देकर देश में गरीबी और पोषण संकेतकों में काफी सुधार की पुष्टि की है।

खाद्य सुरक्षा की उपयोगिता को समझते हुए पिछले कुछ वर्षों में भारत और राज्य सरकारों ने असुरक्षित भोजन और कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता देकर कई योजनाओं को लागू किया है। सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर बायोफोर्टिफाइड बीजों की किस्में जैसे कि आयरन और जिंक संवर्धित बाजरा, हाई ओलेक सरसों और मूंगफली को विकसित करने से लगाकर, मोटे अनाज और न्यूट्री सीरियल्स के प्रचलन, फोर्टिफाइड चावल और मिशन पोषण 2.0 के माध्यम से अनुशंसित आहार सेवन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खाद्य जनित रोग, असुरक्षित भोजन और कुपोषण की इन ज्वलंत समस्याओं का हल अकेले सरकार नहीं कर सकती और इसके लिए हम सब को मिल कर गंभीर प्रयास करने होंगे।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस एक महत्त्वपूर्ण अवसर है, जिसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुमोदन के बाद हर वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है,जिसका उद्देश्य सुरक्षित भोजन, खाने से होने वाली बीमारियों का पता लगाने, उनको रोकने और इनके उपचार की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। दुनिया भर में पिछले 6 वर्षों से विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य मूल्य श्रृंखला प्रणाली व सुरक्षित भोजन के महत्त्व के बारे में जागरूक करना है।

भोजन सुरक्षित है या नहीं, इसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। खाद्य सामग्री चाहे खुली हो या पैकेट बंद, सभी चरणों जैसे कि खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण और बिक्री के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया है। भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएस अधिनियम) के अंतर्गत स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने और मानव उपभोग के लिए इन पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करता है।

एफएसएसएआइ ने 'ईट राइट इंडिया' अभियान चला रहा है। इसे देश के विभिन्न जिलों में सुरक्षित भोजन और खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में उनके प्रयासों को मान्यता देने के लिए जिलों और शहरों के बीच एक प्रतियोगिता के रूप में देखा जाता है। 'ईट राइट इंडिया' अभियान से देश भर में लोगों को 'सुरक्षित भोजन' यानी अगर यह सुरक्षित नहीं है, तो यह भोजन नहीं है, के बारे में जागरूक किया जा रहा है। 'स्वस्थ आहार' यानी भोजन केवल स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि शरीर और मन के लिए भी होना चाहिए और 'सस्टेनेबल आहार' यानी भोजन लोगों और प्लेनेट दोनों के लिए टिकाऊ होना चाहिए।

इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की थीम सभी से 'अप्रत्याशित के लिए तैयार रहने' का आग्रह कर खाद्य सुरक्षा से संबंधित अप्रत्याशित संकटों के लिए उपभोक्ताओं के तैयार रहने के महत्व पर जोर देती है, चाहे वह कितनी भी छोटी या गंभीर समस्या क्यों न हो।

खाद्य सुरक्षा सरकारों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं की सम्मिलित जिम्मेदारी है। खेत से लेकर खाने की टेबल तक इस जिम्मेदारी को निभाना होगा, ताकि खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहें और वे बीमारी का कारण न बनें। सुरक्षित खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने से बीमारियों पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी।

फैक्ट फ्रंट

महात्मा गांधी को ट्रेन से जबरन किया बाहर

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 7 जून 1893 को सविनय अवज्ञा जैसे अहिंसक हथियार का पहली बार इस्तेमाल किया था। वे किसी काम से दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे थे। रंग गोरा नहीं होने के कारण उनको कंपार्टमेंट से निकल जाने को कहा गया। गांधीजी रेलवे अधिकारियों से भिड़ गए और कहा कि वे लोग चाहें तो उनको उठाकर बाहर फेंक सकते हैं लेकिन वह खुद से कंपार्टमेंट छोड़कर नहीं जाएंगे। यही हिम्मत सविनय अवज्ञा थी। उनको धकेल कर ट्रेन से बाहर कर दिया गया।

प्रसंगवश

हरियाली बढ़ाने के नाम पर खानापूर्ति के खतरे आ रहे सामने

तमाम सकारात्मक प्रयासों के बावजूद पर्यावरण से खिलवाड़ का सिलसिला लगातार जारी रहना चिंता का सबब है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के पर्यावरण को शुद्ध रखने में अहम भूमिका निभाने वाले सरिस्का वन क्षेत्र के बफर एरिया में अतिक्रमणों की भरमार व पेड़ों की अवैध कटाई से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। एनसीआर समेत समूचे राजस्थान में गर्मी के बढ़ते प्रकोप की एक बड़ी वजह इसे भी माना जा सकता है। बात अकेले सरिस्का में पेड़ों की अवैध कटाई तक सीमित नहीं है। गांव से लेकर शहरों तक हरियाली चौपट करने का यह सिलसिला जारी है। कभी भारत में सर्वाधिक हरियाली रहती थी लेकिन विकास की दौड़ में अब इस पर ही सर्वाधिक मार पड़ रही है। कभी छह लेन, कभी आठ लेन, कभी गंगा वे तो कभी यमुना वे के नाम पर हजारों पेड़ों की बलि दे दी गई। इसके अलावा कल-कारखाने व आवासीय योजनाओं के नाम पर चाहे शहरी हो या ग्रामीण इलाके, सभी जगह हरियाली चौपट करने का काम सबसे पहले होता है। अफसोजनक तो यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद पेड़ों की अंधाधुंध कटाई न तो थम रही है, न ही कम हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के सामने आते नित नए खतरों के रूप में कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ के हालात बन रहे हैं।

कहने को तो विभिन्न परियोजनाओं को लागू करते समय पेड़ों की कटाई के बदले पौधरोपण का प्रावधान भी है। पौधरोपण के नाम पर कागजी कार्रवाई होती है। साथ ही जहां कहीं वाकई में पौधारोपण होता है, वहां इनकी सारसंभाल की किसी को परवाह नहीं होती। नतीजतन बहुत से पौधे पेड़ बनने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। वहीं बढ़ते शहरीकरण से दो तरह का नुकसान हो रहा है। एक तो हरियाली कम हो रही है, दूसरे कंक्रीट के जंगल बढ़ने से तापमान भी बढ़ रहा है। इसको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) भुवनेश्वर के एक नए शोध से भी समझा जा सकता है। शोध में बताया गया है कि शहरीकरण के कारण भारत के 140 से अधिक प्रमुख शहरों की रात उनके आसपास के गैर-शहरी क्षेत्रों की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक गर्म है। इसी तरह इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने माना है कि पिछले 20 सालों में कई बड़े शहरों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से इन शहरों में हरियाली नाम मात्र ही रह गई है। बहरहाल, ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से बचाव व गिरते भूजल स्तर को नियंत्रित करने के उपायों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, अन्यथा परिणाम भयावह होते देर नहीं लगने वाले।

- महेन्द्र सिंह शेखावत
mahendra.shekhawat@epatrika.com

लोकसभा चुनाव परिणाम : किसी भी दल को बहुमत न देकर मतदाता ने राजनीतिक दलों की मनमानी पर रोक लगाई है

नई सरकार पर सहयोगी दलों का रहेगा दबाव

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 4 जून को चुनावी जीत हासिल की। इस जीत को ज्यादा से ज्यादा 'पाइरहिक विक्ट्री' के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 'पाइरहिक विक्ट्री' शब्द की उत्पत्ति एपिरस (एपिरस दक्षिणपूर्वी यूरोप का एक भौगोलिक और ऐतिहासिक क्षेत्र, जिसे अब ग्रीस और अल्बानिया के बीच साझा किया जाता है) के राजा पाइरहस से सम्बंधित है जिसने 279 ईसा पूर्व में एस्कुलम की लड़ाई में रोमनों को हराया था लेकिन उनकी सेना को अपूरणीय क्षति हुई थी।

भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2024 का चुनाव भले ही जीत लिया हो लेकिन इंडिया गठबंधन ने उसे कड़ी चुनौती दी है। इंडिया गठबंधन खुद को संविधान की भावना के प्रति प्रतिबद्ध बताता है। सबसे ज्यादा नुकसान गंगा के मैदान में हुआ जहां मोदी-योगी की अगुवाई में चल रही डबल इंजन ट्रेन को अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी ने पटरी से उतारने की कोशिश की।

चुनाव नतीजों ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी 2019 में वाराणसी से 4.93 लाख मतों से जीते थे। 2024 में उसी वाराणसी में उन्हें मिले मतों की संख्या घट गई। इसके विपरीत कांग्रेस का गढ़ और गांधी परिवार की एक अन्य सीट अमेठी में 2019 में हार के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली में 3.9 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। यह उलटफेर को दर्शाने वाली कहानी है। पीएम मोदी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने और बड़ा संदेश देने का प्रयास करते रहे हैं लेकिन वक्त उनके खिलाफ रहा। भाजपा की चुनावी सभाओं में मोदी ने अपने संबोधनों के जरिए अपने समर्थकों में उत्साह पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली।

मोदी सरकार ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया लेकिन 95 फीसदी से ज्यादा यात्री अब भी एक-दूसरे के ऊपर लदे हुए और भीड़-भाड़ वाली गंदी ट्रेनों में यात्रा करते हैं, जहां आमतौर पर न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं होती हैं। लेकिन लोगों को यह समझाने की कोशिश की गई कि उनके जीवन-स्तर की स्थितियों में सुधार हुआ है। जीवन स्तर का कथित मानक एक सापेक्ष अवधारणा है। द्वितीय श्रेणी के एक सामान्य डिब्बे में यात्रा करने वाला इंसान आलीशान वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे यात्री को किस हसरत भरी से निगाह देखता है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई एग्जिट पोल की बाढ़ ने हार-जीत के नए मानक खड़े कर दिए। भाजपा की प्रचार सभाओं में राहुल गांधी को पचास से भी कम सीटों पर समेटने की बात कही गई। अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव को लेकर भी चुनावी सभाओं में ऐसे ही बयान दिए गए। पीएम मोदी ने 82 दिनों में देश भर में 206 रैलियों को संबोधित करके मतदाताओं का मन जीतने की कोशिश की। भाजपा की सभाओं में उपलब्धियों का बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बखान किया गया, लेकिन विपक्षी दल मिलकर मैदान में उतरे और भाजपा की संख्या कम कर दी और उसे बहुमत पाने से रोक दिया।

मोहन गुरुस्वामी
नीति विश्लेषक, वित्त मंत्रालय के पूर्व सलाहकार
@patrika.com

चुनाव परिणामों ने जता दिया है कि बुलबुला फूट चुका है। अपने घोषित लक्ष्य -अब की बार चार सौ पार- की तुलना में भाजपा 150 से अधिक सीटों से पीछे रह गई। विडंबना यह है कि भाजपा की सीटें उसके गढ़ वाले प्रमुख राज्यों में भी कम हो गई और केवल उड़ीसा तथा तेलंगाना में बढ़ीं। संसद में भाजपा अब भी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसका आकार छोटा हो गया है। पार्टी को अहसास है कि रास्ता कांटों से भरा है। अब राष्ट्रीय मंच पर नया एनडीए दो राजनीतिज्ञों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू - पर बहुत अधिक निर्भर होगा। हाल के दिनों तक दोनों व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुखर रहे हैं। ऐसे राजनीतिक मामलों को देखना मुश्किल भरा होगा जो भाजपा के एजेंडे वाले होंगे। ऐसा लगता है कि वे सरकार पर शिकंजा कसते रहेंगे। ये लोग नई सरकार को ज्यादा समझौताकारी बनने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

मतदाताओं का स्पष्ट संदेश सबको इज्जत, सबको काम

दो हजार चौबीस के लोकसभा चुनाव परिणाम में जो जनादेश आया है, वह भारत के आम मतदाताओं की अनोखी दार्शनिक अभिव्यक्ति है। भारत के राजनीतिक दलों और भारतीय राजनीति के लिए एक महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश भी इस जनादेश में उजागर हुआ है। चुनाव परिणाम के बाद देश में जो सरकार बनेगी उसके लिए भी और देश के सभी राजनीतिक दलों और विचारधाराओं के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है। यह संदेश सबके लिए है कि चाहे वह सरकार बनाए या विपक्ष में रहे। यह संदेश भारतीय दर्शन, जीवन पद्धति और सामाजिक जीवन की सनातन मर्यादा का मूल बिंदु है कि 'भारत सबका है और सब भारत के हैं।'

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की कोख से निकले भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'हम भारत के लोग' शब्दों का स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता की जीवन शैली का सार सबको साथ लेकर आपसी मेलजोल से शांतिमय जीवन जीते रहना है। यही भारतीय लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना या सनातन विरासत हैं। भारतीय राजनीति में जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं हैं, सबको अपनी राजनीतिक सामाजिक धार्मिक, आध्यात्मिक और आर्थिक समझ को अपने-अपने तरीके से जनता के समक्ष खुलकर रखने का पूरा-पूरा अवसर और अधिकार है।

चुने गए जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों को यह भ्रम हो सकता है कि वे सर्वशक्तिमान और अपरिहार्य हैं। पर भारतीय मतदाता अपने जनादेश को लेकर आजादी के बाद से प्रत्येक आम चुनाव में एकदम स्पष्ट संकेत देने से पीछे नहीं रहता है। राजनीतिक दलों के समर्थक, कार्यकर्ता और कर्ताधर्ता अपनी विवेकशीलता को अक्सर त्याग दिया करते हैं पर भारतीय मतदाता एक समान सोच विचार और सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का न होते हुए भी लोकतंत्र और संविधान की तेजस्विता को लेकर चैतन्य बना रहता है। साथ ही साथ अपनी निर्भीक और लोकतांत्रिक भूमिका को कभी नहीं भूलता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों से जो राजनीतिक घटनाचक्र भारतीय राजनीति में चला, उसके परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति में जो असंतुलन उभरा उसका पटाक्षेप 2024 के जनादेश में स्पष्ट दिखाई देता है। 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में एक अजीब असमंजस, तनाव और आशा-निराशा का राजनीतिक वातावरण होने के बाद भी शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव सम्पन्न हुए। यह भारतीय लोकतंत्र की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता और परिपक्वता का जीवंत उदाहरण है। भारतीय राजनीति और राजनेता निरन्तर अकारण उत्तेजित होते रहते हैं। उनमें शांतचित्तता का निरन्तर अभाव बना रहता है। पर इसके एकदम उलट भारतीय मतदाता धीरज के साथ मौन रहकर हमेशा चुनाव परिणाम में ही बोलता है। भारतीय मतदाता भारतीय राजनीति के राजनीतिक दल को चुनाव में जीत भी दिलाता है और हराता भी है। भारतीय मतदाता के जनादेश की एक अनोखी विशेषता यह भी है कि उसने भारतीय राजनीति के कई राजनीतिक दलों शानदार तरीके से जिताया तो हराया भी।

मुश्किल यह है कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल केवल अपनी पतंग को ही निरंतर ऊंची उड़ान पर देखने के आदी हो चुके हैं। पर भारतीय मतदाता किसी को भी आजीवन पतंगबाजी का एकाधिकार नहीं देता। भारतीय आम चुनावों के परिणामों ने छोटे से छोटे राजनीतिक समूह से लेकर अपने आप को अजेय या अपरिहार्य मानने वाले राजनीतिक समूहों को अपने जनादेश से एक संदेश जरूर दिया है कि लोकतंत्र पर किसी अकेली राजनीतिक जमात का एकाधिकार नहीं है। 'सबको इज्जत, सबको काम' देना ही 2024 के आम चुनाव में भारतीय मतदाता का स्पष्ट जनादेश है। जनादेश के इस अर्थ को समझकर पक्ष-विपक्ष दोनों को अपनी-अपनी राजनीतिक भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। लोकतंत्र में यही राजनीति का मूल है।

अनिल त्रिवेदी
अभिभाषक और लेखक
@patrika.com

अल-उला : जहां हैं संरक्षित खंडहर और कलाकृतियां

अल-उला सऊदी अरब के सबसे दिलचस्प, रोमांचकऔर ऊर्जा से भरपूर पर्यटन स्थल के रूप में तेजी से उभर रहा है। अच्छी तरह से संरक्षित खंडहरों और स्टाइलिश नए होटलों की भरमार के साथ, सऊदी का यह शहर पर्यटकों का पसंदीदा स्थान बन रहा है। सऊदी अरब की पहली यूनेस्को विश्व धरोहर अल-उला में प्राकृतिक खजाने, एक संपन्न कला दृश्य और सऊदी के कुछ सबसे शानदार होटल हैं। हेग्रा से कुछ ही मिनटों की दूरी पर जबल अल-फील - जिसे एलिफेंट रॉक के नाम से भी जाना जाता है, चर्चित आकृति है। यह आकृति लाखों वर्षों के दौरान हवा और पानी के कटाव से बनी है। लाल रंग के बलुआ पत्थर की यह एलिफेंट रॉक डूबते हुए सूरज के समय गहरे लाल रंग की दिखती है।

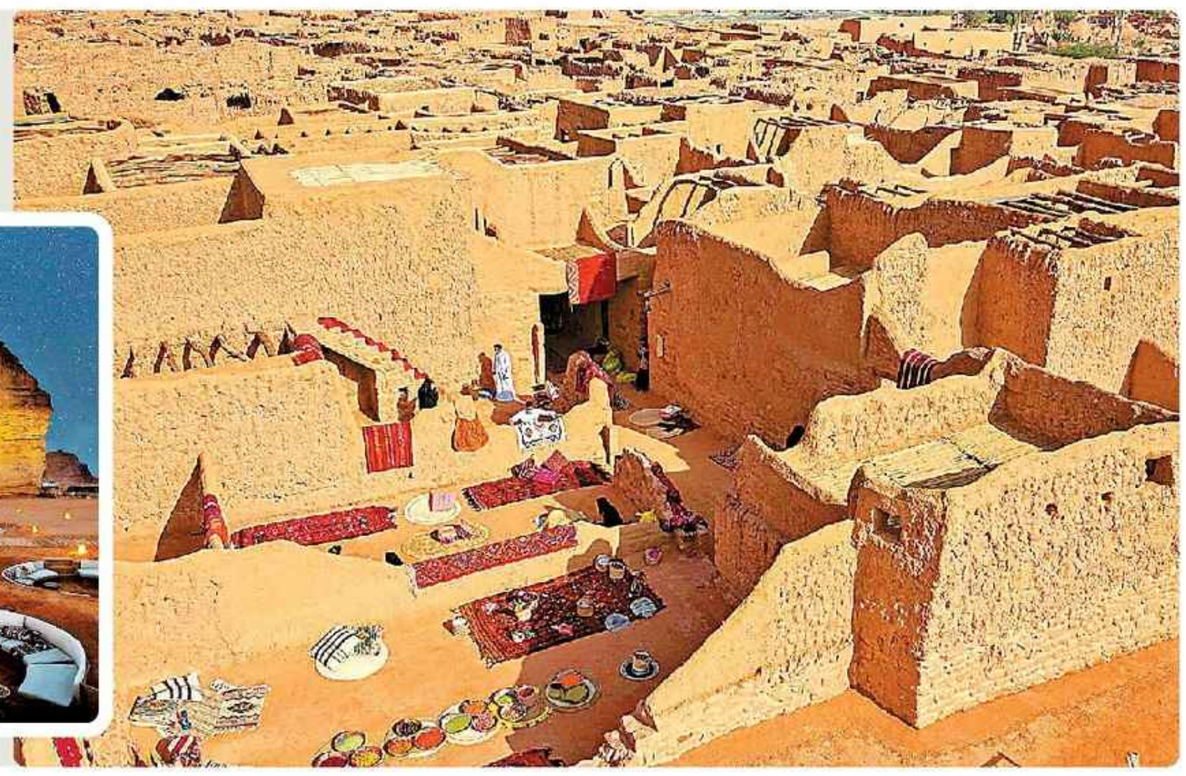

आपकी बात

लगातार बनी रहती है खींचतान

गठबंधन सरकारों का ज्यादातर कार्यकाल खींचतान में व्यतीत होता है। प्रमुख दल अपनी नीतियों को पूरी तरह से लागू करने में असहाय सा नजर आता है।

-ललित महालकरी, इंदौर, मप्र

आज का सवाल

गरीबी उन्मूलन के प्रयास सफल क्यों नहीं हो पा रहे?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'गठबंधन सरकार चलाने में किस तरह की समस्याएं आती हैं?' ऑनलाइन भी देखें।
rb.gy/lmce38
इसे स्कैन करें

https://epaperpatrika.com

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शुक्रवार, 7 जून 2024

सुधारों पर सहमति

NDA के सहयोगी दलों की बैठक में जिस सहजता से नरेंद्र मोदी के नाम पर सर्वसम्मति बन गई, उसे देखते हुए लगभग तय माना जा रहा है कि वह जल्द और सहज ढंग से तीसरे कार्यकाल का आरंभ करेंगे। फिर भी यह सवाल बना हुआ है कि पीएम मोदी का तीसरा टर्म उनके पिछले दोनों कार्यकालों से किन अर्थों में और कितना अलग होगा।

मजबूत नेता की छवि | चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में डेढ़ दशक तक सरकार चलाने का अनुभव हो या केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में एक दशक का, हमेशा सुविधाजनक बहुमत उनके साथ रहा है। उनकी छवि भी बड़े और कड़े फैसले लेने वाले मजबूत नेता की रही है। इस बार उनकी अपनी पार्टी BJP बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से दो-चार नहीं पूरे 32 सीटें दूर खड़ी है। ऐसे में तय है कि उनकी सरकार को समर्थन दे रहे JDU और TDP जैसे दल इसकी कीमत वसूलेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों पर रहेगी खास नजर

कीमत का स्वरूप | अहम सवाल यह है कि इस कीमत का स्वरूप क्या होगा। क्या ये दल पदों और विभागों की बारगेनिंग से ही संतुष्ट हो जाएंगे या वे सरकार की नीतियों और फैसलों को भी खास दिशा देने की कोशिश करेंगे? संभावना यही है कि इन दोनों ही मोर्चों पर ये दल अपना दखल बनाए रखना चाहेंगे। इसके संकेत गुरुवार को उस समय मिले, जब JDU प्रवक्ता ने कहा कि चुनावों के दौरान मतदाताओं के एक हिस्से की आशंकाओं को देखते हुए सरकार को अग्निवीर योजना की समीक्षा करनी चाहिए। यही नहीं, पार्टी ने कास्ट सेंसस को भी वक्त की जरूरत बता दिया। जाहिर है, इन दोनों मसलों पर कोई बीच की राह निकालने की जरूरत अभी से बन गई है।

सुधारों पर आम राय | ऐसे में यह सवाल बड़ा हो जाता है कि मोदी सरकार 3.0 के दौरान क्या सरकार के कामकाज उसी तरह से चल पाएंगे, जैसे पिछले दो कार्यकालों में चले थे। चूंकि आर्थिक सुधारों पर देश में एक तरह की राजनीतिक सर्वसम्मति रही है, इसलिए यह उम्मीद जरूर की जा सकती है कि सुधारों का अजेंडा ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, लेकिन इसकी रफ्तार कम न पड़े, इसके लिए विशेष प्रयासों की जरूरत पड़ सकती है।

चुनौतीपूर्ण दौर | चुनाव नतीजों में सीटों के पैटर्न पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2019 के मुकाबले 2024 में NDA को मिली ग्रामीण सीटों में कमी आई है। इसे इस दौरान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आई गिरावट से जोड़कर देखा जा रहा है। जाहिर है, मोदी सरकार 3.0 इसे दुरुस्त करना चाहेगी। लेकिन पहले उसे बिहार को विशेष दर्जा और आंध्र प्रदेश को विशेष मदद जैसी मांगों से निपटना पड़ेगा। जाहिर है, पीएम मोदी के लिए आने वाला दौर चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है।

रोज़-ब-रोज़

सीट की लड़ाई

शैलेंद्र पांडेय

कई लोग लगभग भागते हुए सीढ़ियां उतरते हैं और हांफते हुए पीली रेखा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन, यह संघर्ष का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। असली लड़ाई तो शुरू होती है इसके बाद, कतार से। पैर भागने के लिए तैयार और हाथ लैपटॉप बैग पर। मेट्रो धीमी रफ्तार से सामने से गुजरती हुई रुकती है, उससे पहले ही आंखें खिड़कियों से भीतर झांक कर माहौल भांप लेती हैं और दिमाग कैलकुलेशन कर लेता है कि दरवाजे खुलने के बाद दाएं जाना है या बाएं।

इतनी जद्दोजहद किसलिए? बस सीट... एक अदद सीट जहां टिककर सफर के दौरान मोबाइल देखा जा सके। सीट को लेकर यह आपाधापी हर जगह है। हाल में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, तो वहां भी सभी की दिलचस्पी का केंद्र सीटें ही रहीं। कुछ वक्त के लिए व्यक्ति गौण हो गए। उनकी जगह सीटों ने ले ली। सबसे बड़ा सत्य आंकड़े बन गए, सीटों का आंकड़ा। और मेट्रो की कतार की तरह यह भी कहानी की शुरुआत है। NDA के घटक दलों की पहली बैठक हुई, तो वहां भी लोगों की नजरें थीं किसको कौन-सी सीट मिली? नरेंद्र मोदी के दाएं कौन था और बाएं कौन? अगर दाएं वाले को उतनी सीटें नहीं मिलतीं तो क्या वह दाएं रह पाता? हो सकता है कि तब उसे किसी ऐसी सीट पर बैठा दिया जाता, जो कोने में रखी होती है! कोने वाला भी तब कोने में नहीं रहता, पोजिशन बदल जाती उसकी। रुतबा, महिमा, प्रताप, ताप - इन सब का सार है सीट। और इसे बचाने के लिए जतन भी बहुत करने पड़ते हैं, फिर लेवल चाहे कोई भी हो। मेट्रो में कई सारी सीटें रिजर्व होती हैं महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए। जो नहीं होतीं, उनके लिए भी अनाउंसमेंट होती रहती है कि अपने से ज्यादा जरूरतमंद को ऑफर करें। अच्छे नागरिक की पहचान है ऐसा करना, लेकिन वह सीट ही क्या जो अपना मोह छूट जाने दे। यह मिलती है तो तरीका अपने आप पता चल जाता है कि इसे बचाए कैसे रखना है। कई लोग इसी चक्कर में आत्मलीन हो जाते हैं, आसपास से खुद को काटकर अपने में मगन। कुछ देखते रहते हैं, पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि रिएक्शन के बाद एक्शन करना होगा।

इससे बेहतर है कि आंखें मूंदे पड़े रहो, जब तक कि सफर खत्म न हो जाए। और यहां भी खत्म सफर होता है, सीट और उसकी जंग जारी रहती है। फिर भी गनीमत है कि इसमें खुद मौजूद रहना पड़ता है वरना लड़ाई तो वह भी होती है जो रुमाल से लड़ी जाती है। सरकारी बसों और रेल के जनरल डिब्बों में जहां देह नहीं पहुंच पाती थी, वहां रुमाल पहले पहुंचाकर दावा कायम किया जाता था सीटों पर। कई जगह वह चलन अब भी जारी है। यूं अलग-अलग स्तरों पर सीटों ने खुद को प्रासंगिक बनाए रखने का रास्ता तलाश लिया है।

एकदा

गणित के चैंपियन

बात 1926 की है। इंग्लैंड में 13 साल की उम्र में एलन को शेरबोर्न स्कूल में दाखिला मिला। यह जगह अपने सख्त नियमों और क्लासिक शिक्षा के लिए जानी जाती थी। एलन को गणित और विज्ञान बहुत पसंद थे। इस वजह से शिक्षक उन्हें पसंद नहीं करते थे। गणित और विज्ञान की जगह शेरबोर्न स्कूल बच्चों को क्लासिक्स के बारे में पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता था। दूसरी ओर एलन का दिमाग गणित की समस्याओं में खोया रहता था। वह घंटों गणित की किताबों में डूबा रहता, नई अवधारणाओं को समझता और उनकी गहराई तक जाता।

Subrata Dhar

बात हेडमास्टर तक पहुंची तो उन्होंने एलन के माता-पिता को चिट्ठी लिखी कि अगर एलन सिर्फ गणित और विज्ञान सीखना चाहता है, तो उसके लिए यह स्कूल नहीं है। उसी दौरान एलन ने एक जटिल गणितीय समस्या देखी। वह इस समस्या को सुलझाने में जुट गया। हर छोटा-मोटा विवरण, हर नियम उसके दिमाग में घूमता रहा। अब वह आइंस्टाइन के सूत्र सिर्फ देखकर ही पहचान लेता था। कई दिन गुजर गए, लेकिन एलन ने हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन उसने समस्या का समाधान ढूंढ निकाला। उसे पता चल गया कि उसकी जिज्ञासा ही उसकी सफलता का आधार थी। बाद में यही एलन महान वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग के नाम से जाने गए, जिन्हें मॉडर्न कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। यह भी कहते हैं कि अगर एलन अपनी Bambe मशीन ना बनाते, तो दूसरा विश्वयुद्ध और लंबा खिंचता। आज के दिन ही इनका निधन हुआ था। इस शर्मीले ब्रिटिश गणितज्ञ को आज भी अमेरिका से लेकर भारत तक के वैज्ञानिक श्रद्धांजलि देते हैं।

संकलन : **अर्चना शर्मा**

लोकसभा के चुनाव परिणाम बताते हैं कि राज्य की जनता ने BJP की तोड़फोड़ वाली राजनीति नकार दी

महाराष्ट्र में हुई असली-नकली की पहचान

गंगाधर ढोबले

महाराष्ट्र में BJP को विपक्षी दलों ने नहीं हराया, तोड़फोड़ की राजनीति अपनाकर उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उसने शिवसेना और NCP तोड़कर उनके नेताओं को तो साध लिया, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को साध नहीं पाई। दोनों दलों का चुनाव चिह्न और नाम छिन जाने के बावजूद जनता में कोई भ्रम नहीं रहा। वोट उद्धव ठाकरे और शरद पवार खेमे की ओर मुड़े और मतदाताओं ने उनकी पार्टियों को ही मूल पार्टियां माना। एकनाथ शिंदे और अजित पवार हाशिए पर आ गए। अब यह सवाल ही खत्म हो गया कि मूल शिवसेना या मूल NCP किसकी?

कुर्सी का खेल | 2019 के लोकसभा चुनाव में BJP और उद्धव ठाकरे की शिवसेना साथ थे। लेकिन, विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने सीएम पद पर दावेदारी जताई तो गठबंधन टूट गया। इससे महाराष्ट्र में अभूतपूर्व राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। राजनीतिक खेल होने लगे। इस खेल के केंद्र में BJP के देवेंद्र फडणवीस और NCP के शरद पवार थे। शिवसेना से टूटे एकनाथ शिंदे और NCP से टूटे अजित पवार और उनके साथी तो महज प्यादे थे। गौर करने लायक है कि BJP के दिग्गज नेता नितिन गडकरी इस खेल में कहीं दिखाई नहीं दिए। वैसे भी चर्चा है कि फडणवीस और गडकरी के दो अलग गुट हैं।

BJP सिमटी | इस बार के वोटिंग पैटर्न से लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ने BJP द्वारा विपक्षी पार्टियों में की गई इस तरह की तोड़फोड़ को पसंद नहीं किया। BJP 10 सीटों पर सिमट गई। उनके साथी शिंदे 13 से सात सीटों पर आ गए। अजित पवार के कोटे में चार सीटें आई थीं। उन्हें जीत मिली केवल रायगढ़ में। बारामती में उनकी पत्नी सुनेत्रा तक हार गईं।

राज्य में बड़ा उलटफेर
- कांग्रेस बड़ी पार्टी, BJP 10 पर सिमटी
- एकनाथ शिंदे, अजित पवार को झटका
- विधानसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण

कांग्रेस का उभार | शरद पवार के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को लोगों ने खूब पसंद किया। कांग्रेस 13 सीटें पाकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पिछले चुनाव में उसे चंद्रपुर की महज एक सीट मिली थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 और शरद पवार की पार्टी को 7 सीटें मिलीं। पश्चिम महाराष्ट्र में पवार को अच्छी सफलता मिली। यह सहकारिता चीनी मिलों का इलाका है और शरद पवार का उस पर दबदबा है। वहां उन्हें 9 में से 5 सीटें मिलीं। इससे पता चलता है कि पश्चिम महाराष्ट्र में उनका जादू अब भी बरकरार है।

अजित की मुश्किल | चुनाव परिणामों से संकेत मिलता है कि अजित पवार के दांव उल्टे पड़े हैं। उनके लिए अब न BJP घास डालेगी, न कांग्रेस। शरद पवार भी उन्हें वापस पार्टी में लेने से कतराएंगे। फिर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति में पिछला दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अजित पवार के साथ जो भी BJP की ओर पलायन कर गए, उनकी घर-वापसी फिर शुरू हो सकती है। अजित भी खुद BJP से कन्नी काट सकते हैं!

चुनौतियां बढ़ीं : देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार (बाएं से दाएं)

शिंदे का संघर्ष | एकनाथ शिंदे भी बहुत खुश नहीं हैं। उनके साथ जो 40 विधायक गए थे, वे एक-एक कर छितर सकते हैं। जल्द ही पंचायत चुनाव होने हैं। इसमें बहुत से नए समीकरण बनेंगे। शिंदे के बहुत से विधायक इधर-उधर जा सकते हैं। इसके बाद भी जो बचेंगे, वे अगले छह माह के भीतर होने वाले विधानसभा चुनाव में छलांगें लगा सकते हैं। परिणामों से संकेत मिलता है कि शिंदे के लिए यह बहुत संघर्षपूर्ण काल होगा।

ठाकरे का हिंदुत्व | शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पार्टी में बगावत के कारण सहानुभूति का लाभ मिला है। पवार युवाओं को पार्टी में जिम्मेदारी सौंपने की बात कर रहे हैं। ये नए युवा कौन होंगे और वे किस तरह जनमत जुटाएंगे, इसका अभी अंदाजा लगाना संभव नहीं है। इस बार पवार अस्वस्थता के बावजूद खूब सक्रिय रहे। अगली बार भी ऐसा कर पाएंगे, इसमें कुछ संदेह तो है ही। ठाकरे को इस बार सहानुभूति मिली और उनके हिंदुत्व को लोगों ने BJP के हिंदुत्व की अपेक्षा तवज्जो दी है। उद्धव के बाद शिवसेना के अगले नेता आदित्य हैं, इस पर भी अब मुहर लग चुकी है।

रणनीतिक सफलता | कहते हैं कि मराठा आरक्षण आंदोलन राज्यभर में फैलाने की BJP की रणनीति थी। यह आरक्षण OBC के कोटे से ही दिया जाना था। इससे मराठा और OBC में फूट पड़ती। शरद पवार से मराठा और अजित के गुट में गए छगन भुजबल से OBC वोटबैंक छिन जाता। जिस जरांगे पाटिल को परभणी-जालना से आगे कोई नहीं जानता था, उसे रातों-रात हीरो बना दिया गया। BJP की यह रणनीति शरद पवार जान गए और तुरंत पाटिल से मुलाकात की। उधर, छगन भुजबल भी विरोध में खड़े हो गए। मतदान से साफ लगता है कि शरद पवार ने BJP की यह रणनीति चुनाव के दौरान पूरी तरह विफल कर दी।

बदलाव का वक्त | इस चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर BJP की रफ्तार को उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ने रोका है। BJP केंद्र में जिस तरह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर हो गई है, वैसे ही राज्य में भी क्षेत्रीय दलों पर निर्भर है। पार्टी में इस पर जरूर मंथन चलेगा। हो सकता है बहुत से बदलाव हों, बड़ों पर गाज गिरे और नया नेतृत्व उभरे। आज की घड़ी में ऐसा लगता है कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी, शायद अगले चुनाव के बाद भी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

बहुत कठिन है डगर संसद की

पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। कुछ दिलचस्प आंकड़ों के जरिए देखते हैं कि मोदी मैजिक कैसे भारत के राजनीतिक इतिहास की अमिट छाप बन रहा है।

मुकाबला

BJP का यह प्रदर्शन उन्हीं सीटों पर आधारित है, जहां पार्टी विजेता या उपविजेता रही। आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस ने BJP से होने वाले सीधे मुकाबलों में खुद को सुधारने में बहुत कम कामयाबी पाई है।

2009

BJP बनाम कांग्रेस
2009 में मुकाबले में 173 सीटें। BJP ने 80, कांग्रेस ने 93 जीतीं।
BJP 41% — कांग्रेस 42.6%

BJP बनाम अन्य
53 सीटों पर BJP के सामने दूसरी पार्टियां थीं। BJP ने 36 जीतीं।
BJP 36% — अन्य 32.9%

2014

189 सीटों पर आमने सामने मुकाबला। BJP ने 166 सीटें जीतीं।
BJP 50.9% — कांग्रेस 34.7%

147 सीटों पर BJP के सामने अन्य पार्टियां थीं। BJP ने 116 सीटें जीतीं।
BJP 41.7% — अन्य 31%

2019

190 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ। BJP ने 175 सीटें जीत लीं।
BJP 56.5% — कांग्रेस 35.3%

185 सीटों पर मुकाबला। BJP ने अन्य पार्टियों से 128 सीटें जीत लीं।
BJP 47.3% — अन्य 40.3%

2024

BJP और कांग्रेस 215 सीटों पर आमने सामने। BJP ने 153 सीटें जीतीं।
BJP 51% — कांग्रेस 40.9%

178 सीटों पर BJP ने अन्य दलों से मुकाबले में 87 सीटें जीतीं।
BJP 44% — अन्य 43.3%

**वोट शेयर*

नेहरू बनाम मोदी

जवाहरलाल नेहरू की तरह ही नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार सरकार के मुखिया बनने जा रहे हैं। लेकिन यहां एक अंतर है। नेहरू मेजॉरिटी से पीएम बने थे, जबकि नरेंद्र मोदी इस बार गठबंधन से पीएम बन रहे हैं।

जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री (15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964)	नरेंद्र मोदी (26 मई 2014 से)
पहला कार्यकाल इलाहाबाद+जौनपुर 38.7%	**पहला कार्यकाल** वडोदरा 72.8% वाराणसी 56.4%
कांग्रेस- 364 सीटें, 45% वोट	BJP- 282 सीटें, 31.3% वोट
दूसरा कार्यकाल फूलपुर 36.9%	**दूसरा कार्यकाल** वाराणसी 63.6%
कांग्रेस- 371 सीटें, 47.8% वोट	BJP- 303 सीटें, 31.3% वोट
तीसरा कार्यकाल फूलपुर 61.6%	**तीसरा कार्यकाल** वाराणसी 54.2%
कांग्रेस- 361 सीटें, 44.7% वोट	BJP- 240 सीटें, 36.6% वोट

● वोट शेयर

कार्यकाल : बतौर PM और CM

नरेंद्र मोदी	8,277
जवाहरलाल नेहरू	6,130
इंदिरा गांधी	5,829
मनमोहन सिंह	3,656
मोरारजी देसाई	2,511
अटल बिहारी वाजपेयी	2,272

*(कार्यकाल दिन में)

बातों का हिसाब

चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों का जमकर प्रयोग किया-

कांग्रेस	5133
मोदी	4320
BJP	1359
राम	1200
गरीब	1094
गठबंधन	966
किसान	879
विकास	834
संविधान	762
हिंदू-मुसलमान	762

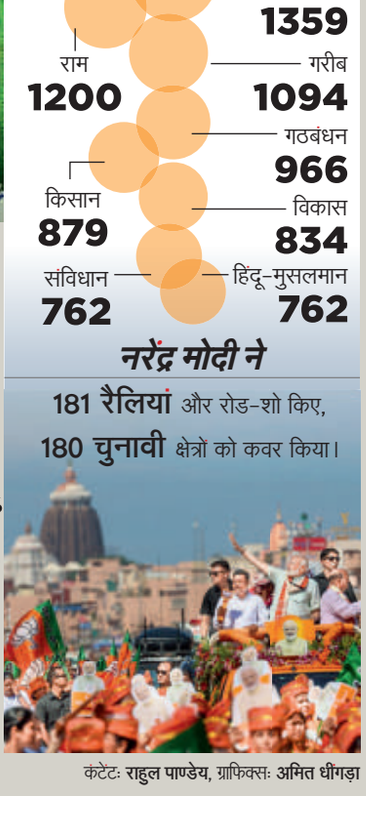

नरेंद्र मोदी ने

181 रैलियां और रोड-शो किए, 180 चुनावी क्षेत्रों को कवर किया।

कंटेंट: राहुल पाण्डेय, ग्राफिक्स: अमित धींगड़ा

विकसित बनने की चुनौती को तैयार भारत

प्रवीण सिंह परदेशी

भारत 2047 तक विकसित देश बनने की दिशा में बढ़ चुका है। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे देश में कारखाने तैयार करने होंगे, जो उसको विश्व की फैक्ट्री का दर्जा दे सकें। साथ ही, उन सेवाओं का सशक्त निर्यातक बनना होगा, जिनसे ग्राहकों को ज्यादा संतुष्टि और सुविधा मिल सके। देश में उच्चस्तरीय कौशल देने की विधा को भी मजबूत करना होगा, जिससे दुनिया की मानव कौशल की जरूरतों को हम पूरा कर पाएं। लेकिन, यह सब संभव होगा कैसे, यह सवाल लोगों को परेशान करता है।

मिशन कर्मयोगी | देश की इन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जरूरी है एक कुशल और बेहतर सिविल सेवा और प्रशासन। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने Mission Karmayogi - National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB) की शुरुआत की। इसका लक्ष्य सिविल सेवकों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। अब सवाल है कि इस मिशन की लॉन्चिंग के बाद क्या हमारी सिविल सेवा 2047 के लक्ष्य को हासिल कर सकने के लिए ज्यादा सक्षम हुई है?

एक मंच | पहले हमारी बड़ी परियोजनाएं अक्सर मुश्किल में पड़ जाती थीं। इनके लिए कई मंत्रालयों से अनुमति लेनी होती है और पहले उनमें देरी आम बात थी। कहीं पर्यावरण से जुड़ी परमिशन में देरी होती, कहीं रेल ओवरब्रिज का डिजाइन पास होने में समय लगता। इन परेशानियों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने मेगा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एकीकृत व्यवस्था 'गति शक्ति' को स्थापित किया। इस पहल में अलग-अलग संस्थाओं के लोग मिलकर काम करते हैं।

लाखों को ट्रेनिंग | पीएम गति शक्ति कारगर तरीके से लागू हो सके इसके लिए आयोग ने डिजिटल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के तहत सिविल सेवकों को उपयुक्त कौशल देने की व्यवस्था की। इस पाठ्यक्रम को बनाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय और रसद विभाग, गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी), राष्ट्रीय सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर अकादमी जैसे सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों ने साथ मिलकर काम किया। विभिन्न विभागों में, परियोजना निर्माण और समन्वय के लिए, 24 हजार से अधिक अधिकारियों ने पीएम गति शक्ति शिक्षण मॉड्यूल पूरा कर लिया है। इसी तरह, Capacity Building Commission (CBC) ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिसिस जैसी उभरती प्रौद्योगिकी पर ऑनलाइन शिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है। हाल-फिलहाल तक विभिन्न मंत्रालयों के लगभग 3.88 लाख सरकारी कर्मियों को इन पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

AI Image

कॉमन रूम

योजना का असर | नई रेल लाइनों का निर्माण 2024 तक 4 किमी प्रति दिन से बढ़कर 12 किमी प्रति दिन हो गया है। भारतमाला-2 के तहत 15 से अधिक राजमार्ग परियोजनाएं तैयार की गई हैं। एकीकृत योजना से संवेदनशील वन्यजीवों और हाथियों को बिना परेशान किए नए रेल और राजमार्ग सर्वेक्षण किए गए हैं।

क्षमता बढ़ी | नागरिक केंद्रित सेवाओं में सुधार और सेवाभाव को बढ़ावा देने के लिए CBC के तहत 50 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। एक स्वतंत्र सर्वे में पाया गया कि प्रशिक्षण के बाद पुलिस थानों मे आने वाले 'बहुत संतुष्ट' नागरिकों का प्रतिशत 24 से बढ़कर 66 हो गया। पुलिस कर्मयोगी प्रशिक्षण के बाद श्रीनगर में एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने कहा कि पुलिसिंग के प्रति उनका रवैया बहुत पेशेवर हो गया है। इसी तरह, लखनऊ में एक कार्यक्रम में रेलवे कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।

निकायों में सुधार | मिशन 2047 को पूरा करने में राज्य सरकारों और नगर निगमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक सेवाएं, मसलन पानी, स्वच्छता और सड़क म्युनिसिपल सरकारों की ओर से दिए जाते हैं। CBC ने अहमदाबाद, राजकोट, नागपुर, पुणे, भुवनेश्वर और मैसूर नगर निगम में कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच पर काम किया। अहमदाबाद और नागपुर नगर निगम के लगभग सभी कर्मचारी iGOT कर्मयोगी भारत लर्निंग पोर्टल पर आ चुके हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं।

सीखने की ललक | मिशन कर्मयोगी का ही प्रभाव है कि सीखने की संस्कृति विकसित करने के लिए मंथन जारी है। देशभर में अधिकारियों और प्रशासनिक सहायकों ने डेटा एनालिटिक्स, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (जीईएम) मॉड्यूल और उन्नत एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर टूल पर 15 लाख ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। मेरा मानना है कि मिशन कर्मयोगी धीरे-धीरे 'राज्य की विफलता की धारणा' को दूर कर रहा है।

(लेखक OAS Retd और Capacity Building Commission के Ex-Member हैं)

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें hindi.speakingtree.in

वक्त के साथ सच बदलता रहता है, आप भी बदलिए

गोपाल अग्रवाल

दुनिया को समझने के लिए हम अक्सर एक खास नजरिए से देखते हैं। हम एक ही सचाई को ढूंढते हैं, मानो यही एक सत्य है। लेकिन क्या दुनिया वाकई इतनी सरल है? क्या एक ही सचाई से जीवन की जटिलताओं को समझा जा सकता है? दुनिया को समझने का एक अलग नजरिया है, जो मानता है कि किसी भी चीज को एक ही तरह से देखना गलत है। सचाई कई तरह की होती है, कई पहलुओं से बनी होती है। जैसे, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज की भी दो या कई सचाइयां हो सकती हैं। केवल एक सच के जरिये जीवन के सत्य को नहीं समझा जा सकता।

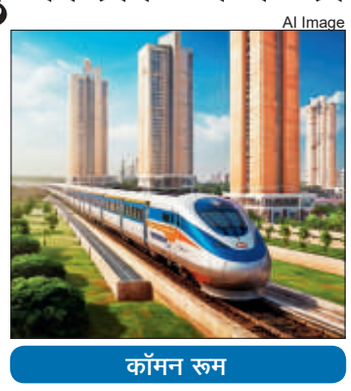

यह सोच हमें ज्ञान की असली दुनिया में ले जाती है, जहां हर चीज को कई नजरियों से देखा जा सकता है। यहां हम सीखते हैं कि किसी भी बात को सिर्फ एक ही तरह से नहीं देखना है, बल्कि उसके हर पहलू को समझना है। कल्पना कीजिए, आप एक पहाड़ को देख रहे हैं। आप उसे बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा महसूस कर रहे हैं। एक छोटे बच्चे के लिए वह पहाड़ बहुत बड़ा होगा, जबकि एक पर्वतारोही के लिए शायद छोटा ही लगेगा। यानी, पहाड़ का आकार आपकी नजरिए पर निर्भर है। आपका नजरिया सचाई को बदल देता है।

इसी तरह, जिस समय आप पहाड़ को देख रहे हैं, उस समय भी उसकी सचाई बदल सकती है। सुबह आपने उसे धुंध में देखा होगा, और शाम को वह धूप में चमकता होगा। एक ही पहाड़, अलग-अलग समय में, अलग-अलग दिखता है। यानी, समय भी सचाई को बदल सकता है। यह विचार बताता है कि सचाई एक अटल सत्य नहीं है, बल्कि एक निरंतर बदलता हुआ दृश्य है। हम जिस नजरिए से देखते हैं, जिस समय में देखते हैं, उस समय की परिस्थिति, सब कुछ सचाई को प्रभावित करता है। यह सोच हमारे दिमाग को खोलती है, हमारी समझ को गहरा करती है। यह हमें बताती है कि कोई भी सत्य एकमात्र सत्य नहीं है। किसी एक सचाई पर अड़े रहने की बजाय हम कई सचाइयों को स्वीकार करें।

जैसे, कोई व्यक्ति किसी एक काम में तो सफल होता है, किसी दूसरे काम में असफल भी हो सकता है। कोई चीज एक तरफ से तो अच्छी लग रही है, दूसरी तरफ से बुरी भी हो सकती है। कोई विचार किसी एक समय में तो ठीक लगता है, लेकिन दूसरे समय में गलत भी साबित हो सकता है। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि दुनिया में हर चीज बहुआयामी है, और सचाई भी बहुआयामी है। हमारी समझ सीमित है, और हम अक्सर पूरी सचाई नहीं जान पाते हैं। यही कारण है कि सोच का मूल सिद्धांत होना चाहिए कि किसी भी चीज को एक ही नजरिए से देखना गलत है।

ये सभी नजरिए यह समझने में मदद करते हैं कि सचाई कितनी जटिल है। यह हमें हर चीज को एक नई रोशनी में देखने का तरीका सिखाता है। यह सिखाता है कि अपनी सोच को सीमित नहीं रखें, बल्कि हर चीज को समझने के लिए खुले दिमाग से सोचें। यह ज्ञान सिर्फ हमारे दिमाग के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए है। यह हमें बताता है कि कैसे दूसरों की बातों को सुनें, उनकी भावनाओं को समझें, और उनकी राय का सम्मान करें। क्योंकि, हर किसी की अपनी सचाई होती है, और हर सचाई की अपनी जगह होती है।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा

नई दिल्ली • शुक्रवार • 7 जून • 2024

www.rashtriyasahara.com

विपक्ष की भावी रणनीति

एक दशक बाद केंद्र की राजनीति ने करवट बदली है। 18वीं लोक सभा की बनावट और प्रकृति पूर्ववर्ती लोक सभा से अलग होगा। 'इंडिया' समूह के रूप में एक ताकतवर विपक्ष उभरा है जो सत्तारूढ़ होने जा रहा एनडीए गठबंधन के लिए चुनौती साबित होगा। विपक्षी दलों के समूह इंडिया में घटक दलों के 234 सांसद हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी के सबसे अधिक 99 सांसद हैं। सरकार को जवाबदेह बनाए रखने के लिए विपक्ष को मजबूत होना आवश्यक है। लोकतंत्र की खूबसूरती भी इसी में है। चुनाव परिणाम आने के बाद बुधवार को विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई। इस बैठक से विपक्ष की भावी रणनीति का संकते मिलता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्किार्जुन खरगे ने विपक्ष

की रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि हम फिलहाल सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। मोदी सरकार के 'फासिस्ट शासन' के विरुद्ध संघर्ष जारी रहेगा। जनता ने गरीबी और बेरोजगारी दूर करने, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए यह जनादेश दिया है। यह जनादेश प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है। खरगे ने यह कहकर सरकार बनाने के विकल्प खुले रखे कि हम सही समय पर सही कदम उठाएंगे। इसका अर्थ है कि विपक्ष चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के अपने खेमे में आने का इंतजार करेगा। राजनीति संभाव्य की कला है। कल कौन किसके पाले में जाता है, यह कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में 'इंडिया' को आत्मनिरीक्षण करना होगा। यह समूह मोदी विरोध के नाम पर एकजुट हुआ है और शायद आगे भी रहेगा लेकिन एक राजनीतिक गठबंधन के रूप में इसका रूपांतरण अभी हुआ नहीं है जो राज्यों के आसन्न चुनावों में भाजपा और एनडीए का मुकाबला कर सके। पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल में इस समूह के अंतर्विरोध सामने हैं जहां इसके घटक दल आपस में ही लड़ते नजर आए हैं। 'इंडिया' के राजनैतिक दल चुनाव में न तो कोई साझा घोषणा पत्र और न ही न्यूनतम साझा कार्यक्रम ही पेश कर सके। इन्होंने गरीबी और महंगाई दूर करने का कोई विजन या रोडमैप भी तैयार नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक रूप से अनुभवी राजनेता हैं। अगर विपक्ष को संसद से सड़क तक इनकी सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना है तो इन सवालों का जवाब भी पूछना होगा।

बाल-बाल बचाया

ज्यों ज्यों तकनीक का प्रचार-प्रसार बढ़ा है, साइबर हैकरों से सारी दुनिया आजिज आ रही है। जिस दरम्यान सबकी निगाहें चुनाव परिणामों पर टिके हुए थे, उस वक्त भी हैकर चुनाव आयोग के सर्वर पर लगातार अटैक कर रहे थे। जिसे देश की नेशनल इंफॉरमेटिक्स सेंटर विफल करने में जुटी रही। उसे मुख्य हाईवे बंद कर, वैकल्पिक सर्वर स्थापित करना पड़ा। ताकि चुनाव परिणाम निर्बाध गति से देशवासियों तक पहुंचते रहें। यही नहीं, बल्कि सेंटर को केंद्र सरकार की तमाम साइटों को डाउन भी करना पड़ा। सरकारी सूचनाएं बेहद गोपनीय व संवेदनशील होती हैं। इसलिए सेंटर की सुरक्षा बेहद मजबूत है। ज्यों-ज्यों मतों की गिनती आगे बढ़ रही थी, उन्हें रियल

टाइम में लोगों तथा मीडिया तक पहुंचाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। अंदेशा है कि हैकर्स चुनाव परिणामों को प्रभावित व बाधित करने की फिराक में थे। अमरीका, ब्रिटेन व न्यूजीलैंड जैसे देशों में हैकरों पर शिकंजा कसने को लेकर लंबे समय से काम हो रहा है। अमेरिका की संघीय जांच एजंसी एफबीआई चीनी हैकरों को लेकर सख्त चेतावनी भी दे चुका है। उसका कहना है, ये कभी भी भारी तबाही ला सकते हैं। चीन को दुनिया भर में होने वाले साइबर अटैक्स के लिए जिम्मेदार माना जाता है। भारत की एक बड़ी साइबर सुरक्षा कंपनी ने इसी वर्ष की शुरुआत में सबसे बड़ी डाटा चोरी का अंदेशा व्यक्त किया था। उनके शोधकर्ताओं को हैक करने वाले डार्क वेब पर 75 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं का ब्योरा बेचे जाने का संदेह है। डेटा चोरी, सिस्टम हैकिंग व साइबर फ्राड पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निजी जानकारी निकालना, उसे तब्दील करना या जानकारी को कॉपी करके किसी अन्य को देना बड़ा अपराध माना जाता है, परंतु अभी अपने यहां सात साल की सजा प्रावधान होने के बावजूद यह जमानती अपराधों की श्रेणी में आता है। इसे और भी सख्त करने के विषय में लंबे समय से चर्चा हो रही है। यह बेहद संवेदनशील मसला है। खैर, हैकर्स की साजिश को विफल करने के लिए सरकार को एनआईसी की पीठ थपथानी चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग के आंकड़ों में कोई हेर-फेर होती तो देश का बहुत उपहास हो सकता था।

चिंता/डॉ. सत्यवान सौरभ

फिर से ठगे गए विद्यार्थी

नीट परीक्षा भारत में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, ठीक हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी की तरह, लेकिन इन क्षेत्रों में पेपर लीक होते हैं, 67 छात्रों ने 720 अंक हासिल किए, यह पूरी तरह असंभव है। पिछले साल 3 छात्रों ने 720 अंक हासिल किए थे। क्या यह यह भारत का सबसे बड़ा घोटाला है? छह छात्रों के सीट नंबर एक ही क्रम से हैं। 2 छात्रों ने 718 और 719 अंक हासिल किए हैं, यह पूरी तरह असंभव है। नीट परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक होते हैं, यदि कोई 1 प्रश्न गलत करता है तो उसके अंक 715 और 716 के आसपास होने चाहिए।

यह पूरी तरह से घोटाला है, लेकिन नीट इसे नजरअंदाज करने जा रही है? सीरियल नंबर 62 से 69 तक के छात्रों के लिए केंद्र कोड एक ही है। नीट 2024 में ग्रेस मार्क्स एक और घोटाला है। क्या सभी टॉपर परीक्षा देने के लिए एक ही केंद्र पर जाते हैं? यानी दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? हर छात्र को निष्पक्ष मौका मिलना चाहिए, कट-ऑफ में यह भारी वृद्धि स्पष्ट रूप से बड़े पैमाने पर पेपर लीक का संकेत देती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा सबसे अधिक संभावना एक बड़ी प्रोग्रामिंग त्रुटि है, जिसमें उन्होंने ओएमआर प्रतिक्रिया पत्रक के आधार पर अंकों का गलत मूल्यांकन किया है। छात्र 718, 719 अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पूर्ण अंक 720 हैं। प्रत्येक सही के लिए, आपको +4 मिलता है और प्रत्येक गलत के लिए आपको -1 मिलता है। इसलिए, यदि कोई छात्र सभी 180 प्रश्न सही करता है, तो उसे 720 अंक मिलते हैं जो प्राप्त करने योग्य है। ऐसे में हम भूल रहे हैं कि इस साल नीट में कितना बड़ा घोटाला हुआ है? एक छात्र को 720/720 स्कोर करने के बाद भी एम्स दिल्ली में मौका नहीं मिल रहा है? क्या यह किसी तरह की लापरवाही है? परिणाम 14 जून के बजाय 4 जून (चुनाव परिणाम दिवस) को क्यों घोषित किए गए? मतलब कुछ तो गड़बड़ है, लाखों नीट उम्मीदवार इसका उत्तर चाहते हैं। यह अपराध है कि एनटीए लाखों छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नीट पेपर लीक के कारण विनाशकारी परिणाम सामने आए हैं। निश्चित तौर पर इस साल परीक्षा पेपर लीक के कई मामलों ने एक बार फिर देश की शिक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की नींव हिलाकर रख दी है।

तेज होगी आर्थिक रफ्तार

नई सरकार

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

जून 4 को 18वीं लोक सभा चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अब बनने वाली एनडीए के तीसरे कार्यकाल की नई सरकार देश को आर्थिक विकास की डगर पर तेजी से आगे बढ़ाएगी। निश्चित रूप से देश को एक बेहतर आर्थिक परिवेश के साथ बेहतर मानसून की सौगात विरासत में मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। स्थिति यह है कि देश की बेहतर आर्थिकी के परिप्रेक्ष्य में दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां यह कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि भारत में कोई भी सरकार बने अब आर्थिकी तेज गति से मजबूत होगी।

उल्लेखनीय कि हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने वर्ष 2023-24 में देश की विकास दर 8.2 फीसद रहने संबंधी रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक आर्थिक व वित्तीय बाजार मजबूत हो रहे हैं। भारत के वित्तीय और गैर वित्तीय क्षेत्रों के दमदार बही-खाते भारत की आर्थिक ताकत बढ़ा रहे हैं। रिजर्व बैंक के द्वारा भारत सरकार को दिया गया रिकॉर्ड लाभांश, वैश्विक आर्थिक संगठनों के द्वारा भारत के विकास के नए-नए प्रभावी विश्लेषण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन सबके साथ-साथ नई सरकार से देश की अर्थव्यवस्था को नई शक्ति मिलने की संभावनाओं से देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ने के शुभ संकेत देते हुए दिखाई दे रही है।

गौरतलब है कि हाल ही में दुनिया की प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, तेज आर्थिक सुधार और बढ़ती राजकोषीय मजबूती के मद्देनजर भारत की रेटिंग को स्थिर यानी स्टेबल से बदलकर पॉजिटिव कर दिया है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि पिछले तीन साल में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की औसत वास्तविक वृद्धि दर 8.1 फीसद सालाना रही है और अब यह विकास दर अगले तीन साल में लगातार 7 फीसद के करीब होगी। दुनिया के प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट बैंकर गोल्डमैन सैक्स ने अपनी नई रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2024 में भारत की विकास दर को बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है। चालू वित्त वर्ष में विकास दर बढ़ने संबंधी अन्य महत्त्वपूर्ण नई रिपोर्टों के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष-आईएमएफ ने 6.8 प्रतिशत, एशियाई विकास बैंक-एडीबी ने 7 प्रतिशत तथा विश्व बैंक ने 7.5 प्रतिशत विकास दर रहने के अनुमान व्यक्त किए हैं।

देश और दुनिया के प्रमुख अर्थ विशेषज्ञों का मत है कि भारत की विकास दर आगामी दशक तक 6.5 से 7 प्रतिशत के स्तर पर दिखाई

देगी। विभिन्न आर्थिक रिपोर्टों में इस बात को भी रेखांकित किया जा रहा है कि भारत में वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) संग्रह 17.7 फ़ीसद बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसी तरह से 2023-24 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) उच्चतम स्तर पर रहा है। इसका आकार 20.18 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 11.7 फ़ीसदी अधिक है। कर संग्रह के ये चमकीले आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज उछाल और व्यक्तियों तथा कॉरपोरेट सेक्टर की आमदनी में वृद्धि को दर्शाते हैं।

इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के द्वारा हाल ही में भारत सरकार के लिए अब तक के सबसे अधिक लाभांश की राशि सुनिश्चित की गई है, वहीं दूसरी ओर देश के शेयर बाजार ने पिछले 10 वर्षों में जो ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, उससे दुनिया भर में भारत के नए तेज विकास की नई संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए लाभांश देने की मंजूरी दी है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में सरकार ने रिजर्व बैंक और सरकारी बैंकों के लाभांश से 1.02 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान लगाया था। ऐसे में 'रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाने वाला लाभांश बजट अनुमान की तुलना में 107 फीसद ज्यादा है। इतना ही नहीं रिजर्व बैंक ने पहली बार आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) बढ़ाकर 6.5 फीसद कर दिया गया है, जो पहले 6 फीसद था। रिजर्व बैंक ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, इसीलिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आकस्मिक जोखिम बफर बढ़ाकर 6.5 फीसद करने का निर्णय लिया गया है।

अब ऐसी आर्थिक मजबूती से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि होगी। यह देश की उत्पादक क्षमता बढ़ाएगा और वृद्धि की संभावनाओं को बेहतर करेगा। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि भारत के प्रति बढ़ते आर्थिक आकर्षण से न केवल देश में ज्यादा एफडीआई लाने में मदद मिलेगी, बल्कि यह विदेशी कंपनियों और निवेशकों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करेगा कि वे भारत से हुई कमाई को फिर भारत में ही निवेश करने के लिए तत्पर रहें। इससे भारत में कारोबारी माहौल में सुधार होगा। यह सुधार उन घरेलू निवेशकों को भी बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा जो अभी किनारे बैठकर निवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एफडीआई का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह भी है कि विदेशी निवेशक तकनीकी विशेषज्ञता भी लाते हैं। चूंकि भारत लगातार चालू खाते के घाटे से जूझ रहा है और भारत को विदेशी बचतों को हासिल करने की जरूरत है, इसलिए एफडीआई भारत में विदेशी बचतों के सबसे टिकाऊ स्रोत के रूप में लाभप्रद होगा।

निश्चित रूप से वर्ष 2023-24 में भारत के विकास दर के 8.2 प्रतिशत रहने, शेयर बाजार के बढ़ने, रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए का बंपर लाभांश दिए जाने से नई सरकार को व्यय प्रबंधन में खासी मदद मिलेगी। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि फरवरी 2024 में संसद में पेश किए वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में सरकार ने 5.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने अपने राजकोषीय मार्ग के तहत वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.5 प्रतिशत पर लाना चाहती है। पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध धन बढ़ने से निश्चित रूप से राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता को बल मिलेगा। इन सबके साथ-साथ नई सरकार आर्थिक विकास की नई रणनीति से देश की आर्थिकी को मजबूती देते हुए तेजी से आगे बढ़ाते हुए दिखाई देगी।

यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि फरवरी 2024 में संसद में पेश किए वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में सरकार ने 5.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने अपने राजकोषीय मार्ग के तहत वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.5 प्रतिशत पर लाना चाहती है। पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध धन बढ़ने से निश्चित रूप से राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता को बल मिलेगा।

'कोल्ड चेन' की मजबूती जरूरी

- दुनिया भर में प्रभावी प्रशीतन की कमी के कारण करीब 14 फीसद भोजन नष्ट हो जाता है, जो एक अरब लोगों का पेट भरने के लिए पर्याप्त है
- नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों में 30 फीसद फल-सब्जियां होती हैं, जो असुरक्षित गोदामों में सड़ जाते हैं। प्रशीतन ढांचे को दुरुस्त करना जरूरी है क्योंकि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते शहरीकरण के फलस्वरूप भोजन, पानी और ऊर्जा की मांग बढ़ने का अनुमान है

(मीडिया इम्पैक्ट)

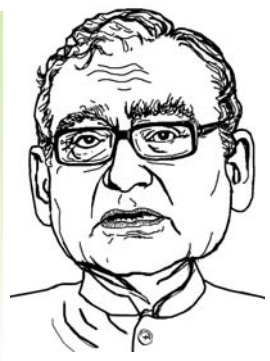

सहयोगियों के रूप में ब्लैकमेलरों के बीच मोदी की बेचारगी...

हर रोज उन्हीं से हंस के मिलना होता है
हमारी कत्ल की साजिश में जिनके दिन गुजरते हैं

पूर्व जस्टिस मार्केण्डेय काटजू
@mkatju

मुद्दा | रजनीश कपूर

न तुम जीते न वो हारे

वर्ष 2024 के लोक सभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। सत्तापक्ष के बड़े-बड़े दावे और उसी से मिलते-जुलते एग्जिट पोल के बाद किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। हालांकि 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं के अलावा एक दो ज्योतिषियों ने टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया था। पर 'इंडिया' गठबंधन पर जिस तरह देश के मतदाताओं ने भरोसा जताया है उससे तो यही सिद्ध हुआ है कि देश में 'लोक' का 'तंत्र' अभी जीवित है। अब सरकार जिस गठबंधन की भी बने देश की संसद में विपक्ष को भी अच्छी संख्या में स्थान मिलेगा। जो भी सरकार बनाएगा अब उसे विपक्ष के दबाव में रह कर कार्य करने पड़ेंगे। एक स्वस्थ लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना भी अनिवार्य है। इसलिए 2024 का चुनाव सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही अच्छा साबित हुआ।

चुनाव के दौरान जिस तरह 'इंडिया' गठबंधन चुनाव आयोग की मशीनरी पर कई तरह के सवाल उठा रहा था उससे आम जनता के मन में भी भ्रम पैदा होने शुरू हो गए थे, लेकिन नतीजों ने एक बार फिर से यह विश्वास जगाया है कि चुनाव में मतदाता ही सर्वोपरि होते हैं। इस बार के चुनावों में किसी भी दल या नेता की, किसी भी तरह की, कोई भी लहर नीं थी। ये चुनाव जनता का चुनाव था। देश भर में फैल रही महंगाई, बेरोजगारी व अन्य परेशानियों से मतदाता त्रस्त था। इसलिए उसे जो जंचा उसी को उसने वोट दिया। आखिरी चरण के मतदान के बाद से जो भी एग्जिट पोल आए वो भी एनडीए की ही सरकार बना रहे थे, परंतु एग्जिट पोल केवल पोल-पट्टी साबित हुए। चुनाव परिणाम के बाद एग्जिट पोल करने वाली एक संस्था के अध्यक्ष जिस तरह एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर फूट-फूट कर रोने लगे उससे तो यह लगा कि उन्हें अपनी करनी पर पछतावा है। पर कई बार जो सामने दिखाई देता है वो असल में सच नहीं होता। उसके पीछे का सच कुछ और होता है। इन सज्जन के विषय में आज ऐसी शंका देश भर में जताई जा रही है। इसका एक कारण यह है कि बिना सर्वेक्षण तकनीकी की बारीकी बताए, बिना सैंपल साइज बताए, बिना प्रश्नावली के प्रश्न बताए, केवल अपना आकलन प्रचारित कर देना अनैतिक होता है। सोचने वाली बात यह है कि जो भी संस्था एग्जिट पोल करती है उसे यह बताने में क्या गुरेज होता है कि उसने एग्जिट पोल करने की

मानक प्रक्रिया को अपनाया या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि ये एग्जिट पोल निहित स्वार्थों के किसी एजेंडा के तहत किए गए? क्या ऐसे सर्वे कराने में किसी मीडिया संस्थान की भी संदिग्ध भूमिका रही?

मिसाल के तौर पर जिस तरह 2024 के लोक सभा चुनावों के एग्जिट पोल दिखाए गए और उसकी प्रतिक्रिया को लेकर देश के शेयर मार्केट में एकदम से भारी उछाल आया उससे आकर्षित हो कर देश के करोड़ों आम निवेशकों ने विश्वास करके बाजार में निवेश कर डाला, परंतु नतीजों के रुझान आने पर शेयर मार्केट बुरी तरह लुढ़का और आम निवेशकों के करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। इससे तो यह साफ प्रतीत होता है कि एकतरफा नतीजे को प्रचारित करके किसी विशेष उद्देश्य से ही एग्जिट पोल को इतना प्रचारित किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि अब जब कोई भी संस्था ईमानदारी से भी एग्जिट पोल या सर्वे करेगी तो उस पर भी संदेह किया जाएगा। शायद गुमराह करने वाले एग्जिट पोल और उसी का प्रचार करने वाले पक्षपाती मीडिया संस्थानों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि नतीजे उनके सर्वेक्षण के विपरीत भी आ सकते हैं। यदि उन्हें ये मालूम था और इस सबके बावजूद एग्जिट पोल वाली संस्था ने ऐसा एग्जिट पोल राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर परोसा तो वो संस्था व चैनल देश की जनता साथ धोखाधड़ी करने के दोषी हैं। जिसकी जांच की जानी चाहिए।

दरअसल, जब तक ऐसा सर्वे करने वाली संस्थाएं अपनी वेबसाइट व अन्य प्रचार सामग्री पर इस बात को पूरी तरह से प्रकाशित न करें कि उस संस्था का किसी भी राजनैतिक दल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है या अपनी तकनीकी का खुलासा न करें, तब तक उस संस्था द्वारा किए गये एग्जिट पोल को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, परंतु हमारे देश में जिस तरह से एग्जिट पोल की भेड़-चाल होती है, वो किसी मनोरंजन से कम नहीं होती।

कुछ भी हो 2024 का चुनाव भी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अपनी जगह बना चुका है। एक ओर जहां एनडीए का 'अबकी बार 400 पार' का नारा विफल हुआ है, वहीं विपक्षी एकता का 'इंडिया' गठबंधन भी कई बार बिगड़ते-बिगड़ते मजबूती से उभर कर आया। विपक्षी दल हों या सत्तापक्षी दल, सभी ने जनता के सामने भी बड़े-बड़े वादे किए हैं और उनको पूरा करने का प्रण भी किया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में वे अपने वायदों को पूरा करेंगे, उन्हें 'जुमला' कह कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ेंगे। जहां तक नई लोक सभा के गठन का सवाल है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि 'न तुम जीते न वो हारे'।

आत्मोकर्ष | श्रीराम शर्मा आचार्य

सृष्टि के मुकुटमणि कहे जाने वाले मनुष्य का गौरव इसमें है कि उसकी चेतना व्यापक क्षेत्र में सुविस्तृत हो। शरीर और परिवार का उचित

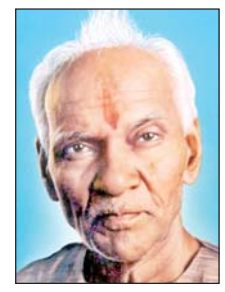

निर्वाह करते हुए भी श्रम, समय, चिंतन और साधनों का इतना अंश बचा रहता है कि उससे परमार्थ प्रयोजनों की भूमिका निभाई जाती रह सके। आत्मीयता का विस्तार होने से शरीर और कुटुम्बियों की ही तरह सभी प्राणी अपनेपन की भावश्रद्धा में बंध जाते है और सबका दुःख अपना दुःख और सबका सुख अपना सुख बन जाता है। वसुधैव कुटुम्बकम की विश्व परिवार की आत्मवत सर्वभूतेषु की भावनाएं बलवती होने पर मनुष्य का स्वार्थ-परमार्थ में परिणत हो जाता है। जो अपने लिए चाहा जाता था वही सब को मिल सके ऐसी आकांक्षा जगती है। जो व्यवहार, सहयोग दूसरों से अपने लिए पाने का मन रहता है। उसी को स्वयं दूसरों के लिए देने की भावना उमड़ती रहती है। लोक-मंगल की-जन-कल्याण की-सेवा साधना की इच्छाएं जगती हैं और योजनाएं बनती है। ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति ससीम न रह कर असीम बन जाता है और उसका कार्यक्षेत्र व्यापक परिधि में सत्प्रवृत्तियों को संवर्धन बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं को पैरों तले कुचल कर फेंक देते हैं। अपनी आवश्यकताओं को घटाते हैं और निर्वाह को न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के उपरांत अपनी सत्प्रयोजनों में लगाए रहते हैं। देश, धर्म, समाज, संस्कृति के उत्कर्ष के लिए किए गए प्रयत्नों में उन्हें इतना आनंद आता है जितना स्वार्थ परायण व्यक्तियों को विपुल धन प्राप्त करने पर भी नहीं मिल सकता। संसार के इतिहास में-आकाश में महामानवों के जो उज्ज्वल चरित्र झिलमिला रहे हैं वे सभी इसी आत्म-विकास के मार्ग का अवलम्बन करते हुए महानता के उच्च शिखर पर पहुंचे थे। संत सुधारक, शहीद यह तीन सामाजिक जीवन के सर्वोच्च सम्मान हैं। महात्मा, देवात्मा और परमात्मा यह तीन अध्यात्म जीवन की समग्र प्रगति के परिचायक स्तर हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए आत्मविकास के सिवाय और कोई मार्ग नहीं। अपनेपन को हम जितने व्यापक क्षेत्र में विस्तृत कर लेते हैं उतने ही विश्वास से यह कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का सुनिश्चित मार्ग मिल गया।

रीडर्स मेल

जोड़-तोड़ की राजनीति

'कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा' इस मुहावरे का मतलब होता है असंगत वस्तुओं या व्यक्तियों को इकट्ठा करके कुछ बना देना। यानी इधर-उधर से अपनी जरूरत की चीजें लेकर कुछ बना देना। इसे आज के हालात में देखें, क्योंकि 2024 के लोक सभा चुनावों में स्पष्ट बहुमत की अनुपस्थिति ने एक बार फिर गठबंधन की राजनीति में निहित जटिलताओं और संकटों को उजागर किया है। यह 1989 के बाद के राजनीतिक परिदृश्य का प्रतीक है, जो एक-पक्षीय प्रभुत्व से लेकर विविध राजनीतिक भागीदारी और खंडित जनादेश वाले युग की ओर चल रहे बदलाव को रेखांकित करता है, जबकि गठबंधन की राजनीति अधिक समावेशी प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दे सकती है, यह संकट से भी भरी हुई है, जो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की स्थिरता और अखंडता को चुनौती देती है। गठबंधन की राजनीति की चुनौतियों का समाधान करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत जैसे चुनावी सुधार, अधिक संतुलित और निष्पक्ष राजनीतिक परिदृश्य बनाने में मदद कर सकते हैं।

देवेन्द्रराज सुथार, जालोर, राजस्थान

गठबंधन सरकार है मजबूरी

देश के चुनाव पर दुनिया भर की नजर थी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में और बड़े बहुमत से लौटने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कम सीटें आने और भाजपा के बहुमत से दूर रह जाने के कारण अब भाजपा को अपने घटक दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी निर्णायक तरीके से राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण क्या अब भी कर पाएंगे। इस लोक सभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जोड़ी ने भाजपा की उम्मीदों से कहीं ज्यादा सीटें लाकर भाजपा को हैरान कर दिया है। फिलहाल एनडीए व इंडिया दोनों ही गठबंधन अपनी-अपनी बैठक करके भविष्य की रणनीति तैयार कर रहे हैं। एक बात को परिणाम देखकर कहा जा सकता है कि लोगों ने मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा नहीं किया है, तभी तो अबकी बार चार सौ पार का नारा ध्वस्त हो गया और भाजपा गठबंधन दलों के भरोसे चलने पर मजबूर हो गई।

डॉ. श्रीगोपाल नारसन, ई मेल से

प्रकृति का साथ सामंजस्य जरूरी

सदियों से महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री पूजा करती आ रही हैं। इसी दिन माता सावित्री ने यमराज से अपने मृत पति को वापस जीवित लेकर आई थी, तभी से पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं वट सावित्री पूजा का अनुष्ठान करती है। इस पूजा के दौरान महिलाएं वट वृक्ष (बरगद) की पूजा करती है, एवं वट वृक्ष के समान अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। यह एक प्रकृति पूजा भी है, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में इस पूजा के दौरान वट वृक्ष के पत्ते तोड़ने की गलत परंपरा जुड़ गई है। यह प्रकृति प्रेम का अनादर है। इस पूजा के दौरान वट वृक्ष में पानी डालना चाहिए एवं नए वट वृक्ष लगाना चाहिए। दरअसल, प्रकृति का संरक्षण ही वास्तविक पूजा है। इसलिए हर किसी को प्रकृति के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना होगा। यह बात सच है कि जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाएंगे तो प्रकृति भी हमारे बारे में ममतमयी होगी। इस बात को गांठ बांध लेना होगा।

हिमांशु शेखर, गया

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

वर्ष-33, अंक 294 | आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026 | *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/All_new

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

दिल्ली के लिए पानी

जल संकट से पीड़ित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पक्ष में देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सुखद और स्वागतयोग्य है। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को दोटूक निर्देश दिया है कि वह दिल्ली को शुक्रवार को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी प्रदान करे। यह प्रशंसनीय है कि हिमाचल प्रदेश सरकार अतिरिक्त पानी छोड़ने पर सहमत हो गई है। हरियाणा सरकार के वजीराबाद बैराज के जरिये यह पानी दिल्ली तक पहुंचेगा। गौर करने की बात है कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलता रहा है, पर आबादी के साथ दिल्ली की जरूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। अतः उसे अतिरिक्त पानी की जरूरत पड़ रही है। क्या दिल्ली में पानी का दुरुपयोग हो रहा है या क्या दिल्ली में आने वाले अतिरिक्त पानी का दुरुपयोग होगा? शायद सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा ही लगता है, इसलिए न्यायालय ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी के खिलाफ चेतावनी भी दी है। वास्तव में, पानी की बर्बादी पर सभी राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए।

पानी की कमी आज की एक निर्मम सच्चाई है और इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को मिलकर प्रबंध करना चाहिए। इसमें अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत कतई नहीं पड़नी चाहिए। गौर करने की बात है कि पिछले सप्ताह, दिल्ली सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से पानी की अतिरिक्त आपूर्ति की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। यह स्थिति प्रशंसनीय नहीं है, शासन-प्रशासन के स्तर पर ही ऐसे मामलों को मिल-जुलकर निपटाना चाहिए। न्यायालय के हस्तक्षेप को आमंत्रित करने से इन प्रदेशों के बीच परस्पर विश्वास कम होगा। बुनियादी रूप से जल की कमी पर सभी को मिलकर गौर करने की जरूरत है। भीषण गरमी के बीच दिल्ली लगभग हर साल जल की कमी से जूझती है। क्या दिल्ली के पास अपने जलाशय नहीं हैं? वर्षा-जल के संग्रहण की क्या व्यवस्था की गई है? क्या जल स्रोतों को संरक्षित करने, खासकर यमुना के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास कारगर नहीं हैं? जल शोधन और जल के पुनः इस्तेमाल के लिए कितने कारगर कदम उठाए गए हैं? दिल्ली चूंकि राजधानी है, अतः जल संरक्षण के मोरचे पर उसे एक आदर्श स्थिति देश के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। जल संकट जैसी बुनियादी समस्या सिर्फ बड़े-बड़े सियासी दावों की वजह से दूर नहीं हो सकती। दिल्ली सरकार आज जिन राज्यों से पानी मांग रही है, उन्हीं राज्यों के साथ मिलकर उसे जलापूर्ति की स्थायी व्यवस्था बनानी चाहिए।

बड़े कदमों की जरूरत है। जल संकट जैसी बुनियादी समस्या सिर्फ बड़े-बड़े सियासी दावों या सर्वोच्च न्यायालय के फौरी फैसलों से कतई दूर नहीं हो सकती।

वैसे, दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पानी बर्बाद करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। निर्माण स्थलों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर किसी भी अवैध जल कनेक्शन को काटने का भी निर्देश दिया गया है। अवैध जल कनेक्शन एक बड़ी समस्या है, जल विभाग को पूरी ईमानदारी से जल की चोरी को रोकना चाहिए। वास्तव में, जल की चोरी करने वाले उसकी बर्बादी भी खूब करते हैं। आम तौर पर व्यावसायिक संस्थान और साधन संपन्न लोग भी जल का बेरहमी से दोहन करते हैं, अतः आम गरीब आदमी को जल का अभाव सर्वाधिक झेलना पड़ता है। भविष्य में जल जब नीला सोना होता जाएगा, तब उसे सहेजने का हुनर सीखना सबके लिए जरूरी होता जाएगा, पर क्या हम यह हुनर सीख-सिखा रहे हैं?

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 07 जून, 1949

चन्द्रनगर में जनमत-संग्रह

चन्द्रनगर की म्यूनिसिपल असेम्बली ने जनमत-संग्रह को स्थगित करने की फ्रांसीसी प्रार्थना ठुकरा दी है। यह इस बात का द्योतक है कि चन्द्रनगर की जनता फ्रांस की एकतंत्रीय सत्ता से संतप्त हो उठी है और अपने भविष्य का शीघ्र से शीघ्र निर्णय करना चाहती है। भारत में बसने वाले अपने ही भाई-बहनों को स्वतंत्र देखकर उसकी व्याकुलता और भी बढ़ गई है और अपने पैरों से पराधीनता की बेड़ियों को वह किसी प्रकार तोड़ फेंकना चाहती है जिस प्रकार भारतवासियों ने किया है।

१५ अगस्त १९४७ को, जब भारत सदियों पुरानी ब्रिटिश दासता से मुक्त हुआ, तो यह बात सभी को अखरी कि देश के कुछ अंग तब भी साम्राज्यवादी शृंखला में आबद्ध थे और वहां की जनता शेष भारत के निवासियों की ओर सहायता के लिए तृषित नयनों से देख रही थी। यह अभाव हृदय को उद्वेलित करने वाला अवश्य था, किंतु किसी को इस बात में लेशमात्र भी सन्देह नहीं था कि जब ब्रिटेन जैसे शक्ति-सम्पन्न साम्राज्यवादी राष्ट्र को भारत से बिस्तर गोल करना पड़ा तो फ्रांस या पुर्तगाल किस गिनती में थे। देश के स्वतंत्र होने के थोड़े ही दिनों पश्चात शेष आठ पराधीन बस्तियों में भी आंदोलन आरंभ हुआ और आज वह आंदोलन फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। इसी महीने की १९ तारीख को चन्द्रनगर में और आगामी दिसम्बर मास की ११ तारीख को शेष फ्रांसीसी बस्तियों में जनमत लिया जायेगा। यही सर्वोत्तम जनतंत्रीय प्रणाली है, यह सिद्ध करने के लिए कि इन बस्तियों की जनता अपनी मातृभूमि भारत के अंक में आना चाहती है या उसे अपनी वर्तमान पराधीनता ही शिरोधार्य है।

जहां तक चन्द्रनगर का प्रश्न है, वह एक स्वतंत्र नगर घोषित किया जा चुका है और वहां की म्यूनिसिपल असेम्बली- जिसमें जनता के ही प्रतिनिधि हैं- बहुत पहले ही भारत में सम्मिलित होने का निर्णय कर चुकी है। सच पूछिये तो उसने फ्रांसीसी सरकार से प्रार्थना की थी कि वह जनमत लिये बिना ही चन्द्रनगर को भारत के हाथों में सौंप दे, किंतु रस्सी जल जाने के बाद भी उसकी ऐंठन नहीं जाती। फ्रांस, भारत में ब्रिटेन के विशाल साम्राज्यवाद की अन्त्येष्टि होते देख चुका है, किंतु अभी उसका खोखला अहंकार उसे वह मार्ग ग्रहण करने से रोक रहा है, जिस पर सद्भावना और मैत्री के वृक्षों की सघन छाया होती है।

उच्च शिक्षा में वाजिब ऊंचाई का इंतजार

क्यूएस ही नहीं, अन्य प्रतिष्ठित रैंकिंग में भी सिर्फ आईआईटी, डीयू-जेएनयू-जामिया मिल्लिया-बीएचयू जैसे केंद्रीय संस्थान और कुछ निजी विश्वविद्यालय ही क्यों शुमार होते हैं?

यहां स्कैन करें

हरिवंश चतुर्वेदी | मुख्य शिक्षा सलाहकार, बिमटेक

दुनिया भर के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग बताने वाली कुकक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) संस्था ने साल 2025 की अपनी रैंकिंग जारी की है, जिससे भारतीय विश्वविद्यालयों की संवर रही तस्वीर की कुछ झलक दिखती है। पूर्व की तरह इस वर्ष भी रैंकिंग में शीर्ष पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) काबिज है, जबकि चार अन्य स्थान क्रमशः इम्पीरियल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के नाम हैं। मगर भारतीय शिक्षण संस्थानों ने भी अपनी रैंकिंग ठीक-ठाक सुधारी है। जैसे, आईआईटी, बॉम्बे को इस बार 118वां स्थान मिला है, जबकि पिछली रैंकिंग में वह 149वें पायदान पर थी। आईआईटी, दिल्ली भी पिछली बार के 197वें स्थान से 150वें पायदान पर पहुंच गई है। इस वर्ष रैंकिंग में शामिल हमारे शीर्ष दस संस्थानों में सबसे अधिक आईआईटी (सात) हैं, जबकि शेष तीन संस्थानों में आईआईएस (211वीं रैंकिंग), दिल्ली यूनिवर्सिटी (328) और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी (323) शामिल हैं।

सवाल है कि क्यूएस ही नहीं, अन्य दो प्रतिष्ठित रैंकिंग- एसजेटीयू व टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में सिर्फ आईआईटी, डीयू-जेएनयू-जामिया मिल्लिया-बीएचयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और कुछ निजी विश्वविद्यालय ही क्यों शुमार होते हैं? बाकी शिक्षण संस्थान मानकों पर क्यों खरे नहीं उतर पाते? इसकी एक वजह तो इन रैंकिंग की रूपरेखा है, जो काफी हद तक पश्चिमी विश्वविद्यालयों के अनुकूल होती है। इनमें कैंपस में विविधता, छात्रों को मिलने वाले रोजगार के अवसर, शोध-कार्य, बुनियादी ढांचा, ब्रांड-वैल्यू आदि तमाम कसौटियों पर संस्थानों को परखा जाता है। ऐसे में, उन भारतीय संस्थानों को इसमें परोक्ष लाभ मिलता है, जो आजादी के पहले या स्वतंत्रता के तुरंत बाद खोले गए, क्योंकि उनको लगातार धनराशि मिलती रहती है। वे इसका जो हिस्सा खर्च नहीं कर पाते, वह धन 'सरप्लस' के रूप में उनके पास जमा रह जाता है और इन पर मिलने वाला ब्याज आदि उनके लिए 'अक्षय निधि' बन जाता है। चूंकि ये पुराने संस्थान हैं, इसलिए इनका यह फंड भी करोड़ों रुपये में हो गया है, जिसका इस्तेमाल ये अपने हित में करते रहते हैं। यह सुविधा अन्य संस्थानों को हासिल नहीं है।

बेशक, तमाम संस्थानों में ट्यूशन फीस ली जाती है, पर यह उनकी कुल आमदनी का बमुश्किल 10 से 20 फीसदी हिस्सा होती है। आमदनी के अन्य स्रोतों का अधिकतम इस्तेमाल शिक्षकों-कर्मचारियों के वेतन-पेंशन आदि में किया जाता है। फिर, उच्च शिक्षा वित्तीयन एजेंसी (हेफा) से जो ब्याज रहित या नाममात्र ब्याज पर कर्ज मिलता है, वह अमूमन केंद्रीय विश्वविद्यालयों या अच्छे संस्थानों के ही खाते में जाता है। इससे स्वाभाविक ही राज्य-स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थिति दयनीय हो जाती है। फिर, राज्यों की आमदनी अलग-अलग है और उनका प्रबंधन भी। आलम यह है कि अब भी हमारे देश में कुल जीडीपी का बमुश्किल तीन फीसदी हिस्सा ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है, जबकि 1968 की पहली शिक्षा नीति में इसे छह प्रतिशत करने की वकालत की गई थी। जब राज्य सरकारों के पास पैसे होंगे ही नहीं, तो वे छह फीसदी कैसे खर्च करेंगी?

यहां यह नहीं समझा जाना चाहिए कि उच्च शिक्षा में महंगी फीस की वकालत की जा रही है। कम फीस के कारण ही देश में कई ऐसे छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर पाते हैं, जिनकी आर्थिक हैसियत निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ने की नहीं होती। मगर सच यह भी है कि राज्य के शिक्षण संस्थानों में शोध-कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, पुस्तकालयों में प्रचुर मात्रा में किताबें नहीं हैं और प्रयोगशालाओं में उचित उपकरण नहीं हैं। इस सूरतेहाल में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होगी कैसे?

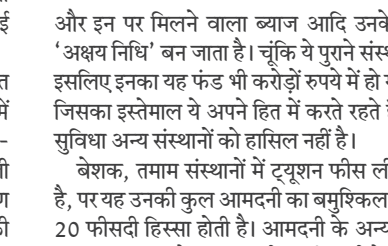

इसका एक उपाय यह हो सकता है कि जो छात्र विपन्न हों, उनसे पूर्ववत फीस ली जाए, पर जो महंगी फीस का भार उठाने में सक्षम हैं, उनसे कुछ अधिक फीस वसूली जाए। हमें यह भी समझना होगा कि अच्छी उच्च शिक्षा के लाभार्थी सिर्फ विद्यार्थी नहीं होते, बल्कि वे संस्थाएं भी होती हैं, जो बच्चों की शिक्षा या कौशल का इस्तेमाल करती हैं। इन कंपनियों से शिक्षण संस्थानों में निवेश करवाया जा सकता है। अगर कंपनियां सीधे निवेश नहीं कर सकतीं, तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) में यह प्रावधान बनाया जा सकता है कि अगर वे अपने सीएसआर मद का तय हिस्सा किसी शिक्षण संस्थान में खर्च करेंगी, तो उनको इन्सेंटिव या टैक्स में छूट मिलेगी।

जाने-माने कारोबारी नौशाद फोर्ब्स ने अपनी किताब *द स्ट्रगल ऐंड द प्रॉमिस* में लिखा है कि हम शोध-अनुसंधान पर जितना खर्च करते हैं, उसका 80 से 90 फीसदी हिस्सा देश के 47 सरकारी प्रयोगशालाओं को चला जाता है। हम इस पैसे को सालाना पांच फीसदी की दर से यदि कम करते जाएं और ये पैसे सरकारी शिक्षण संस्थानों को मुहैया कराएं, तो वहां शिक्षा और शोध-कार्य, दोनों सुधर जाएंगे, उनकी रैंकिंग में बेहतर हो जाएगी। इसी तरह, एक सुझाव यह भी हो सकता है कि जो संस्थान अपनी वैश्विक रैंकिंग सुधारते हैं, उनको इन्सेंटिव दिए जाएं। इस इन्सेंटिव का इस्तेमाल शिक्षकों-कर्मचारियों की बेहतरी पर किया जा सकता है, क्योंकि राज्यस्तरीय विश्वविद्यालयों के करीब 99 फीसदी अध्यापकों के पास आज भी लैपटॉप जैसे आधुनिक उपकरण नहीं हैं। अगर हम अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों से मुकाबला करना चाहते हैं, तो हमें अपने शिक्षकों-कर्मचारियों की गुणवत्ता सुधारनी ही होगी।

यहां हम चाहें, तो चीन से भी सबक ले सकते हैं। उसने पिछले कुछ दशकों में अपने उन नागरिकों को वापस बुलाया है, जो पढ़ने के लिए विदेश गए और वहीं के होकर रह गए। अध्यापन कर्म में लगे ऐसे चीनी नागरिकों को स्वदेश में वे तमाम सुविधाएं दी गईं, जो उन्हें विदेश में मिल रही थीं। इसका फायदा चीन की शिक्षा-व्यवस्था में दिखा है। हमारे देश में भी आईआईटी, आईआईएम या कुछ केंद्रीय व निजी विश्वविद्यालयों के छात्र उच्च शिक्षा हासिल करने विदेश जाते हैं और वहीं कॉलेजों में अपना भविष्य देखते हैं। उनको स्वदेश बुलाना चाहिए और उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि, मुश्किल यह भी है कि देश के कई संस्थानों में भाई-भतीजावाद इस कदर हावी है कि वहां कुलपति तक की नियुक्ति शायद ही प्रतिभा के आधार पर होती है। हमें ऐसे संस्थानों को भी चिह्नित करके वहां पारदर्शी व्यवस्था बनानी होगी, तभी वे अन्य वैश्विक संस्थानों के साथ कदमताल कर सकेंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भारत को और बेहतर बनाने के लिए चंद जरूरी कदम

यहां स्कैन करें

धनेंद्र कुमार | पूर्व अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत कर रहे हैं। आइए, इसे मोदी 3.0 कहें। एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से परिवर्तनकारी नीतियों की आशा इस बार बहुत अधिक है। कन्याकुमारी में अपने 45 घंटे के ध्यान के बाद देश के नाम नरेंद्र मोदी का पत्र भी यही बताता है कि मोदी 3.0 की योजनाओं को जमीन पर उतारेंगे। ऐसे में, हम भावी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं:

मेक इन इंडिया 2.0 के साथ विनिर्माण को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। उनके फोकस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स व बड़े डाटा जैसी उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और दवा जैसे क्षेत्रों के लिए हम विशेष उत्पादक समूहों के विकास की भी आशा कर सकते हैं, ताकि निवेश को आकर्षित करने के लिए कर में छूट, सब्सिडी और सुविधाओं के अलावा दक्षता बढ़ाने और विशेष कौशल विकसित करने में मदद मिल सके और उत्पादन से जुड़े आर्थिक प्रोत्साहन का विस्तार हो सके। नई नौकरियों के अवसर पैदा करने की प्रतिबद्धता के साथ उद्योगों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं भी आ सकती हैं।

तमाम सेवाओं में सुधार करना होगा। बुनियादी ढांचे को और बेहतर करना होगा। महंगाई पर नियंत्रण के ज्यादा बेहतर उपाय करने होंगे।

ज्यादा राजमार्ग, ज्यादा हवाई अड्डे, बंदरगाह और लॉजिस्टिक पार्क बनाकर बुनियादी ढांचे के विकास, गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर होगा। स्मार्ट सिटी मिशन को ज्यादा शहरी क्षेत्रों तक फैलाया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और अन्य दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हाई-स्पीड रेल और राजमार्ग लिंक बनाए जाएंगे। विमान, हथियार और अन्य सैन्य उपकरणों के स्थानीय उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके मजबूत रक्षा तैयारी सरकार के एजेंडे में होगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के आधुनिकीकरण से वित्तीय क्षेत्र में सुधार शुरू किए जा सकते हैं। ऋण और राज्य प्रोत्साहन तक पहुंच को आसान बनाकर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देना जरूरी है। साथ ही, उद्योग लगाने के नियमों व प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा, ताकि उद्योगों का विस्तार देश के पिछड़े राज्यों में भी हो सके।

आर्थिक विविधीकरण जरूरी है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बल मिलेगा। अक्षय ऊर्जा, पर्यटन और सेवाओं में सुधार प्राथमिकता में रहेगा। इस बार कर ढांचे को सरल बनाने की उम्मीद की जा सकती है। निवेश आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट कर में और कटौती की जा सकती है।

व्यापार समझौतों और कूटनीति के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है। अन्य देशों के साथ नए सौदों से नए बाजार खोलने में मदद मिलेगी, जिससे यूरोपीय संघ, आसियान और अफ्रीकी देशों में भारत का व्यापार बढ़ेगा। भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाने के मकसद से शुल्क, सब्सिडी और अन्य उपायों पर ज्यादा काम करना होगा। निर्यात बढ़ने से उत्पादन को भी बल मिलेगा और उत्पादन दक्षता बढ़ेगी।

महंगाई पर नियंत्रण के बेहतर उपाय करने होंगे। कृषि सुधारों, प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग व आपूर्ति शृंखला में सुधार से लोगों को राहत देने की कोशिश होगी। विशेष रूप से फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारत की कोल्ड स्टोरेज क्षमता को बढ़ाना होगा। एक मजबूत राष्ट्रीय कृषि बाजार किसानों को बेहतर मूल्य दिला सकता है।

ऊर्जा दक्षता और लागत में कमी के लिए ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र फोकस में रहेंगे। डिजिटल इंडिया 2.0 और अधिक क्षेत्रों में फैलेगा और बेहतर दक्षता व पारदर्शिता को बढ़ाएगा। हर गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंच जाएगा। अंतरिक्ष उद्योग के क्षेत्र में भी भारत के आकर्षक वैश्विक बाजार बनने की उम्मीद की जा सकती है।

एक हालिया भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हजार साल की अवधि में भारत के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में कहा है कि 'यदि आप बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो बड़ा सोचिए।' हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनका नेतृत्व 2047 तक एक मजबूत और विकसित देश के लिए ठोस नींव रखने का काम करेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सचेतन चुनाव करें

हर व्यक्ति चुनाव कर रहा है; लेकिन अनजाने में किए गए चुनाव दबाव बन जाते हैं। माना कि आप अभी गुस्से में हैं। गुस्सा करना वास्तव में आपका चुनाव है। कहीं न कहीं, आप यह मानते हैं कि स्थिति से निपटने का यही तरीका है, लेकिन चुनाव इतने अनजाने में किया गया है कि वह एक बाध्यता बन जाता है। जिस तरह से आप जी रहे हैं, यह आपका चुनाव है, लेकिन यह चुनाव बिना जागरूकता के, यानी चेतना रहित है। इसलिए महत्वपूर्ण यही है कि हम सचेतन चुनाव करने लगें।

जब आप सुबह जागते हैं, तो अचेतन चुनाव यह होता है कि आप उठना नहीं चाहते। जब सूरज निकलता है, तब अपने चेहरे पर चादर थोड़ी ऊंची तान लेते है। क्या आपने कभी गौर किया है? आपका भौतिक शरीर थोड़ी देर और बिस्तर में रहना चाहता है, और थोड़ी देर, थोड़ी देर और, कई कारणों से यह उठना नहीं चाहता। जीवन के कई पहलू हैं, जिनमें आपकी कई सीमाएं हैं। मान लीजिए, कल आपने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई है। उस दिन सूरज निकलने के पहले ही आप जग जाते हैं। कैसे? एक दिन पहले आपने सचेतन यह फैसला किया था, आप उत्साहित हैं। आप कल की प्रतीक्षा में थे। यह एक आनंदपूर्ण अनुभव है। आप देखेंगे कि सूरज निकलने से पहले आप उठ जाते हैं। अन्यथा, अनजाने में आप चादर और ऊंची तानने की कोशिश करते हैं।

रोशनी ऐसी चीज नहीं है, जिसके लिए आप उत्सुक हैं, क्योंकि उस रोशनी के साथ आज की समस्याएं भी आती हैं; उस रोशनी के साथ पूरा संसार आता है। इसलिए अचेतनतापूर्वक आप खुद को उससे बचाने का प्रयास करते हैं; लेकिन अब हम सचेतन चुनाव करते हैं। आपके जगने के बाद अचेतन चुनाव यह होता है कि आप कॉफी पीना चाहते हैं। उससे शरीर आराम महसूस करता है। लेकिन अब आप एक सचेतन चुनाव करते हैं, 'नहीं, मैं पहले स्नान करूंगा।'

यही कारण है कि तपस्या का मार्ग बनाया गया। आप ऐसी चीजें करना शुरू करते हैं, जो आपके लिए आरामदेह नहीं होतीं। जब आप ऐसा काम करना शुरू करते हैं, जो आपके लिए असुविधाजनक है, तब आप उसे करते तो हैं, लेकिन पसंद नहीं करते। अगर आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है, जो आप पसंद नहीं करते, तो वह केवल सचेतन ही कर सकते हैं; उसे करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। है न? जिन चीजों को आप पसंद करते हैं, आप उन्हें बाध्यतावश कर सकते हैं। मगर जिन चीजों को आप पसंद नहीं करते, उनको आप चेतनापूर्वक ही कर सकते हैं। इसीलिए तपस्या का मार्ग है। इससे आप हर चीज को सचेतन करना शुरू करते हैं। जीने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है।

सच तो यही है कि रोशनी ऐसी चीज नहीं है, जिसके लिए आप बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि उसके साथ आपके सामने आज की समस्याएं आती हैं; उस रोशनी के साथ पूरा संसार आता है।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

डॉ एस वाई कुरैशी | पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

मैंने ईवीएम की विश्वसनीयता का हमेशा बचाव किया। खुशी है, यह भरोसा फिर सही साबित हुआ। मगर मतदाता सूची की शुद्धता, बूथ प्रबंधन जैसी चिंताओं के बजाय कई लोग ईवीएम विरोधी अभियान में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते रहते हैं।

जनादेश से कांग्रेस को मिली संजीवनी

कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में पाया ही पाया है, खोया कुछ नहीं। असल में, उसके पास खोने के लिए कुछ था भी नहीं। मगर सबसे बड़ी बात यह रही कि रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद हारी हुई घोषित इस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत गठबंधन किया और सत्तारूढ़ दल को बढ़िया टक्कर दी। 2014 और 2019 के ठीक उलट इस बार कांग्रेस की पिच पर चुनाव लड़ा गया। इसमें धर्म और पाकिस्तान मुद्दा बन नहीं पाए, मुद्दा बने तो अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी उनका आरक्षण। भाजपा जिसे सवर्णों की पार्टी कहा जाता है और कथित आरक्षण विरोधी भी, इस बार उसके नेताओं को मजबूरन आरक्षण के समर्थन में बार-बार बोलना पड़ा। राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और पाकिस्तान जैसे मुद्दे मतदाताओं के अवचेतन में हो सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर कम ही जनता इस पर बात करती हुई दिखी। जाहिर है, हिंदी पट्टी में कांग्रेस से छिटक चुके दलित, पिछड़े और मुस्लिम वोटरों की उसकी तरफ वापसी पार्टी के भविष्य के लिए सुखद है।

अब इस बात में कोई दोराय नहीं कि इस चुनाव में एक समर्थ कांग्रेस नेता के रूप में राहुल गांधी मजबूती से उभरे हैं और भाजपा द्वारा बनाई गई छवि से आजाद हुए हैं। गरीब और पिछड़े तबके को वह प्रभावित करते दिखे। साफगोई से बात करने की उनकी शैली आम जनता को उनसे जोड़ती है। दो बार की भारत जोड़ो यात्रा ने भी उन्हें लोगों से सीधा संवाद करना सिखा दिया है। स्पष्ट है, दस साल तक शक्तिशाली सत्ता के निशाने पर रहने के कारण वह और ज्यादा परिपक्व व मुखर हो गए हैं। इसी कारण सहयोगी दलों के नेता भी उनका बराबर सम्मान कर रहे हैं, जिससे भारतीय राजनीति में उनका कद अब काफी बढ़ गया है।

हालांकि, कांग्रेस और विपक्ष से जो गलती हमेशा होती आई है, वह इस बार भी हुई है। हद से ज्यादा मोदी विरोध से चुनाव 'मोदी बनाम अन्य' हो गया और कई जगह स्थानीय मुद्दे गौण हो गए। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मतदाताओं की मोदी के प्रति सहानुभूति ने कांग्रेस का खाता नहीं खुलने दिया। वैसे, इस बार मोदी जी का तेज कमजोर पड़ा है और चुनाव नतीजों के बाद की उनकी भाव-भंगिमा भी बता रही है। 2024 में चुनाव नतीजों के बाद भले ही सत्ता एनडीए के पास है, पर देश की राजनीति में कांग्रेस, विशेषकर राहुल गांधी की प्रासंगिकता और स्वीकार्यता बढ़ती दिख रही है। लिहाजा, मृतप्रायः विपक्ष और लोकतंत्र के लिए यह चुनाव किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हुआ है।

नरेश पाराशर, बीमा अधिकारी

अनुलोम-विलोम

कांग्रेस

रणनीति के मोर्चे पर यह अब भी कमजोर

चुनाव नतीजे आने के बाद 'इंडिया' ब्लॉक, खासतौर से कांग्रेस के लोग खुश हैं। कई लोग गठबंधन के प्रदर्शन की तारीफ करते नहीं थक रहे, लेकिन मेरा आकलन कुछ अलग है। मेरा अब भी यही मानना है कि राहुल गांधी ने शुरू में बहुत बढ़िया तरीके से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले करने शुरू किए और उनके लिए कटु शब्दों का प्रयोग शुरू किया, उनकी गाड़ी पटरी से उतरती चली गई। अगर कांग्रेस और 'इंडिया' ब्लॉक के नेतागण सिर्फ मोदी सरकार की कमियों को जनता में उछालते रहते या उनकी बातें करते, तो निस्संदेह गठबंधन का प्रदर्शन इससे बेहतर हो सकता था। मगर नरेंद्र मोदी पर निजी हमले ने उसकी प्रतिष्ठा धूमिल की। रही-सही कसर राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में न जाकर पूरी कर दी गई। जब राम मंदिर ट्रस्ट ने नेहरू-गांधी परिवार को निमंत्रण दिया था, तब भाजपा के कई बड़े नेता इस डर से सहम गए थे कि यदि यह परिवार समारोह में आया, तो कांग्रेस अकेले काफी सीटें जीत सकती है। इसी कारण भाजपा के कई नेता ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि नेहरू-गांधी परिवार इस प्राण-प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार कर दे। ठीक यही हुआ। इसके बाद कांग्रेस ने अपने पैरों पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी कि वह एक बड़ी आबादी की नजर में खलनायक बन गई। कहने वाले कह सकते हैं कि राम मंदिर का नतीजों पर उतना असर नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस यदि राम मंदिर समारोह में शामिल होती, तो मुमकिन है कि उसे फायदा ही मिलता।

जितेंद्र सिंह, टिप्पणीकार

अति-आत्मविश्वास

कांग्रेस इस बार आत्ममुग्धता का शिकार लगी। एक तो चुनाव प्रचार में इसके नेताओं ने आक्रामक तरीका अपनाया। जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। ईवीएम पर सवाल उठाए गए। चुनाव आयोग जैसे संस्थानों को कठघरे में खड़ा किया गया। और जब दाल नहीं गली, तो चुनाव खत्म होने के बाद 295 सीटें आने का दावा किया जाने लगा। यह सब चुनाव जीतने के हथकंडे थे, जिसे कभी भी सकारात्मक राजनीति नहीं माना जा सकता, जिसका दंभ कांग्रेस के नेतागण, विशेषकर राहुल गांधी लगातार भरते रहे हैं। यही कारण रहा कि जनता ने भी कांग्रेस को आईना दिखा दिया। उसकी ऐसी गत बना दी कि वह सत्ता तक नहीं पहुंच सकी। यह सही है कि 99 सीटें उसके खाते में आई हैं, लेकिन बहुमत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को ही मिला है। कांग्रेस चाहे, तो इस चुनाव को एक सबक के तौर पर याद रख सकती है।

संजीव, टिप्पणीकार

दैनिक जागरण

चुनौतियां ही जीवन की वास्तविक परीक्षा हैं

राज्य प्रायोजित हिंसा

बंगाल को लेकर यह आशंका सही साबित होना चिंताजनक भी है और राष्ट्रीय शर्म का विषय भी कि वहां चुनाव बाद हिंसा हो सकती है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का सिलसिला चुनाव के पहले ही कायम हो गया था। राज्य में हिंसा की अनेक घटनाएं चुनाव के दौरान भी देखने को मिलीं और अब चुनाव समाप्त हो जाने के बाद भी देखने को मिल रही हैं। तृणमूल कांग्रेस समर्थक विरोधी दलों और विशेष रूप से भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। ऐसा तब हो रहा है, जब चुनाव आयोग के निर्देश पर बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती 19 जून तक बढ़ा दी गई है। ऐसा चुनाव बाद हिंसा की प्रबल आशंका को देखते हुए किया गया था। यह अश्चर्यजनक है कि बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की चार सौ कंपनियां तैनात हैं और फिर भी वहां हिंसा हो रही है। इसका सीधा अर्थ है कि यह हिंसा तृणमूल कांग्रेस नेताओं के इशारे पर हो रही है। हैरानी नहीं कि अराजक तत्वों को बंगाल पुलिस का मौन समर्थन हासिल हो। इसके आसार इसलिए हैं, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान भी बड़े पैमाने पर जो हिंसा हुई थी, वह बंगाल पुलिस के मूकदर्शक बने रहने के कारण ही हुई थी और इसी के चलते तमाम भाजपा कार्यकर्ता और उसके समर्थकों की हत्या की गई थी। तब हिंसा का दौर इतना भयानक था कि कुछ महिलाओं से दुष्कर्म तक किया गया था। उस समय आतंक का ऐसा माहौल बनाया गया था कि कई लोगों को अपना घर-बार छोड़कर पड़ोसी राज्य असम में शरण लेनी पड़ी थी।

2021 में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का संज्ञान लेते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआइ को हिंसक घटनाओं की जांच करने को कहा था। इस जांच के दौरान तृणमूल कांग्रेस के अनेक नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कार्रवाई भी तृणमूल कांग्रेस के अराजक तत्वों के दुस्साहस का दमन नहीं कर सकी। इसका प्रमाण 2023 में पंचायत चुनाव के दौरान हुई भीषण हिंसा से मिला था, जिसमें 40 से अधिक लोगों की जान गई थी। इस लोकसभा चुनाव में भी हिंसा के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है। यह ठीक है कि चुनाव बाद हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए यहां तक कहा कि यदि राज्य सरकार हिंसा पर लगाम नहीं लगा सकती तो केंद्रीय सुरक्षा बलों को बंगाल में पांच साल तक तैनात करने का आदेश देना पड़ सकता है। उच्च न्यायालय की इस कठोर टिप्पणी के बाद भी ममता सरकार की सेहत पर शायद ही कोई असर पड़े, क्योंकि वह सारा दोष विरोधी दलों पर मढ़ देती है। वास्तव में जब तक बंगाल में हिंसा के लिए ममता सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, तब तक राज्य के हालात सुधरने वाले नहीं हैं।

जीवन के पक्ष में

सफल जीवन के लिए सकारात्मक सोच आवश्यक है। कई बार जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं। इससे व्यक्ति में नकारात्मक विचार भी आते हैं, लेकिन भावावेश में आकर किसी तरह का घातक कदम कतई नहीं उठाना चाहिए। संयमित एवं सहनशील व्यक्ति दृढ़ता से चुनौतियों का सामना करते हैं और नकारात्मक विचारों को हावी नहीं होने देते। आज के प्रतियोगी युग में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी हैं। इसके लिए लोग आय के साधन बढ़ाने के प्रयास करते हैं और कई बार गलत लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। जब व्यक्ति को धोखे का पता चलता है तो वह तनाव में आ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में वह जीवन ही नष्ट करने की ठान लेता है। ऐसा ही मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सामने आया है। स्वास्थ्य उपकेंद्र सैणालाथू में कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ आफिसर (सीएचओ) ने आर्थिक बोझ के कारण आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि उसने क्रिप्टो करेंसी में लोगों का पैसा लगाया था। धोखाधड़ी का मामला सामने आने पर लोग उससे पैसा मांग रहे थे। इस कारण वह तनाव में थी। चिंतनीय है कि राज्य में आत्महत्या के मामले निरंतर सामने आ रहे हैं। परीक्षा में असफल रहने पर बच्चे जान देने लगे हैं। कई बार स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, लेकिन उनसे हार मान लेना कतई सही नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं है, जिसे हल नहीं किया जा सकता। संयम और संवाद से काफी हद तक समस्या को निपटाया जा सकता है। जीवन को नष्ट करना किसी समस्या का हल नहीं है। परिस्थितियों से लड़कर ही जीवन की राहें आसान की जा सकती हैं। विकट परिस्थितियों में यह हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाए ताकि वह परेशानी का कारण न बने।

चिंता का विषय है कि लोग विकट परिस्थितियों में जीवन को ही दांव पर लगा रहे हैं

देश-दुनिया के लिए जनादेश का संदेश

शिवकांत शर्मा

मतदाताओं का रुझान दर्शाता है कि वे ऐसा सशक्त विपक्ष चाहते थे, जो सत्तापक्ष को निरंकुश न होने दे और सरकार की योजनाओं में लोकहित को सुनिश्चित करे

पिछली संसद के अंतिम बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था, 'मैं आंकड़ों में नहीं पड़ता। मैं बस देश का मिजाज देख रहा हूं, जो इस बार राजग को 400 सीट पार तो कराकर रहेगा ही और अकेले भाजपा को 370 सीट मिलेंगी।' संसदीय बहस की गहमागहमी में ऐसी गर्वोक्तियां चलती हैं। चुनावी रणनीति बनाते समय भी पार्टियां इस तरह के ऊंचे लक्ष्य लेकर चलती हैं, परंतु उन्हें चुनावी नारा नहीं बनाया जाता, अन्यथा उनके हासिल न होने पर जीत भी हार जैसी दिखने लगती है और पार्टी उपहास का पात्र बन सकती है। इस आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और उनके नाम पर जनादेश लेने मैदान में उतरी भाजपा के साथ यही हुआ। इतिहास में केवल दूसरी बार मिले लगातार तीसरे जनादेश को उनकी जीत की जगह हार के रूप में देखा जा रहा है और उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वह पार्टी को पूर्ण बहुमत न दिला पाने की नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दें।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया में 'मोदी की अजेयता की आभा टूटी', 'मोदी के नेतृत्व का अप्रत्याशित अस्वीकार' और 'मोदी को अप्रत्याशित धक्का' जैसे शीर्षक लगाए गए हैं। वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग 21 सीटों के बहुमत से जीता है। भाजपा भी 240 सीटें जीतकर संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसने दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस से ढाई गुना सीटें जीती हैं। राजग को 45 प्रतिशत वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन 42 प्रतिशत वोट ले पाया। भाजपा को कांग्रेस से 15 प्रतिशत अधिक वोट मिले हैं। यह काफी बड़ी बढ़त है।

इसलिए चुनाव नतीजों की तस्वीर साफ होते ही मोदी को लगातार तीसरा जनादेश हासिल करने पर विश्व भर के नेताओं ने बधाई संदेश भेजे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने फोन कर ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी और भारत के साथ व्यापार एवं सामरिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के संकल्प को रेखांकित किया। साथ ही मानव इतिहास के वृहत्तम लोकतांत्रिक पर्व में भाग लेने के लिए भारत के लोगों की सराहना की। उनकी इस सराहना से भारत की चुनाव प्रक्रिया, संवैधानिक संस्थाओं और ईवीएम मशीनों पर भारत और बाहर से उठाए जाने वाले सवालों की आधारहीनता भी साबित हो जाती है। बाइडन के अलावा रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत विश्व के कई अन्य नेताओं ने बधाई के लिए फोन किए। मोदी को चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्राजील समेत सौ से अधिक देशों के बधाई संदेश मिल चुके हैं।

अवधेश राजपूत

जनादेश से लगता है कि लोग ऐसा सशक्त और जिम्मेदार विपक्ष चाहते थे, जो सत्तापक्ष को निरंकुश न होने दे और सरकार की योजनाओं में लोकहित को सुनिश्चित करे। मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से चली आ रही बहुमत की सरकार से कुछ लोगों को सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि वह अपने बहुमत का प्रयोग आक्रामक शैली में करती थी। अब जनता ने विपक्ष को और मजबूत बनाकर भेजा है। उम्मीद है कि मोदी और उनकी पार्टी बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए अपनी सरकार को गठबंधन धर्म से चलाएंगे। यदि मोदी ऐसा करते हैं तो विपक्ष को भी अपने रवैये को बदलते हुए रचनात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए। देश में इससे पहले भी लंबे समय तक गठबंधन सरकारें रह चुकी हैं। इसलिए भारतीय चुनावों पर नजर रखने वाले ऐसे मित्र देशों को भी मोदी सरकार को कम बहुमत मिलने और विपक्ष के मजबूत होने पर चिंता नहीं होगी, जो मोदी सरकार की आक्रामक नीतियों के कारण प्रतिरोधी स्वरों को दबाए जाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर पड़ने की आशंका से असहज रहते थे, लेकिन वैश्विक समुदाय यह भी नहीं चाहेगा कि भारत की नई गठबंधन सरकार धरने-प्रदर्शनों से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता में उलझकर अपनी उन नीतियों पर ढीली पड़ जाए, जो आर्थिक सुधारों और जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए आवश्यक हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हुई बयानबाजी से ऐसे संकेत मिले थे कि विपक्षी गठबंधन मोदी सरकार की बजट संयम, आर्थिक सुधार और जलवायु परिवर्तन की रोकथाम संबंधी नीतियों को पलटने का इरादा रखता है। इसीलिए परिणामों के प्रारंभिक रुझानों को देखते ही भारत के शेयर और मुद्रा बाजारों में भूचाल जैसा आ गया था।

दुनिया इस समय दो बड़े सामरिक संकटों से जूझ रही है। गाजा में चल रही लड़ाई से हुए व्यापक विनाश के बाद भी युद्धविराम समझौता नहीं हो पा रहा है। उधर रूस यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव पर कब्जे की तरफ बढ़ रहा है। चीन और अमेरिका के बीच भी व्यापारिक और सामरिक तनाव बढ़ रहा है, जिसके कारण दुनिया फिर से दो खेमों में बंटी नजर आती है। एक खेमे में अमेरिका, यूरोप और उनके मित्र देश हैं। दूसरे खेमे में रूस, चीन और उनके मित्र देश। इस विषम परिस्थिति में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वह दोनों खेमों के बीच शांति और सुलह के एक पुल की भूमिका अदा कर सकता है और विश्वमंच पर अपना उचित स्थान हासिल कर सकता है।

इस वर्ष अमेरिका समेत दुनिया के लगभग 75 देशों में हो रहे चुनावों की वजह से राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल भी बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपतीय चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है। कई संगीन मामलों के अभियुक्त होने और एक में दोषी ठहराए जाने के बावजूद वह लोकप्रियता में राष्ट्रपति बाइडन से आगे चल रहे हैं। उनकी जीत अमेरिका समेत पूरे विश्व के राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक समीकरणों पर असर डाल सकती है। उनके आने पर भारत को अपनी चीन संबंधी सामरिक नीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)

response@jagran.com

नई सरकार की आर्थिक चुनौतियां

डा.ब्रजेश कुमार तिवारी

अर्थव्यवस्था के बढ़ते आकार के बीच भारत के लिए आर्थिक असमानता को पाटने की भी एक बड़ी चुनौती है

आर्थिक सुधारों से ही गति पकड़ेगी आर्थिकी। प्रतीकात्मक

नरेन्द्र मोदी लगातार तीसरी बार देश की कमान संभालने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में नई सरकार के कंधों पर वित्त वर्ष 2023-24 में दर्ज की गई 8.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि को आगे बढ़ाने के साथ ही भारत को पांच ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की अहम जिम्मेदारी होगी। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में भारत वैश्विक स्तर पर 11वीं से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। नई सरकार की नजर भारत को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में ले जाने पर होगी। आर्थिक मोर्चे पर तात्कालिक चुनौती महंगाई और बेरोजगारी है। तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। भारत में 94 प्रतिशत कर्मचारी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और देश का 35 प्रतिशत उत्पादन इसी में होता है। कई वर्षों से असंगठित क्षेत्र का दायरा सिकुड़ रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ का आगमन सेवा क्षेत्र के रोजगारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत की जीडीपी में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान इसी क्षेत्र का है। बेरोजगारी एवं महंगाई केवल राजनीतिक विषय नहीं हैं। अगर बेरोजगारी रहेगी और आय नहीं बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति प्रभावित होगी। उपभोग और निवेश का स्तर भी इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए सबसे पहले बेरोजगारी दूर करने पर ध्यान देना होगा। आज देश के 85 प्रतिशत स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। इसके लिए स्टार्टअप इंडिया योजना को और अधिक महत्व देना होगा। अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार की जरूरत के साथ ही सरकारी भर्तियों में तेजी लानी होगी। असंगठित क्षेत्र को हाशिए पर धकेलने वाली नीतियों में भी बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। आज भारत में प्रति व्यक्ति आय 2,601 डालर है और 197 देशों में प्रति व्यक्ति आय के मामलों में भारत 142वें पायदान पर है। मुद्रास्फीति भी देश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। पिछले कुछ समय से रसोई का बजट अनियंत्रित और असंतुलित हुआ है।

आम लोगों पर महंगाई की मार के दूरगामी असर होते हैं। याद रहे कि महंगा भोजन आबादी के स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है। इसे देखते हुए आज हमें जीडीपी से ज्यादा मानव विकास पर फोकस करना चाहिए, जिसमें शिक्षा एवं स्वास्थ्य सबसे ऊपर हैं। आज देश के सामने बड़ी चुनौतियों में अच्छी शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रमुख हैं। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी ओर, उच्च शिक्षा के केवल कुछ संस्थान ही उन्नत अनुसंधान में शामिल हैं। भारत में शुरू से शिक्षा पर तुलनात्मक रूप से सार्वजनिक व्यय कम रहा है। वहीं प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का शोध एवं विकास (आरएंडडी) व्यय-जीडीपी अनुपात में मात्र 0.7 प्रतिशत है। यह 1.8 प्रतिशत के विश्व औसत से भी बहुत कम है। यदि सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद आज भी अगर देश के 80 करोड़ लोग को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है तो निश्चित ही यह जनसंख्या अकुशल है। स्किल इंडिया योजना कई कारणों से अपेक्षित सफलता नहीं पा सकी, जिसका मुख्य कारण प्रशिक्षण से संबंधित बुनियादी ढांचे की कमी और निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी है। याद रहे एक कुशल और शिक्षित श्रम बल ही देश को उच्च विकास दर की ओर ले जाता है।

कौशल एवं शिक्षा ऐसा क्षेत्र है, जहां निवेश के कई प्रभाव होते हैं। जब कार्यबल अधिक कुशल बनेगा, तब आर्थिक विकास की गति को बल मिलेगा, सामाजिक बुराइयां कम होंगी और महिलाएं भी सुरक्षित होंगी। परिणामस्वरूप देश का तेजी से विकास होगा। भारत चालू खाते के घाटे से भी लगातार जूझता रहा है, जिसका अर्थ है कि देश का आयात इसके निर्यात से अधिक है। पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत की वैश्विक निर्यात में बमुश्किल 1.6 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 'मेक इन इंडिया' अभियान का एक प्राथमिक उद्देश्य 2022 तक भारतीय जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक बढ़ाना था। हालांकि पिछले नौ वर्षों में यह स्तर 14 से 16 प्रतिशत के बीच अटका है। अर्थव्यवस्था के बढ़ते आकार के बीच भारत के लिए आर्थिक असमानता को पाटने की भी बड़ी चुनौती है। देश में केवल अरबपतियों की संख्या बढ़ने से काम नहीं बनेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भले भारत की स्थिति पांचवीं हो गई हो, मगर विकास का हिस्सा बहुतों तक अभी पहुंच नहीं रहा है।

खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने, आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कृषि आधारित उद्योगीकरण द्वारा संचालित होना चाहिए। सरकार के निवेश प्रोत्साहन पर निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया अपर्याप्त रही है, फिर भी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर सरकारी खर्च जारी रहना चाहिए। नई सरकार को बांड बाजार, बीमा बाजार और पेंशन बाजार का विकास भी करना चाहिए, जो अवसंरचना के लिए दीर्घकालिक वित्त और वृद्ध जनों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जीएसटी को भी सुसंगत बनाने की जरूरत है। सरकार अगर चाहे तो कर राजस्व बढ़ाने के लिए कारपोरेट कर, संपत्ति कर जैसे कर बढ़ा सकती है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण नीतियों का सख्ती से कार्यान्वयन भी जरूरी है। अर्थव्यवस्था पर बढ़ते कर्ज का कारगर समाधान भी निकालना होगा। निजी निवेश में सुधार अर्थव्यवस्था में तरक्की का सबसे अहम कारक होगा और अगली सरकार को इस पर खास जोर देना चाहिए। हाल में आरबीआइ ने केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये के लाभांश (डिविडेंट) भुगतान करने का एलान किया है। सरकार को इस धन को शिक्षा एवं रोजगार निर्माण में लगाना चाहिए और किसी भी रेवड़ी वाली योजना से दूर रहना चाहिए।

(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ऊर्जा

परख

परीक्षण शक्ति को परख कहते हैं। संसार में अच्छे-बुरे की पहचान इसी से होती है। अतः किसी के प्रति आकर्षण या विकर्षण का कारण यही है। यह मानव की आंतरिक शक्ति है, जो प्रायः सभी में नहीं होती। जिसमें यह क्षमता होती है, उसे विशिष्ट बना देती है। फिर सभी कार्य जांच-परखकर किए जाते हैं। कभी पश्चाताप नहीं होता। इसलिए यदि जीवन की दिशा की निर्धारणा संगति से होती है, तो संगति की परख से। इसके बिना बच्चे ही नहीं, बड़े भी कुसंग में सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। जिनमें यह शक्ति होती है उनमें सत्संग के कारण अवगुणों का आगमन नहीं होता। मन, वाणी एवं कर्म पवित्र रहते हैं। सामाजिक प्रवंचना का शिकार नहीं होना पड़ता। अतः जीवन की सफलता पारखी शक्ति पर निर्भर है। यद्यपि इसका प्रारंभ परिवार से होता है। वास्तव में इसकी प्राप्ति गुरु के सान्निध्य में होती है, क्योंकि शिष्य में पारखी शक्ति का विकास करना गुरु का प्रथम कर्तव्य है।

परख का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, जहां इसकी आवश्यकता न हो। जीवन में पूर्ण सफलता के लिए परख केवल बाह्य जगत की नहीं, अपनी भी होनी चाहिए। जब यह क्षमता जागृत हो जाती है तब हम अपने भी गुरु बन जाते हैं। हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होने लगता है और हम परमात्मा के सामीप्य का अनुभव करते हैं। इस विलक्षण शक्ति के जन्मदाता गुरु सहज ही शिष्य की आंतरिक शक्तियों को पहचान लेते हैं।

स्वामी विवेकानंद जब गुरु के पास गए तो प्रथम दृष्टि में ही उन्होंने इन्हें पहचान लिया। फिर उनकी आत्मिक परख को जागृत कर तर्क बुद्धि को राष्ट्रभक्ति में परिवर्तित कर दिया। परिणामतः उन्होंने राष्ट्र को जगद्गुरु के गुरुतर पद पर प्रतिष्ठापित किया। यह उनकी आत्मिक परख का परिणाम था। अतः आत्ममंगल के लिए इसे अपने अंदर जागृत करना प्रत्येक मानव का धर्म है।

डा. सत्य प्रकाश मिश्र

जरूरतों पर भारी पड़ रहीं इच्छाएं

सोनम लववंशी

अब समय आ गया है जब धरती पर उपलब्ध संसाधनों का संयमित उपभोग और सही जीवनशैली को अपनाया जाए

तपती धरती, नष्ट होते जंगल, गहराता जल संकट और हवा में घुलते जहर की शिकायत तो सभी करते हैं, पर पर्यावरण के बिगड़ते हालात के प्रति जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। जबकि पर्यावरण का मुद्दा समग्र समुदाय से जुड़ा है। आज बढ़ती आधुनिकता ने हमारी जीवनशैली को काफी हद तक प्रभावित कर दिया है। आज का युवा यूज एंड थ्रो के कल्चर की तरफ बढ़ चला है। लोग फैशन के चक्कर में आए दिन नई नई गाड़ी, फोन, घर के समान, कपड़ा आदि खरीद रहे हैं। हर दो-चार साल में पुरानी के बदले नई चीजें लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अब से कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं होता था। आज स्क्रीन पर एक टच से घर बैठे कुछ भी मंगाया जा सकता है। इसने जीवन को आसान भले बना दिया है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पर्यावरण के लिए बहुत ही दुखदायी है। अकेला कपड़ा बाजार वैश्विक स्तर पर सालाना 92 मिलियन टन कचरा पैदा करता है। सोचिए यह पर्यावरण के बिगड़ते स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है। कपड़ा बाजार को साल 2050 तक वैश्विक तापमान दो डिग्री कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन कटौती में 26 प्रतिशत योगदान करना होगा।

अब समय आ गया है जब धरती पर उपलब्ध संसाधनों का संयमित उपभोग और सही जीवनशैली को अपनाया जाए। क्योंकि पर्यावरण की आबोहवा जहरीली बनाने में हमारी जीवनचर्या भी जिम्मेदार है। दिखावे की बढ़ती संस्कृति ने हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। आज हमारी जरूरतों पर इच्छाएं भारी पड़ रही हैं। शहरों ही नहीं, गांवों में भी गैर-जरूरी सुविधा को जुटाना आम हो चला है। आधुनिक जीवनशैली से जुड़ी ऐसी तमाम चीजें हैं, जो धरती पर बोझ बढ़ाने का काम कर रही हैं।

हमारी सनातन संस्कृति में पेड़-पौधों से लेकर नदियों और पहाड़ों तक को पूजने की परंपरा रही है, लेकिन पश्चिमी संस्कृति के मोहजाल में हम अपनी पुरातन परंपरा को भूलते जा रहे हैं। सुख-सुविधाएं जुटाता हुआ इंसान यह भूल कर रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण खुद उसके अस्तित्व को बचाने के लिए भी जरूरी है। धरती का अंधाधुंध दोहन हमारे जीवन के लिए संकट बन गया है। देश में वायु प्रदूषण से हर एक मिनट में दो लोगों की जान जा रही है। वायु प्रदूषण के कारण भारत में 15 फीसद बच्चे समय से पहले पैदा हो रहे हैं। जिस भारतीय संस्कृति में रि-साइकिल न हो सकने वाली किसी चीज के प्रयोग का प्रविधान ही नहीं था, वहां अब यूज एंड थ्रो कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते कचरे के पहाड़ इसके सुबूत हैं। यूज एंड थ्रो की संस्कृति ने प्लास्टिक की खपत भी बढ़ा दी है। यदि हमने इस कल्चर को नहीं छोड़ा तो आने वाले समय में विश्व पालीथीन कचरे का ढेर बन जाएगा।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

नई चुनौतियों के बीच भाजपा

'भाजपा को बदलनी होगी रीति-नीति' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में अवधेश कुमार ने बदलते राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा को अपनी रीति-नीति में बदलाव लाकर जमीनी स्तर पर काम करने और युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने पर जोर डाला है। 2014 के बाद से भाजपा ने अपनी नीतियों और चुनावी रणनीतियों में कई बदलाव किए, जिससे उसे अद्वितीय सफलता मिली, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में केवल विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे काफी नहीं हैं। जनता अब ठोस परिणाम चाहती है और स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान चाहती है। भाजपा को जमीनी स्तर पर काम करना होगा, जिससे जनता का विश्वास फिर से जीत सके। पार्टी को क्षेत्रीय नेताओं को सशक्त करना और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ाना होगा और उनकी समस्याओं को समझकर समाधान निकालना होगा। इसके अलावा गठबंधन सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बनाना जरूरी है। गठबंधन राजनीति में समझौता और संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होता है, ताकि केंद्रीय और राज्य स्तर पर पार्टी की स्थिति मजबूत बनी रहे। युवाओं के लिए नई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत भी भाजपा के लिए आवश्यक है। आज का युवा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दे रहा है। यदि भाजपा इन क्षेत्रों में सुधार करती है तो उसका जनाधार और मजबूत हो सकता है। पार्टी को चाहिए कि वह युवाओं की अपेक्षाओं को समझे और उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए। अंततः भाजपा को अपनी रीति-नीति में लचीलापन लाना होगा और समय के साथ चलना होगा। परिवर्तन ही स्थिरता का मंत्र है। भाजपा अगर इन बातों को ध्यान में रखती है तो भविष्य में उसे अपेक्षित सफलता मिल सकती है।

अमरजीत सिंह, चिरैला, बिहार

मेलबाक्स

संभलना होगा भाजपा को

लोकसभा चुनाव के परिणाम कतई भाजपा की अपेक्षा के अनुसार नहीं हैं और उसका खुद बहुमत की 272 सीट न पाना इसी का नतीजा है। हालांकि नरेन्द्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे। लेकिन भाजपा निस्संदेह कमजोर हुई है और मोदी स्वयं को असहाय भी महसूस कर सकते हैं। जब से वह चुनावी राजनीति का हिस्सा हैं, उन्होंने कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है और यह उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। आंकलन करने के बाद कई चीजें निकलकर आती हैं, जो भाजपा की हार के पीछे के कारण हो सकते हैं। इंटरनेट मीडिया के हैंडल पर चुनाव नहीं लड़े और जीते जाते हैं। गलत सीटों का बंटवारा, दूसरे दलों से नेता लेकर उनको भाजपा से चुनाव लड़वाना और अपनी आलोचना न सुनना, जमीनी कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों से दूरी बना लेना ऐसे कई कारण हैं। सबसे अहम बात भाजपा के विधायकों और सांसदों को समझनी पड़ेगी कि ब्रांड मोदी भी एक सीमा तक ही चल सकता है। ऐसे में उनका खुद का काम और व्यवहार बोलना चाहिए। मोदी नाम की बैसाखी से आप लंबे समय तक चुनाव नहीं जीत सकते हैं। सांसद और विधायक को संसद और विधानसभा के सत्र के बाद सदैव अपने क्षेत्र में लोगों के बीच रहना चाहिए और 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए। जेपी नड्डा का यह कहना कि भाजपा और भगवा का कोई संबंध नहीं है और हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, अहंकार से भरे हुए बयान थे, जो पार्टी को बेहद महंगे साबित हुए। जब विपक्ष बार-बार यह कह रहा था कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान बदल देंगे और दलितों का आरक्षण समाप्त कर देंगे। जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था तो भाजपा इस भ्रांति को भी नहीं समाप्त कर पाई। सब लोग यह सोचकर बैठ गए कि मोदी के नाम पर वोट मिल जाएगा और बहुमत बना लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस झटके से भाजपा नेतृत्व को सीख लेने की जरूरत है। वरना आने वाले प्रदेश चुनावों में हालत और खराब हो सकते हैं।

बाल गोविंद, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

चुनौतियां ही जीवन की वास्तविक परीक्षा हैं

राज्य प्रायोजित हिंसा

बंगाल को लेकर यह आशंका सही साबित होना चिंताजनक भी है और राष्ट्रीय शर्म का विषय भी कि वहां चुनाव बाद हिंसा हो सकती है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का सिलसिला चुनाव के पहले ही कायम हो गया था। राज्य में हिंसा की अनेक घटनाएं चुनाव के दौरान भी देखने को मिलीं और अब चुनाव समाप्त हो जाने के बाद भी देखने को मिल रही हैं। तृणमूल कांग्रेस समर्थक विरोधी दलों और विशेष रूप से भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। ऐसा तब हो रहा है, जब चुनाव आयोग के निर्देश पर बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती 19 जून तक बढ़ा दी गई है। ऐसा चुनाव बाद हिंसा की प्रबल आशंका को देखते हुए किया गया था। यह आश्चर्यजनक है कि बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की चार सौ कंपनियां तैनात हैं और फिर भी वहां हिंसा हो रही है। इसका सीधा अर्थ है कि यह हिंसा तृणमूल कांग्रेस नेताओं के इशारे पर हो रही है। हैरानी नहीं कि अराजक तत्वों को बंगाल पुलिस का मौन समर्थन हासिल हो। इसके आसार इसलिए हैं, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान भी बड़े पैमाने पर जो हिंसा हुई थी, वह बंगाल पुलिस के मूकदर्शक बने रहने के कारण ही हुई थी और इसी के चलते तमाम भाजपा कार्यकर्ता और उसके समर्थकों की हत्या की गई थी। तब हिंसा का दौर इतना भयानक था कि कुछ महिलाओं से दुष्कर्म तक किया गया था। उस समय आतंक का ऐसा माहौल बनाया गया था कि कई लोगों को अपना घर-बार छोड़कर पड़ोसी राज्य असम में शरण लेनी पड़ी थी। 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का संज्ञान लेते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआइ को हिंसक घटनाओं की जांच करने को कहा था। इस जांच के दौरान तृणमूल कांग्रेस के अनेक नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कार्रवाई भी तृणमूल कांग्रेस के अराजक तत्वों के दुस्साहस का दमन नहीं कर सकी। इसका प्रमाण 2023 में पंचायत चुनाव के दौरान हुई भीषण हिंसा से मिला था, जिसमें 40 से अधिक लोगों की जान गई थी। इस लोकसभा चुनाव में भी हिंसा के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है। यह ठीक है कि चुनाव बाद हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए यहां तक कहा कि यदि राज्य सरकार हिंसा पर लगाम नहीं लगा सकती तो केंद्रीय सुरक्षा बलों को बंगाल में पांच साल तक तैनात करने का आदेश देना पड़ सकता है। उच्च न्यायालय की इस कठोर टिप्पणी के बाद भी ममता सरकार की सेहत पर शायद ही कोई असर पड़े, क्योंकि वह सारा दोष विरोधी दलों पर मढ़ देती है। वास्तव में जब तक बंगाल में हिंसा के लिए ममता सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, तब तक राज्य के हालात सुधरने वाले नहीं हैं।

दूर हो गतिरोध

राज्य के विश्वविद्यालयों में बीते कुछ दिनों से व्याप्त वित्तीय संकट व अन्य समस्याओं को दूर करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कुलपतियों की बैठक बुलाई है। जिसके जरिए सरकार विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति की वास्तविक स्थिति को समझने तथा उसके समाधान की कोशिश करेगी। थोड़ा विलंब से ही सही, लेकिन यह पहल काफी कारगर साबित होगी। इस पर राजभवन सचिवालय की ओर से सहमति मिल गई है कि बैठक में संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति बैठक में शामिल होंगे। विदित हो कि इस वजह से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक-गैरशैक्षणिक कर्मियों व पेंशनधारकों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था तथा दैनिक कार्यकलाप पर भी असर पड़ रहा था। राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। स्कूली हो या उच्च शिक्षा, दोनों ही मामले में मानव संसाधन तथा आधारभूत संरचना पर विशेष जोर दिया जा रहा है। किसी भी मद में धनराशि की कमी से ऐसे प्रयासों को बाधा पहुंचती है। अतएव, जितनी जल्दी हो इस संदर्भ में किसी भी स्तर पर किसी भी तरह के गतिरोध को यथाशीघ्र दूर करने की जरूरत है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा भी तीसरी अध्यापक नियुक्ति पुनर्परीक्षा जल्द से जल्द लेने की कवायद शुरू कर दी गई है। जाहिर है, विभागीय टकराव को छोड़ बेहतर समन्वय के साथ सामूहिक प्रयास नहीं किए जाएंगे तबतक अपेक्षित परिणाम की कल्पना बेमानी ही रहेगी। विश्वविद्यालयों व कालेजों में शैक्षणिक सत्र सममय चले, यह जरूरी है। उम्मीद की जा सकती है कि बैठक के बाद वित्तीय संकट सहित जो अन्य समस्याएं हैं, उनका भी समाधान निकलेगा।

किसी व्यवस्था के सुचारु संचालन में वित्तीय संकट उत्पन्न न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। यदि कोई बाधा है तो उसे तत्काल दूर करने का प्रयास होना चाहिए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

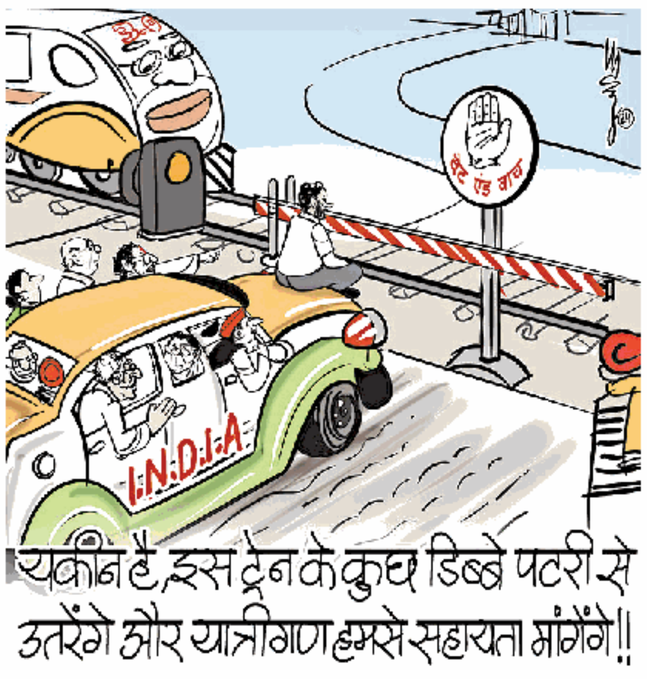

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या नई राजग सरकार में सुधारों का सिलसिला जारी रहेगा?

आज का सवाल
क्या गठबंधन सरकार को सहयोगी दलों के दबाव का सामना करना पड़ेगा?

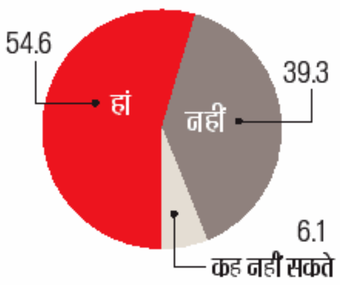

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

देश-दुनिया के लिए जनादेश का संदेश

शिवकांत शर्मा

मतदाताओं का रुझान दर्शाता है कि वे ऐसा सशक्त विपक्ष चाहते थे, जो सत्तापक्ष को निरंकुश न होने दे और सरकार की योजनाओं में लोकहित को सुनिश्चित करे

पिछली संसद के अंतिम बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था, 'मैं आंकड़ों में नहीं पड़ता। मैं बस देश का मिजाज देख रहा हूं, जो इस बार राजग को 400 सीट पार तो कराकर रहेगा ही और अकेले भाजपा को 370 सीट मिलेंगी।' संसदीय बहस की गहमागहमी में ऐसी गर्वोक्तियां चलती हैं। चुनावी रणनीति बनाते समय भी पार्टियां इस तरह के ऊंचे लक्ष्य लेकर चलती हैं, परंतु उन्हें चुनावी नारा नहीं बनाया जाता, अन्यथा उनके हासिल न होने पर जीत भी हार जैसी दिखने लगती है और पार्टी उपहास का पात्र बन सकती है। इस आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और उनके नाम पर जनादेश लेने मैदान में उतरी भाजपा के साथ यही हुआ। इतिहास में केवल दूसरी बार मिले लगातार तीसरे जनादेश को उनकी जीत की जगह हार के रूप में देखा जा रहा है और उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वह पार्टी को पूर्ण बहुमत न दिला पाने की नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दें।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया में 'मोदी की अजेयता की आभा टूटी', 'मोदी के नेतृत्व का अप्रत्याशित अस्वीकार' और 'मोदी को अप्रत्याशित धक्का' जैसे शीर्षक लगाए गए हैं। वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग 21 सीटों के बहुमत से जीता है। भाजपा भी 240 सीटें जीतकर संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसने दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस से ढाई गुना सीटें जीती हैं, जो पूरे विपक्षी गठबंधन को मिली कुल सीटों से भी आठ अधिक हैं। राजग को 45 प्रतिशत वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन 42 प्रतिशत वोट ले पाया। भाजपा को कांग्रेस से 15 प्रतिशत अधिक वोट मिले हैं। यह काफी बड़ी बढ़त है।

इसलिए चुनाव नतीजों की तस्वीर साफ होते ही मोदी को लगातार तीसरा जनादेश हासिल करने पर विश्व भर के नेताओं ने बधाई संदेश भेजे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने फोन कर ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी और भारत के साथ व्यापार एवं सामरिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के संकल्प को रेखांकित किया। साथ ही मानव इतिहास के वृहत्तम लोकतांत्रिक पर्व में भाग लेने के लिए भारत के लोगों की सराहना की। उनकी इस सराहना से भारत की चुनाव प्रक्रिया, संवैधानिक संस्थाओं और ईवीएम मशीनों पर भारत और बाहर से उठाए जाने वाले सवालों की आधारहीनता भी साबित हो जाती है। बाइडन के अलावा रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत विश्व के कई अन्य नेताओं ने बधाई के लिए फोन किए। मोदी को चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्राजील समेत सौ से अधिक देशों के बधाई संदेश मिल चुके हैं।

अवधेश राजपूत

जनादेश से लगता है कि लोग ऐसा सशक्त और जिम्मेदार विपक्ष चाहते थे, जो सत्तापक्ष को निरंकुश न होने दे और सरकार की योजनाओं में लोकहित को सुनिश्चित करे। मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से चली आ रही बहुमत की सरकार से कुछ लोगों को सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि वह अपने बहुमत का प्रयोग आक्रामक शैली में करती थी। अब जनता ने विपक्ष को और मजबूत बनाकर भेजा है। उम्मीद है कि मोदी और उनकी पार्टी बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए अपनी सरकार को गठबंधन धर्म से चलाएंगे। यदि मोदी ऐसा करते हैं तो विपक्ष को भी अपने रवैये को बदलते हुए रचनात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए। देश में इससे पहले भी लंबे समय तक गठबंधन सरकारें रह चुकी हैं। इसलिए भारतीय चुनावों पर नजर रखने वाले ऐसे मित्र देशों को भी मोदी सरकार को कम बहुमत मिलने और विपक्ष के मजबूत होने पर चिंता नहीं होगी, जो मोदी सरकार की आक्रामक नीतियों के कारण प्रतिरोधी स्वरों को दबाए जाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर पड़ने की आशंका से असहज रहते थे, लेकिन वैश्विक समुदाय यह भी नहीं चाहेगा कि भारत की नई गठबंधन सरकार धरने-प्रदर्शनों से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता में उलझकर अपनी उन नीतियों पर ढीली पड़ जाए, जो आर्थिक सुधारों और जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए आवश्यक हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हुई बयानबाजी से ऐसे संकेत मिले थे कि विपक्षी गठबंधन मोदी सरकार की बजट संयम, आर्थिक सुधार और जलवायु परिवर्तन की रोकथाम संबंधी नीतियों को पलटने का इरादा रखता है। इसीलिए परिणामों के प्रारंभिक रुझानों को देखते ही भारत के शेयर और मुद्रा बाजारों में भूचाल जैसा आ गया था।

दुनिया इस समय दो बड़े सामरिक संकटों से जूझ रही है। गाजा में पिछले आठ महीनों से चल रही लड़ाई से हुए व्यापक विनाश के बाद भी युद्धविराम समझौता नहीं हो पा रहा है। उधर रूस यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव पर कब्जे की तरफ बढ़ रहा है। चीन और अमेरिका के बीच भी व्यापारिक और सामरिक तनाव बढ़ रहा है, जिसके कारण दुनिया फिर से दो खेमों में बंटी नजर आती है। एक खेमे में अमेरिका, यूरोप और उनके मित्र देश हैं। दूसरे खेमे में रूस, चीन और उनके मित्र देश। इस विषम परिस्थिति में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वह दोनों खेमों के बीच शांति और सुलह के एक पुल की भूमिका अदा कर सकता है और विश्वमंच पर अपना उचित स्थान हासिल कर सकता है।

इस वर्ष अमेरिका समेत दुनिया के लगभग 75 देशों में हो रहे चुनावों की वजह से राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल भी बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपतीय चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है। कई संगीन मामलों के अभियुक्त होने और एक में दोषी ठहराए जाने के बावजूद वह लोकप्रियता में राष्ट्रपति बाइडन से आगे चल रहे हैं। उनकी जीत अमेरिका समेत पूरे विश्व के राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक समीकरणों पर असर डाल सकती है। उनके आने पर भारत को अपनी चीन संबंधी सामरिक नीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)

response@jagran.com

नई सरकार की आर्थिक चुनौतियां

डा. ब्रजेश कुमार तिवारी

अर्थव्यवस्था के बढ़ते आकार के बीच भारत के लिए आर्थिक असमानता को पाटने की भी एक बड़ी चुनौती है

आर्थिक सुधारों से ही गति पकड़ेगी आर्थिकी● प्रतीकात्मक

नरेन्द्र मोदी लगातार तीसरी बार देश की कमान संभालने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में नई सरकार के कंधों पर वित्त वर्ष 2023-24 में दर्ज की गई 8.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि को आगे बढ़ाने के साथ ही भारत को पांच ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की अहम जिम्मेदारी होगी। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में भारत वैश्विक स्तर पर 11वीं से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। नई सरकार की नजर भारत को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में ले जाने पर होगी। आर्थिक मोर्चे पर तात्कालिक चुनौती महंगाई और बेरोजगारी है। तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। भारत में 94 प्रतिशत कर्मचारी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और देश का 35 प्रतिशत उत्पादन इसी में होता है। कई वर्षों से असंगठित क्षेत्र का दायरा सिकुड़ रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ का आगमन सेवा क्षेत्र के रोजगारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत की जीडीपी में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान इसी क्षेत्र का है। बेरोजगारी एवं महंगाई केवल राजनीतिक विषय नहीं हैं। अगर बेरोजगारी रहेगी और आय नहीं बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति प्रभावित होगी। उपभोग और निवेश का स्तर भी इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या दूर करने पर ध्यान देना होगा। आज देश के 85 प्रतिशत स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। इसके लिए स्टार्टअप इंडिया योजना को और अधिक महत्व देना होगा। अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार की जरूरत के साथ ही सरकारी भर्तियों में तेजी लानी होगी। असंगठित क्षेत्र को हाशिए पर धकेलने वाली नीतियों में भी बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। आज भारत में प्रति व्यक्ति आय 2,601 डालर है और 197 देशों में प्रति व्यक्ति आय के मामलों में भारत 142वें पायदान पर है। मुद्रास्फीति भी देश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। पिछले कुछ समय से रसोई का बजट अनियंत्रित और असंतुलित हुआ है।

आम लोगों पर महंगाई की मार के दूरगामी असर होते हैं। याद रहे कि महंगा भोजन आबादी के स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है। इसे देखते हुए आज हमें जीडीपी से ज्यादा मानव विकास पर फोकस करना चाहिए, जिसमें शिक्षा एवं स्वास्थ्य सबसे ऊपर हैं। आज देश के सामने बड़ी चुनौतियों में अच्छी शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रमुख हैं। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी ओर, उच्च शिक्षा के केवल कुछ संस्थान ही उन्नत अनुसंधान में शामिल हैं। भारत में शुरू से शिक्षा पर तुलनात्मक रूप से सार्वजनिक व्यय कम रहा है। वहीं प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का शोध एवं विकास (आरएंडडी) व्यय-जीडीपी अनुपात में मात्र 0.7 प्रतिशत है। यह 1.8 प्रतिशत के विश्व औसत से भी बहुत कम है। यदि सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद आज भी अगर देश के 80 करोड़ लोग को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है तो निश्चित ही यह जनसंख्या अकुशल है। स्किल इंडिया योजना कई कारणों से अपेक्षित सफलता नहीं पा सकी, जिसका मुख्य कारण प्रशिक्षण से संबंधित बुनियादी ढांचे की कमी और निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी है। याद रहे एक कुशल और शिक्षित श्रम बल ही देश को उच्च विकास दर की ओर ले जाता है।

कौशल एवं शिक्षा ऐसा क्षेत्र है, जहां निवेश के कई प्रभाव होते हैं। जब कार्यबल अधिक कुशल बनेगा, तब आर्थिक विकास की गति को बल मिलेगा, सामाजिक बुराइयां कम होंगी और महिलाएं भी सुरक्षित होंगी। परिणामस्वरूप देश का तेजी से विकास होगा। भारत चालू खाते के घाटे से भी लगातार जूझता रहा है, जिसका अर्थ है कि देश का आयात इसके निर्यात से अधिक है। पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत की वैश्विक निर्यात में बमुश्किल 1.6 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 'मेक इन इंडिया' अभियान का एक प्राथमिक उद्देश्य 2022 तक भारतीय जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक बढ़ाना था। हालांकि पिछले नौ वर्षों में यह स्तर 14 से 16 प्रतिशत के बीच अटका है। अर्थव्यवस्था के बढ़ते आकार के बीच भारत के लिए आर्थिक असमानता को पाटने की भी बड़ी चुनौती है। देश में केवल अरबपतियों की संख्या बढ़ने से काम नहीं बनेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भले भारत की स्थिति पांचवीं हो गई हो, मगर विकास का हिस्सा बहुतों तक अभी पहुंच नहीं रहा है।

खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने, आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कृषि आधारित उद्योगीकरण द्वारा संचालित होना चाहिए। सरकार के निवेश प्रोत्साहन पर निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया अपर्याप्त रही है, फिर भी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर सरकारी खर्च जारी रहना चाहिए। नई सरकार को बांड बाजार, बीमा बाजार और पेंशन बाजार का विकास भी करना चाहिए, जो अवसंरचना के लिए दीर्घकालिक वित्त और वृद्ध जनों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जीएसटी को भी सुसंगत बनाने की जरूरत है। सरकार अगर चाहे तो कर राजस्व बढ़ाने के लिए कारपोरेट कर, संपत्ति कर जैसे कर बढ़ा सकती है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण नीतियों का सख्ती से कार्यान्वयन भी जरूरी है। अर्थव्यवस्था पर बढ़ते कर्ज का कारगर समाधान भी निकालना होगा। निजी निवेश में सुधार अर्थव्यवस्था में तरक्की का सबसे अहम कारक होगा और अगली सरकार को इस पर खास जोर देना चाहिए। हाल में आरबीआइ ने केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये के लाभांश (डिविडेंट) भुगतान करने का एलान किया है। सरकार को इस धन को शिक्षा एवं रोजगार निर्माण में लगाना चाहिए और किसी भी रेवड़ी वाली योजना से दूर रहना चाहिए।

(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

परख

परीक्षण शक्ति को परख कहते हैं। संसार में अच्छे-बुरे की पहचान इसी से होती है। अतः किसी के प्रति आकर्षण या विकर्षण का कारण यही है। यह मानव की आंतरिक शक्ति है, जो प्रायः सभी में नहीं होती। जिसमें यह क्षमता होती है, उसे विशिष्ट बना देती है। फिर सभी कार्य जांच-परखकर किए जाते हैं। कभी पश्चाताप नहीं होता। इसलिए यदि जीवन की दिशा की निर्धारणा संगति से होती है, तो संगति की परख से। इसके बिना बच्चे ही नहीं, बड़े भी कुसंग में सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। जिनमें यह शक्ति होती है उनमें सत्संग के कारण अवगुणों का आगमन नहीं होता। मन, वाणी एवं कर्म पवित्र रहते हैं। सामाजिक प्रवंचना का शिकार नहीं होना पड़ता। अतः जीवन की सफलता पारखी शक्ति पर निर्भर है। यद्यपि इसका प्रारंभ परिवार से होता है, वास्तव में इसकी प्राप्ति गुरु के सान्निध्य में होती है, क्योंकि शिष्य में पारखी शक्ति का विकास करना गुरु का प्रथम कर्तव्य है।

परख का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, जहां इसकी आवश्यकता न हो। जीवन में पूर्ण सफलता के लिए परख केवल बाह्य जगत की नहीं, अपनी भी होनी चाहिए। जब यह क्षमता जागृत हो जाती है तब हम अपने भी गुरु बन जाते हैं। हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होने लगता है और हम परमात्मा के सामीप्य का अनुभव करते हैं। इस विलक्षण शक्ति के जन्मदाता गुरु सहज ही शिष्य की आंतरिक शक्तियों को पहचान लेते हैं।

स्वामी विवेकानंद जब गुरु के पास गए तो प्रथम दृष्टि में ही उन्होंने इन्हें पहचान लिया। फिर उनकी आत्मिक परख को जागृत कर तर्क बुद्धि को राष्ट्रभक्ति में परिवर्तित कर दिया। परिणामतः उन्होंने राष्ट्र के आध्यात्मिक ध्वज को विश्वक्षितिज पर फहराया और अपने राष्ट्र को जगद्गुरु के गुरुतर पद पर प्रतिष्ठापित किया। यह उनकी आत्मिक परख का परिणाम था। अतः आत्ममंगल के लिए इसे अपने अंदर जागृत करना प्रत्येक मानव का धर्म है।

डा. सत्य प्रकाश मिश्र

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

नई चुनौतियों के बीच भाजपा

'भाजपा को बदलनी होगी रीति-नीति' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में अवधेश कुमार ने बदलते राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा को अपनी रीति-नीति में बदलाव लाकर जमीनी स्तर पर काम करने और युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने पर जोर डाला है। 2014 के बाद से भाजपा ने अपनी नीतियों और चुनावी रणनीतियों में कई बदलाव किए, जिससे उसे अद्वितीय सफलता मिली, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में केवल विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे काफी नहीं हैं। जनता अब ठोस परिणाम चाहती है और स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान चाहती है। भाजपा को जमीनी स्तर पर काम करना होगा, जिससे जनता का विश्वास फिर से जीत सके। पार्टी को क्षेत्रीय नेताओं को सशक्त करना और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ाना होगा और उनकी समस्याओं को समझकर समाधान निकालना होगा। इसके अलावा गठबंधन सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बनाना जरूरी है। गठबंधन राजनीति में समझौता और संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होता है, ताकि केंद्रीय और राज्य स्तर पर पार्टी की स्थिति मजबूत बनी रहे। युवाओं के लिए नई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत भी भाजपा के लिए आवश्यक है। आज का युवा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दे रहा है। यदि भाजपा इन क्षेत्रों में सुधार करती है तो उसका जनाधार और मजबूत हो सकता है। पार्टी को चाहिए कि वह युवाओं की अपेक्षाओं को समझे और उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए। अंततः भाजपा को अपनी रीति-नीति में लचीलापन लाना होगा और समय के साथ चलना होगा। परिवर्तन ही स्थिरता का मंत्र है। भाजपा अगर इन बातों को ध्यान में रखती है तो भविष्य में उसे अपेक्षित सफलता मिल सकती है।

अमरजीत सिंह, चिरैला, बिहार

कांग्रेस की मनोवृत्ति

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का यह कथन कि लोकसभा चुनाव में अकेले भाजपा के बहुमत से पीछे रह जाने के कारण नरेन्द्र मोदी को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक एवं राजनैतिक हक नहीं है, निःसंदेह उनकी मानसिक अपरिपक्वता दर्शाता है। बहुमत पाने के लिए 272 सीट की आवश्यकता होती है एवं एनडीए को उससे 20 अधिक 292 सीट मिली है। यह गठबंधन चुनाव पूर्व का गठबंधन है, इसलिए उसको सरकार बनाने का नैतिक एवं संवैधानिक दोनों हक है। एनडीए के प्रमुख घटक भाजपा ने अकेले 240 सीटें जीती हैं, जो आइएनडीआइए की कुल सीटों 234 से अधिक है। सच तो यह है कि कांग्रेस बदहाली की हालत में है। 36 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में से 13 में वह अपना खाता नहीं खोल सकी तो 10 में एक-एक सीट से संतोष करना पड़ा। उसकी 99 सीटें सदन की कुल सीटों का मात्र 18 प्रतिशत है। आइएनडीआइए में तालमेल भी नहीं दिखा। कांग्रेस केरल में एलडीएफ, पंजाब में आप एवं बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध लड़ी, जबकि यह सभी दल आइएनडीआइए के घटक हैं। इधर, मोदी तो प्रथम बैठक में ही एनडीए के नेता निर्वाचित हो गए।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, दुर्गादेवी मंदिर मार्ग चौक, पटना

युवाओं की अपेक्षाएं पूरी करे भाजपा

'भाजपा को बदलनी होगी रीति-नीति' शीर्षक आलेख में अवलेश कुमार ने बदलते राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा को अपनी रीति-नीति में बदलाव लाकर जमीनी स्तर पर काम करने एवं युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता की मांग पर प्रकाश डाला है। 2014 के बाद से भाजपा ने अपनी नीतियों और चुनावी रणनीतियों में कई बदलाव किए, जिससे उसे अद्वितीय सफलता मिली। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में केवल विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे काफी नहीं हैं। जनता अब ठोस परिणाम चाहती है और स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान चाहती है। भाजपा को जमीनी स्तर पर काम करना होगा, जिससे जनता का विश्वास फिर से जीत सके। पार्टी को क्षेत्रीय नेताओं को सशक्त करना होगा। वहीं संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता आज भी कायम है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ाना होगा और उनकी समस्याओं को समझकर समाधान निकालना होगा। गठबंधन सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल रखना होगा। गठबंधन राजनीति में समझौता और संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होता है, ताकि केंद्रीय और राज्य स्तर पर पार्टी की स्थिति मजबूत बनी रहे। युवाओं के लिए नई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत भी भाजपा के लिए आवश्यक है। आज का युवा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दे रहा है।

अमरजीत सिंह, चिरैला, औरंगाबाद, बिहार

पोस्ट

दुनिया के किस चुनाव में आखिरी बार ऐसा देखा गया, जहां चुनाव हारने वाला चुनाव जीतने वाले से ज्यादा खुश नजर आया हो?

सदानंद धूमे@dhume

जो लोग भाजपा को लेकर अतिआत्मविश्वास और अहंकार की शिकायत कर रहे थे, वे जरा एक बार 99 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस का रुख-रवैया देख लें।

अद्वैता काला@AdvaitaKala

भारत में लोकतंत्र की व्यापकता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। करीब 44 दिन चली चुनाव प्रक्रिया, 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता, 64 करोड़ लोगों द्वारा मतदान, जिनमें करीब आधी महिलाएं रहीं, 11 लाख पोलिंग बूथ और 55 लाख ईवीएम से इस प्रक्रिया को संपन्न किया गया।

हुसैन हक्कानी@husainhaqqani

आम चुनाव में एक ताकतवर सरकार को अपेक्षा के विपरीत बड़ा झटका लगा। इसके बावजूद सब कुछ शांतिपूर्ण निपटा। कोई गड़बड़ी नहीं। किसी प्रत्याशी को कोई क्षति नहीं पहुंची, जबकि मेक्सिको के चुनाव में करीब 37 लोगों की मौत हो गई, जिसकी जीडीपी भारत से लगभग चार गुना अधिक है। भारत की चुनाव प्रक्रिया पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है।

शेखर गुप्ता@ShekharGupta

जनपथ

चुपके-चुपके हो गया देखो वोट जिहाद,
रहे चलाते आप-हम केवल समाजवाद।
केवल समाजवाद याद ना आया राशन,
गया जाति से हार मिला जो हमें सुशासन!
अपनों ने ही वार किया मोदी पे छुपके,
अपनी ही नस काट रहे हम चुपके-चुपके!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 56

****

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ शुक्रवार, 7 जून 2024

उस व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं, जिसने पूरा जीवन एक ही विचार को समर्पित कर दिया। -फ्रांसिस क्रिक

पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की चालीसवीं बरसी पर खालिस्तान समर्थन में नारे लगना चिंताजनक है। पंजाब ने आतंकवाद का एक लंबा दौर देखा है और अब दोबारा वह उस काले दौर में नहीं लौट सकता। ऐसे में, केंद्र सरकार के साथ पंजाब सरकार को भी सतर्क रहने की जरूरत है।

सतर्कता जरूरी

पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की चालीसवीं बरसी पर स्वर्ण मंदिर परिसर में भारी भीड़ की मौजूदगी के बाद भी कोई हिंसक घटना बेशक न घटी हो, लेकिन वहां जिस तरह तलवारें लहराते हुए खालिस्तान समर्थन के नारे लगाए गए, वह चिंताजनक होने के साथ सीमावर्ती राज्य के लिए खतरे की घंटी भी है। इस खतरे को समझने के लिए घटनाओं के क्रम को समझना होगा। पंजाब में तीन दिन पहले आए लोकसभा चुनाव परिणामों में भी दो खालिस्तान समर्थक रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। इससे पहले, किसान आंदोलन के दौरान भी खालिस्तानी अलगाववादियों के शामिल होने के आरोप लगे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने मणिपुर हिंसा में भी अलगाववादियों की लिप्तता का खुलासा किया था, जब पिछले वर्ष एक शीर्ष कुकी नेता के खालिस्तानी अलगाववादियों से कथित संपर्क के सिलसिले में गिरफ्तारियां की गई थीं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की संचालक कंपनी मेटा ने हाल ही में खुलासा किया कि चीन से संचालित हो रहे फर्जी खाते किस तरह खालिस्तान के नाम पर सिखों को भड़काते हुए एक फर्जी आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पंजाब में आतंकवाद के सफाए के बाद खालिस्तानी नेताओं ने पाकिस्तान में पनाह ली और अपना नेटवर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से चलाना शुरू किया। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका में भी खालिस्तानी गुटों ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनयिक मिशनों को भी निशाना बनाने की कोशिशें की हैं। पिछले वर्ष स्कॉटलैंड में खालिस्तानी अलगाववादियों ने जिस तरह से भारतीय उच्चायुक्त को स्थानीय गुरुद्वारे में प्रवेश से रोक दिया था, वह उनकी बढ़ी हुई हिम्मत को ही दिखाता है। कनाडा में प्रतिबंधित केटीएफ (खालिस्तानी टाइगर फोर्स) के सरगना हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से अलगाववाद को गहरा झटका जरूर लगा था। कनाडा इसके पीछे भारत की लिप्तता का मनगढ़ंत आरोप जरूर लगाता रहा, लेकिन इस कुत्सित अभियान में उसे

अपने सहयोगी देशों तक का समर्थन नहीं मिला। पंजाब ने आतंकवाद का एक लंबा दौर देखा है, जिससे उबरने में उसे खासा वक्त भी लगा है और अब दोबारा वह उस काले दौर में नहीं लौट सकता। आतंकवाद दोबारा सिर न उठाए, इसके लिए जरूरी है कि केंद्र व राज्य स्तर पर बेहतर समन्वय हो और आतंकियों की फंडिंग रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। लोकतंत्र में सरकार से असहमति या विरोध स्वाभाविक है और देश का इतिहास ऐसे विरोध और असहमतियों से भरा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही यह भी देखने की जरूरत है कि निहित स्वार्थ इसकी आड़ में राष्ट्रीय हितों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे।

उदार अमेरिका में कट्टरपंथियों का ठिकाना

अमेरिका बांग्लादेशियों को आकर्षित करता है, तो इसकी वजह वहां नौकरी करने, व्यापार करने, स्वतंत्रता से चलने-फिरने, अपने धर्म का पालन करने और बच्चों को स्कूलों में मुफ्त में पढ़ाने की सुविधा है। इसके बावजूद अमेरिका में रहने वाले ये लोग अमेरिकी आदर्शों को थोड़ा भी नहीं मानते।

कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क में सुचित्रा सेन चलचित्र उत्सव का आयोजन हुआ। इसका आयोजन न्यूयॉर्क में रह रहे अनिवासी बांग्लादेशियों ने किया था। इससे कुछ ही दिनों पहले न्यूयॉर्क में बांग्ला पुस्तक मेला और साहित्य अनुष्ठान आयोजित हुए थे। इनके आयोजक भी अनिवासी बांग्लादेशी थे। इससे ऐसा लगता है कि अमेरिका में रहने वाले सभी बंगाली शायद प्रगतिशील हैं, सभी शायद साहित्य या संस्कृति प्रेमी हैं। क्या सच में ऐसा है?

बेशक ढाका और न्यूयॉर्क में बहुत अंतर है। अमेरिका और बांग्लादेश में जो अंतर है, ढाका और न्यूयॉर्क में वही अंतर है। अमेरिका चूंकि बांग्लादेश की तुलना में अत्यधिक विकसित और सभ्य देश है, इस कारण बड़ी संख्या में बांग्लादेशी अमेरिका की स्थायी नागरिकता पाने के लिए अमेरिका जाते हैं। कट्टर मुस्लिम भी, जो हमेशा धर्म के नशे में चूर रहते हैं, ईसाइयों-यहूदियों से घृणा करते हैं, उन्हें गाली देते हैं, मौका मिलने पर वे भी अमेरिका जाने का जुगाड़ बिठाते हैं। वे अगर चाहें, तो आराम से अरब देशों में बस सकते हैं, पर वे ऐसा नहीं करते।

तसलीमा नसरीन
चर्चित लेखिका

बांग्लादेशियों को भी अमेरिका बहुत आकर्षित करता है। अमेरिका की नागरिकता मिलने पर उनका जीवन धन्य हो जाए। स्थायी निवास के लिए उन्हें ईसाइयों, यहूदियों और नास्तिकों का देश अमेरिका ही पसंद है। बहुत लोग तो जोखिम उठाकर भी पश्चिमी देशों में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। रात के अंधेरे में नाव से भूमध्यसागर पार कर यूरोप पहुंचते हैं। नाव के डूब जाने से बहुतों की जान भी जाती है। इसके बावजूद नाव से समुद्र पार करने की जोखिम भरी कोशिशों पर विराम नहीं लगता। अरब देश में हज करने जाने, अरब देशों की पोशाक पहनने, अरब देशों की भाषा और आचार-व्यवहार का अनुसरण करने और अरब लोगों को महामानव समझने के बावजूद बांग्लादेश के लोग अरब देशों में बसने की उत्सुकता नहीं दिखाते। इसके बजाय अरब देशों में श्रमिक

का काम करने गए लोग जितनी जल्दी संभव हो सके, घर लौट आने के बारे में सोचते हैं। और अरब देशों में लोगों के घरों में काम करने वाली बांग्लादेशी महिलाएं अपनी जान बचाने के लिए घर लौट आती हैं, या फिर लाश बनकर लौटती हैं।

अमेरिका बांग्लादेशियों को आकर्षित करता है, तो उसकी वजह है। अमेरिका में नौकरी करने, व्यापार करने, स्वतंत्रता से चलने-फिरने, अपने धर्म का पालन करने, बच्चों को स्कूलों में मुफ्त में पढ़ाने की सुविधा है। वहां रुपये-पैसे न रहने पर फूड पैकेट मिलता है, मुफ्त में इलाज, दवा, आया आदि की सुविधा है। सर्वोपरि, अमेरिका में मानवाधिकार पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है, जबकि बांग्लादेश में मानवाधिकार की किसी को परवाह ही नहीं है। इसके बावजूद अमेरिका में रहने वाले ये लोग अमेरिकी आदर्शों को थोड़ा भी नहीं मानते। अमेरिका इन्हें उदार नहीं बना पाता। अमेरिका में रहते हुए भी ये बांग्लादेशी बने रहते हैं। भोजन की खोज इन्हें हलाल मीट की दुकान पर ले जाती है। अमेरिका में आने के बावजूद ये बांग्लादेश का पहनावा नहीं छोड़ते। महिलाएं बुर्का और नकाब नहीं छोड़तीं। अमेरिका में रहते हुए भी ये धार्मिक कट्टरता को बरकरार रखते हैं। ये मानते हैं कि उनका धर्म दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वहां रहकर भी ये लोग मानते हैं कि ट्विन टावर्स को ध्वस्त कर देने वाले आतंकवादियों ने बहुत बड़ा काम किया था। इनमें से कुछ तो यह सपना तक देखते हैं कि पश्चिम के तमाम देश मुस्लिमों से भर गए हैं और यह पृथ्वी सिर्फ मुस्लिमों के लिए है।

बांग्लादेशियों की नई पीढ़ी में अमेरिका जाने की इच्छा प्रबल है। यही नहीं, ये लोग अपने देश से बाहर यह बताने में भी कतराते हैं कि उनके माता-पिता बांग्लादेशी हैं। दूसरी ओर, अपने घर में कट्टरवादियों द्वारा लगातार ब्रेनवॉश किए जाने के कारण कुछ लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। इस तरह के भटके हुए लोग दूसरे देशों के मुस्लिमों को अपना समझने की गलती कर डालते हैं। हालांकि दूसरी तरफ यह भी सच है कि अमेरिका में पैदा हुई पीढ़ी के अनेक बच्चे बांग्ला में बातचीत करते हैं, बांग्ला गीत गाते हैं। हालांकि यह इस पर निर्भर करता है कि इन बच्चों के माता-पिता घर में बांग्ला संस्कृति को कितना प्रोत्साहित करते हैं।

अनिवासी बांग्लादेशियों ने अमेरिका के विभिन्न शहरों में छोटे-छोटे बांग्लादेश बना लिए हैं। पश्चिम उनके जीवन-यापन और सोच-विचार में किसी प्रकार का बदलाव नहीं ला पाया है। अमेरिका में रह रहे बांग्लादेशी अब भी जात-पांत, अंधविश्वास और कठोर पुरुषतंत्री सोच में जकड़ा हुआ है। इनके अपने देश में नारी विरोध का जो इतिहास है, उसे ये बांग्लादेशी बंगाल की खाड़ी के किनारे से अटलांटिक और प्रशांत महासागर के किनारे तक ढोकर ले आए हैं। अनिवासी नागरिक शायद ऐसे ही होते हैं। जिस मिट्टी से वे आते हैं, आजीवन उसी मिट्टी से जुड़े रहते हैं। विदेशी संस्कृति से वे वस्तुतः उतना ही ग्रहण करते हैं, जितना उनके रोजगार के लिए जरूरी होता है। लेकिन सोच-विचार की दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए जिस दर्शन की जरूरत होती है, उसे वे कभी जान-सीख-अपना नहीं सकते। वे आजीवन सिर्फ उसी पर चर्चा करते हैं, जो अपने देश से सीखकर आए होते हैं।

मैं यह नहीं कह रही कि न्यूयॉर्क में बांग्ला साहित्य और संस्कृति के कर्णधारों ने सिर्फ मुझे ही प्रतिबंधित किया। हो सकता है, और भी लेखकों-कवियों-संस्कृतिकर्मियों को उन्होंने प्रतिबंधित किया हो, और भविष्य में भी करते रहेंगे। और वहां आमंत्रित कवियों-लेखकों ने न तो इस प्रतिबंध के विरोध में कुछ कहा, न भविष्य में कुछ कहेंगे। धारा के विरुद्ध चलने वाले या अलग विचार रखने वालों की उपेक्षा करते हुए बांग्ला पुस्तक मेला इसी तरह सालोंसाल आयोजित होते रहेंगे। इसी कारण मैं कहती हूं कि बांग्लादेश और अमेरिका में भले ही फर्क हो, लेकिन इन जगहों में रहने वाले बांग्लादेशियों में आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। जिस तरह ढाका में होने वाले पुस्तक मेले में मेरा प्रवेश प्रतिबंधित है, ठीक उसी तरह न्यूयॉर्क में होने वाले पुस्तक मेले में भी मुझे प्रतिबंधित किया जाता है। सात समुद्र पार बस जाने के बावजूद संकुचित बंगाली संकुचित ही रह जाता है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

एंजेला डकवर्थ

सभी बच्चे एकसमान प्रतिभावान नहीं होते, लेकिन सबमें कुछ न कुछ खासियत जरूर होती है। यदि उनमें सीखने की ललक है, तो वे पहले से घोषित प्रतिभावान से आगे निकल सकते हैं।

सही दिशा में की गई मेहनत जरूर सफल बनाती है

जाहिर है कि योग्यता सफलता की गारंटी नहीं होती। हालांकि परंपरागत ज्ञान तो यही कहता है कि गणित एक ऐसा विषय है, जिसमें विद्यार्थी जितने ज्यादा प्रतिभावान होंगे, उनके सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। वे कक्षा के उन साथियों को पीछे छोड़ देंगे, जो वास्तविकता में गणित के लायक नहीं हैं। ईमानदारी से कहूं तो स्कूल की शुरुआत मैंने भी इसी धारणा के साथ की थी। मैंने ऐसा समझ लिया था कि जो विद्यार्थी आसानी से बातें समझते हैं, वे अपने साथियों से आगे बने रहेंगे। स्कूल में पढ़ाने के दौरान प्रतिभा के विषय ने मेरा ध्यान विचलित कर दिया था। धीरे-धीरे मैंने खुद से कठिन सवाल पूछना शुरू कर दिया। मैंने कोई पाठ पढ़ाया और वह अवधारणा विद्यार्थियों को समझ नहीं आई, तो इसके क्या कारण हैं? क्या मुझे अपना तरीका बदलना पड़ेगा? बाद में सोचा कि शिक्षक होने के नाते क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है?

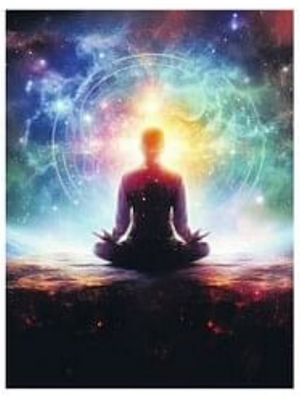

अब मैंने कमजोर विद्यार्थियों की आवाज बनने की ठान ली। वे अपनी पसंदीदा बातें करते हुए खुल जाते थे। बास्केटबाल, गानों आदि पर उनसे खूब संवाद किया। जब हम लोग एक-दूसरे के साथ खुल गए तब कमजोर विद्यार्थियों की पेचीदगियां समझ आईं। दरअसल सभी विद्यार्थी एकसमान प्रतिभावान नहीं होते। लेकिन सबमें कुछ न कुछ खासियत जरूर होती है। भले ही कोई विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन यदि उसके अंदर सीखने की ललक और निष्ठा है, तो वह पहले से घोषित प्रतिभावान से आगे निकल सकता है। यह साबित किया मेरे एक विद्यार्थी डेविड लुओंग ने। वह एकदम शांत रहता था और कक्षा में एकदम पीछे बैठता था। वह ब्लैकबोर्ड पर सवाल हल करने के लिए बड़ी मुश्किल से आता था। लेकिन मैंने उसके अंदर एक बात देखी कि उसे जब भी कोई काम दिया गया, तो वह अच्छे से करता था। मैंने उसकी प्रतिभा का आकलन किया और तत्काल डेविड को विभाग प्रमुख के पास ले गई और कहा कि इसे उन विद्यार्थियों के ग्रुप में शामिल कीजिए जो तेज हैं। डेविड ने तेज बच्चों में पहुंचकर खुद को कुछ समय तक असहज महसूस किया, लेकिन मैंने उसकी जो खूबी पहचानी थी, उसने वैसा ही किया। वह परिस्थितियों से घबराया नहीं और उसने खूब मेहनत कर खुद को इस लायक बनाया कि वह अव्वल विद्यार्थियों की बराबरी कर सके। दरअसल शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि वे विद्यार्थी की खूबी को पहचानकर आगे बढ़ें। डेविड एयरोस्पेस कॉरपोरेशन में इंजीनियर बनने के बाद मुझसे मिला, उसने बताया कि यदि आप मुझे अपनी कक्षा से निकालकर तेज विद्यार्थियों के ग्रुप में शामिल नहीं करवातीं, तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। जाहिर है, प्रतिभावान होना अच्छा है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत आपको जरूर सफल बनाती है।

एंजेला डकवर्थ की 'द ग्रिट' किताब के अनूदित अंश

डार्विन ने कहा

सूत्र

डार्विन ने अपने भाई को लिखा था कि केवल मूर्खों को छोड़कर बुद्धिमत्ता के हिसाब से लोगों में ज्यादा अंतर नहीं होता। अंतर केवल जिद और कड़ी मेहनत में होता है। इसलिए डार्विन के विचार पर ज्यादा गहराई से सोचने की जरूरत है। दरअसल जिद और कड़ी मेहनत बौद्धिक क्षमता से ज्यादा मायने रखती है। डार्विन की जीवनी लिखने वाले भी यही दावा करते हैं कि वे अलौकिक प्रतिभा के धनी नहीं थे, लेकिन मेहनती इन्सान थे।

दूसरा पहलू

आस्ट्रेलिया में घरेलू हिंसा के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। 2022-23 में 34 महिलाओं की हत्या उनके मौजूदा या पूर्व पार्टनरों ने की थी।

घरेलू हिंसा से जूझतीं ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं

विगत अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुकी है। अल्बानीज को ऐसा कहना पड़ा, क्योंकि औरतों के खिलाफ हिंसा के खिलाफ देश के अलग-अलग शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। एक आंकड़े के मुताबिक, इस साल अब तक घरेलू हिंसा से त्रस्त 29 महिलाएं आत्महत्या कर चुकी हैं। जबकि एक सरकारी आंकड़े के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में 34 महिलाओं की हत्या उनके मौजूदा या पूर्व पार्टनरों ने की थी। फिलहाल भले यह आंकड़ा अमेरिका में घरेलू हिंसा के आंकड़ों से कम हो, लेकिन इस सच से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ऑस्ट्रेलिया में घरेलू हिंसा के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।

जुलिया बर्गिन

यह इतनी बड़ी समस्या है कि नए बजट में सरकार ने घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं व बच्चों की मदद के लिए अगले पांच साल में एक अरब डॉलर का आवंटन किया है।

मेलबर्न के उपनगरीय इलाकों में कम आय और मामूली पृष्ठभूमि की कम उम्र महिलाओं के घरेलू हिंसा का सामना करने की आशंका अब भी सबसे अधिक है, और उनकी कहीं सुनवाई भी नहीं होती।

यह इतनी बड़ी समस्या है कि नए संघीय बजट में अल्बानीज सरकार ने घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं व बच्चों की मदद के लिए अगले पांच साल में एक अरब डॉलर का आवंटन किया है। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और विशेषज्ञों का मानना है कि बजट आवंटन से समस्या हल नहीं होगी। वुमैन इलावारा नाम के गैरलाभकारी संगठन के लिए काम करने वाली मिशेल ग्लासगो के मुताबिक, जो दशकों से घरेलू हिंसा झेलने वाली महिलाओं के साथ काम कर रही हैं, अनेक महिलाएं घरेलू हिंसा, यौन अत्याचार, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित आवास व नौकरी में महिलाओं की समान हिस्सेदारी मांग रही हैं। लेकिन इनमें से बहुत कम ही महिलाओं को अपेक्षित मदद मिल पाई है। मिशेल के मुताबिक, कोविड लॉकडाउन के बाद से ही उनके इलाके में उनके संगठन द्वारा पीड़ित महिलाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, अदालती मदद आदि की मांग काफी बढ़ गई है।

मेलबर्न के उपनगरीय इलाकों में खुद घरेलू हिंसा से पीड़ित एक महिला टारा शुल्ज कहती हैं कि कम आय और मामूली पृष्ठभूमि की कम उम्र महिलाओं के घरेलू हिंसा का सामना करने की आशंका अब भी सबसे अधिक है, और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। वह कहती हैं कि ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई युवतियां अब भी उन्हीं समस्याओं से जूझती हैं, जिनसे कभी वह जूझती रही थीं। और यह समस्या सिर्फ शहरी-उपनगरीय इलाकों में नहीं, बल्कि दूरस्थ इलाकों में भी है। मसलन, नॉर्दन टेरिटरी में, जहां देश की मात्र एक फीसदी आबादी रहती है, घरेलू हिंसा में मरने वाली महिलाओं का आंकड़ा राष्ट्रीय आंकड़े की तुलना में सात गुना ज्यादा है। जाहिर है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार इन दिनों घरेलू हिंसा की बड़ी चुनौती का सामना कर रही है।

©The New York Times 2024

आंकड़े

आमों के शौकीन

विदेश में बड़े स्तर पर भारतीय आम को पसंद किया जाता है। इनमें यूएई, ब्रिटेन और अमेरिका सबसे बड़े आयातक हैं।

3.18 फीसदी के साथ कनाडा छठे नंबर पर है।

स्रोत : DGCIS

अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने पर अर्जुन और सुधन्वा के बीच भीषण युद्ध हुआ। दोनों भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण को आना पड़ा।

भगवान में लीन हो गए सुधन्वा

अंतर्यात्रा
संकलित

महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा चंपकपुरी राज्य में पहुंचा, तो वहां के महाराज हंसध्वज ने सेना और योद्धाओं को बुलाया, लेकिन उनके छोटे बेटे सुधन्वा को पहुंचने में विलंब हुआ।

राजा ने पूछा कि इसे क्या सजा दी जाए, तो पुरोहितों ने कहा कि पूर्व घोषणा के अनुसार, गर्म तेल के कढ़ाहे में डाला जाए। सुधन्वा भगवान का नाम लेकर कढ़ाहे में उतर गए, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। शंका हुई कि राजा ने ठंडा तेल डलवाया होगा। परखने के लिए उसमें नारियल डाला तो वह दो हिस्सों में फट गया। इसके बाद यज्ञ का घोड़ा पकड़ने के लिए सुधन्वा को भेजा। उनके साथ पांडव सेना ने अर्जुन के नेतृत्व में युद्ध किया। अर्जुन सुधन्वा का सामना नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि महाभारत में कई योद्धाओं को परास्त किया, लेकिन यहां क्या हुआ। सुधन्वा ने याद दिलाया कि यहां आपके सारथी भगवान कृष्ण नहीं हैं। उन्हें बुलाएं। अर्जुन ने भगवान का आह्वान किया।

भगवान के प्रकट होने पर दोनों ने उनको नमन किया। सुधन्वा ने कहा, पार्थ अब युद्ध कीजिए। अर्जुन बोले कि मैं तीन बाण में तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं तो नरक का गामी बनूं। सुधन्वा बोले, मैं उनको काट दूंगा। अर्जुन के तीनों ही बाण सुधन्वा ने काट दिए, लेकिन अंतिम बाण के एक टुकड़े ने निकलकर सुधन्वा की गर्दन काट दी। सुधन्वा के शरीर से ज्योति निकलकर भगवान में लीन हो गई। इस तरह भगवान ने दोनों ही भक्तों के प्रण की रक्षा की।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 05 अप्रैल, 1951

कांग्रेस से अलग होंगे डेमोक्रेटिक फ्रंट के कांग्रेसी

'डेमोक्रेटिक फ्रंट' नई में कांग्रेस से अलग होगा, श्रीसक्सेना द्वारा घोषणा

डेमोक्रेटिक फ्रंट संगठनकर्ता प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना ने कहा कि कांग्रेस को बर्बाद होने से बचाना है, तो अवसरवादियों को निकालना होगा। डेमोक्रेटिक फ्रंट के कांग्रेसी मई में कांग्रेस से अलग हो जाएंगे।

भूमि पर रेंगती मौत है मरुस्थलीकरण

दुनिया भर के कई क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण एक कठोर वास्तविकता बन गया है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका को खतरा है।

वीर सिंह

संकट

भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण, और सूखा प्रतिरोधकता। इस महत्वपूर्ण और चुनौती भरे विषय पर केंद्रित इस वर्ष का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टीफिकेशन (यूएनसीसीडी) की पार्टियों का 16वां सम्मेलन रियाद में 2 से 13 दिसंबर तक होना है। इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में विश्व को भूमि की सुरक्षा व जलवायु परिवर्तन के सामने मरुस्थलीकरण और सूखे से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्यवाही की तत्काल आवश्यकता को पहचानने का आह्वान किया गया है।

मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता व आजीविका के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जिससे पारिस्थितिक रूप से सुदृढ़ भूमि प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना अनिवार्य हो जाता है। प्रत्येक बीते वर्ष के साथ, इन चुनौतियों से निपटने की तात्कालिकता और अधिक स्पष्ट हो जाती है, जिससे

हमें उनके प्रभाव को कम करने के लिए सामूहिक प्रयासों के महत्व की अनुभूति होती है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित जितने भी अंतरराष्ट्रीय दिवस हैं, उनमें पर्यावरण दिवस ऐसा है, जिसे उत्साह और चिंतन के साथ मनाया जाता है। हमारे ग्रह के भूमि संसाधनों के लिए मरुस्थलीकरण सबसे घातक खतरों में से एक है, जो चुपचाप पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता और आजीविका पर अतिक्रमण कर रहा है। मरुस्थलीकरण वास्तव में भूमि पर रेंगती मौत है। एक बार यह जिस भूखंड पर रेंग जाता है, वह भूमि का मृत हिस्सा बनकर रह जाता है, वहां की मिट्टी सांस नहीं ले सकती, वहां कोई पौधा नहीं पनप सकता, वहां जीवन की खाद्य शृंखला टूट जाती है। मरुस्थलीकरण कोई यकायक घटी प्रलयंकारी घटना नहीं, वरन भूमि क्षरण की क्रमिक प्रक्रिया है, जिसमें वनस्पति की हानि, मिट्टी का क्षरण और जल संसाधनों की कमी सम्मिलित है। यह शुष्क, अर्ध शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में होता है, जहां जलवायु परिवर्तन और अस्थिर भूमि प्रबंधन प्रथाएं और शहरीकरण भूमि के क्षरण में योगदान करते हैं, जिससे मरुस्थलीकरण का प्रसार बढ़ता है।

मरुस्थलीकरण प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। इससे पारिस्थितिक तंत्रों में जैव विविधता की हानि, मिट्टी की उर्वरता में कमी तथा सूखे और वनों की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं की एक अटूट शृंखला शुरू हो जाती है। दुनिया भर के कई क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण एक कठोर वास्तविकता बन गया है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका को खतरा है और सतत विकास के प्रयास कमजोर हो रहे हैं। विशेष रूप से अफ्रीका में विशाल भूमि मरुस्थलीकरण की निरंतर प्रगति का शिकार हो रही है। मरुस्थलीकरण की गंभीर वास्तविकताओं के बीच कार्यवाही के लिए आशा और अवसर उपलब्ध हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने का प्रयास किया है। 1994 में अपनाया गया यूएनसीसीडी इस दिशा में एक ऐतिहासिक समझौता है, जिसका उद्देश्य स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना और सूखे के प्रभावों को कम करना है। पुनर्वनीकरण और वनीकरण की पहल मरू भूमि को बहाल करने और मरुस्थलीकरण को कम करने, वन्यजीवों के लिए आवश्यक आवास प्रदान करने और कार्बन पृथक्करण लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि वानिकी, संरक्षण कृषि और एकीकृत जल प्रबंधन जैसी टिकाऊ कृषि प्रथाएं मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने, सूखे के प्रति लचीलापन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में योगदान करती हैं।

स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना प्रभावी मरुस्थलीकरण शमन रणनीतियों का आवश्यक घटक है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और क्षमता निर्माण गतिविधियों में स्वदेशी समुदायों व छोटे किसानों सहित स्थानीय हितधारकों को सम्मिलित करके, हम विशिष्ट समाधानों को लागू करने के लिए पारंपरिक ज्ञान और विशेषज्ञता का उपयोग कर सकते हैं, जो मरुस्थलीकरण के मूल कारण का निराकरण करते हैं। मरुस्थलीकरण के विरुद्ध लड़ाई ऐसी नहीं है, जिसे रातोंरात जीता जा सके, बल्कि ठोस प्रयास, दृढ़ संकल्प और नवीनता के साथ हम धरा पर रेंगती मौत को मात दे सकते हैं।

वह सभ्यता, जिसके पास आधुनिक तकनीकी ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं कर सकती।

– अब्दुल कलाम

गठबंधन धर्म

गठबंधन सरकारों में सहयोगी दलों की मंत्री पद और विभागों की मांग को लेकर खींचतान नई बात नहीं है। हर दल का मुखिया अपने नेताओं की सामूहिक आकांक्षाओं को साथ लेकर चलता है। गठबंधन का पहला धर्म होता है, नीतियों और योजनाओं पर फैसले के समय निजी या दलगत स्वार्थों से ऊपर उठ कर सहमति बनाने का। गठबंधन का एक भी दल इस धर्म का निर्वाह नहीं कर पाता, तो वह सरकार चल नहीं पाती। देश में गठबंधन सरकारें बनी और चली हैं, पर वे तब-तब गिर गई हैं, जब गठबंधन धर्म के निर्वाह में दलगत स्वार्थ या वैचारिक मतभेद आड़े आए हैं। इस बार फिर गठबंधन सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने नरेंद्र मोदी की अगुआई में सरकार बनाने पर सहमति जता दी है। मंत्रालयों के बंटवारे आदि को लेकर मंथन चल रहा है। हर बड़े दल से बड़प्पन की अपेक्षा रहती है और वह थोड़ा झुक कर अपने सहयोगियों का मान ऊपर रख भी लेता है। मगर सरकार गठन से पहले ही जिस तरह जद (एकी) और तेलगुदेसम की तरफ से नीतियों को लेकर शर्तें रखी जाने लगी हैं, उससे गठबंधन के भविष्य पर आशंका गहराने लगी है।

जद (एकी) ने कहा है कि अग्निवीर योजना पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। यही मांग विपक्षी दल शुरू से उठाते आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया गठबंधन ने तो सार्वजनिक रूप से एलान किया था कि अगर उसकी सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। वही बात अगर सहयोगी करने लगेंगे, तो सरकार के लिए मुश्किल होगी। भाजपा समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती है। इस दिशा में वह आगे भी बढ़ चुकी है। मगर उसके दोनों प्रमुख सहयोगी दलों ने इस पर भी पुनर्विचार की बात कही है। सभी राज्य सरकारों से सहमति की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सरकार अगर लचीला रुख अपनाए, तो सहमति बन सकती है। राजनीति में हर कदम के दूरगामी परिणाम होते हैं। कौन-सा दल किस मुद्दे पर अपनी बात मनवा लेता है, उससे उसके राजनीतिक भविष्य पर असर पड़ता है। भाजपा को इस वक्त सहयोगी दलों के साथ मिल कर सरकार चलाने की मजबूरी है, पर वह अपने सिद्धांतों और नीतियों से डिगेगी, तो नुकसान का खतरा बना रहेगा।

ऐसी स्थितियों में सरकार की अगुआई कर रहे दल के सामने चुनौती होती है कि वह कैसे अपने सहयोगियों को नीतियों पर एकमत करे और किस हद तक उनकी शर्तों को माने। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक छवि टिकाऊ और भरोसेमंद सहयोगी की नहीं रही है। इससे पहले भी वे कई बार राजग के साथ रहे, बीच में छोड़ कर चले गए, फिर आ गए हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने जैसी उनकी कुछ पुरानी मांगें हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के आरक्षण के मुद्दे पर भी उनके विचार अलग हैं। अब जब वे मोलभाव करने की स्थिति में हैं, ये मुद्दे उठा सकते हैं। मगर इससे सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी ही। गठबंधन की सरकारें शर्तों की रस्साकशी से नहीं, सहयोग और सहमति के संकल्प से चलती हैं। अगर इसकी कमी इस गठबंधन में रहेगी, तो अनिश्चितताओं के बादल शायद ही कभी छंटेंगे।

पानी पर निगरानी

नदियों के जल के बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद नया नहीं है। देश में कई राज्य नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर मुकदमा लड़ रहे हैं। विभिन्न प्राधिकार बने हुए हैं, लेकिन विवादों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को यमुना का जल मिले और सुगमता से मिले, यह मुद्दा अब राजनीतिक स्वरूप ले चुका है। दिल्ली में जल संकट की स्थिति गंभीर है। गुरुवार को दिल्ली सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि हिमाचल प्रदेश 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ेगा और हरियाणा दिल्ली की तरफ पानी के प्रवाह को सुगम बनाएगा। यह व्यवस्था देते हुए शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी बिल्कुल सटीक है कि पानी को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

यह विडंबना है कि जब लोग प्यासे हों तो पानी छोड़ने को लेकर खींचतान मचे और जो राज्य दबाव डाल सकता है, वह अड़ जाए। हरियाणा और दिल्ली की सरकारों में हथिनीकुंड बांध से छोड़े जाने वाले पानी को लेकर अक्सर ठनी रहती है। इस बार दिल्ली सरकार उच्चतम न्यायालय पहुंची। इस मामले में शीर्ष न्यायालय ने मामले से जुड़े राज्यों – उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से पूछा कि वे दिल्ली को कितना पानी दे सकते हैं। हिमाचल ने हामी भरी। अब हिमाचल प्रदेश, हरियाणा को पूर्व सूचना देकर पानी छोड़ेगा और यूवाईआरबी हथिनीकुंड में आने वाले अतिरिक्त पानी को मापेगा ताकि इसे वजीराबाद और दिल्ली तक पहुंचाया जा सके। जाहिर है, दिल्ली को मिल रहा पानी हरियाणा रोक तो नहीं रहा, इसकी निगरानी शीर्ष अदालत करेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि अदालत द्वारा दी गई इस व्यवस्था का समुचित पालन होगा। कोई सरकार रोड़े नहीं अटकाएगी और आम जन को सुगमता से पानी मिल सके, इसके लिए सभी मिलकर प्रयास करेंगे। इसके साथ ही, लोगों को भी पानी बचाने की सामूहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसके लिए उन्हें पानी की खपत के लिए जिम्मेदाराना व्यवहार अपनाना चाहिए।

जलवायु अनुरूप नगरों की जरूरत

महानगरों में हरियाली और जल-संरचनाओं का क्षेत्र कम होने से गर्म क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। शहरों में हरियाली और नमी बनाए रखने वाले तालाब, नदी-झीलों का अस्तित्व सिमटता जा रहा है। यह जलभराव गर्मी से बचाव करता था।

प्रमोद भार्गव

सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से पृथ्वी, प्राणी के शरीर, समुद्र और जल के अन्य स्रोतों से नमी सोख लेता है। नतीजतन उम्मीद से ज्यादा तापमान बढ़ता है, जो गर्म हवाएं चलने का कारण बनता है। यही हवाएं लू कहलाती हैं। अब यही हवाएं देश के पचास से ज्यादा शहरों को 'उष्मा-द्वीप' (हीट आइलैंड) में बदल रही हैं। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्यप्रदेश में पारा 43 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है। राजस्थान के बाड़मेर में दिन का तापमान 48 डिग्री और कश्मीर में गरम हवाओं के चलते तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया है। आमतौर से गरम हवाएं तीन से आठ दिन चलती हैं और एक-दो दिन में बारिश हो जाने से तीन-चार दिन राहत रहती थी, लेकिन इस बार गरम हवाएं चलने की निरंतरता बनी हुई है। इस कारण कई शहर ऊष्मा-द्वीप में बदल गए हैं और रहने लायक नहीं बचे हैं। इसके प्रमुख कारणों में शहरीकरण का बढ़ना और हरियाली का क्षेत्र घटना माना जा रहा है।

सामान्य स्थिति में द्वीप का अर्थ समुद्री या नदी-घाटियों में पानी से घिरे उस ऊंचे स्थल से लिया जाता है, जिसके चारों ओर जल भरा होता है। लेकिन अब उष्मा-द्वीप उन शहरी इलाकों को कहा जाने लगा है, जो ज्यादा तापमान से झुलस रहे हैं। ज्यादातर उष्मा-द्वीप घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में आमद दर्ज करा रहे हैं। ऐसे इलाकों में बाहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक तापमान का सामना करना पड़ता है। ऊंची इमारतें, सीसी की सड़कें, पैदलपथ और अन्य बुनियादी ढांचागत विकास इसके लिए दोषी हैं। हरियाली कम होने के कारण उच्च ताप वाले क्षेत्र उष्मा-द्वीप में परिवर्तित हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में दिन का तापमान लगभग 1-7 डिग्री और रात का तापमान लगभग 2-5 डिग्री तक बढ़ जाता है।

सीएसई ने देश में अलग-अलग जलवायु वाले नौ शहरों के अध्ययन में पाया कि जयपुर जैसे शहरों में ज्यादा तापमान वाले दिनों में शहर का 99.52 फीसद हिस्सा गर्म हवाओं के केंद्र में आकर ऊष्मा-द्वीप बन जाता है। सतत आवास कार्यक्रम (सस्टेनेबल हैबिटैट प्रोग्राम) के निदेशक रजनीश सरीन का कहना है कि हीट सेंटर उस क्षेत्र को कहते हैं, जहां जमीनी सतह का तापमान (एलएसटी) छह साल या उससे अधिक समय में बार-बार मैदानी इलाकों में 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। महानगरों में हरियाली और जल-संरचनाओं का क्षेत्र कम होने से हीट सेंटर का विस्तार हो रहा है। शहरों में हरियाली और नमी बनाए रखने वाले तालाब, नदी-झीलों का अस्तित्व सिमटता जा रहा है। यह जलभराव गर्मी से बचाव करता था। इनके सिमटने से शहरों में और शहरों के आस-पास बंजर भूमि और ईंट, सीमेंट, कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं, जो गर्मी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सीएसई ने नागपुर, अहमदाबाद, चेन्नई, पुणे, जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और भुवनेश्वर में यह सर्वेक्षण किया है। लेकिन जिन शहरों में इस नजरिए से सर्वे नहीं हो पाया है, वे भी ऐसे ही हालातों के शिकार हो सकते है।

मानव निर्मित प्रदूषण से जुड़ी इस आपदा के कारणों में आधुनिक विकास और बढ़ता शहरीकरण है। इन्हीं कारणों से हवाएं आवारा होकर लू का रूप लेने लगी हैं। सुनामी जैसे तूफान इन्हीं आवारा हवाओं के दुष्परिणाम हैं। अमेरिका के नेशनल ओसियानिक एंड एटमासफेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की रपट के अनुसार भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया के कई देश गरम हवाओं से जूझ रहे हैं। इन देशों में गरम हवाएं चलने की आशंका 45 गुना बढ़ गई है। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमा शामिल हैं। वियतनाम में तो हालात इतने बदतर हो गए हैं कि गर्मी की वजह से कई तालाब पूरी तरह सूख गए हैं और लाखों टन मछलियां मर गई हैं। पश्चिम एशिया के देश सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, जार्डन और लेबनान में गरम हवाएं पांच गुना बढ़ सकती हैं। एशिया में घातक गरम हवाएं लगातार चलने का यह तीसरा वर्ष है। इसकी एक वजह अलनीनो भी मानी जा रही है। प्रशांत महासागर से आने वाली गरम हवाओं की वजह से दुनिया में गरम हवाएं चल रही हैं।

> वायुमंडल में गर्म हवाएं आमतौर से क्षेत्र विशेष में अधिक दबाव की वजह से उत्पन्न होती हैं। वैसे तेज गर्मी और लू पर्यावरण और बारिश के लिए अच्छी होती हैं। अच्छा मानसून इन्हीं आवारा हवाओं का पर्याय माना जाता है, क्योंकि तपिश और बारिश में गहरा अंतर्संबंध है। जिस तरह से बेमौसम बरसात ने दुबई शहर को बाढ़ में बदल दिया, उसने आधुनिकतम शहरी विकास के माडल को नकार दिया है। यही हालात मुंबई, चेन्नई और बंगलुरु में देखने में आ रहे हैं। अतएव हमें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल शहरों का निर्माण करना होगा।

हरेक जुबान पर प्रचंड धूप और गर्मी जैसे बोल आमफहम हो गए हैं। हालांकि लू और प्रचंड गर्मी के बीच भी एक अंतर होता है। गर्मी के मौसम में ऐसे क्षेत्र जहां तापमान, औसत तापमान से कहीं ज्यादा हो और पांच दिन तक यही स्थिति यथावत बनी रहे तो इसे 'लू' कहने लगते हैं। मौसम की इस असहनीय विलक्षण दशा में नमी भी समाहित हो जाती है। यही सर्द-गर्म थपेड़े लू की पीड़ा और रोग का कारण बन जाते हैं। किसी भी क्षेत्र का औसत तापमान, किस मौसम में कितना होगा, इसकी गणना एवं मूल्यांकन पिछले 30 साल के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। वायुमंडल में गर्म हवाएं आमतौर से क्षेत्र विशेष में अधिक दबाव की वजह से उत्पन्न होती हैं। वैसे तेज गर्मी और लू पर्यावरण और बारिश के लिए अच्छी होती हैं। अच्छा मानसून इन्हीं आवारा हवाओं का पर्याय माना जाता है, क्योंकि तपिश और बारिश में गहरा अंतर्संबंध है। जिस तरह से बेमौसम बरसात ने दुबई शहर को बाढ़ में बदल दिया, उसने आधुनिकतम शहरी विकास के माडल को नकार दिया है। यही हालात मुंबई, चेन्नई और बंगलुरु में देखने में आ रहे हैं। अतएव हमें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल शहरों का निर्माण करना होगा।

हवाओं के गर्म या आवारा हो जाने का प्रमुख कारण ऋतुचक्र का उलटफेर और भूतापीकरण (ग्लोबल वार्मिंग) का औसत से ज्यादा बढ़ना है। इसीलिए वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि इस बार प्रलय धरती से नहीं आकाशीय गर्मी से आएगी। आकाश को हम निरीह और खोखला मानते हैं, किंतु वास्तव में यह खोखला है नहीं। भारतीय दर्शन में इसे पांचवां तत्त्व यूं ही नहीं माना गया है। सच्चाई है कि यदि परमात्मा ने आकाश तत्त्व की उत्पत्ति नहीं की होती, तो संभवतः आज हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। हम श्वास भी नहीं ले पाते। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चारों तत्त्व आकाश से ऊर्जा लेकर ही क्रियाशील रहते हैं। ये सभी तत्त्व परस्पर परावलंबी हैं। यानी किसी एक तत्त्व का वजूद क्षीण होगा तो अन्य को भी छीजने की इसी अवस्था से गुजरना होगा। प्रत्येक प्राणी के शरीर में आंतरिक स्फूर्ति एवं प्रसन्नता की अनुभूति आकाश तत्त्व से ही संभव होती है, इसलिए इसे ब्रह्मतत्त्व भी कहा गया है। अतएव प्रकृति के संरक्षण के लिए सुख के भौतिकवादी उपकरणों से मुक्ति की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति भी बढ़ रही है और जलीय स्रोतों पर दोहन का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में प्रकृति से उत्पन्न कठिन हालातों के साथ जीवन यापन की आदत डालनी होगी तथा पर्यावरण संरक्षण पर गंभीरता से ध्यान देना होगा।

सौहार्द का परिवेश

नरेंद्र सिंह 'नीहार'

आत्मीय होना किसी का गौरव की बात है। आत्मीय होने का संबंध आत्मा से जोड़ा जाता है, जो मन और बुद्धि से आगे है। आत्मीयता शब्द का अर्थ अपनेपन, अपनत्व या अपने करीबी के रूप में लिया जाता है। इसे बहुत ही कोमल और पवित्र भाव माना जाता है। हम जिसको आत्मीय बना लेते हैं, उसको दिल की गहराई तक प्रेम करते हैं। उसकी हर पल चिंता करते और ध्यान रखते हैं। अपने ईष्ट से उसके कल्याण की कामना करते हैं। उसके बिना कहे या बिना मांगे ही अभीष्ट को प्रस्तुत कर देते हैं। यही आत्मीयता है और आत्म-तत्त्व का विस्तार भी।

आत्मीयता प्रदर्शन या किसी के सामने इसे जताने का विषय ही नहीं है। चुपचाप मुदित या कातर होना ही सच्ची आत्मीयता कही जाती है। हमारी वाणी की मृदुता और कंपन, ललाट की रेखाएं और नयनों के कोर आत्मीयता को दर्शाने वाले स्रोत हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कभी अपने स्वजन या स्नेहीजन की उन्नति या प्रगति को देखते हैं तो मन थोड़ा भावुक हो जाता है। उनसे मिलने पर कुछ कहते हुए गला रुंधने लगता है और आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। हम उन्हें अंक में भर लेते हैं। अपनी झोली फैलाकर उनकी बेहतरी के लिए दुआएं मांगते हैं। यही आत्मीयता का प्रत्यक्ष दर्शन है। दूसरी ओर आत्मीय जन के दुखी या निराश होने पर हम भी अपने मन के किसी कोने में दुख की आंच को महसूस करते हैं। स्वयं भी उदास और अन्यमनस्क हो जाते हैं। दिनचर्या में हमारा मन नहीं लगता और अपने आत्मीय जन को उस निराशाजनक परिस्थिति से निकालने में भरपूर कोशिश भी करते हैं। यही आत्मीयता की सच्ची कसौटी भी है। इस लगाव की पृष्ठभूमि भी होती है, जब किसी दौर में आपसी सद्भाव या लगाव की वजह से ऐसी संवेदनाओं का विकास होता है, जब कोई व्यक्ति आत्मीय हो जाता है।

आत्मीय होना भी कोई आसान काम नहीं है। केवल रक्त संबंध आत्मीयता के आधार होंगे, ऐसा भी नहीं है। बल्कि इतिहास साक्षी है कि रक्त के संबंधी ही एक-दूसरे के रक्त के प्यासे भी रहे हैं। सारे षड्यंत्र, कुचक्र और लाक्षागृह रक्त संबंध वालों ने ही बुने हैं। वहीं आत्मीय होने के लिए किसी का संस्कारी, श्रद्धामय और सद्भावी होना बहुत जरूरी है। तभी हम किसी की आत्मा तक पहुंच बना सकते हैं। यह परकाया प्रवेश करने के समान है। इसलिए सदुणी और आज्ञाकारी होकर हम भी किसी के आत्मीय बन सकते हैं। यहां रक्तसंबंधी होने की बाध्यता नहीं है। रिश्ते-नाते से बाहर ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे, जिनके लिए हमारे मन में ज्यादा मजबूत जगह बन जाती है। यों भी, सुख में साथ होने के मुकाबले दुख में साथ खड़े होने वाले लोग अपने आप हमारे दिल में उतरते चले जाते हैं और आत्मीय हो जाते हैं।

आज के दौर की आत्मीयता और उसके उद्घाटन पर गौर किया जा सकता है। आत्मीयता के आवरण प्याज की बारीक परतों के समान झीने से नजर आते हैं। मसलन, आत्मीयता का ढोंग, आत्मीयता का प्रपंच और आत्मीयता का राग आदि। आजकल पैमाने बदल रहे हैं। आत्मीयता का खेल बड़े नाप-तोल के साथ खेला जाता है। मानवीय स्वभाव कभी भी एक सरल और सीधी रेखा के समान नहीं होता है। वह कब वक्राकार या सर्पिलाकार हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। किसी लचीली वस्तु की तरह आत्मीयता भी घटती-बढ़ती रहती है। यह बाजार की मांग और पूर्ति के संतुलन से प्रभावित होने लगी है। दूसरे, किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारी आत्मीयता हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। घर-परिवार के बच्चों के लिए भी अलग-अलग हो सकती है। जो बालक आज्ञाकारी, वफादार और प्रगतिशील होता है, उसके प्रति हमारी आत्मीयता हद से ज्यादा होती है। उसका एक बड़ा-सा नुकसान अन्य संतानों में विद्रोह और ईर्ष्या के रूप में देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सामाजिक आत्मीयता के भी कई सोपान होते हैं। हमारे सगे-संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी-पहचान वाले और दोस्त। इनमें क्या हमारी आत्मीयता सबके साथ एकरस होती है? शायद नहीं। आत्मीयता का सहज बीजारोपण सामने वाले के हमारे प्रति व्यवहार से होता है। हमारी स्वीकृति, सम्मान और विश्वास। हमारी चिंता, ध्यान और अपेक्षाओं की पूर्ति आत्मीयता का खाद-पानी होती है। हम उस पर अलग से ध्यान देते हैं और उस पर सोचते हैं। चिंतन करते हैं और वक्त जरूरत पर छाता बनकर तन भी जाते हैं। इसके विपरीत, अगर हम घर-परिवार और समाज में निरंतर उपेक्षित और अपमान को सहन कर रहे हैं, तो किसी के प्रति भी आत्मीयता का विकास नहीं हो सकेगा। नतीजे में हम विद्रोही और किसी पक्ष ो अलग होने के समर्थक हो जा सकते हैं। मथुरा हमेशा तीन लोक से न्यारी ही बसेगी।

एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आत्मीयता से भरे रिश्तों की बड़ी जरूरत है। ऐसी आत्मीयता, जो लेनदेन के कारोबार से ऊपर हो। हमारी प्राथमिकता और हमारा नजरिया हमेशा प्रगतिशील होना चाहिए। जिस भाव से हम अपनी स्वीकृति और सम्मान चाहते हैं, वही भाव दूसरों के लिए भी प्रस्तुत करें। आत्मीयता दीप से दीप जलाने जैसा उत्सव है, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान, सौहार्द और सहकार का परिवेश बनाने में मददगार साबित होगा।

दुनिया मेरे आगे

> मानवीय स्वभाव कभी भी एक सरल और सीधी रेखा के समान नहीं होता है। वह कब वक्राकार या सर्पिलाकार हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। किसी लचीली वस्तु की तरह आत्मीयता भी घटती-बढ़ती रहती है। यह बाजार की मांग और पूर्ति के संतुलन से प्रभावित होने लगी है।

संभलने की जरूरत

लगभग दो महीने की गहमा-गहमी के बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व खत्म हो गया। इस दौरान काफी संख्या में रैलियां हुईं, जनता से कई तरह के वादे किए गए, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए, पक्ष और विपक्ष ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के दावे करते रहे। परिणाम आने से पहले 'एग्जिट पोल' देखकर ही जीत की खुशियां मनाने की तैयारी की जाने लगी! मगर जैसे ही चुनाव नतीजे आने शुरू हुए, एक तरफ मायूसी थी और दूसरी तरफ खुशी का माहौल। भाजपा जहां अपने दम पर 370 से ऊपर और राजग के 400 से ऊपर सीटें आने के दावे कर रही थी, चुनाव परिणाम देखकर भौंचक्की रह गई। इस चुनाव परिणाम ने जहां एक तरफ भाजपा को झटका दिया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को संजीवनी दी। मतदाताओं ने भी बता दिया कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अहमियत हमारी है। आम आदमी ने रोजी-रोटी, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर अपना वोट दिया। भाजपा को अब संभल जाना चाहिए, नहीं तो अति आत्मविश्वास अगली बार उसे और नीचे ले जाएगा।

– **चरनजीत अरोड़ा, नरेला, दिल्ली**

न्याय की आस

यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में वैसे भी दोष सिद्धि और सजा की दर बहुत कम है। फिर अगर ऐसे मामलों में रसूखदार लोग शामिल हों, तो पीड़ितों को इंसाफ मिलना मुश्किल होता है। प्रज्वल रेवन्ना और उसके पिता पर लगे आरोपों की कितनी निष्पक्ष और प्रभावी जांच हो पाएगी, यह देखने की बात है। यही प्रकरण भारत के किसी अन्य प्रदेश में घटित हुआ होता तो इसकी जांच-पड़ताल और अदालती कार्यवाही की प्रतीक्षा किए बिना अभी तक आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल चुका होता। फिलहाल जांच दल पर निगाहें टिकी हुई हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि वह इस मामले को ऐसे निर्णय तक पहुंचाएगा जो एक नजीर बन सकेगा। अच्छी बात है कि प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी से वापस स्वदेश आ चुका है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर उचित कार्रवाई हो रही है। दुनिया उम्मीद पर टिकी है, स्वाभाविक रूप से इस मामले में भी अच्छे फैसले की उम्मीद है।

– **इशरत अली कादरी, भोपाल**

मौसम का मिजाज

अल-नीनो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में पानी के असामान्य रूप से गर्म होने और ग्रीन हाउस गैसों की वजह से वायुमंडल तथा महासागर में फंसी अतिरिक्त ऊर्जा के कारण बनता है। अल-नीनो का असर भारत और दुनिया के अनेक हिस्सों में पड़ता है।

अल-नीनो का प्रभाव अभी बना हुआ है, लेकिन यह कमजोर हो रहा है। इसके प्रभाव के कारण ही भारत और पाकिस्तान सहित दक्षिण एशिया में लाखों लोगों ने अप्रैल और मई में भीषण गर्मी का सामना किया है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर तक अल-नीनो कमजोर पड़ कर ला-नीना में परिवर्तित हो जाएगा। ला-नीना की प्रकृति अल-नीनो के विपरीत होती है। ला-नीना में मानसून के दौरान भरपूर बारिश होती है, लेकिन अल-नीनो के खत्म होने से जलवायु परिवर्तन रुकेगा नहीं, क्योंकि ग्रीनहाउस गैसों के कारण पृथ्वी गर्म होती रहेगी। अब इस पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी हम सब पर है।

– **वेद सिंह यादव, लखनऊ**

गर्मी की मार

'लू के थपेड़े' (संपादकीय, 3 जून) में इस गर्मी में जान देने वालों की सच्चाई बयान की गई है। मतदान प्रक्रिया तो समाप्त हो गई, पर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। इस जानलेवा गर्मी के मौसम में आखिर क्या सोचकर चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को इतना लंबा खींचा, इसके लिए चुनाव आयोग की आलोचना भी हो रही है। मरने वाले अधिकांश छोटी श्रेणी के कर्मचारी हैं। चुनाव आयोग को मौसम विभाग से गर्मी की जानकारी लेकर ही चुनाव प्रक्रिया का समय निर्धारित करना चाहिए था। अधिक से अधिक मई के पहले हफ्ते में चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जानी चाहिए थी। जानलेवा पिछले लोकसभा चुनाव से बहुत कम हुए मतदान के पीछे भी गर्मी भी एक कारण थी। चुनाव आयोग को मतदान की तारीख निर्धारित करते समय सुरक्षा कर्मियों और मतदान कर्मचारियों की सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए।

– **बीर सैन सरल, गाजियाबाद**

www.readwhere.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

चिंतन

दागी नेताओं का संसद पहुंचने का द्वार बंद हो

देश में चुनाव दर चुनाव राजनीतिक व चुनाव सुधार की चर्चा होती है। लेकिन चुनाव में जीत कर आने वाले जनप्रतिनिधियों के बारे में जब जानकारी मिलती है, तो निराशा होती है। पता चलता है कि न तो धनबल के प्रयोग पर अंकुश लगा है, न अपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के चुनकर आने पर रोक लग पाई है और न ही ज्यादा से ज्यादा धनकुबेरों को ही प्रत्याशी बनाने की प्रवृति पर लगाम लगी है। 18वीं लोकसभा के लिए जीत कर आए 543 सांसदों द्वारा पर्चा भरने के समय चुनाव आयोग की दी गई जानकारी का 'एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) ने विश्लेषण किया है, जिसमें कहा गया है कि नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों में 46 प्रतिशत के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। कहने का तात्पर्य कि 543 सदस्यों में से 251 सांसदों पर आपराधिक आरोप हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग आपराधिक रिकार्ड वाले नेताओं के खिलाफ सख्त हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है। उच्चतम न्यायालय ने 13 फरवरी, 2020 को संविधान के अनुच्छेद 129 तथा अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए सभी राजनीतिक दलों को अपने विधानसभा और लोकसभा उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का आदेश दिया था। इस आदेश का आशय राजनीति को आपराधिक छवि वाले नेताओं से मुक्त करना था। पर ऐसा नहीं हुआ। 2019 में हुए आम चुनाव में करीब 43 फीसदी जनप्रतिधि आपराधिक रिकार्ड वाले थे, जबकि 2014 में 185 (34 प्रतिशत), 2009 में 162 (30 प्रतिशत) तथा 2004 में 125 (23 प्रतिशत) थे। विश्लेषण के मुताबिक 2009 के बाद से आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा करने वाले सांसदों की संख्या में 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2024 में जीतकर आने वाले सांसदों में 93 फीसदी करोड़पति हैं, जो 2019 के 88 प्रतिशत के मुकाबले पांच प्रतिशत अधिक है। इस बार चुनाव के दरम्यान हजारों करोड़ की नकदी जब्त की गई थी। ये सभी चीजें दर्शाती हैं कि हमारा चुनाव धनबल व बाहुबल से मुक्त नहीं हो पाया है। गंभीर अपराध के मामलों वाले सदस्यों की संख्या 2009 से 124 प्रतिशत बढ़ गई है। इस बार तो आतंकवाद के आरोपित दो लोग भी सांसद चुनकर आए हैं। अब तक चुनाव सुधार पर तारकुंडे समिति (1974-75) व दिनेश गोस्वामी समिति (1990), राजनीति के अपराधीकरण पर वोहरा समिति (1993), चुनावों में राज्य वित्तपोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998),चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की रिपोर्ट (1999) व चुनाव आयोग की रिपोर्ट (2004), चुनाव कानूनों और चुनाव सुधार पर तनखा समिति (2010) आदि ने अपनी सिफारिशें दी हैं। जिनके आधार पर सजायाफ्ता के चुनाव लड़ने पर रोक, दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध और उम्मीदवार की मौत पर चुनाव स्थगित न होना, ईवीएम, वीवीपैट, नोटा, चुनावी खर्च पर सीलिंग, पोस्टल बैलेट व तकनीक के प्रयोग आदि सुधार किए गए हैं। इसके बावजूद आरोपित अपराधियों के चुनाव लड़ने व अपराधिक रिकार्ड वाले नेताओं के सांसद बनने पर रोक नहीं लग पाई है। चुनाव आयोग के साथ राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन नेता पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं, उन्हें वे टिकट ही न दें। राजनीतिक दल चाहेंगे तो अपराधियों के चुनाव लड़ने का द्वार बंद हो सकता है।

अब तेज आर्थिक विकास की चुनौती

मोदी 3:0 सरकार
डॉ. जयंतीलाल भंडारी

18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब बनने वाली एनडीए के तीसरे कार्यकाल की नई सरकार देश को आर्थिक विकास की डगर पर तेजी से आगे बढ़ाएगी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने वर्ष 2023-24 में देश की विकास दर 8.2 फीसदी रहने संबंधी रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक आर्थिक व वित्तीय बाजार मजबूत हो रहे हैं। भारत के वित्तीय और गैर वित्तीय क्षेत्रों के दमदार बही-खाते भारत की आर्थिक ताकत बढ़ा रहे हैं। इन सबके साथ नई सरकार के सामने आर्थिक विकास की नई रणनीति से देश की आर्थिकी को मजबूती देते हुए तेजी से आगे बढ़ाने की चुनौती होगी।

4 जून को 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब बनने वाली एनडीए के तीसरे कार्यकाल की नई सरकार देश को आर्थिक विकास की डगर पर तेजी से आगे बढ़ाएगी। निश्चित रूप से देश को एक बेहतर आर्थिक परिवेश के साथ बेहतर मानसून की सौगातें विरासत में मिलते हुए दिखाई दे रही हैं । स्थिति यह है कि देश की बेहतर आर्थिक के परिप्रेक्ष्य में दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां यह कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि भारत में कोई भी सरकार बने अब आर्थिकी तेज गति से मजबूत होगी। उल्लेखनीय कि हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने वर्ष 2023-24 में देश की विकास दर 8.2 फीसदी रहने संबंधी रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक आर्थिक व वित्तीय बाजार मजबूत हो रहे हैं। भारत के वित्तीय और गैर वित्तीय क्षेत्रों के दमदार बही-खाते भारत की आर्थिक ताकत बढ़ा रहे हैं। रिजर्व बैंक के द्वारा भारत सरकार को दिया गया रिकॉर्ड लाभांश, वैश्विक आर्थिक संगठनों के द्वारा भारत के विकास के नए-नए प्रभावी विश्लेषण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन सबके साथ- साथ नई सरकार से देश की अर्थव्यवस्था को नई शक्ति मिलने की संभावनाओं से देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ने के शुभ संकेत देते हुए दिखाई दे रही है।

गौरतलब है कि हाल ही में दुनिया की प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसएेंडपी ने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, तेज आर्थिक सुधार और बढ़ती राजकोषीय मजबूती के मद्देनजर भारत की रेटिंग को स्थिर यानी स्टेबल से बदलकर पॉजिटिव कर दिया है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि पिछले तीन साल में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की औसत वास्तविक वृद्धि दर 8.1 फीसदी सालाना रही है और अब यह विकास दर अगले तीन साल में लगातार 7 फीसदी के करीब होगी। दुनिया के प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट बैंकर गोल्डमैन सैक्स ने अपनी नई रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2024 में भारत की विकास दर को बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है। चालू वित्त वर्ष में विकास दर बढ़ने संबंधी अन्य महत्वपूर्ण नई रिपोर्टों के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष- आईएमएफ ने 6.8 प्रतिशत , एशियाई विकास बैंक -एडीबी ने 7 प्रतिशत तथा विश्व बैंक ने 7.5 प्रतिशत विकास दर रहने के अनुमान व्यक्त किए हैं। देश और दुनिया के प्रमुख अर्थ विशेषज्ञों का मत है कि भारत की विकास दर आगामी दशक तक 6.5 से 7 प्रतिशत के स्तर पर दिखाई देगी। विभिन्न आर्थिक रिपोर्टों में इस बात को भी रेखांकित किया जा रहा है कि भारत में वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) संग्रह 17.7 फ़ीसदी बढ़कर 19.58 लाख करोड रुपए हो गया है। इसी तरह से 2023- 24 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) उच्चतम स्तर पर रहा है। इसका आकार 20.18 लाख करोड रुपए रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 11.7 फ़ीसदी अधिक है। कर संग्रह के ये चमकीले आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज उछाल और व्यक्तियों तथा कॉरपोरेट सेक्टर की आमदनी में वृद्धि को दर्शाते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के द्वारा हाल ही में भारत सरकार के लिए अब तक के सबसे अधिक लाभांश की राशि सुनिश्चित की गई है, वहीं दूसरी

ओर देश के शेयर बाजार ने पिछले 10 वर्षों में जो ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, उससे दुनिया भर में भारत के नए तेज विकास की नई संभावनाएँ आगे बढ़ी हैं।

रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये लाभांश देने की मंजूरी दी है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में सरकार ने रिजर्व बैंक और सरकारी बैंकों के लाभांश से 1.02 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान लगाया था। ऐसे में 'रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाने वाला लाभांश बजट अनुमान की तुलना में 107 फीसदी ज्यादा है। यह एक तरह से सरकार के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 1.09 लाख करोड़ रुपये के अप्रत्याशित लाभ जैसा है। इतना ही नहीं रिजर्व बैंक ने पहली बार आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया गया है, जो पहले 6 फीसदी था। रिजर्व बैंक ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, इसीलिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आकस्मिक जोखिम बफर बढ़ाकर 6.5 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक के द्वारा सरकार को रिकॉर्ड लाभांश के दिए जाने के निर्णय और वैश्विक आर्थिक संगठनों व वैश्विक क्रेडिट एजेंसियों के द्वारा वर्ष 2024-25 में भारत की ऊंची विकास दर के अनुमानों के बाद भारतीय शेयर बाजार को लाभ मिला। यह उल्लेखनीय है कि शेयर बाजार और निवेशकों को उम्मीद थी कि 4 जून के लोकसभा चुनाव परिणामों से भाजपा और एनडीए को भारी बढ़त मिलेगी, लेकिन चुनाव में भारी अनुमान के मुताबिक ऊंचाई नहीं होने के कारण शेयर बाजार की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं। फिर भी यह कोई छोटी बात नहीं है कि बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पांच लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंचने के साथ ही भारत इस मुकाम तक पहुँचने वाला दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश बन गया है। कोरोनाकाल के बाद भारतीय घरेलू खुदरा निवेशकों की रूचि शेयर बाजार में बढ़ी है। साथ ही पिछले 10 साल में डीमेंट अकाउंट 2.3 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ हो गए हैं और म्यूचुअल फंड-निवेशकों की संख्या 1 करोड़ से बढ़कर 4.5 करोड़ हो गई है। स्थिति यह है कि पिछले 10 साल में शेयर बाजार कहां से कहां पहुंच गया है। लाखों छोटे निवेशक आज उत्साहपूर्वक बाजार से जुड़े हैं। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार है और वैश्विक निवेशकों का भरोसा भी भारत के शेयर बाजार पर बढ़ा है।

अब ऐसी आर्थिक मजबूती से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि होगी। यह देश की उत्पादक क्षमता बढ़ाएगा और वृद्धि की संभावनाओं को बेहतर करेगा। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि भारत के प्रति बढ़ते आर्थिक आकर्षण से न केवल देश में ज्यादा एफडीआई लाने में मदद मिलेगी, बल्कि यह विदेशी कंपनियों और निवेशकों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करेगा कि वे भारत से हुई कमाई को फिर भारत में ही निवेश करने के लिए तत्पर रहें। इससे भारत में कारोबारी माहौल में सुधार होगा। यह सुधार उन घरेलू निवेशकों को भी बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा जो अभी किनारे बैठकर निवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एफडीआई का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह भी है कि विदेशी निवेशक तकनीकी विशेषज्ञता भी लाते हैं।

निश्चित रूप से वर्ष 2023-24 में विकास दर के 8.2 प्रतिशत रहने, शेयर बाजार के बढ़ने, रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये का बंपर लाभांश दिए जाने से नई सरकार को व्यय प्रबंधन में खासी मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में सरकार ने 5.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5 प्रतिशत पर लाना चाहती है। इन सबके साथ- साथ नई सरकार के सामने आर्थिक विकास की नई रणनीति से देश की आर्थिकी को मजबूती देते हुए तेजी से आगे बढ़ाने की चुनौती होगी।

(लेखक ख्यात अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस
बाल मुकुन्द ओझा

सबको पौष्टिक आहार सुनिश्चित हो

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और खाद्य जनित रोगों पर नियंत्रण के उपायों को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष की थीम सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य रखी गई है। मानव जीवन के लिए खाद्य पदार्थों की सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है। लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन का प्रकृति प्रदत अधिकार है। राज्य का दायित्व है कि प्रकृति की ओर से प्रदान किए गए अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करे। खाद्य सुरक्षा का अधिकार भी इसमें शामिल है। भारत ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय आर्थिक विकास किया है और यह विश्व की सबसे तेज़ी से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न उपलब्धियों के बावजूद देश में गरीबी और खाद्य असुरक्षा की स्थिति अभी भी चिंता का विषय है। खाद्य या आहार को किसी व्यक्ति के भरण-पोषण, विकास और वृद्धि के लिए मूलभूत आवश्यकता माना जाता है।

देश में खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है। 2022 में, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ने खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत को 113 प्रमुख देशों में से 68वें स्थान पर रखा। 2023 में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने भारत को 125 देशों में से 111वें स्थान पर रखा। इससे स्थिति का पता चलता है। देश में भुखमरी की यह स्थिति है कि सरकार करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज कोरोना काल से ही दे रही है, यह अभी आगे भी जारी है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में हर साल चार लाख बीस हजार लोग दूषित खाने की वजह से अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं। दुनियाभर में लगभग 10 में से एक व्यक्ति दूषित भोजन का सेवन करने से बीमार पड़ जाता है जो कि सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। इस वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हम ऐसे समय में मनाने जारहे है जब भारत भूख और गरीबी के दल दल से बाहर निकलने के लिए निरंतर प्रयासरत है। खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में विशेष रूप से संकट के समय खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। खाद्य पदार्थ की बर्बादी प्रमुख समस्या बन गई है। दुनिया भर में सभी खाद्य पदार्थों का लगभग 50 प्रतिशत बर्बाद हो जाता है और कभी भी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता है। मानव उपभोग के लिए लगभग एक तिहाई भोजन विश्व स्तर पर बर्बाद हो जाता है। दुनिया में लाखों लोग भूखे पेट सोने को मजबूर है या आधा पेट खाकर जीवन जीते हैं, वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सारा भोजन बर्बाद कर देते हैं। विकासशील देशों में सबसे अधिक अन्न सही रख-रखाव न हो पाने के कारण भी बर्बाद हो जाता हैं जो बेहद चिंतनीय है। अन्न या भोजन की बर्बादी के प्रति हम सबको जागरूक होना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए ताकि एक सशक्त समाज और देश का निर्माण हो सके।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में देश और दुनिया का ध्यान भोजन की बर्बादी की ओर दिलाया है। रिपोर्ट के अनुसार खाने के लिए उपलब्ध भोजन का 17 प्रतिशत बर्बाद हो गया और लगभग 69 करोड़ लोगों को खाली पेट सोना पड़ा था। खाने की बर्बादी को लेकर दुनियाभर में चिंता व्यक्त की जा रही है। यही भोजन यदि गरीबों को सुलभ कराया जाये तो भूखे पेट सोने वालों की कमी आएगी। भारत भी खाना बर्बाद करने वाले देशों में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने खाने की बर्बादी को लेकर डराने वाले आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक भारत में हर साल प्रति व्यक्ति 50 किलो खाने की बर्बादी हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा खाना लोग अपने घरों के भीतर बर्बाद करते हैं। वे जरूरत से ज्यादा खाना बनाकर फिर बचे खाने को फेंकते संकोच नहीं करते। होटलों और खाने-पीने के दूसरे स्थान भी इस कार्य में आगे है। खुदरा दुकानदार भी अनाज का ठीक से भंडारण नहीं कर पाते और खराब होने पर उसे फेंकना पड़ जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि लोग अपना खाना बर्बाद करते हैं या आपने अपने घर में सुना होगा कि, आपके माता-पिता हमेशा आपको खाने को बर्बादी न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि वे बखूबी समझते है कि खाना उनके लिए क्या माइने रखता है। एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि इतना ही लो थाली में जो ना जाए नाली में। लेकिन आज इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। अभी भी हमारे देश के कई राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड जैसे राज्य भुखमरी से जूझ रहे हैं। केवल बातें करने से न खाद्य सुरक्षा होगी और न ही भूखे को खाना मिलेगा। अब जबकि केंद्र में मोदी सरकार की वापसी हुई है, तो कठिन वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अपने देश में सबके लिए न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, बल्कि पौष्टिक आहार के साथ स्वास्थ्य की रक्षा भी करनी होगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

गुणों के विकास से आध्यात्मिक स्वास्थ्य संभव

संकलित
दर्शन

एक शरीर है, हमें उसका पोषण करना है और जब वह रोगग्रस्त हो जाता है, तब हमें उसकी देखभाल करनी है। हमें उसके आरोग्य का उपाय ढूंढ़ना है और जीवन के भौतिक पक्ष से जुड़े सभी विषयों पर ध्यान देना है, परंतु बात यह है कि प्रायः मानव जाति केवल यहीं पर रुक जाती है। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमारे अस्तित्व का एक मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और उच्चतर आध्यात्मिक आयाम भी है। इसलिए सफलता का उनका (परमहंसजी का) मार्ग था उचित संतुलन को प्राप्त करना। वहां, जहां आप भौतिक सफलता और समृद्धि प्राप्त करते हैं। जहां आपके पास भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शांति होती है। आध्यात्मिक रूप से आपके पास एक उच्चतर उद्देश्य के लिए अपने जीवन को संचालित करने का ज्ञान होता है, न केवल धन एकत्र करना और परिवार व संतानों की उपलब्धि, अपितु यह अनुभव करने का एक उच्चतर उद्देश्य कि मैं ईश्वर का एक स्फुलिंग हूं, मैं इस भौतिक शरीर में निवास करने वाला आत्मा हूं और अपने जीवन के सभी पक्षों में ईश्वर के पूर्ण साक्षात्कार और अभिव्यक्ति की प्राप्ति ही मेरा अंतिम उद्देश्य है। एक बार जब आप यह धारणा बना लेते हैं, तो जीवन अत्यंत रोमांचक हो जाता है, क्योंकि सब प्रकार के कौशल, क्षमताएं और योग्यताएं आपके लिए उपलब्ध हैं। ये प्रत्येक मनुष्य की अक्षय निधि का अंग हैं, परंतु वे तब तक पूर्ण रूप से निष्क्रिय रहती हैं, जब तक उन्हें सचेतन एकाग्रता और सचेतन प्रयास के द्वारा जाग्रत नहीं किया जाता है।

महिमा राम नाम की

संकलित
प्रेरणा

एक आदमी बर्फ बनाने वाली कम्पनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बन्द होने से पहले अकेला फ्रिज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाजा बंद हो गया। और वह अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया की कोई अंदर फंस गया है। वह समझ गया की दो-तीन घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो, भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा। एक घंटे ही गुजरे थे कि अचानक फ्रीजर रूम में खट खट की आवाज हुई। दरवाजा खुला चौकीदार भागता हुआ आया। उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला कि साहब मैं 20 साल से यहां काम कर रहा हूं। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते हैं। मैं देखता हूं लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हो, जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझसे हंस कर राम राम करते हो और हालचाल पूछते हो और निकलते हुए आपका राम राम काका कहना मेरी सारे दिन की थकावट दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं गुजर जाते हैं कि जैसे मैं हूं ही नहीं। आज हर दिनों की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना लेकिन राम राम काका सुनने के लिए इंतज़ार करता रहा।

अंतर्मन

आज की पाती

अबकी बार सरकार की कठिन होगी राह

हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है और एक राजनेता को प्राथमिक तौर पर अपने देश के लिए पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है। सभी राजनीतिक दलों को जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। इस बार के लोकसभा चुनाव में जिन राजनीतिक दलों को जीत हासिल हुई है, उन्हें बिना किसी भेदभाव के आमजन के लिए गंभीरता से काम करना चाहिए, और जिन्हें हार मिली, उन्हें आमजन की समस्याओं को प्रमुखता से सत्ता पक्ष के सामने रखना चाहिए।

– कृष्णा साहू, दुर्ग

ट्रेंड

मुलाकात की

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू के मुलाकात की और ईसीआई द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति, 18वीं लोकसभा के चुनावों के बाद लोक सभा के लिए चुने गए सदस्यों के नाम शामिल हैं, प्रस्तुत की गई।

-द्रोपदी मुर्मू, राष्ट्रपति

अनमोल उपहार

मुझे एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू कर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। ये आपकी तरफ से उन्हें एक अनमोल उपहार होगा।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

वादे को पूरा करेंगे

तिरुपति में आपने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने का वादा किया था। क्या वह वादा अब पूरा होगा? क्या विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के निजीकरण को अब रोकेंगे? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर चुनावी वादे को पूरा करेंगे?

-जयराम रमेश, कांग्रेस नेता

चैटजीपीटी चित्रण

वान गाफ़की तारों भरी रात और प्रबुद्धता के क्षण में बुद्ध का चैटजीपीटी चित्रण? मैंने चैटजीपीटी से बुद्ध के ज्ञानोदय के क्षण का वर्णन करने को कहा। इसने एक छवि बनाई। मैंने इसके लिए नहीं कहा था तो जाहिर है कि चैटजीपीटी मुझे जान रहा है।

-शेखर कपूर, फिल्म निर्माता

करंट अफेयर

तालिबान ने 63 लोगों को मारे कोड़े, संरा ने की निंदा

अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएएमए) ने बुधवार को सारी पुल प्रांत में तालिबान द्वारा एक दर्जन से अधिक महिलाओं सहित 60 से अधिक लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाने की निंदा की। यूएनएएमए ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान के अधिकारियों ने मंगलवार को कम से कम 63 लोगों को कोड़े मारे। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का सम्मान करने के लिए कहा। तालिबान के उच्चतम न्यायालय ने एक बयान में 14 महिलाओं समेत 63 लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाने की पुष्टि की। इन लोगों पर अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न, चोरी और अनैतिक संबंधों जैसे अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। उन्हें एक खेल स्टेडियम में कोड़े मारे गए। तालिबान ने एक उदार शासन देने के वादों के बावजूद, 2021 में फिर से सत्ता पर काबिज होने के बाद सार्वजनिक रूप से कठोर दंड देना शुरू कर दिया। वे लोगों को किसी भी अपराध के लिए फांसी, कोड़े मारना और पत्थर मारने जैसे दंड देते हैं। तालिबान के 1990 के दशक के शासन में भी यही होता था।

ऑफ बीट

अंतरिक्ष के अजीब रेडियो सिग्नल से वैज्ञानिक हैरान

जब खगोलशास्त्री हमारी रेडियो दूरबीनों को अंतरिक्ष की ओर मोड़ते हैं, तो कभी-कभी ब्रह्मांड के विशाल विस्तार से उत्पन्न होने वाली रेडियो तरंगों के छिटपुट विस्फोटों का पता चलता है। हम उन्हें 'रेडियो क्षणिकाएं' कहते हैं: कुछ केवल एक बार फूटते हैं, फिर कभी नहीं देखे जाते हैं, और अन्य पूर्वानुमानित पैटर्न में टिमटिमाते और बुझते रहते हैं। हमारा मानना है कि अधिकांश रेडियो क्षणिकाएं घूमते हुए न्यूट्रॉन सितारों से आती हैं जिन्हें पल्सर के नाम से जाना जाता है, जो ब्रह्मांडीय प्रकाशस्तंभों की तरह रेडियो तरंगों की नियमित चमक उत्सर्जित करते हैं। आमतौर पर, ये न्यूट्रॉन तारे अविश्वसनीय गति से घूमते हैं, प्रत्येक घूर्णन को पूरा करने में मात्र कुछ सेकंड या सेकंड का एक अंश भी लेते हैं। हाल ही में, हमने एक रेडियो क्षणिक की खोज की है जो खगोलविदों द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज़ से अलग है। न केवल इसका चक्र लगभग एक घंटे लंबा है (अब तक देखा गया सबसे लंबा), बल्कि कई अवलोकनों के दौरान हमने इसे कभी-कभी लंबी, उज्ज्वल चमक, कभी-कभी तेज़, कमजोर लहर उत्सर्जित करते हुए देखा - और कभी-कभी कुछ भी नहीं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

Want to get these Newspapers Daily at earliest

1. AllNewsPaperPaid
2. आकाशवाणी (AUDIO)
3. Contact I'd:- https://t.me/Sikendra_925bot

Type in Search box of Telegram
@AllNewsPaperPaid And you will find a Channel
Name All News Paper Paid Paper join it and receive
daily editions of these epapers at the earliest

Or you can tap on this link:

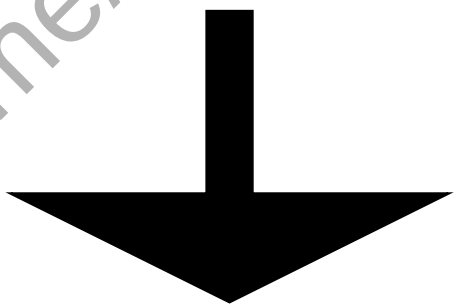

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid